



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---------|---|
| सं. 26] | नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2015/पौष 23, 1936 |
| No. 26] | NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2015/PAUSA 23, 1936 |

रक्षोपाय महानिदेशालय

(सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद कर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2015

विषय : फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (एफएसपी) के आयातों से सम्बंधित रक्षोपाय जांच-सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के अंतर्गत अंतिम जांच परिणाम।

सा.का.नि.28(अ).—सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 11 को ध्यान में रखते हुए

क. प्रक्रिया

1. मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, चेन्नई द्वारा अपने परामर्शदाता मैसर्स एपीजे-एसएलजी ला आफिसेस के माध्यम से सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात रक्षोपाय नियमावली कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत एक आवेदनपत्र 3000 से 4000 मालिक्यूलर भार के फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (जिसे एतदपश्चात पीयूसी या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के भारत में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए दायर किया है जिससे भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के सम्बंधित आयातों द्वारा कारित गम्भीर क्षति/गम्भीर क्षति की चुनौती से इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की रक्षा की जा सके। भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच की शुरुआत का नोटिस दिनांक 22 मई, 2014 को जारी किया गया था और उसे जीएसआर के तहत उसी भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

2. दिनांक 22 मई, 2014 को जारी जांच शुरुआत नोटिस की एक प्रति के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य सम्बंधित मंत्रालयों, निर्यातकर्ता देशों की सरकारों को नई दिल्ली स्थित उसके राजदूतावासों/उच्चायुक्तों के जरिए और अधोलिखित सूचीबद्ध

सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) और 6 (3) के अनुसार प्रेषित की गई :

I. घरेलू उत्पादक :

(क) मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, चेन्नई

II. आयातक/प्रयोगकर्ता

1. आगोश पाली फोम प्राइवेट लिमिटेड, 40, इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, चण्डीगढ़
2. अरविन्द इण्टरनेशनल लिमिटेड, 15 गणेश चन्द्र एवेन्यू, द्वितीय तल, कलकत्ता
3. बानमोर फोम प्राइवेट लिमिटेड, 106/107 इण्डस्ट्रियल एरिया, बानमोर, जिला-मुरेना, मध्य प्रदेश
4. कोजी फोम प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट 17, सर्वे नं. 820/आईपी, ग्राम-माहिम, चन्द्रूपाड़ा, पालघर, थाणे।
5. डी पी फोम प्राइवेट लिमिटेड ए 38-40, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, सिंदारापेट, पाण्डिचेरी-605101
6. डुरा फोम इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 123, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, पिपरिया, दादर और नगर हवेली
7. डियना फोम्स प्राइवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, रायरंगपुर, उड़ीसा-757043
8. देवी पालीयूरीथीन प्राइवेट लिमिटेड, गेट नं. 391/ए गोंडीडुमाला, तेलीगेटपुरी, नासिक-बाम्बे हाईवे, जिला-नासिक
9. इन्के फोम प्राइवेट लिमिटेड, गांव-खेकड़ा, तहसील-बागपत, दिल्ली-बागपत रोड, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
10. फैदर फोम इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ए-10, सेक्टर-VII, नोएडा-201301 (उ. प्र.)
11. फोम हाऊस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, एच 30/2 एम आई डी सी तलाव, महाराष्ट्र
12. फदर फोम इण्टरप्राइजेज, प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 257, उमरकुई, साइली, सिलवासा
13. जाय फोम प्राइवेट लिमिटेड, 30 और 35, सिडको इण्डस्ट्रियल एस्टेट, रानीपेट
14. जूही फोम प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-डीएचएसयू माजरा, जिला रोपड़, खड़ाड़ (पश्चिम बंगाल) 140031
15. कर्लान लिमिटेड, प्लॉट क्रमांक 88 बी, सेक्टर-चण्डका इण्डस्ट्रियल एस्टेट, भुवनेश्वर-751031
16. कमल फोम बी 110 और 111, पिपडिक इण्डस्ट्रियल एस्टेट मेहुपालायम, पाण्डिचेरी-605009
17. एम आर फोम्स, प्लॉट 67, आई डी ए मेल्लापुर, हैदराबाद
18. मल्टीविन फोम्स, प्राइवेट लिमिटेड, 38 कैमाक स्ट्रीट, कोलकाता-700016
19. माडर्न फोम उद्योग, ग्राम-काक्का, लुधियाना, पंजाब रोपड़
20. एन एल फोम इण्डस्ट्रीज, रोड ए 2, 3 और 4, जीआईडीसी, वात्वा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अहमदाबाद
21. नेटसन फोम मैन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक संख्या 218/1, टी. के. कालोल, जिला मेहसाणा, ग्राम नन्दोली
22. पनामा पाली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, साइट-1, बुलन्दशहर एरिया, बी-8, यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद (उ. प्र.)
23. पल्लवी फोम इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम हबीबपुर, जिला गाजियाबाद, नोएडा दादरी रोड (उ.प्र.)
24. पाली फोम, प्लॉट नं.-3, सर्वे नं. 820/आईपी, ग्राम-माहिम पालघर, जिला-थाणा (चन्द्रूपाणा)
25. प्रभात पालीयूरीथीन प्राइवेट लिमिटेड, पिपडिक इण्डस्ट्रियल एस्टेट, 42, चौथा क्रॉस रोड, सिंदार पेट, पाण्डिचेरी
26. प्रताप पालीयूरीथीन प्राइवेट लिमिटेड, 530, मार्शल हाउस, 33/ए, एन एस रोड, कलकत्ता-700001
27. पी. यू. फोम्स प्राइवेट लिमिटेड 96, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता-700007
28. राज लैदर क्लथ इण्डस्ट्रीज, प्राइवेट लिमिटेड, 20वां एम एस जी टी करनाल रोड, ग्राम-बड़खालसा, जिला-सोनीपत (हरियाणा)
29. शीला फोम, प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 37/2, साइट संख्या-4, गाजियाबाद, साहिबाबाद, उ. प्र. -201001
30. एसएसएफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शिवालय मार्केट, अशोक राजपथ, पटना-800004
31. शीला फोम प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-II, ए-10, सेक्टर-8, नोएडा (उ. प्र.)
32. तिरुपति फोम लिमिटेड, प्लॉट संख्या 1023-मेहसन्स हाईवे, ग्राम-राजपुर, कालोल, ताल्लुकाकाडी, जिला-मेहसाड़ा
33. तिरुपति फोम लिमिटेड, प्लॉट संख्या 4-ए, ब्लॉक संख्या-65, ग्राम-खटराज, डाकघर-बड़सार, तालुक-कालोल

34. यू फोम प्राइवेट लिमिटेड, बी-15, 16, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, संतनगर, हैदराबाद-500018
35. मैसर्स सूर्या फोम सिदारपेट मेन रोड, सिदारपेट, पाण्डिचेरी
36. मैसर्स अपर्णा पाली प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 452, गणपति प्लाजा, एम आई रोड, जयपुर-302001 (राजस्थान)
37. मैसर्स साफ्ट फोम इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सर्वे सं. 3852, मेडचल इण्डस्ट्रियल एरिया, आर. आर. जिला-501401 (आंध्र प्रदेश)
38. मैसर्स मद्रास पालीमोल्डस 28, सी एंड डी, कृष्णास्वामी एवेन्यू, मायलापुर, चेन्नई-4
39. मैसर्स जे. जे. फोम्स प्राइवेट लिमिटेड, बी 12/2, साइट-IV साहिबाबाद इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, (उ.प्र.)
40. मैसर्स एम एच पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-15, साइट-बी, सूरजपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, तहसील, दादरी, जिला गाजियाबाद (उ. प्र.)
41. मैसर्स श्री मालानी फोम्स, (प्राइवेट) लिमिटेड, आइडियल टावर्स, सर्वे सं. 115, अकबर रोड, तटबंद, सिकन्दराबाद-500009
42. मैसर्स अलाइड फोम्स प्राइवेट लिमिटेड, डी-32, महेन्द्र एन्क्लेव, जी डी करनाल रोड, दिल्ली-110033
43. मैसर्स नैटसन फोम मैन्यूफैक्चरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 5, पंचायत भवन, भाद्रा, अहमदाबाद-380001
44. मैसर्स कैमी प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 902, जी डी-आईटीएल टावर्स, बी-08, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034
45. मैसर्स तिरुपति फोम लिमिटेड, तिरुपति हाऊस, टोपाल रेस्तरां के निकट, विश्वविद्यालय रोड, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015
46. मैसर्स शीला फोम प्राइवेट लिमिटेड, सी-55, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
47. मैसर्स बानमोर फोम (प्रा.) लिमिटेड, 105-106, इण्डस्ट्रियल एरिया, बानोर-476444 (म. प्र.)
48. मैसर्स भारत फोम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, 15/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003
49. मैसर्स प्यारेलाल फोम्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कोय्यामारककाडु, कांझीकोड, पालक्कड-678621 केरल
50. मैसर्स प्यारेलाल क्वायर प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड 1501/ए, राम गली, भागीरथ प्लेस, दिल्ली- 110006
51. मैसर्स पी. यू. फोम्स, प्राइवेट लिमिटेड दक्खिन राज्याधारपुर, दिल्ली रोड (निकट पावर हाऊस), सीरमपुर हुगली (पश्चिम बंगाल)
52. मैसर्स मोका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, सी-42, सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, बैस गोदाम, जयपुर-302006
53. मैसर्स डाव कैमिकल इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम तल, ब्लाक बी, 02, गोदरेज बिजनेस जिला, एल बी एम मार्ग, बिखरोली (पश्चिम), मुम्बई-400079
54. मैसर्स बेयर मैटीरियल साइंस, प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट 1 ए, उद्योग केन्द्र, सेक्टर इकोटेक-III, ग्रेटर नोएडा-201306
55. मैसर्स डियना फोम्स (प्राइवेट) लिमिटेड, रायरंगपुर, मयूरभंज, उड़ीसा
56. मैसर्स फ्लेक्सीपोल फोम्स प्राइवेट लिमिटेड, ई-1162, भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-IV भिवाड़ी (राजस्थान)
57. मैसर्स स्प्रिंगवेल मैट्रिसेज प्राइवेट लिमिटेड, ए-49, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, दिल्ली-34
58. पालीयूरीथीन एसोसिएशन आफ इण्डिया, श्री के. राममूर्ति, सचिव, 6/6 पोयस रोड, पहली गली, चेन्नई-600018

III. निर्यातक

1. एस. के. आक्सीकैमिकल कम्पनी लिमिटेड 23-10, योड़गो डांग, संगडंगयो-जीयू, सियोल, दक्षिण कोरिया-180-0101
2. बेयर पालीयूरीथीन ताइवान लिमिटेड, 2 एफ 290, चंग सियाओ, ई रोड, सेक्टर 4, ताइपेई, ताइवान
3. झेजियांग सैनहुआन कैमिकल कम्पनी लिमिटेड सं. 1007, जिउ लिंग XI रोड, योंगकांग झेजियांग 321300 चीन जन-गण
4. डाव क्विमिका एसए, रुआ एलेक्जेन्डर ड्यूमास 1671, पी ओ बाक्स-9037, 010065-970, साओ पाउलो, ब्राजील
5. शेल कैमिकल्स, शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड, सिंगापुर-239920

6. ब्ल्यू डायमंड आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड एसीएन 00 3068344, पी. ओ. बाक्स-349, कोल्लारी, एनएसडब्ल्यू, 2097 आस्ट्रेलिया
7. सैनियो कैमिकल्स, जापान
8. बेयर पालीयूरीथीन एशिया (पीटीई) लिमिटेड, फेशर जीएमबीएच, वोल्फ वाल्सोड, एजी, जर्मनी
10. रैपसाल क्विमिका सा पैसिओ डि ला कैस्टेलाना, 280 ई-28086 मैड्रिड स्पेन
11. टोयोटा टश्यूशो कारपोरेशन 2-13-13 कोनन, मिंटो-कू, टोक्यो (जापान)
12. मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड, सिंगापुर
13. मैसर्स शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लिमिटेड, सिंगापुर
14. मैसर्स डाव यूरोप जीएमबीएच
15. मैसर्स डाव कैमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
16. मैसर्स बेयर (साउथ ईस्ट एशिया), पीटीई लिमिटेड, 63 चूलिया स्ट्रीट 14वां तल, ओसीबीसी सेन्टर ईस्ट, सिंगापुर-049514
17. मैसर्स आईआरपीसी पालियोल कम्पनी लिमिटेड, 555/2, एनर्जी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग-बी, 7वां तल, विभावाडी रंगसिट रोड, चाटुचार्क, बैंकाक 10900, थाईलैण्ड

IV. नियातकर्ता राष्ट्र

1. मैसर्स यूरोपियन यूनियन, भारत में प्रतिनिधिमंडल, 65, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली-110003
 2. जापान सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला जापान का राजदूतावास, 50जी, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
 3. रूस का राजदूतावास, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
 4. मैक्सिको का राजदूतावास, सी-8, बैनिटो जुआरेज मार्ग, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली-110021
 5. यूएसए का राजदूतावास, शान्तिपथ, नई दिल्ली
 6. सिंगापुर गणराज्य का उच्चायोग, ई-6, चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
 7. दक्षिण कोरिया का राजदूतावास, 9 चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
 8. शाही थाई राजदूतावास, 13-1/3, वसन्त विहार, नई दिल्ली
 9. भारत में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, 34, 4 पश्चिमी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली
 10. नीदरलैण्ड का राजदूतावास, 6/50 एफ, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
 11. चीन का राजदूतावास 50 घ, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
 12. आस्ट्रेलिया का राजदूतावास 1/50-जी, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
 13. इण्डोनेशिया गणराज्य का राजदूतावास, 50-ए, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021
 14. भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल, ब्लाक 50-ई, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-10021
6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का स्थल दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया। सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा या।
7. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त सभी विचारों को समुचित निर्धारण करते वक्त ध्यान में रखा गया। प्राप्त या अधिप्राप्त अगोपनीय सूचनाको सार्वजनिक फाइल में रखा गया। कई हितबद्ध पक्षकारों/आयातकों/निर्यातकों ने जांच शुरूआत पश्चात प्रस्तुतीकरण भी दायर किए।
8. दिनांक 29.09.2014 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया, इस सार्वजनिक सुनवाई के लिए नोटिस सं. 15.09.2014 को जारी किया गया इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वह इस सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अभिव्यक्त किए गए अपने विचारों का सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) के अनुरूप अपने लिखित प्रस्तुतीकरण भी दिनांक 10.10.2014 तक कर दें। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित

प्रस्तुतीकरणों की प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई। हितबद्ध पक्षकारों को भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतीकरणों की प्रतुक्तियां, यदि कोई, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

9. सभी हितबद्ध पक्षकारों या अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा घरेलू उपयोग के प्रस्तुतीकरणों पर लिखित प्रस्तुतीकरणों के रूप में या प्रत्युत्तर और प्रत्युक्तियों के रूप में अभिव्यक्त विचारों की जांच की गई और समुचित निर्धारण करते वक्त उन्हें ध्यान में रखा गया।

ख. जांच शुरूआत नोटिस के पश्चात दायर घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों के विचार :

(I) घरेलू उद्योग के विचार

(क) यह आवेदक सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार घरेलू उद्योग है क्योंकि वे ही इस विचाराधीन उत्पाद के भारत में एक मात्र उत्पादक हैं और इस प्रकार वर्तमान याचिका दायर करने का उनका हक बनता है। वे इस डीओपी के कुल भारतीय उत्पादन में भारी अनुपात का उत्पादन करते हैं।

(ख) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक की अवधि के पैरामीटरों जैसे उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग, रोजगार, उत्पादकता, नकदी प्रवाह, निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ, ग्राही उपयोग, स्टॉक, खपत, बिक्री, बाजार हिस्सा, कीमत अधोरदन एवं लाभ प्रदायकता का व्यापक मूल्यांकन सम्बद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों को गम्भीर क्षति अथवा भारी परिक्षण दर्शाता है।

(ग) भारतीय उत्पादक का बाजार हिस्सा जो कि वर्ष 2010-11 में 39%, घटकर जांच की अवधि के दौरान 19% रह गया। विभिन्न देशों में निर्यातोन्मुख क्षमताओं की शुरूआत के कारण आयातों में भयंकर वृद्धि हुई है। यह भारतीय बाजार आयातों का सम्बर्धित आगमन प्रदर्शित करता है।

(घ) घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। यह एक स्पष्ट संकेतक है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के एक बड़े भाग पर आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

(ङ.) आधार वर्ष अर्थात् 2010-11 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदाता में भारी गिरावट आई है। वर्ष 2010-11 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदाता 11 से परिवर्तित होकर वर्ष 2013-14 में घाटे में बदल गई। वर्ष 2010-11 की तुलना में घरेलू उद्योगको **** लाख रुपये का घाटा हुआ। उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ/एमटी में 571% का घाटा हुआ है।

(च) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग भी में क्षति जांच की अवधि के दौरान 34.60% तक की भारी गिरावट आई है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि उसी अवधि के दौरान मांग में लगभग 76% तक की वृद्धि हुई है।

(छ) संक्षेप में, घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई गम्भीर क्षति और न्यूनतर कीमतों पर होने वाले सम्बर्धित आयातों के बीच एक सह-संबंध है और उन आयातों में इस वृद्धि का कीमतों पर दबाव और घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री मात्रा में कमी के रूप में क्षतिकारी प्रभाव हुआ है।

(II) निर्यातकर्ता राष्ट्रों के विचार

(क) रूसी परिसंघ

रूसी परिसंघ के उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने यह प्रस्तुतीकरण किया है कि जांच की अवधि वर्ष 2010 से 2013 के दौरान सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप-शीर्षक संख्या 39072010 के अंतर्गत आने वाली वस्तु का आयात और भारत को रूसी परिसंघ से किया गया आयात तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है इसलिए सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की (धारा 8 ख) के अंतर्गत बने रक्षोपाय प्रावधानों और डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 के अनुसार रूसी परिसंघ को जांच के अंतर्गत आने वाले देशों की सूची से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए।

(III) निर्यातकों के विचार

(क) मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड और मैसर्स शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लिमिटेड ने अपने प्रारम्भिक प्रस्तुतीकरण मैसर्स लक्ष्मी कुमारन एण्ड श्रीधरन अटार्नीज के माध्यम से दायर किए हैं जो निम्नलिखित हैं-
(i) प्रारम्भिक आपत्तियां

- वर्तमान जांच की शुरुआत करना विधिविरुद्ध है क्योंकि भारत-आशियान एफटीए और भारत-सिंगापुर सीईसीए में क्रमशः इन दो करारों के अंतर्गत शुरु की गई रक्षोपाय जांच के मामले में विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के लिए प्रावधान हैं।
- यह आवेदक व्यापार उपचारों का श्रृंखला (सीरियल) प्रयोक्ता है, इसने लगभग उन सभी देशों के विरुद्ध, जिन्होंने भारत को सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया है, पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन किया है और उसने विगत 14 वर्षों में सम्बद्ध वस्तु के विभिन्न देशों से होने वाले लगभग सभी आयातों को बाहर निकाल देने का प्रयास किया है।
- इस आवेदनक ने अभी हाल ही में वर्ष 2013 में पाटनरोधी शुल्क के रूप में संरक्षण प्राप्त करने के लिए पाटनरोधी महा निदेशालय में भी आवेदन किया है। घरेलू उद्योग ने स्वतः ही यह स्वीकार किया है कि उसे पाटन के कारण, यह मानते हुए कि केवल एक ही उद्योग था, क्षति हुई है, इसलिए इस कारण से भी वर्तमान रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने में कोई तत्त्व नहीं है।
- आवेदक ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि वह भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। तथापि, प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैसर्स एक्सपैन्डेड पालिमेर सिस्टम्स भी भारत में समान वस्तु के उत्पादक के रूप में अर्ह होगी। उनके साथ याचिका में आवेदक द्वारा कहीं भी पत्राचार नहीं किया गया है और प्राधिकारी को चाहिए कि वह इस याचिका में पूर्णता के अभाव के कारण इस जांच को समुचित रूप से समाप्त कर दे।
- आवेदक द्वारा दायर की गई याचिका और महा निदेशक रक्षोपाय द्वारा जारी किया गया जांच शुरुआत नोटिस, आयात सांख्यिकी के अलग-अलग स्रोतों के कारण पूर्णतया आधारहीन है।
- क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए अपरिष्कृत एवं छंटी हुई आयात सांख्यिकी की एमएस-एक्सेल रूपान्तर प्रदान कराया जाना चाहिए।
- यह कि आयातों की दोहरी प्रविष्टि की गई है, क्योंकि सम्बद्ध उत्पाद का भारत को जब आयात किया जाता है तब उन्हें पहले एक वेयरहाउसिंग प्रविष्टि बिल भरकर सीमा शुल्क बाण्डेड वेयर हाऊसों में एकत्र किया जाता है और फिर एक निश्चित समय के अन्दर घरेलू खपत के लिए प्रविष्टि बिल भरके छोटी-छोटी मात्रा में वहां से उठाया जाता है। तथापि, आयात सांख्यिकी में इन दोनों सम्यवहारों को अलग-अलग रिपोर्ट किया जाता है जिसके कारण दोहरी गणना हो जाती है।
- 9 माह की आयात सांख्यिकी का वार्षिकीकरण करके वर्तमान मामले के तथ्यों में वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक आयात आंकड़ों का निर्धारण करने का तरीका उचित नहीं है।
- बाजार आसूचना के अनुसार यह माना जाता है कि आवेदक अपने ग्राहकों को वस्तुतः डिस्काउंट की पेशकश करता है। प्रतिवादियों ने प्राधिकारी से इस तथ्य की जांच करने का अनुरोध किया है।
- यह याचिका भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें कई अनवांछित गोपनीयता के दावे किए गए हैं। आवेदक ने उपर्युक्त क्षति एवं लेखाकरण आंकड़ों का अनुक्रमित रूपांतर प्रदान नहीं कराया है।
- वर्तमान जांच में आवेदक ने न तो कारणों का कोई उल्लेख किया है और न ही उसने संदर्भित साक्ष्यों का कोई संक्षिप्तीकरण भी नहीं दिया है कि उक्त सूचना को निर्मुक्त करने से आवेदक के वैध वाणिज्यिक हित किस तरह से अथवा क्यों प्रभावित होंगे।
- आवेदक ने उचित बाजार कीमत का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रिया पद्धति का खुलासा भी नहीं किया है।

II. विशेष प्रस्तुतीकरण-

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XIX का अनुपालन

(ख) प्राधिकारी पर (i) अनपेक्षित विकास की पहचान करने और (ii) ऐसे सम्पर्क स्थापित करने कि इस अनपेक्षित विकास से आयात में वृद्धि कैसे हुई, का दोहरा उत्तरदायित्व था। न तो आवेदक ने और न ही प्राधिकारी ने किसी अनपेक्षित विकास की पहचान कर पाई।

(ग) प्राधिकारी पर (i) सम्बद्ध उत्पाद के संबंध में भारत द्वारा जीएटीटी के अंतर्गत प्राप्त प्रशुल्क रियायतों सहित विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की पहचान करना और (ii) यह सिद्ध करना कि क्या भारत में सम्बद्ध उत्पाद का सम्बर्धित आयातों के साथ किसी विशिष्ट प्रतिबद्धता का कोई सम्बन्ध है, का दोहरा उत्तरदायित्व है।

(घ) वर्तमान मामले में यह आयात अभिनव, अचानक, तीव्र और बहुत अधिक भी नहीं है, जिसके कारण सीमा सम्बंध पूरा नहीं होता है।

(ङ.) महा निदेशक रक्षोपाय ने लाइनियर अल्कायल बेन्जीन (लैब) के जांच परिणाम में स्वयं ही यह उत्पादित किया है कि यद्यपि समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से वृद्धि जारी रही तथापि धारा 8 ख (1) के अंतर्गत पूरी नहीं की जा सकी।

(च) वर्तमान मामले में वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 को मिलाकर बनी क्षति अवधि में कोई वृद्धि नहीं हुई है और जहां तक जांच शुरुआत नोटिस में आंकड़ों का संबंध है आयात में वर्ष 2013-14 में केवल मामूली सी ही वृद्धि हुई है।

(छ) आयातों में वृद्धि आकस्मिक रूप से नहीं हुई है और न ही यह बहुत तीव्र है, यह सामान्य रूप से एक क्रमिक वृद्धि है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आयातों में वृद्धि अचानक, अभिनव, तीव्र और बहुत अधिक नहीं हुई है और आवेदक द्वारा दिए गए इस तर्क को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

(ज) किसी गम्भीर क्षति अथवा कारणात्मकता के किसी मामले के संबंध में कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं दिया गया है।

झ) फीड स्टॉक की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन और बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(ञ) आवेदक प्रोपायलीन का अधिप्रापण सीपीसीएल से करता है जो आवेदक को प्रोपायलीन का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। यह मात्रा भी सीमित है क्योंकि सीपीसीएल एक निर्धारित मात्रा से अधिक प्रोपायलीन की आपूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए सीपीसीएल द्वारा आवेदक को प्रोपायलीन की इस अधिकतम सीमा के कारण आवेदक केवल एक निश्चित मात्रा में ही प्रोपायलीन ऑक्साइड (पी ओ) का विनिर्माण कर सकता है और सम्बद्ध उत्पाद का विनिर्माण करने में एक निश्चित मात्रा में ही पी ओ का उपयोग कर सकता है उससे अधिक नहीं।

(ट) प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई क्षमता की सत्यपरकता पर भी संदेह है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए विरोधाभाषी आंकड़ों का स्पष्टीकरण लें और उनकी जांच करें।

(ठ) क्षमता उपयोग में कमी होने के दो कारण हैं:

i. फीड स्टॉक प्रोपायलीन ऑक्साइड (पी ओ) की उपलब्धता की कमी, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है और जिससे क्षमता का कम उपयोग होगा और क्षमता उपयोग में कमी आएगी।

ii. आवेदक की क्षमता में 36% तक की वृद्धि जिससे भी क्षमता उपयोग में स्पष्टतः कमी आएगी।

(ड) क्षमता उपयोग में होने वाली किसी भी कमी के लिए सम्बद्ध उत्पाद का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित फीड स्टॉक (पी ओ) की उपलब्धता में कमी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है आवेदक ने वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 में यह स्वीकार किया है कि क्षमता उपयोग में यह कमी पी ओ के अभाव के कारण आई है। वे 'पी ओ' का भारी मात्रा में आयात करने के लिए एन्नोर पत्तन पर एक आयात टर्मिनल की स्थापना कर रहे हैं जिससे पी ओ की उपलब्धता में सुधार किया जा सके।

(ढ) यह भी नोट किया जाता है कि इस तरह का भारी मात्रा में भण्डारण अभी भी प्रगति में हो सकता है और हो सकता है कि यह अभी पूरा न हो पाया हो। इसे आवेदक द्वारा याचिका में, अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 के पृष्ठ 179 पर, स्वीकार किया गया है।

(ण) पाटनरोधी याचिका में प्रदान कराए गए लाभ प्रदाता के आंकड़ें आवेदक द्वारा इस वर्तमान जांच में प्रदान कराए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

(त) यह आवेदक अपने उत्पाद का 2010-11 में 101%, वर्ष 2011-12 में 99%, वर्ष 2012-13 में 96% और जांच की अवधि में 98% बिक्री करने में सक्षम रहा है। इसलिए, आवेदक के पास उत्पादन और बिक्री के अनुपात से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है; फीड स्टॉक (पी ओ) की अनुपलब्धता के कारण ही लाभ प्रदाता में कमी आई है।

17. आवेदक द्वारा दायर की गई याचिका के एनसीवी में अनुक्रमित रूप में कीमत अधोरदन, निग्रहण और अवमंदन आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

18. आवेदक अपना 100% क्षमता उपयोग करके भी मांग को पूरा नहीं कर सकता है। भारत स्थित प्रयोगकर्ताओं को अपेक्षित मांग का अनिवार्यतः कम से कम 66% का आयात करना ही होगा और विशिष्टतः यदि वे एकमात्र आपूर्तिकर्ता पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं तो दीर्घावधिक आपूर्तियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्हें विदेशों में स्थायी संबंधों में निवेश करना होगा।

19. आवेदक मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी क्षमता में विस्तार करना चाहता है परंतु वह आवेदक के अपने निजी स्वीकरण के अनुरूप, पूरी नहीं की जा सकती है, कि मनाली क्षेत्र का ऋण स्थगन क्षमता वृद्धि में किसी दायरे को अस्वीकार कर देता है।

20. वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 में आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि ग्राही विद्युत संयंत्र (सीपीपी) के लिए बायोमास ईंधन की उपलब्धता में कमी हो गई है जिसके कारण आवेदक को अपना सीपीपी न्यूनतर लोड पर प्रचालित करने पर मजबूर होना पड़ता है।

21. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विद्युत की खपत से संबंधित प्रतिबंध और ग्राही विद्युत उत्पादन में कमी से आवेदक पर भारी दबाव आ गया जिसके कारण उत्पादन में कमी आ गई।

22. यह कि आवेदक द्वारा सहन की गई "गम्भीर क्षति" कुछ अन्य कारणों से भी हो सकती है जैसे:

(i) फीड स्टॉक उपलब्धता की कमी

(ii) उत्पादन और बिक्री में परिणामी कमी

(iii) आवेदक की भारत में प्रोपायलीन के एकमात्र आपूर्तिकर्ता चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर निर्भरता; और

(iv) सम्बद्ध उत्पाद की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करने में आवेदक की अक्षमता

23. उपर्युक्त में से कोई भी कारण किसी भी रूप में सम्बद्ध उत्पाद की आयात मात्रा से जुड़ा नहीं है। इसलिए वर्तमान जांच में कारणात्मक संबंध विश्लेषण असफल हो जाता है और इसलिए इस जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

24. आवेदक ने एक असाध्य समायोजन योजना प्रस्तुत की है।

25. इसके अतिरिक्त, अवरोधों को दूर करना भी सम्भव नहीं है जैसा कि आवेदक ने अपने वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 में उल्लेख किया है और याचिका के पृष्ठ 103 पर प्रावधान किया है कि आवेदक ने यह प्रयास पहले ही कर लिया है और स्पष्टतः आवेदक को इससे अपनी क्षति दूर करने में सहायता नहीं मिली।

26. यह भी प्रस्तुत करने की योजना त्रुटिपूर्ण है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। हर हाल में, नियम लागत कम करने का अंतिम लागत 1% से भी कम प्रभाव पड़ेगा।

27. क्षमता उपयोग में वृद्धि नहीं की जा सकती है क्योंकि फीड स्टॉक उपलब्ध नहीं है।

28. आवेदक ने यह उल्लेख भी किया है कि उसकी अपनी ग्राही प्रोपायलीन ऑक्साइड उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की योजना है तथापि, यह योजना कच्चे माल, जो कि प्रोपायलीन है, की पर्याप्त आपूर्ति के बिना निष्प्रभावी है।

29. पी ओ के भारी परिवहन का बहुत ही अल्पतम प्रभाव होगा।

30. महानिदेशक, रक्षोपाय ने मिथायल एसिटोएसिटेट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच में दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 के अंतिम जांच परिणाम के तहत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई समायोजन योजना को यह प्रेक्षण करते हुए नकार दिया कि इसमें सकारात्मक समायोजन के लिए कोई ठोस समयबद्ध योजना नहीं है और यह केवल एक प्रस्ताव है जिसे वह भविष्य में क्रियान्वित करना चाहता है। ऐसी ही स्थिति इस जांच में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए इन तथ्यों पर भी लागू होगी।

ख) मैसर्स डाउ यूरोप जीएम बीएच-

1. वर्तमान आवेदन दुर्भावना के आशय से दायर की गई है इसके अतिरिक्त, यह त्रुटिपूर्ण है और इसमें विशिष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है और तदनुसार अनुप्रयोज्य नियमों और संधि प्रतिबद्धताओं को तत्काल समाप्त करने के लिए अधिदेशित है।
2. जहां तक डाउ का संबंध है और आयातक प्रश्नवाली में प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आयातों का कोई भी उद्रेक नहीं हुआ है। डाउ यूरोप से आयातों में भारी कमी आई है जैसा कि गोपनीय आंकड़ों से स्पष्ट है।
3. आवेदनकर्ता व्यापार प्रतिविधानों का आदतन प्रयोगकर्ता है और यह वर्ष 1998 से रक्षोपाय एवं पाटनरोधी शुल्क का लाभग्राही रहा है।
4. पाटनरोधी जांच एमपीएल के अनुरोध पर वर्ष 2001 से शुरू की गई है। यह पूर्णतया सपष्ट है कि यह एक अकार्यकुशल उद्योग का मामला है जो सम्बद्ध वस्तु के संबंध में अतिजीविता के लिए प्रतिस्पर्धा के बजाय संरक्षणवादी प्रणाली पर भरोसा करता है। यह विधि में अनुमेय नहीं और इसलिए यह रक्षोपाय महानिदेशालय (महानिदेशक) पर निर्भर करता है कि वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना पर ध्यान दें और इस आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दें।
5. इस आवेदन में अत्यधिक गोपनीयता की मांग की गई है।
6. मांग और आपूर्ति में अन्तराल में निर्यात को आवश्यक कर दिया है। मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, अपनी सौ प्रतिशत क्षमता उपयोग के बावजूद, भारत में सम्बद्ध वस्तु की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी।
7. आयातों से रक्षोपाय जांच प्रारम्भ करना या शुल्क अधिरोपित करना अधिदिष्ट नहीं जान पड़ता है।
8. जहां तक डाउ का संबंध है और आयातक प्रश्नवाली में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर यह पूर्णतया स्पष्ट है कि आयातों का कोई उद्रेक नहीं हुआ।
9. जांच की अवधि के दौरान (2010-14) एमपीएल की लाभ प्रदाता में वृद्धि हुई है।
10. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट/तुलनापत्र के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि जांच की अवधि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 के दौरान सकल मार्जिन में भारी वृद्धि हुई है। इससे इन वर्षों के दौरान उनके लाभ में सुधार होना और कोई वित्तीय घाटा न होना भी स्पष्टतया न्यायोचित ठहरता है।
11. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट/तुलनापत्र के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी पालियोल क्षमता 33000 एमटी से बढ़ाकर 50000 एमटी कर ली परन्तु उनकी सभी रिपोर्टों में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि पालियोल की संस्थापित क्षमता ग्रेड पर आश्रित है। इसलिए 25000 एमटी की संस्थापित क्षमता को ही लोचशील स्लैब पालियोल/एमएसपी के रूप में नहीं माना जा सकता है।
12. यह सुस्थापित तथ्य है कि घरेलू उद्योग की अक्षमता को ढकने के लिए रक्षोपाय शुल्क और पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और निश्चित रूप से लाभ को शेयरहोल्डरों को इनाम देने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने लाभांश भुगतान जो वर्ष 2001 में 0.38 रुपये/प्रति शेयर (एफ वी:5 रुपये) था, बढ़ाकर वर्ष 2012 में 0.6 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
13. घरेलू उद्योग का यह दावा कि जांच की अवधि के दौरान प्रोपायलीन की लागत में वृद्धि हो गई है परन्तु पालियोल की कीमतों में आयातों के कारण वृद्धि नहीं की जा सकी। इससे तथ्यों का गलत प्रतिनिधित्व होता है।
14. एमपीएल हमेशा ही अप्रतिस्पर्धी रहा है क्योंकि उसकी संस्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन प्रचालनों का अर्थशास्त्रीय पैमाना प्राप्त करने और बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए घरेलू उद्योग की अक्षमता को कवर करने के लिए घरेलू उद्योग ने पिछले पन्द्रह वर्षों से सदैव ही बेहद आपातकालीन उपायों जैसे रक्षोपाय और पाटनरोधी शुल्क की सहायता की तलाश करता रहा है।
15. तथ्यों से इसकी सम्पुष्टि होती है कि फ्लेक्सिबिल स्लैब फोम की प्रति व्यक्ति खपत इस क्षेत्र में सबसे कम रही है।
16. याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी जांच के लिए एक याचिका पहले ही दायर कर रखी है। जो समीक्षाधीन है और उद्योग के लिए यह पूरी तरह से अनुचित होगा कि वह एक ही समय पर विविध प्रकार का संरक्षण प्राप्त करें जिससे अनुप्रवाही उद्योग की क्षमता पूर्णतया अप्रतिस्पर्धी हो जाए।

17. आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। ऊपर दर्शाए गए अनुसार यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को होने वाली कोई भी कथित क्षति अपनी निजी लागत निर्धारण अक्षमता कच्चे माल का उच्च कीमतों पर आयात, तथा अन्य कारणों से बाजार की जरूरत को पूरा करने के कारण हुई है।

(IV) आयातकों/प्रयोगकर्ताओं के विचार

क) मैसर्स स्प्रिंगफ़ल पालीयूरीथीन फोमस प्राइवेट लिमिटेड

(क) मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (संक्षेप में डब्ल्यूपीसी) की फ्लेक्सिबिल स्लैब स्टॉक पालियोल का उत्पादन करने की संस्थापित क्षमता सम्पूर्ण भारत में स्थित विभिन्न पालीयूरीथीन फोम (संक्षेप में पीयूपी) की मांग की तुलना में बहुत कम है।

(ख) एमपीएल स्लैब स्टॉक पालियोल का अन्य देशों को निर्यात भी करता है। सीमा शुल्क के पास उपलब्ध रिकार्डों की प्रतियों से यह देखा जा सकता है कि वह कीमत जिस पर हम आयात कर रहे हैं, उसी अवधि के दौरान उस कीमत के बिल्कुल अनुरूप है जिस पर एमपीएल निर्यात कर रहा है और यह कि यह कीमतें इस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित देशों के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप हैं।

(ग) एम पी एल की विभिन्न मध्यवर्तियों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे वस्तु उत्पादों का विनिर्माण करने की मिली जुली उत्पादन क्षमता है। इस प्रकार की शेयर्ड उत्पादन क्षमता का आशय यह है कि स्लैब स्टॉक पालियोल की उत्पादन क्षमता में कमी का आशय यह नहीं कि वह अपनी संस्थापित क्षमता का कम उपयोग कर रहा है। इसका साधारण सा आशय यह है कि वे कुछ अन्य उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं (उदाहरण के लिए डीजीपी)

(घ) वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए प्रकाशित उनके तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखाओं का अध्ययन लाभ दर्शाता है और उसने अपने शेयर धारकों को लाभान्श की घोषणा की है।

(ड.) अत्यधिक समानपूर्वक यह तर्क दिया जाता है कि एमपीएल द्वारा रक्षोपाय शुल्क के लिए किया गया आवेदनपत्र खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(च) यह कि फ्लेक्सिबिल स्लैब स्टॉक पालियोल की कीमत निर्धारण कर निश्चय बाजार के डायनामिक्स द्वारा किया जाता है।

(छ) फ्लेक्सिबिल स्लैब स्टॉक फोम के एक विनिर्माता के रूप में हम पालियोल के आयातों पर अतिरिक्त शुल्क के गैर न्यायोचित उदग्रहण द्वारा बोझ से अधिक दबे हुए नहीं हैं।

ख) मैसर्स तिरुपति फोम लिमिटेड

(क) हम विचाराधीन पालियोल का प्रयोग करते हुए फोम के सबसे बड़े उत्पादनकर्ताओं में से एक हैं।

(ख) हम इस विचाराधीन पालियोल पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का सख्ती से विरोध करते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमारी कम्पनी, उद्योग और उपयोगकर्ताओं को भारी घाटा होगा।

(ग) हम पालियोल का आयात करने के लिए इसलिए मजबूर नहीं हैं कि उसका आयात करना सस्ता है बल्कि हम इसका आयात इसलिए करते हैं क्योंकि घरेलू आपूर्तिकर्ता मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड उसकी आपूर्ति करने में अक्षम है।

(घ) उनकी आपूर्तियां असंगत हैं और पीक सीजन के दौरान हम केवल स्थानीय स्रोत पर निर्भर रहें तो हमें कष्ट सहन करना पड़ सकता है।

(ड) हम यह उल्लेख करते हैं कि आयातित पालियोल की गुणवत्ता मनाली पेट्रो द्वारा आपूर्ति पालियोल से बेहतर हैं।

(च) ऐसा देखा गया है कि याचिका में दिए गए आयात आंकड़े जांच शुरुआत के लिए प्रयोग किए गए आयात आंकड़ों से भिन्न हैं। आयात आंकड़ों सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्षक 39072010 पर आधारित है जो 3000 से कम मालिक्यूलर भार के तथा 4000 से अधिक मालिक्यूलर भार के पालियोल सहित सभी प्रकार के पालियोल को कवर करता है। दूसरी ओर भारी मात्रा में विचाराधीन पालियोल का आयात प्रशुल्क शीर्षक सं. 39072090 के अंतर्गत किया जाता है जिसे आयात आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि यह

सम्पूर्ण जांच शुरुआत गलत आयात आंकड़ों पर आधारित है इसलिए जांच शुरुआत की कार्रवाई को अविलम्ब समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(ग) मैसर्स शीला फोम्स प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स टीएलसी लीमल के जरिए

(क) इस जांच शुरुआत नोटिस का घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र से कोई सामंजस्य नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई सूचना इस जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ न तो पर्याप्त है और न ही यथार्थ है। तदनुसार प्राधिकारी ने ऐसे साक्ष्य को नामंजूर कर दिया है आगे की कार्रवाई डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों के आधार पर करने का निश्चय किया है जो आवेदन पत्र में समाहित नहीं हैं परंतु प्राधिकारी ने उन्हें प्राप्त किया है। इस जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई सूचना के बीच स्पष्ट विसंगतियां हैं।

(ख) उपर्युक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने त्रुटिपूर्ण सूचना प्रस्तुत की है और केवल इस कारण से ही यह आवेदन पत्र नामंजूर किया जा सकता है क्योंकि आवेदन पत्र में अर्न्निहित सूचना न तो परिशुद्ध है और न ही समुचित।

(ग) डीजीसीआईएस द्वारा प्राप्त सूचना उपर्युक्त नहीं है क्योंकि यह प्रस्तुत किया जाता है कि, सम्बद्ध वस्तु के दायरे से बाहर आने वाली मर्दों का भी उपर्युक्त शीर्षक के अंतर्गत आयात किया जा रहा है। इसी तरह, 3000-4000 के बीच के मालिक्यूलर भार के कुछ ऐसे पालियोल भी हैं जिनका आयात 39072090 के अंतर्गत किया जाता है।

(घ) इस तथ्य के मद्देनजर कि यह दर्शाने के लिए कोई अधिप्रमाणित आंकड़े नहीं हैं जो रक्षोपाय करार के साथ पठित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8 ख की जरूरतों को पूरा करने के लिए यथा तथ्य आयातों और आयातों के उद्रेक, यदि कोई, को दर्शाता हो। जीएटीटी के अनुच्छेद xix का पालन करना प्राधिकारी पर दोहरी प्रतिबद्धता डालता है : (i) ऐसे विकास की पहचान करना जो अनपेक्षित थे; और (ii) ऐसे सम्पर्क स्थापित करना कि अनपेक्षित विकास से आयातों में वृद्धि कैसे हुई। परंतु उसे स्पष्ट नहीं किया गया है।

(ड.) जीएटीटी के अनुच्छेद xix का पालन करना प्राधिकारी पर दोहरी प्रतिबद्धता डालता है: (i) जीएटीटी के अंतर्गत सम्बद्ध वस्तु के संबंध में भारत द्वारा प्राप्त प्रशुल्क रियायतों सहित विशिष्ट दायित्वों की पहचान करना; और (ii) उस विशिष्ट बाध्यता का संबंध भारत में सम्बद्ध उत्पाद के आयातों में वृद्धि के साथ स्थापित करना। परंतु यह कार्य नहीं किया गया है।

(च) अन्य देशों के साथ-साथ भारत भी आयातों पर सीमा शुल्क कम करने पर सहमत हुआ है और उसने एक ऐसी अधिकतम दर का प्रावधान किया है जिससे अधिक पर वह आधारभूत सीमा शुल्क प्रभारित नहीं करेगा। वह अधिकतम दर जिस पर सहमति हुई है "बाउण्ड रेट" के रूप में जाना जाता है और यह वह दर है जिसके लिए केवल भारत ने ही अपनी बाध्यता दर्शायी है। सीमा शुल्क में इस बाउण्ड दर से नीचे कोई अन्य कमी करना भारत द्वारा दर्शायी गई बाध्यताओं के अनुरूप नहीं होगा भारत के सीमा शुल्क प्रशुल्क 2013-14 के अनुसार बाउण्ड दर 40% है और सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर वर्तमान सीमा शुल्क की दर 7.5 प्रतिशत है। इसलिए सीमा शुल्क में 40 प्रतिशत की कमी करने से आयात में हुई किसी भी वृद्धि को वर्ष 1994 में भारत द्वारा प्रदान कराई गई बाध्यताओं और प्रशुल्क रियायतों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है।

(छ) आयातों में कोई उद्रेक नहीं है: वर्तमान मामले के तथ्य यह संकेत करते हैं कि रिकार्ड में यह दर्शाने के लिए कोई अकाट्य साक्ष्य नहीं है कि आयातों में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि आयातों में उद्रेक हुआ है।

(ज) आवेदन में लाभ प्रदाता के सम्बंध में अशुद्ध या असत्य सूचना दी गई है। बिक्रियों पर लाभ में पिछले दो वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है। पुनः यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक द्वारा लाभ का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की गई उत्पादन लागत का खुलासा किया जाए। आवेदक से कम से कम यह प्रकटन करने की मांग की जाए कि आवेदक द्वारा विनिर्मित सम्बद्ध वस्तु और अन्य उत्पादों के बीच सामान्य लागत आबंटित करने का आधार क्या है।

(झ) समायोजन योजना व्यवहार्य नहीं है। आवेदन में घरेलू उत्पादकों की समायोजन योजना का केवल खाका ही दिया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि क्षमता उपयोग का स्तर बढ़ जाएगा। तथापि, यह खुलासा नहीं किया

गया है कि इस क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए कौन-कौन से ढांचागत बदलाव किए जाएंगे। योजना, इस तथ्य का संकेत करती है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, यदि कोई है, तो वह उसकी अकार्यकुशलता के कारण है।

(ज) लाभ में कमी और आयातों के बीच कोई कारणात्मक सम्बंध नहीं है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि आयातों में वृद्धि हुई हो या न हुई हो, फिर भी याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में निरन्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों में आयातों में हुई कोई भी वृद्धि अत्यधिक क्रमिक वृद्धि हुई है, यह वृद्धि अचानक और बहुत अधिक नहीं है। वास्तव में, वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग भी कमोवेश रूप से समान ही बना रहा जिससे यह संकेत मिलता है कि आयातों और याचिकाकर्ता द्वारा दावाकृत क्षति के बीच कारणात्मक सम्बंधों का अभाव है।

(ट) वर्तमान जाँच में भारत में सम्बद्ध वस्तु के आयातों के अलावा कई अन्य ऐसे कारण भी हैं जिन्होंने याचिकाकर्ता को क्षति कारित की है:-

(क) घरेलू उद्योग समुचित गुणवत्ता और संगतता की सम्बद्ध वस्तु की आपूर्ति करने में अक्षम है। गुणवत्ता में असंगतता के कारण अक्सर आपूर्ति की गई वस्तु का उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

(ख) घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता 25000 एमटी है जो भारत में कुल मांग की लगभग 1/3 है। घरेलू एक इकाई, जैसे प्रतिवादी की जरूरतों को ही पूरा करने में सक्षम नहीं है और इसके परिणामस्वरूप आयात अनिवार्य हो जाते हैं। मांग एवं आपूर्ति के बीच का अन्तर इतना अधिक है कि यह रक्षोपाय कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है।

(ग) अधिकांश उपयोक्ता उद्योग उत्तर भारत में अवस्थित हैं, जबकि घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधा दक्षिण भारत में है। अन्तरदेशीय परिवहन पर आने वाली संभारतंत्रीय लागत बहुत अधिक है और इसलिए आवेदक को होने वाला यह घाटा अपनी यूनिट की स्थापना करने के लिए आवेदक द्वारा स्थान के त्रुटिपूर्ण चयन के कारण हो रहा है।

(घ) घरेलू उद्योग उच्च स्तर का क्षमता उपयोग प्राप्त करने में अक्षम है, मांग में कमी के कारण नहीं बल्कि आपूर्ति में अवरोध के कारण है।

(ङ) यह प्रचुरता स्पष्ट है कि इन देशों से होने वाले आयातों में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा आशियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की अपनी पहल और उन्हें शुल्क की रियायती दर प्रदान करना है। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड बनाम काउन्सिल ऑफ यूरोपियन यूनियन (जे सी 331, 12.11.2011) के पैरा 81 में ईसी न्यायालय ने कारण टाइप ब्रेड लिनेन के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यूरोपियन कमीशन सम्बद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि पर सामान्यीकृत प्रशुल्क अधिमानताओं की स्कीम और ईयू में घरेलू उद्योग को उत्तरवर्ती क्षति की जांच करने में असफल रहा था।

(ट) बहुत अधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।

(ठ) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा।

(घ) **मैसर्स एलायड फोम्स प्राइवेट लिमिटेड**

इस सम्बंध में हम निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण करते हैं:-

1. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ लेने-देन इस कम्पनी के साथ लेने-देन करने का हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा है। वे अपनी आपूर्ति वचन बद्धताओं की, खासकर व्यस्ततम समय में, आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। उनके द्वारा आपूरित पालियोल की गुणवत्ता आयातित माल की गुणवत्ता से घटिया क्वालिटी की है क्योंकि यह बी ओ (इथायलीन आक्साइड) कैण्ड नहीं होती है जबकि आयातित सामग्री ऐसी होती है।
2. पीयू फोम उद्योग के हित में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आयातित पालियोल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की मनाली पेट्रोकेमिकल्स की अपील को अस्वीकार कर दें। यदि आपके कार्यालय को किसी अन्य सूचना या स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो हमें वह प्रदान करते हुए खुशी होगी।

(ङ) **मैसर्स एम.एच. पालीमर्स**

1. हम विचाराधीन पालियोल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का विरोध निम्नलिखित कारणों से करते हैं:- इससे हमारी कम्पनी, उद्योग और उपभोक्ताओं को भारी घाटा होगा।

-मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड नामक घरेलू आपूर्तिकर्ता हमें इसकी पर्याप्त मात्रा प्रदान करने में अक्षम है।

-मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से की गई आपूर्तियां नामुनासिब हैं और व्यस्ततम समय के दौरान अगर हम केवल स्थानीय श्रोत पर ही निर्भर रहें तो हमें भारी घाटा उठाना पड़ सकता है।

-आयातित पालियोल की गुणवत्ता मनाली पेट्रो द्वारा प्रदान किए गए पालियोल की तुलना में बेहतर होती है।

(ग) सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् दायर किए गए प्रस्तुतिकरण

इस मामले की सार्वजनिक सुनवाई दिनांक 29.09.2014 को आयोजित की गई थी। घरेलू उद्योग तथा कई अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने-अपने प्रस्तुतिकरण और प्रत्युक्तियाँ निम्नवत की हैं:-

1) घरेलू उद्योग:

1. घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय आवेदन पत्र दायर करने की अपनी स्थिति को इस आधार पर पुनः दोहराया है कि वे इस वस्तु का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन करने वाले एक मात्र उत्पादक हैं और यह कि सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाई के दौरान एक्सपैण्डेड पालिमर्स के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान लगभग 6 एमटी का उत्पादन किया था। इस सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाई के दौरान किए गए अपने प्रस्तुतिकरण में उपभोक्ता उद्योग ने यह भी सम्पुष्ट किया है कि आवेदनकर्ता ही इस वस्तु का बाजार में एकमात्र उत्पादक है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य भी है कि मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स का भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन में भारी हिस्सा बना रहेगा और इसलिए वह धारा 8 ख (6) (ख) के अनुरूप अपनी स्थिति की जरूरतों को पूरा करता है।
2. उपर्युक्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् किए गए हैं और इसलिए आवेदनपत्र में उल्लिखित सूचना की परिशुद्धता और उपयुक्तता के सम्बंध में किए गए प्रस्तुतिकरण और जांच शुरुआत से सम्बंधित मुद्दों को रिकार्ड में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें स्वीकार कर दिया जाना अपेक्षित होगा।
3. घरेलू उद्योग नियमावली द्वारा यथा अपेक्षित पर्याप्तता, उपयुक्तता और परिशुद्धता के साक्ष्य की जांच से सम्बंधित नियम 5(1) और (2) की जरूरतों को पूरा करता है।
4. वर्तमान आवेदनपत्र में विचाराधीन उत्पाद 3000-4000 मालिक्यूलर भार का फ्लेक्सिबिल स्लैबस्यक पालियोल है। इसके मुख्य प्रयोग, असबाब, चटाइयों, तकियों, मसनदों, परिवहन सीटिंग और पैकेजिंग में होता है। इस विचाराधीन उत्पाद का विभिन्न ब्रैंड नामों से आयात एवं व्यापार किया जाता है। यह भी नोट किया जा सकता है कि इन ब्रैंडों पर उत्पादकों/निर्यातकों का स्वामित्व है। इसके अतिरिक्त इन ब्रैंडों के तकनीकी विनिर्देशनों को सम्बंधित निर्यातक की वेबसाइट से देखा जा सकता है। किसी भी निर्यातक ने इस तथ्य का विरोध नहीं किया है कि उपर्युक्त ब्रैंड सम्बद्ध वस्तु से सम्बंधित नहीं है।
5. यह कि यदि जांच की अवधि के दौरान देश में सम्बंधित आयात होते रहे तो घरेलू उद्योग रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण प्राप्त करने की हकदार है। वर्तमान मामले में, यह देखा जा सकता है कि आयातों में भारी वृद्धि हुई है और वे पर्याप्त रूप से बहुत अधिक हैं और जांच की अवधि के दौरान उनका स्तर बहुत अधिक रहा है।
6. यह कि महानिदेशक को घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित कारकों का विश्लेषण करना चाहिए :
 - क. आयातों में समग्र रूप से एवं संगत रूप से वृद्धि की दर एवं राशि,
 - ख. आयातों द्वारा घरेलू बाजार पर किए गए कब्जे का हिस्सा,
 - ग. बिक्री के स्तर में परिवर्तन,
 - घ. उत्पादन,
 - ङ. उत्पादकता,
 - च. क्षमता उपयोग,
 - छ. लाभ/हानि।

7. घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात जो वर्ष 2010-11 में 100 अनुक्रमित बिंदु थे, से बढ़कर 2013-14 में 282 अनुक्रमित बिंदु हो गए। इसी तरह, बिक्री के संबंध में आयात जो वर्ष 2010-11 में 100 अनुक्रमित बिंदु थे, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 291 अनुक्रमित बिंदु हो गए और मांग के संबंध में आयात वर्ष 2010-11 में 100 अनुक्रमित बिंदु थी, से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 291 अनुक्रमित बिंदु हो गए और मांग के संबंध में आयात जो वर्ष 2010-11 में 100 अनुक्रमित बिंदु थी, से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 134 अनुक्रमित बिंदु हो गई। उपर्युक्त से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि आयातों में समग्र और संगत दोनों रूपों में वृद्धि हुई है।

8. खपत या मांग में आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 60.87 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 81.93 प्रतिशत हो गया। यह स्पष्ट है कि इन संवर्धित आयातों के घरेलू उद्योग के हिस्से पर कर लिया और यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले वर्षों में घरेलू उद्योग को जीवित रहना दुष्कर हो जाएगा।

9. यह कि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई और तत्पश्चात इसमें तेजी से गिरावट आई। यह घटी हुई बिक्री खपत के समग्र और संगत दोनों रूपों में हुई है।

10. घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि उसे घरेलू मांग में वृद्धि होने से कोई फायदा नहीं हुआ और इसके घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट आई। यह कि वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई और तत्पश्चात फिर इसमें भारी गिरावट आई। उत्पादन में इस गिरावट का घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

11. उत्पादकता ने भी उत्पादन की तरह की प्रवृत्ति अपनाई, चूंकि उत्पादकता का मापन उत्पादन को दिनों की संख्या से विभाजित करके किया जाता है और यदि उत्पादन में कमी आएगी तो उत्पादकता में उसी अनुपात में कमी आएगी।

12. क्षमता उपयोग जो आधार वर्ष अर्थात् 2010-11 में 90 प्रतिशत था, घटकर जांच की अवधि अर्थात् वर्ष 2013-14 में 55 प्रतिशत रह गया। क्षमता उपयोग में इस कमी का आयातों में वृद्धि के कारण बिक्री और उत्पादन में कमी के साथ सीधा संबंध है।

13. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2011-12 में पूर्णतया समाप्त हो गई और तत्पश्चात उन्हें भारी घाटा उपगत हुआ।

14. सभी संगत पैरामीटर घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में गिरावट दर्शाते हैं। उपर्युक्त मद्देनजर, जब तक शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जाता है तब तक घरेलू उद्योग अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने में अक्षम रहेगा। घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की गई है जैसाकि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति में और अधिक कमी आना आसन्न है।

15. इस समय आयात उच्च स्तर पर हैं और वे निरंतर बढ़ रहे हैं।

16. संबद्ध वस्तु का वर्ष 2011-12 से भारी मात्रा में आयात होता रहा है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और उसे भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता की तो उत्तरजीविता ही खतरे में पड़ गई है और इसके अतिरिक्त, गंभीर जोखिम की चुनौती भी आसन्न है। घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई गंभीर क्षति और आयातों के बीच कारणात्मक संबंध है।

17. संवर्धित आयातों और घरेलू उद्योग को कारित की गई गंभीर क्षति के बीच प्रत्यक्ष सह संबंध है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 में आयात शिखर पर थे और घरेलू उद्योग को इन दो वर्षों में ही गंभीर क्षति सहन करनी पड़ी है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ, घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट आई। इस अवधि के दौरान जब आयात अपनी चरम सीमा पर थे तब जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की स्थिति बदतर हो गई थी।

18. उपर्युक्त विश्लेषण स्पष्ट यह सिद्ध कर रहा है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन के विश्लेषण के आधार पर वृद्धि हुई है। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि आयातों का भारी कीमत अधोदहन, कीमत अधोबिक्रयण और कीमत निग्रहण किया जा रहा है। जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में भी प्रचंड गिरावट

आई है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि गंभीर क्षति कारित की गई है और इसके अतिरिक्त, गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न है। आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध भी सिद्ध हो जाता है।

19. अन्य ऐसे कोई कारक नहीं हैं जिन पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति उपरोपित की जा सकती हो। इससे ही पुनः इस तथ्य से सिद्ध किया जा सकता है कि इस संबद्ध वस्तु की मांग विगत तीन वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है। आधार वर्ष की तुलना में मांग में लगभग 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथापि, घरेलू उद्योग बाजार में हुई वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन, क्षमता उत्पादन और बिक्री या लाभ में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है।

20. यह भी नोट किया जा सकता है कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में किए गए अभिकथनों पर भरोसा किया है और उस मुद्दे को अपने दावे के समर्थन के लिए जांच की अवधि के दौरान खींचने का भी प्रयास किया है कि वर्तमान मामले तथ्यों के आधार पर कोई भी कारणात्मक संबंध नहीं है। यह मुद्दा कई अन्य मामलों में भी विवाद का विषय रहा है और यह निरंतर उपपादित किया गया है कि वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित विवरणों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह अधिगम ठोस विधिक आधारिका पर आधारित है कि जांचाधीन विचाराधीन उत्पाद होता है न कि कंपनी। घरेलू उद्योग के निष्पादन को विधि के प्रावधानों के अनुरूप केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए ही आंका जाना चाहिए।

21. यह दावा कि तमिलनाडु में बिजली की कमी है, बड़े सामान्यीकृत ढंग से बिना किसी साक्ष्य के यह सुझाव देने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग को इस कारण से भी घाटा हुआ है इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि उसके पास विद्युत आपूर्ति के तीन स्रोत हैं अर्थात् स्वयं उत्पादित विद्युत (ग्राही विद्युत संयंत्र के लिए), राज्य विद्युत बोर्डों से विद्युत तथा डीजल जनरेटर सेट। इससे घरेलू उद्योग को यह सुनिश्चित करने की पर्याप्त लोचशीलता प्राप्त हो जाती है कि विद्युत के किसी विशिष्ट स्रोत से आपूर्ति की कमी होने के कारण उनके उत्पादन में कोई कमी न आए। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया यह प्रस्तुतिकरण कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में विद्युत की कमी के कारण कमी आई होगी, पूर्णतया असंगत है और उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

22. कच्चे माल अर्थात् प्रोपायलीन आक्साइड (पीओ) की अनुपलब्धता के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी जरूरत के लिए पीओ की पर्याप्त आपूर्ति बना रखी है। घरेलू उद्योग पीओ का इन-हाउस उत्पाद करता है और जब कभी जरूरत पड़ती है तब उसका आयात भी करता है। उन्होंने ईटीटीएल पर पीओ का भंडारण करने की सुविधा भी बना रखी है जिससे उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक भारी मात्रा में आयात करने की अनुमति मिल जाती है। उपर्युक्त के मद्देनजर यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमुख कच्चे माल अर्थात् पीओ की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे में कोई बल नहीं है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिए जाने की जरूरत है।

23. मनाली क्षेत्र जहां घरेलू उद्योग का संयंत्र अवस्थित है में क्षमताओं में वृद्धि करने के संबंध में कतिपय प्रतिबंधों से संबंधित कुछ हितबद्ध पक्षकारों के दावे गलत हैं और इसलिए उन्हें न कर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक की पालियोल की कुल क्षमता 50,000 एमटी है जिसका संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयोग किया जा सकता है। अतः इस तथ्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि घरेलू उद्योग के पास इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता है और यह कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर पाटित आयातों का प्रभाव विगत में कतिपय अवरोधों के कारण तनुकृत नहीं हुआ है। किसी भी हाल में, क्षमताओं में वृद्धि करने से संबंधित विलम्बन को भी सितम्बर, 2013 से उठा लिया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए क्षमता से संबंधित मुद्दे को अस्वीकार कर दिए जाने की जरूरत है।

24. खपत के प्रतिमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि क्षति इस कारक से ही हुई है। इसके अतिरिक्त, मांग में भी वृद्धि हुई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है।

25. उपर्युक्त की पूर्वावधारणा के बिना यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में यह आवश्यक नहीं है कि आयात की क्षति के लिए मुख्य कारण होने चाहिए, बशर्ते कि इससे यह दर्शाया जा सकता है कि यह क्षति कारित करने वाले कारकों में से एक है।

26. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कोई अन्य परिस्थितियां या कारक नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हों।

27. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदनपत्र में विस्तृत पुनर्गठन योजना प्रदान की है।
28. उपर्युक्त के अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीओ का भंडारण करने की सुविधा, जो एन्नोर टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (ईटीटीपीएल) में शुरू की गई है, ने अब कार्य करना शुरू कर दिया है और वहां प्रोपायलीन आक्साइड के परीक्षण पार्शल पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ईसीएच (इपिक्लोरोहाइड्रिन) का पीओ में संपरिवर्तन करने के लिए इंजीनियरिंग क्रियाकलाप अग्रणी स्तर पर हैं।
29. अवरोधों को दूर करके मौजूदा क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसंधान और विकास प्रयासों के कारण घरेलू उद्योग अपनी मौजूदा सुविधाओं से अवरोध दूर करने में सक्षम होगा और अपनी लागत कम करने में सफल रहेगा।
30. यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि मनाली क्षेत्र में अपनी क्षमता में विस्तार करने पर लगा प्रतिबंध सितम्बर, 2013 से हटा लिया गया है और घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं में संवृद्धि करने के लिए क्लीयरेंस हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास आवेदन कर रखा है।
31. उपर्युक्त के मद्देनजर यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग की एक अत्यधिक ठोस एवं भरोसेमंद पुनर्गठन योजना है।
32. हालांकि महानिदेशक (रक्षोपाय) पर भारतीय विधियों के अनुरूप अनपेक्षित परिस्थितियों का विश्लेषण करने का कोई अभिव्यक्त वचनबद्धता/अपेक्षा नहीं है तथापि हम यह समझते हैं कि महानिदेशक "अनपेक्षित विकास" का विश्लेषण करने को अधिमानता दे सकते हैं। किसी भी स्थिति में यह नोट किया जा सकता है कि जीएटीटी या डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार में भी ऐसा कोई मार्गदर्शी सिद्धांत या क्रियापद्धति नहीं है जिसका अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करते समय अनुपालन किया जाना चाहिए। तथापि, घरेलू उद्योग ने वास्तव में अपने आवेदन के अन्य स्थानों पर अनपेक्षित परिस्थितियों के लिए आधार प्रस्तुत किए हैं।
33. अर्जेंटीना फुटवियर मामला (डब्ल्यूटी/डीएस 121/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999) में अपीलीय निकाय निर्णय में यह उपपादित किया गया कि वाक्यांश "अनपेक्षित विकास" का आशय उस विकास से है जो प्रत्याशित न हो। कोरिया डेयरी मामले (डब्ल्यूटी/डीएस 98/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999) में अपीलीय निकाय ने यह उपपादित किया कि अनपेक्षित विकास वह विकास होता है जो सदस्य द्वारा उपगत बाध्यता (दायित्व) के समय अपेक्षित अथवा प्रत्याशित न हो।
34. यह उल्लेख किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग तो यह पूर्वानुमान कर सकता है और न ही यह भविष्यवाणी कर सकता है कि कच्चे माल की कीमतों में समस्त संस्पर में वृद्धि होने के बावजूद संबद्ध वस्तु की कीमत में भारी कमी हो जाएगी। कीमतों में इस कमी के कारण संबद्ध वस्तु के भारत में होने वाले आयातों में भारी वृद्धि हुई जैसाकि आयात सांख्यिकी से देखा जा सकता है। संबद्ध वस्तु की कीमतों में अचानक गिरावट होने और आयात मात्रा में अचानक वृद्धि होने की अवधि का उस अवधि से संयोगमात्र है जिस अवधि में घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तु की कीमत में इस कमी ने घरेलू उद्योग की उस क्षमता को भी कम कर दिया जिस हैशियत से वह ग्राहकों से बेहतर कीमतों के लिए वार्ता किया करता था।
35. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत आशियान एफटीए और भारत-सिंगापुर सीईसीए के कारण बड़े-बड़े आपूर्तिकर्ताओं ने इस लाभ का फायदा उठाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थीं। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि 98 प्रतिशत से अधिक आयात सिंगापुर से आ रहे हैं, जिसकी इस मौजूदा खुली बाजार में कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी एक स्रोत से इस सामग्री की अचानक वृद्धि और वह भी अलाभकर कीमतों पर होना, घरेलू उद्योग द्वारा एक अनपेक्षित घटना है।
36. इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जिन रियायतों पर वार्ता की जा रही है, उनमें आयात मात्रा के विशिष्ट स्तर और प्रचलित कीमत स्तर को ध्यान में रखा जाता है। यदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जिनकी वार्ताकारों ने वार्ता करते समय प्रत्याशा नहीं की थी तब निश्चित तौर पर यह अनपेक्षित विकास का मामला बनता है। इसके अतिरिक्त, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी सरकार या वार्ताकार यह पूर्व कल्पना करने में सक्षम नहीं होगा कि एफटीए के पश्चात आयात बढ़ चढ़कर केवल एक ही बड़े स्रोत से होंगे। उपर्युक्त सभी अनपेक्षित परिस्थितियां हैं जिनकी

पूर्वावधारणा वार्ता करते समय न तो घरेलू उद्योग ने और न ही भारत-आशियान एफटीए और भारत-सिंगापुर सीईसीए के वार्ताकारों ने की थी।

37. यह प्रस्तुत किया जाता है कि बड़े-बड़े निर्यातकों (खासकर शेल कंपनियों) ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। विनम्रतापूर्वक यह उल्लेख किया जाता है कि विहित प्रश्नावली दायर किए बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच में उनकी प्रतिभागिता महानिदेशक को सहयोग करने के लिए है।

38. निर्यातकों और आयातकों ने भारत में निर्यातों/आयातों की मात्रा के संबंध में भी बहुत अधिक गोपनीयता का दावा किया है।

39. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हम माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वह घरेलू उद्योग की गंभीर क्षति को दूर करने के लिए यथासंभव शीघ्र अंतिम जांच-परिणाम जारी करें। इसके अतिरिक्त, हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वह विगत में किए गए हमारे सभी प्रस्तुतिकरणों को इन प्रस्तुतिकरणों का एक भाग माने क्योंकि संक्षिप्तता के कारण उनकी यहां पुनरावृत्ति नहीं की गई है।

(II) निर्यातकर्ता राष्ट्रों के विचार

1. सिंगापुर गणराज्य का उच्चायोग

- (i) सिंगापुर यह रेखांकित करना चाहता है कि यद्यपि डब्ल्यूटीओ करार में सदस्यों को उपचारी उपाय करने की अनुमति है, तथापि, वे यह सुनिश्चित करने की मांग भी कर सकते हैं कि इन साधनों का दुरुपयोग संरक्षणवादी प्रयोजनों के लिए न किया जाए। रक्षोपाय कार्रवाई में घरेलू उद्योग से यह परिकल्पना की जाती है कि वह बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवश्यक ढांचागत समायोजन करेगा।
- (ii) यह इस संदर्भ में है कि सिंगापुर बड़ी चिंता के साथ यह नोट करता है कि याचिकाकर्ता मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (एफएसबी) पर पाटनरोधी कार्रवाई के लिए अक्सर आवेदन किया है जिसमें सिंगापुर के खिलाफ अभी हाल ही का एक मामला भी था जिसे वर्ष 2012 में समाप्त कर दिया गया।
- (iii) वर्तमान मामले में कंपनी ने संगामी रूप से एक ही उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय साधन के लिए आवेदन किया है। इन दोनों साधनों से क्षति का दावा और उपचार की मांग एक साथ करने से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता आयात प्रतिस्पर्धा से अविवेकी संरक्षण की मांग कर रहा है।
- (iv) सिंगापुर यह तर्क प्रस्तुत करता है कि इस मामले में तथ्य, जिनका उप-पैराग्राफ (v) में उल्लेख किया गया है, किसी ऐसे दावे का समर्थन नहीं करते हैं कि आयातों में विशेषकर भारत में आयातों की ऐतिहासिक रूप से बढ़ती प्रवृत्ति और एफएसपी का प्रयोग करने वाले यह वृद्धि अनपेक्षित विकास का परिणाम है, भारत के अनुप्रवाही उद्योग की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वृद्धि अनपेक्षित विकास का परिणाम है।
- (v) सिंगापुर यह कहना भी चाहता है कि यदि याचिकाकर्ता इस विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र घरेलू उत्पादक है, जैसा कि वह दावा करता है, तो महानिदेशक रक्षोपाय भारतीय बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद की वाणिज्यिक उपलब्धता पर विचार कर सकते हैं। कई तथ्य इसे पूरा करने में याचिकाकर्ता की अक्षमता को उजागर करेंगे।
- (vi) उन आयातकों और प्रयोगकर्ताओं की लंबी सूची, जिन्होंने इस मामले में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया हुआ है, स्पष्टता यह संकेत करती है कि इस उत्पाद की भारी मांग है जिसे यह अकेली कंपनी पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- (vii) यद्यपि, सिंगापुर से एफएसपी के आयातों पर वर्ष 2002 से वर्ष 2011 के बीच पाटनरोधी शुल्क प्रभावी थे फिर भी भारत में सिंगापुर से इन उत्पादों के आयातों ने 10 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है।
- (viii) इस उत्पाद की प्रकृति, जिसका पालीयूरीथीन में संपरिवर्तन किए जाने के पश्चात मैट्रिसेस से लेकर परिवहन सीटों तक में विविध अंतिम प्रयोग होता है, का आशय केवल यह हो सकता है कि रक्षोपाय

साधन से भारत के अनुप्रवाही उत्पादों को घाटा होने की संभावना होगी। बदले में, इन उत्पादकों की प्रतिस्पर्धी बाजार हिस्सा बनाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(III) निर्यातकर्ताओं के विचार

- (क) मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड, मैसर्स शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लिमिटेड, और
- (ख) मैसर्स बेयर (दक्षिण पूर्व एशिया) पीटीई लिमिटेड दोनों ने मैसर्स लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन, एडवोकेट्स, 5, लिंकरोड, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014, भारत के जरिए अपने प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किए हैं।

1. आवेदक ने रक्षोपाय (महानिदेशक) द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में यह स्वीकार किया कि संबद्ध वस्तु के आयातों का 98 प्रतिशत आयात सिंगापुर से उद्भवित होता है। ऐसी स्थिति में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इससे इस तथ्य के बावजूद कि 98 प्रतिशत आयात केवल एक देश अर्थात् सिंगापुर से उद्भवित होता है, अन्य सभी देशों के आयात भी दंडित होंगे।
2. प्रतिवादी यह प्रस्तुत करते हैं कि सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के आयातों से उत्पन्न किसी भी मुद्दे का पाटनरोधी जांच में निराकरण किया जा सकता है। उपर्युक्त के आलोक में वर्तमान रक्षोपाय जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
3. भारत-आशियान एफटीए और भारत-सिंगापुर सीईसीए में इन दो करारों के अंतर्गत रक्षोपाय जांच शुरुआत के मामलों में अनुकरण किए जाने वाले विशिष्ट दिशानिर्देशों का प्रावधान है। भारत-सिंगापुर सीईसीए और भारत-आशियान एफटीए में द्विपक्षीय रक्षोपाय साधनों का अधिरोपण करने के लिए पृथक प्रणालियों का अनुपालन की जाने वाली अतिरिक्त अधिदेशित अपेक्षाओं सहित उल्लेख है।
4. आवेदक व्यापार उपचारी प्रक्रियाओं का श्रृंखलाबद्ध प्रयोक्ता है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि क्या आवेदक द्वारा इन कार्यवाहियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वर्ष 1998 में रक्षोपाय कार्यवाई के साथ-साथ वर्ष 2011 से पाटनरोधी कार्यवाई में भी अंतर्गस्त रहा है।
5. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 (जिसे एतदपश्चात "भारतीय रक्षोपाय नियमावली" कहा गया है) के अनुबंध के नियम शिकायत को पाटनरोधी/पाटन सब्सिडी प्राधिकारी के पास किसी ऐसे मामले को भेजे की जिम्मेदारी महानिदेशक (रक्षोपाय) पर डालते हैं जिसके लिए यह कहा जाता है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और जिस क्षति को संवर्धित आयातों पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रस्तुतिकरण में यह दर्शाया गया है कि आवेदक द्वारा सहन की गई क्षति (यदि कोई हो) (संवर्धित आयातों के अलावा अन्य) कारकों के कारण हुई है। इसलिए महानिदेशक (रक्षोपाय) को चाहिए कि वह वर्तमान रक्षोपाय जांच समाप्त कर दें।
6. यह याचिका त्रुटिपूर्ण भी है क्योंकि इसमें कई अवांछित गोपनीयता दावे किए गए हैं।
7. वर्तमान जांच में, आवेदक ने न तो कारणों का विवरण उपलब्ध कराया है और न ही उल्लिखित किसी साक्ष्य को उपयुक्त रूप से संक्षेप में बताया है। आवेदक ने यह स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है कि उपर्युक्त सूचना की निर्मुक्ति क्यों और कैसे आवेदक के हित में विधिक वाणिज्यिक हित प्रभावित होंगे।
8. जिस सीमा तक आवेदक की गोपनीय सूचना को संगतता, परिशुद्धता और पूर्णतः के लिए सत्यापित नहीं किया जा सकता है, उसकी अवहेलना कर दी जानी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के हित में हम बड़े आदर के साथ यह प्रस्तुतिकरण करते हैं कि महानिदेशक रक्षोपाय इस आवेदन पत्र को अपनी याचिका का संशोधित एवं उचित एनसीवी प्रदान करने के लिए वापस कर दें।
9. यह प्रतिवादी महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह अनुरोध करता है कि आयात आंकड़ों उत्पाद सूचना, कीमत विवरण, विनिर्माण प्रक्रिया आदि से युक्त उपर्युक्त उल्लिखित सूचना हमें प्रदान कराई जाए ताकि आवेदक के दावे के संबंध में सार्थक टिप्पणियां की जा सकें।
10. आवेदक ने याचिका में यह दावा किया है कि वह भारत में समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। तथापि, प्रतिवादीगण यह प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं कि मैसर्स एक्सपेंडर पालियर सिस्टम भी भारत में समान वस्तु के उत्पादक के रूप में अर्ह बन सकता है। इस याचिका में आवेदक द्वारा उनके संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

11. प्राधिकारी को चाहिए कि वह उस संबद्ध उत्पाद की मात्रा की जांच करें जिसका उत्पादन मैसर्स एक्सपैंडर पालीमर सिस्टम्स द्वारा किया जा सकता है या किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस सूचना का प्रकटन आवेदक द्वारा अपनी याचिका में किया जाना चाहिए था और प्राधिकारी को चाहिए कि वह इस जांच को याचिका की पूर्णता के अभाव में उपयुक्ततः खारिज कर दें। प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या इस मामले में आवेदक का कोई आधार भी है।
12. महानिदेशक रक्षोपाय ने वर्तमान रक्षोपाय जांच की शुरुआत सौदावार डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर भरोसा करते हुए की है। आवेदक ने "एक्सिमनेट बीबीएस" से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि सौदावार डीजीसीआईएंडएस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार आवेदक द्वारा दायर की गई यह याचिका और महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जारी यह जांच शुरुआत नोटिस आयात आंकड़ों के पूर्णतया भिन्न स्रोतों पर आधारित है।
13. जांच शुरुआत नोटिस के पैराग्राफ 5 से यह भी प्रेक्षण किया जा सकता है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने क्षति विश्लेषण अवधि के लिए अन्य रक्षोपाय क्षति पैरामीटरों का सत्यापन किया है। तथापि, वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन पर टिप्पणियां करने के लिए प्रदान नहीं कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण को इस बात की आशंका भी है कि आवेदक द्वारा दायर की गई याचिका को महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा सत्यापित क्षति पैरामीटरों के अनुरूप अद्यतन नहीं किया गया है। इसलिए, हमारे दिनांक 16 जून, 2014 के पिछले अनुरोध के अनुरूप हम महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह अनुरोध करते हैं कि वह आवेदक को निदेश दें कि वह यह याचिका वापस ले ले या एक विकल्प यह भी हो सकता है कि वह आवेदक को अनुदेश दें कि वह इस याचिका को किसी उपयुक्त साक्ष्यांकन सहित डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के आधार पर सुधारे और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां करने के लिए प्रदान कराए।
14. याचिका में किए गए सभी दावों का समुचित विश्लेषण करने के लिए यह अनुरोध किया जाता है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) या आवेदक को चाहिए कि वह खेपवार अपरिष्कृत आयात आंकड़े तथा छांटे गए आयात आंकड़े हितबद्ध पक्षकारों को एम एस एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए। महानिदेशक (रक्षोपाय) से आवेदक को यह निदेश देने का भी अनुरोध किया जाता है कि वह यह स्पष्टीकरण दे कि उसने अपरिष्कृत आंकड़ों से आंकड़ों की छंटाई किस तरह की है। उपर्युक्त सूचना क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए अति महत्वपूर्ण है।
15. प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए प्रस्तुत अपनी याचिका के आंकड़ों और संबद्ध वस्तु के विरुद्ध रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने के लिए संप्रेषित दिनांक 22 मई, 2014 को जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रदान कराए गए आंकड़ों में कई विसंगतियां हैं।
16. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में केवल 3000-4000 के मालीक्यूलर भार के फ्लेक्सिबिल स्लैब स्टाक पालियोल को ही शामिल किया गया है। तथापि, कुछ आयात सौदे यह भी दर्शाते हैं कि आयात सांख्यिकी में 5000 मालीक्यूलर भार के फ्लेक्सिबिल स्लैब स्टाक पालियोल को भी शामिल किया गया है। प्रतिवादियों को यह आशंका है कि इस आयात सांख्यिकी में कई ऐसे सौदे होंगे जिससे आयात की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई होगी। प्रतिवादीगण महानिदेशक (रक्षोपाय) से अनुरोध करते हैं कि वह इसकी जांच करें।
17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयात आंकड़ों का एमएस एक्सेल पाठ भी संगत है क्योंकि इस याचिका में दोहरी गणना है और आयातों का दोहराकरण है जिसके कारण सिंगापुर से आयातों की मात्रा बहुत बढ़ गई है। सर्वप्रथम, इन आयात आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस संभ्रम को सुधार लेना चाहिए।
18. प्रतिवादीगण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित वार्षिकीकृत आंकड़ों का विरोध इस आधार पर करते हैं कि यह आंकड़े परिशुद्ध आंकड़े नहीं हैं और इसलिए उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि जांच शुरुआत नोटिस में प्रदान कराए गए वार्षिकीकृत बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाए गए हैं और उनसे सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती है।
19. याचिका की एनसीवी के पृष्ठ 28 पर, घरेलू उत्पादकों के लिए प्रश्नावली के खंड 3 में प्रश्न संख्या xii के उत्तर में आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि वे किसी भी डिस्काउंट की पेशकश नहीं करते हैं। बाजार आसूचना के अनुसार

यह माना जाता है कि आवेदक अपने ग्राहकों को वस्तुतः डिस्काउंट की पेशकश करता है। प्रतिवादीगण प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वह इसकी जांच करें।

20. आवेदक ने उचित बाजार कीमत का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति का भी खुलासा नहीं किया है।

21. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच शुरूआत नोटिस और याचिका दोनों ही अनपेक्षित विकास के पहलू के संबंध में चुप हैं जिनकी वजह से भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई।

22. गाट के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं के अनुसरण में भारत तब तक रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं कर सकता है जब तक कि यह महानिदेशक (रक्षोपाय) की संतुष्टि के लिए यह निरूपित नहीं कर देता है कि आयातों में तथाकथित वृद्धि और उनके परिणामस्वरूप हुई क्षति अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप तथा गाट के अंतर्गत भारत द्वारा उपगत बाध्यताओं के प्रभाव के कारण हुई।

23. महानिदेशक (रक्षोपाय) ने अपनी पिछली जांचों में अनपेक्षित विकास की अपेक्षाओं की समनुरूप ढंग से जांच की। वास्तव में, महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा 304 स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर चीन विशिष्ट रक्षोपाय जांच की शुरूआत में महानिदेशक रक्षोपाय ने यह उपपादित किया कि इस मामले में अनपेक्षित विकास की कोई घटना मौजूद नहीं है। तदनुसार महानिदेशक, रक्षोपाय ने यह संस्तुति की कि इस पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

24. इसलिए, आवेदक को यह दिखाना पड़ा है जब भारत को 1994 में गाट के अंतर्गत बाध्यताएं उपगत करनी पड़ी और उसके कारण जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि हो गई तो कैसे कोई विकास अनपेक्षित विकास बन गया। यदि आवेदक उसका स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, तो भी यह बोझ प्राधिकारी पर बना रहता है कि वह उपर्युक्त विश्लेषण करें। ऐसा न करने पर संबद्ध जांच को खारिज किया जा सकता है।

25. यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो याचिका में और न ही संबद्ध जांच की जांच शुरूआत अधिसूचना में किसी ऐसे अनपेक्षित विकास की पहचान की गई है जिसकी वजह से संबद्ध उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई हो।

26. प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि गाट 1994 के अनुच्छेद XIX में संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी पर दोहरा दायित्व डाला गया है। प्रथमतः, इसमें प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह गाट के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सदस्य देश द्वारा, इस मामले में भारत द्वारा, उपगत प्रशुल्क रियायतों सहित विशिष्ट बाध्यताओं की पहचान करें। द्वितीयतः, इसमें प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपर्युक्त विशिष्ट बाध्यताओं और भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों की वृद्धि के बीच कारणात्मक संबंध सिद्ध करें और तद्वारा उस बाध्यता के प्रभाव का विश्लेषण करें जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। ऐसा करने में असफल रहने पर संबंधित जांच समाप्त हो जाएगी।

27. यदि आवेक उसका स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है तो भी यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि प्राधिकारी का यह नैतिक दायित्व रहता है कि वह इस मुद्दे का विश्लेषण करें और इस संबंध में कोई न कोई निष्कर्ष प्रदान करें। ऐसा करने से असफल रहने पर प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी जांच परिणाम अयथार्थ अतर्कसंगत और गाट के अनुच्छेद XIX के अंतर्गत नैतिक दायित्वों का अननुपालनीय होगा।

28. उपर्युक्त प्रस्तुतिकरणों के आलोक में प्राधिकारी कृपया वर्तमान जांच को समाप्त कर दें। यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि संबद्ध जांच को समाप्त कर देने से व्यापारियों और उन देशों की सरकारों का भारत की प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा कायम होगा और उसके द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों की विधिक उम्मीदों की रक्षा होगी।

29. प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि आयातों की मात्रा में वृद्धि को इस समय भारत और सिंगापुर के बीच मौजूद वस्त्रापक आर्थिक भागीदारी करार ("सीईसीए") पर उपरोपित किया जा सकता है। भारत-सिंगापुर सीईसीए द्वारा प्राप्त प्रशुल्क रियायतें सिंगापुर से भारत को संबद्ध वस्तु के आयातों के लिए आकर्षक है।

30. तथापि, प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि भारत-सिंगापुर सीईसीए के अंतर्गत प्रशुल्क उदारीकरण के कारण आयातों में वृद्धि को गाट के अंतर्गत अनपेक्षित विकास या किसी बाध्यता के रूप में नहीं माना जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क में कमी करने की दर को निर्दिष्ट करती हुई समय सारणी जून, 2005 में भारत-सिंगापुर सीईसीए

सम्पन्न होने के पश्चात सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी। इसलिए, साधारणतः ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें इस तथ्य की अपेक्षा न की जा सकती हो कि संबद्ध वस्तु पर शुल्क दरों में करार के अंतर्गत वचनबद्धताओं की भारत की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार क्रमिक कमी आएगी। भारत-सिंगापुर सीईसीए के अंतर्गत 0 प्रतिशत शुल्क के कारण आयातों में वृद्धि को गाट के अनुच्छेद XIX के अनुरूप गाट के अंतर्गत किसी बाध्यता या अनपेक्षित विकास के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इस मुद्दे को डीएस 415-418 डोमिनिकन रिपब्लिक रक्षोपाय साधन में डब्ल्यूटीओ पैनल के एक अभिनव निर्णय द्वारा ईमानदारी से कवर किया गया है जिसमें पैनल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जिस सीमा तक डोमिनिकन रिपब्लिक द्वारा उठाए गए मुद्दे में बाध्यता गाट के अंतर्गत होने के बजाय क्षेत्रीय मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत थी, उस सीमा तक अनुच्छेद XIX की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। इस कारण से भी उपर्युक्त तर्क अस्वीकार किया जा सकता है।

31. इस तथ्य के संबंध में विधि की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि संवर्धित आयात पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त आकस्मिक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त महत्वपूर्ण होने चाहिए। वर्तमान मामले में, आयात न तो अभिनव हैं, न ही अचानक तीव्र और महत्वपूर्ण है जिसके कारण शुरुआती मापदंड भी पूरा नहीं हो पाता है।

32. आवेदक उद्योग ने गंभीर क्षति का मामला बनने के लिए कोई भरोसेमंद साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसने कई तथ्यों के संबंध में महत्वपूर्ण क्षति सूचना रोक रखी है। इसके अतिरिक्त, आवेदनपत्र में प्रस्तुत किए गए तथ्य स्वतः ही गंभीर क्षति का मामला नहीं बनाते हैं।

33. यह भी नोट किया जा सकता है कि आवेदक ने संबद्ध वस्तु की लगभग उस सभी संबद्ध वस्तु की बिक्री कर दी है जिसका उसने उत्पादन किया है। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि उत्पादन के प्रतिशत के रूप में यह बिक्री वर्ष 2010-11 में 101 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 99 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में 96 प्रतिशत और वर्ष 2013-14 में 98 प्रतिशत थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को संबद्ध वस्तु की बिक्री करने में कोई समस्या नहीं है, मुख्य समस्या उत्पादन की है।

34. आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों के अनुसार आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन जो वर्ष 2010-11 में 16510 एमटी था, बढ़कर वर्ष 2011-12 में 18381 एमटी हो गया और वर्ष 2012-13 में यह घटकर 13986 एमटी तथा वर्ष 2013-14 में 13812 एमटी हो गया। आवेदक द्वारा संबद्ध उत्पाद की बिक्री जो वर्ष 2010-11 में 16615 एमटी थी, बढ़कर वर्ष 2011-12 में 18192 एमटी हो गई और वर्ष 2012-13 में इसमें कुछ कमी होकर यह 13451 एमटी तथा वर्ष 2013-14 में 13474 एमटी हो गई।

35. तथापि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान उत्पादन और बिक्री में आई गिरावट का कारण आयातों की मात्रा नहीं था बल्कि इसका मुख्य कारण संबद्ध उत्पाद का उत्पादन करने के लिए फीडस्टॉक की अनुपलब्धता था। यह नोट किया जाता है कि प्रोपायलीन आक्साइड, जिसका प्रयोग संबद्ध उत्पाद का उत्पादन करने के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है, की गंभीर कमी है।

36. आवेदक प्रोपायलीन का प्रापण सीपीसीएल से करता है जो आवेदक को प्रोपायलीन का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। यह मात्रा भी सीमित है क्योंकि एक अधिकतम सीमा है जिसके बाद सीपीसीएल प्रोपायलीन की आपूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए, आवेदक को प्रोपायलीन की आपूर्ति के लिए सीपीसीएल द्वारा एक सीमा निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात अनेक केवल एक निश्चित मात्रा में ही प्रोपायलीन आक्साइड का विनिर्माण कर सकता है और संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने के लिए पीओ का उत्पादन कर सकता है, उससे अधिक नहीं।

37. शुरु में, प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई क्षमता की यथार्थता संदिग्ध है। प्राधिकारी से आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए परस्पर विरोधी आंकड़ों की जांच करने और उसकी सच्चाई जानने का अनुरोध किया जाता है।

38. क्षमता उपयोग में कमी होने के दो कारण हैं :

1. ऊपर यथावर्णित फीडस्टॉक प्रोपायलीन आक्साइड की उपलब्धता में कमी होना जिससे क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा और क्षमता उपयोग में कमी जाएगी।

2. आवेदक की क्षमता 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी जिससे उसके क्षमता उपयोग में स्पष्ट रूप से कमी आएगी।

39. क्षमता उपयोग में होने वाली किसी भी कमी के लिए संबद्ध उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए फीडस्टॉक (पीओ) की उपलब्ध में कमी को उपरोपित किया जा सकता है। आवेदक ने अपनी वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि उसके क्षमता उपयोग में यह कमी पीओ की उपलब्धता न होने के कारण आई है।

40. जांच शुरुआत नोटिस में लाभप्रदता से संबंधित अनुक्रमित आंकड़ों को वर्ष 2010-11 में 100 अनुक्रमित बिंदु होना दर्शाया गया है, इसके बाद वर्ष 2011-12 में इसमें अत्यधिक तेजी से एवं सारभूत वृद्धि होकर यह 324 अनुक्रमित बिंदु हो गया और फिर यह घटकर वर्ष 2012-13 में (331) अनुक्रमित बिंदु और जांच की अवधि में (559) अनुक्रमित बिंदु हो गया। इसी तरह, आवेदक द्वारा दायर याचिका में बिक्री कीमत, जो वर्ष 2010-11 में 100 अनुक्रमित बिंदु थी, बढ़कर वर्ष 2011-12 में 115 अनुक्रमित बिंदु हो गई और यह वर्ष 2012-13 में घटकर 110 अनुक्रमित बिंदु हो गई तथा यह वर्ष 2013-14 में एक बार पुनः बढ़कर 128 अनुक्रमित बिंदु हो गई।

41. बिक्री लागत के संबंध में, यह वर्ष 2010-11 में 100 अनुक्रमित बिंदु से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 120 अनुक्रमित बिंदु हो गई और यह वर्ष 2012-13 में घटकर 102 अनुक्रमित बिंदु हो गई तथा वर्ष 2013-14 में इसमें एक बार पुनः वृद्धि हुई और यह बढ़कर 124 अनुक्रमित बिंदु हो गई। बिक्री लागत में वृद्धि होने पर लाभप्रदता तीन गुनी बढ़ने की संभावना नहीं है, परंतु बिक्री लागत में घटौती होते ही बोझ तेजी से बढ़ जाता है। प्रवृत्ति यह उदघाटित करती है कि हो सकता है कि लाभ से संबंधित आंकड़े परिशुद्ध न हों और उसके आलोक में प्रतिवादीगण महानिदेशक रक्षोपाय से अनुरोध करते हैं कि वह इसकी जांच करें।

42. शुरु में, प्रतिवादीगण जांच शुरुआत नोटिस में दिए गए लाभप्रदता के आंकड़ों की सच्चाई को चुनौती देते हैं। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने संबद्ध उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए एक आवेदनपत्र दायर कर रखा है। पाटनरोधी याचिका में प्रदान कराए गए लाभप्रदता आंकड़े संबद्ध जांच में आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों से भिन्न हैं।

43. प्रतिवादीगण इस तथ्य पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं कि उपर्युक्त की इस तथ्य से पुनः संपुष्टि हो जाती है कि आवेदक, अपने उत्पादन की प्रतिशत के रूप में बिक्री वर्ष 2010-11 में 101 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 99 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में 96 प्रतिशत और जांच की अवधि में 98 प्रतिशत करने में सक्षम था। इसलिए, उत्पादन और बिक्री के अनुपात के संबंध में आवेदक के पास कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि फीडस्टॉक (पीओ) की अनुपलब्धता के कारण ही उसकी लाभप्रदता में कमी आई है।

44. आवेदक द्वारा दायर याचिका की एनसीवी में कीमत अधोदहन अवमंदन एवं निग्रहण आंकड़ों को अनुक्रमित रूप में नहीं दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण उक्त आंकड़े न होने के कारण कोई सार्थक प्रस्तुतिकरण करने में समर्थ नहीं हैं।

45. आवेदक की वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट युक्त याचिका के पृष्ठ 179 पर आवेदक ने उल्लेख किया है कि ग्राही पावर प्लांट के लिए बायोमास की उपलब्धता कम हो गई, जिसके कारण आवेदक को सीपीपी का प्रचालन न्यूनतर लोड पर करा पड़ा। अतः, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कोई क्षति मौजूद है तो यह आवेदक द्वारा अनुभव किए गए उत्पादन अवरोधों का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है।

46. प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि आवेदक मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तथापि ऐसा आवेदक की निजी स्वीकृति के अनुरूप नहीं किया जा सकता है क्योंकि मनाली क्षेत्र में क्षमता संवर्धन पर अधिस्थगन है। आवेदक ने इस तथ्य को अपनी वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है जिसे याचिका के पृष्ठ 180 पर प्रदान कराया गया है।

47. यह कि यदि आवेदक 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग से भी प्रचालन करता तब भी वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करके केवल 34 प्रतिशत बाजार की जरूरतों को ही पूरा कर पाता क्योंकि इसकी संस्थापित क्षमता केवल 25,000 एमटी है जब कि वर्ष 2013-14 के दौरान कुल मांग 74624 एमटी थी।

48. प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि प्राधिकारी के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 और 11 के साथ पठित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख के अनुरूप आवेदक

को होने वाली "गंभीर क्षति" और "सम्बन्धित आयातों" के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करें। इस तरह के कारणात्मक संबंध के बिना वर्तमान जांच में कोई भी रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

49. तथापि, प्रतिवादियों के उपर्युक्त प्रस्तुतिकरणों से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सहन की गई "गंभीर क्षति" निम्नलिखित कई अन्य कारणों से भी हो सकती है जैसे :

1. फीडस्टाक की उपलब्धता का अभाव;
2. उसके परिणामस्वरूप उत्पादन और बिक्री में कमी होना;
3. प्रोपायलीन के लिए चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, एकमात्र आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता;
4. संबद्ध उत्पाद की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करने में आवेदक की अक्षमता।

इनमें से कोई भी कारण संबद्ध उत्पाद की आयात मात्रा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए, वर्तमान जांच कारणात्मक विवरण असफल हो जाता है तथा उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

50. रक्षोपाय जांच में एक समायोजन योजना होना अनिवार्य है। यद्यपि आवेदक ने यह दावा किया है कि यह समायोजन योजना अगोपनीय होनी चाहिए फिर भी आवेदक द्वारा लगभग संपूर्ण समायोजन योजना को अपनी याचिका में गोपनीय रखा गया है।

51. ऐसा कोई विवरण नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि प्रतिवादीगण उस पर अपनी टिप्पणी देने में सक्षम होंगे। प्रतिवादीगण बिना किसी सूचना के समायोजन योजना के संबंध में कोई सार्थक प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते हैं और यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी हमें समायोजन योजना प्रदान करेंगे।

52. आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि वह मौजूदा क्षमता के अवरोधों को दूर करके अपनी क्षमता उपयोग में वृद्धि करेंगे। तथापि, आवेदक की स्वीकृति के अनुरूप उसने यह कार्य पहले ही पूरा कर लिया है और निःसंदेह, इसने आवेदक की क्षति को दूर करने में कोई सहायता नहीं की है। इसलिए, समायोजन योजना वाला भाग बेमानी है। इसका संगत उद्धरण वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में याचिका के पृष्ठ 103 पर दिया गया है।

53. इस संबंध में यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रति एमटी नियम लागत को कम करने की आवेदक की योजना त्रुटिपूर्ण है और इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। समायोजन योजना में दी गई तालिका में आवेदक ने उपर्युक्त दावा करने के पश्चात उपयोगी वस्तुओं/उपभोज्यों/श्रमिक लागत की सूची प्रदान की है, यह सभी परिवर्तनशील लागत है न कि नियम लागत। किसी भी हाल में नियम लागत को कम करने की आवेदक की योजना का अंतिम लागत पर 1 प्रतिशत से भी कम प्रभाव पड़ेगा।

54. आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि वह अपने क्षमता उपयोग स्तर में वृद्धि करने की योजना बना रहा है। तथापि, प्रतिवादीगणों ने पहले ही यह सिद्ध कर दिया है कि आवेदक के पास प्रोपायलीन और पीओ की भारी कमी है जिस पर आवेदक विजय पाने में सफल नहीं रहा है। इसलिए, यह एक बार फिर बेमानी हो जाता है कि आवेदक क्षमता उपयोग में वृद्धि करने की योजना बना रहा है। कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति के बिना ग्राही प्रोपायलीन आक्साइड की क्षमता में वृद्धि करने की आवेदक की योजना एक निरर्थक प्रयास होगा।

55. आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि वह ग्राही प्रोपायलीन आक्साइड की उत्पाद क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तथापि, वह कच्चे माल अर्थात् प्रोपायलीन की पर्याप्त आपूर्ति के बिना निष्प्रभावी हो जाएगा। कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति के बिना ग्राही प्रोपायलीन आक्साइड की क्षमता में वृद्धि करने की आवेदक की योजना एक निरर्थक प्रयास होगा।

56. आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि वह पीओ का भारी मात्रा में परिवहन करेंगे और अपने संभारतंत्र में सुधार करेंगे। प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि यह प्रयास भी परिवहन लागत में मार्जिनल कमी करने से ही प्रभावी होगा और इसका आवेदक द्वारा उपगत लागत पर कोई समग्र प्रभाव नहीं पड़ेगा।

57. महानिदेशक रक्षोपाय ने मिथायल एसिटोएसिटेट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच में दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 की अपनी अंतिम जांच परिणाम में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई समायोजन योजना यह प्रेक्षण करके नामंजूर कर दी कि इसमें सकारात्मक समायोजन के लिए कोई समयबद्ध ठोस योजना नहीं है और यह केवल एक प्रस्ताव है जिसको भविष्य में लागू किए जाने का इरादा है। यही स्थिति इस जांच में भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर भी लागू होती है।

58. यह भी निःसंदेह है कि यह आवेदक पिछले 16 वर्षों से पाटनरोधी और रक्षोपाय उपचारों का प्रयोग करता आ रहा है। आवेदक को प्रदान कराए गए इस संरक्षण के बावजूद वह अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने में सफल नहीं रहा जिससे यह तथ्य स्थापित होता है कि उसके द्वारा सहन की गई कोई क्षति अपने अंतर्निहित कारणों से है। इस कारण से भी हम महानिदेशक रक्षोपाय से यह अनुरोध करते हैं कि वह आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई समायोजन योजना को नामंजूर कर दें और वर्तमान जांच को समाप्त कर दें।

(ग) **मैसर्स आईआरपीसी पालियोल कंपनी लिमिटेड, एनर्जी काम्प्लेक्स भवन-ख, 7वां तल, विभावाडी रंगित रोड, चाटुचक बैंकाक-10900, थाईलैंड** ने अपना प्रस्तुतिकरण दिनांक 24.09.2014 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया कि उन्होंने भारत को होने वाले कुल आयात मात्रा में से 2 प्रतिशत से भी कम का निर्यात किया है।

(घ) **मैसर्स डाव यूरोप जीएमबीएच और मैसर्स डाव कैमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपना प्रस्तुतिकरण मैसर्स दुआ एसोसिएशन 202-206 टायस्टाय हाउस, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली के माध्यम से प्रस्तुत किया।**

1. वर्तमान प्रस्तुतिकरण डीसीआईपीएल और डाव यूरोप द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2014 को किए गए अपने प्रस्तुतिकरणों द्वारा दायर प्रारंभिक प्रस्तुतिकरणों और 29 सितम्बर, 2014 को किए गए पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के अलावा हैं; और
2. वर्तमान मामला एक अनूठा मामला है। यह प्रदर्शित करता है कि किसी संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक ने किस तरह पाटनरोधी महानिदेशालय (डीजीएडी) और रक्षोपाय महानिदेशालय (डीजी) से पिछले 15 वर्षों में बार-बार व्यापार उपचारी संरक्षण प्राप्त किया है।
3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच की अवधि (पीओआई) के लिए उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टें और तुलनपत्र कंपनी की एक सशक्त और लाभप्रद तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।
4. उपलब्ध आंकड़े स्पष्टतः यह अभिव्यक्त करते हैं कि बाजार की मांग को देखते हुए आयात अनिवार्य हो गए थे और यह तथ्य है कि घरेलू उद्योग घरेलू मांग के एक छोटे से भाग को ही पूरा करने में सक्षम है। लाभप्रदता में कोई गिरावट, यदि हुई है तो वह ऐसे कारकों के कारण हुई है जिसका आयातों से कोई लेना-देना नहीं जैसे उप-इष्टतम लागत ढांचा, कच्चे माल के लिए आयातों पर निर्भरता आदि।
5. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए जो शर्त है वह है पीयूसी का भारत में बहुत अधिक मात्रा में और कुछ विशेष शर्तों पर आयात। इस संबंध में लागू विधिक प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है।
6. यह आयात न तो अचानक हुए हैं, न ही बहुत तीव्र हैं और न ही इतनी अधिक मात्रा में हुए हैं कि वह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2 में निर्धारित शर्त को पूरा करते हों। वास्तव में वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान तो आधार वर्ष के दौरान हुए आयातों से तुलना करने पर आयातों में कमी आई थी।
7. इसके अतिरिक्त, आयातों में यह वृद्धि विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग में वृद्धि और उस मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के परिणामस्वरूप हुई है। आयातों में ऐसे होने वाली कोई भी वृद्धि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में हुई वृद्धि का ही परिणाम है।
8. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आयातों में यह वृद्धि भारत में इस एफएसपी की मांग वृद्धि के ही अनुरूप है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग संपूर्ण मांग के छोटे से ही भाग को पूरा करने में सक्षम है क्योंकि यदि मनाली अपनी क्षमता का शत-प्रतिशत उत्पादन भी करने लगे तब भी आयात होते ही रहेंगे। यह आयात न तो अचानक हुए हैं और न ही बहुत अधिक तीव्र हैं।

9. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि भारत में होने वाले आयातों से घरेलू उद्योग को "गंभीर क्षति" कारित की जा रही हो। "गंभीर क्षति" का आशय है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में एक समग्र बहुत अधिक परिक्षण होगा।
10. उन पैरामीटरों में से एक जिनपर घरेलू उद्योग ने गंभीर क्षति का दावा किया है, क्षमता उपयोग में कमी होना है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उसका क्षमता उपयोग जो आधार वर्ष में 90 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2013-14 (वार्षिकृत) में 55 प्रतिशत ही रह गया। क्षमता उपयोग में इस कथित गिरावट का आयातों से कोई लेना देना नहीं है। घरेलू उद्योग की समग्र पालियोल क्षमता 33,000 एमटी से बढ़कर 50,000 एमटी हो गई (घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, पृष्ठ 103/127)। तथापि, पालियोल संयंत्र की यह संवर्धित क्षमता भी प्रोपायलीन आक्साइड क्षमता में वृद्धि हुए बिना अपने प्रयोजन को पूरा नहीं करती है।
11. घरेलू उद्योग ने इस विचाराधीन उत्पाद के लिए 25,000 एमटी की संस्थापित क्षमता का दावा किया है। तथापि, यह क्षमता अनन्यतः विचाराधीन उत्पाद के लिए ही नहीं है। इसका कारण यह है कि :
 - (क) यह माना जाता है कि इस पालियोल संयंत्र की प्ररूपी ढंग से विविध उत्पाद करने की क्षमता है जिसे आसानी से एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में स्विच किया जा सकता है, स्पष्टतः दैनिक आधार पर। यह बात संपूर्ण उद्योग के लिए सच है कि संपूर्ण विश्व में प्रत्येक उत्पादक बाजार डायनामिक्स के आधार पर ग्रेडों का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता में परिवर्तन लाता है।
 - (ख) ऐसे विविध उत्पाद प्रचालनों के मामले में कुल उत्पाद मिश्रण में से लागत आबंटन किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए करने से उसकी विकृति होने की संभावना बढ़ जाती है।
 - (ग) वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की मिली-जुली उत्पादन लाइन है। इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद की क्षमता में गिरावट आना घरेलू उद्योग के इस व्यवसाय निर्णय का परिणाम है कि उस संयंत्र का उपयोग अन्य ऐसे पालियोलों का उत्पादन करने के लिए किया जाए जिनकी बाजार/जिनका अनुप्रयोग इस विचाराधीन उत्पाद की तुलना में अधिक आकर्षक और लाभप्रद है। इसलिए यह पूर्णतया स्पष्ट है कि क्षमता उपयोग में गिरावट का आयातों से कोई लेना-देना नहीं है और इसे घरेलू उद्योग के व्यवसाय निर्णयों के साथ स्पष्टतः उपरोपित किया जा सकता है।
12. इस क्षमता उपयोग में गिरावट का एक अन्य स्पष्ट कारण है कि इस विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता का संपरिवर्तन निर्यात बाजारों के लिए भी किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने अपनी वर्ष 2013-14 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि "निर्यात बिक्री 2.83 करोड़ रुपए से बढ़कर 17.58 करोड़ रुपए हो गई जो अब तक दर्ज की गई बिक्री की सर्वाधिक है।"
13. घरेलू उद्योग के वित्तीय रिकार्डों से यह देखा जा सकता है कि कंपनी का निर्यात जो वर्ष 2010-11 में केवल 2.51 करोड़ रुपए का था, 600 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में 17.58 करोड़ रुपए हो गया, जिससे यह संपुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग उसी आस्ति का प्रयोग करके घरेलू बाजार के लिए एफएसपी का उत्पादन करने के बजाय उच्च मूल्य वाले विशिष्ट पालियोल का निर्यात करने के लिए उत्पादन करने पर अधिक ध्यान देता है।
14. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग स्केल्स की अर्थव्यवस्था कुछ विदेशी उत्पादकों की वजह से प्राप्त नहीं कर सकता है इसके लिए कारण यह है कि पालियोल उद्योग में स्केल्स की अर्थव्यवस्था केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब संयंत्रकी क्षमता 20,000 एमटी से 40,000 एमटी (लगभग) के बीच हो। घरेलू उद्योग का संयंत्र, जिसकी समग्र पालियोल क्षमता 50,000 एमटी है, लागत निष्प्रभावी ही रहेगा और वह केवल घिसीपिटी प्रविधिका ही उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग प्रोपायलीन आक्साइड के आयातों पर निर्भर है, जिसके कारण उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

15. घरेलू उद्योग लाभ में गंभीर कमी आने का दावा करता है। तथापि, उसकी वार्षिक रिपोर्ट और तुलनपत्र पालियोल सेक्टर में भी वर्ष-दर-वर्ष लाभ और विकास दर्शाते हैं। यद्यपि, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में कमी आई है, तथापि, घरेलू उद्योग यह उल्लेख करने में असफल रहा कि उन्होंने अपनी क्षमता का उपयोग पालियोल के अन्य ग्रेडों का उत्पादन करने में किया है जो पालियोल बिक्री के राजस्व में वृद्धि होने का मुख्य कारण है। इसलिए घरेलू उद्योग को यह चाहिए कि वह इस विचाराधीन उत्पाद के बारे में अलग से प्रदर्शन न करे बल्कि खंडवार लाभप्रदता (सभी पालियोल खंडों के लिए) प्रदर्शित करें। यदि संपूर्ण पालियोल सेगमेंट को नुकसान हो, केवल तभी यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को भारी क्षति का घाटा हुआ है।
16. घरेलू उद्योग द्वारा लाभप्रदता के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्टों में किए गए कुछ उद्धरणों को संदर्भ की आसानी के लिए नीचे उद्धृत किया जाता है :

प्रचालनात्मक हाईलाइट्स (पृष्ठ 2)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी पालियोल संभरकों से बेहद प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद कंपनी का प्रचालन विगत वर्ष की तुलना में बेहतर रहा। इस वर्ष के लिए निवल लाभ पिछले वर्ष हुए 27.32 करोड़ रुपये की तुलना में 6 प्रतिशत बढ़कर 29.05 करोड़ रुपया हो गया। उद्योग ढांचा एवं विकास (पृष्ठ 2) वर्ष 2007-2012 के दौरान भारतीय पालीयूरीथीन उद्योग का कार्यनिष्पादन दो अंकों तक वृद्धि प्राप्त करके काफी कारगर रहा है परंतु समग्र आर्थिक विकास में मंदी होने, वैश्विक आर्थिक संकट का भारतीय विनिर्माताओं पर प्रभाव, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, मानसून की असफलता आदि जैसे विभिन्न कारणों से वर्ष 2013 में बाजार की स्थिति स्थिर बनी रही।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुछ सुधार भी देखा गया।

17. घरेलू उद्योग की वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालती है :
 - यह एक साइकिलिकल उद्योग जिसमें पीक और आफ-पीक अवधि आती है।
 - बाजार विकास/खपत मानदंड पर निर्भर करती है।
 - घरेलू उद्योग की ही बिक्री वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक थी, जबकि उसके तत्काल अगले वर्ष ही इसमें गिरावट आ गई, यह गिरावट आयातों के कारण नहीं आई बल्कि यह गिरावट स्पष्टतः आर्थिक विकास में कमी होने के कारण आई।
 - डब्ल्यूटीओ ने वैश्विक व्यापार विकास वर्ष 2011 में 5.11 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2013 में 3.30 प्रतिशत होने की भविष्यवाणी की है। इसलिए लाभप्रदता में आरोपित कमी का स्पष्टतः आयातों से कोई लेना-देना नहीं है।
18. यद्यपि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता में प्रपाती गिरावट होने का दावा किया है। फिर भी उसने अपने शेयरहोल्डरों को वार्षिक लाभांश वितरित किया है जैसाकि उसकी वार्षिक रिपोर्टों और तुलनपत्रों से स्पष्ट है। यदि किसी कंपनी की लाभप्रदता में इतनी अधिक कमी आ जाएगी तो वह उस ढंग से अपने लाभांश का वितरण करने में सक्षम नहीं होगी जिस ढंग से जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने किया है।
19. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उसका उत्पादन जो वर्ष 2010-11 में 16510 एमटी था, घटकर वर्ष 2013-14 में 13811 एमटी ही रह गया। तथापि, उत्पादन में इस गिरावट का कारण आयात नहीं है बल्कि यह गिरावट कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण आई है।

- (क) घरेलू उद्योग प्रोपायलीन के एकमात्र संभरक चेन्नई पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) पर निर्भर है। सीपीसीएल ने ही कम आपूर्ति की जैसाकि आवेदन के पृष्ठ 103 पर घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है।
- (ख) प्रोपायलीन आक्साइड का आयात करने की जरूरत। प्रोपायलीन आक्साइड का आयात उच्च लागत पर किया गया है और इससे इस विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग का लागत ढांचा उप-इष्टतम हो गया। उपर्युक्त अभिकथनों से इस तथ्य का संकेत मिलता है कि बिक्री, उत्पादन, लाभप्रदता आदि में गिरावट, अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख कच्चे की उपलब्धता में कमी, घरेलू उद्योग के व्यवसाय निर्णय और उप-इष्टतम लागत ढांचा, के कारण आई है।
20. घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान गिरावट केवल एक अंक की अर्थात् 6 प्रतिशत गिरावट ही है। यह भी नोट किया जा सकता है कि शत-प्रतिशत उत्पादन करने पर भी घरेलू उद्योग इस विचाराधीन उत्पाद की मांग के एक छोटे से भाग की है आपूर्ति करने में सक्षम होता और इसलिए आयात करना अनिवार्य हो गया। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के उत्पाद में त्रुटिपूर्ण आपूर्तियाँ, उपभोक्ताओं के साथ की गई वचनबद्धता को समय से पूरा न करने और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण भी गिरावट आई है। इसलिए, बाजार हिस्से का खो जाना घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का संकेतक नहीं है।
21. घरेलू उद्योग वर्ष 2012-13 की तुलना में इस वर्ष स्टॉक की भारी मात्रा का संचलन करने में सक्षम था।
22. घरेलू उद्योग यह दावा करता है कि जांच की अवधि के दौरान रोजगार में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है तथापि, इस गिरावट का विचाराधीन उत्पाद के आयातों से कोई कोई संबंध नहीं है। कर्मचारियों की संख्या में यह कमी कई ऐसे कारणों की वजह से भी आ सकती है जिसका आयात से कोई लेना-देना न हो जैसे : यह एक सर्वविदित तथ्य है कि प्ररूपिक तौर पर जब प्रविधि का उन्नयन होता है तब कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी जाती है और इस मामले में घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान पालियोल संयंत्र की समग्र क्षमता में निःसंदेह वृद्धि की थी। घरेलू उद्योग ने वेतनपत्रक में कर्मचारियों की संख्या में कमी करके और अधिकाधिक संविदा श्रम का नियोजन करके अपने कर्मचारियों की संख्या घटाई हो। पालियोल संयंत्र की बहु उत्तार-चढ़ाव क्षमता होती है और इस विचाराधीन उत्पाद के लिए रोजगार के वास्तविक प्रमाणन की पुष्टि करने की जरूरत है।
23. यह सुस्पष्ट है कि डब्ल्यूटीओ विधि और म्युनिसिपल विधि दोनों के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4 (ख) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(1) और रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 और 11 के अनुसार कारणात्मक संबंध स्थापित करना अपेक्षित होता है।
24. ऊपर चर्चा किए गए सभी तथ्यों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए यह विधिक अपेक्षा हो जाती है कि वह साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध करे कि घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति और संवर्धित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध है। तथापि, इस मामले में उपलब्ध तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग को होने वाली अभिकथित गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
25. बाजार बिक्री, उत्पादन और उत्पादकता, क्षमता उपयोग का अभिकथित नुकसान यदि सही भी है तो यह अन्य घटकों पर आधारित है : पीओ और प्रोपायलीन जो इस विचाराधीन उत्पाद के मुख्य कच्चे माल हैं की कमी होना क्योंकि इनके लिए आयात पर निर्भरता है और इसलिए लागत प्रगुणता उप-इष्टतम हो जाती है, जिसके कारण लाभ में गिरावट आई, निःसंदेह इस उद्योग की घूर्णित प्रकृति और सामान्य आर्थितमंदी। घरेलू उद्योग एकाधिकारवादी है और इसलिए लागत प्रगुणता में सुधार करने के लिए उसके पास कोई प्रोत्साहन नहीं है। मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होने के कारण आयात करना आवश्यक हो गया था। घरेलू उद्योग अपनी शत-प्रतिशत क्षमता से उत्पादन करके भी घरेलू बाजार की 25 प्रतिशत से

- 30 प्रतिशत मांग को पूरा करने में सक्षम था। निश्चय ही घरेलू उद्योग को विद्युत की कमी का सामना भी करना पड़ा जिससे उसकी लाभप्रदता प्रभावित हुई। अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि "इस कंपनी ने विद्युत की खरीद ऊर्जा विनिमय के जरिए की और विद्युत की कमी को दूर करने के लिए उसने यह खरीद तीसरे पक्षकारों से भी की। इसके परिणाम विद्युत की उच्च लागत देनी पड़ी और परिणामस्वरूप कंपनी की लाभप्रदता भी प्रभावित हुई।
26. घरेलू उद्योग एक अद्यतन संरक्षण की मांग करने वाली कंपनी है और यह वर्ष 1998 से ही रक्षोपाय और पाटनरोधी शुल्कों की लाभग्राही रही है। यह सुस्पष्ट है कि घरेलू उद्योग बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए रक्षोपाय शुल्क और पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने भरोसा करता है। पाटनरोधी और रक्षोपाय न्यायविज्ञान दोनों में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शुल्क का अधिरोपण करने का उद्देश्य घरेलू उद्योग के लिए समान अवसरों का सृजन करना है, न कि दमनकारी कर शासन प्रणाली से अकुशल घरेलू उद्योग को सहायता करना।
 27. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक अकुशल उद्योग का स्पष्ट मामला है जो इस संबद्ध वस्तु की होने वाली प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए संरक्षणवादी प्रणाली पर भरोसा करता है। विधि में इसकी इजाजत नहीं है और इसलिए महानिदेशक का यह दायित्व है कि वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इस सूचना पर ध्यान दें और घरेलू उद्योग के आवेदन को अस्वीकार कर दें। वर्तमान जांच की शुरुआत करना ही विधि विरुद्ध है।
 28. आवेदन के अगोपनीय पाठ का अध्ययन करने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अतिशय गोपनीयता का दावा किया गया है।
 29. इन उपायों का अंतिम उपयोगकर्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इस अवधि के दौरान लगभग 47 कंपनियां बंद हो गईं क्योंकि वे इस घरेलू उत्पादक की वजह से प्रतिस्पर्धी नहीं रहीं। औसतन रूप से एक फोमिंग संयंत्र में 15-20 कर्मचारी होते हैं और रक्षोपाय शुल्क तथा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से लगभग 900 व्यक्तियों ने अपना रोजगार खो दिया।
 30. इसके अतिरिक्त, भारत में पोलियो की कीमत एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक है और इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क की अधिरोपण करने से यह उत्पाद और भी अधिक महंगा हो जाएगा तथा इससे यह अनुप्रवाही उद्योग के लिए और अधिक हानिकारक हो जाएगा।
 31. अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान महानिदेशक को चाहिए कि वह व्यापक जनहित पर ध्यान दें और इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क को नकार दें। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से कोई जनहित नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता उद्योग बंद हो जाएंगे जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी।

(IV) आयातों/उपयोगकर्ताओं के विचार

(क) मैसर्स शीलाफोम प्राइवेट लिमिटेड ने अपना प्रस्तुतिकरण मैसर्स टीएलसी लीगल आईआर-163, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली के माध्यम से किया है।

1. याचिका के साथ-साथ सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतिकरणों में जांच शुरुआत अधिसूचना में किए गए प्रस्तुतिकरणों से काफी अंतर है।
 - (क) जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 2 में यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वह भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। तथापि, सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने यह स्वीकार किया कि इस विचाराधीन उत्पादक का कोई अन्य उत्पादक भी है। इस प्रकार, यह जांच शुरुआत दोषपूर्ण प्रकल्पना पर आधारित है कि आवेदक इस संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है जबकि इस संबद्ध वस्तु का भारत में एक अन्य विनिर्माता भी है।
 - (ख) जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 3 में यह उल्लेख किया गया है कि इस विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 39072010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और केवल उपर्युक्त

शीर्षक के अंतर्गत किए गए आयातों पर ही विचार किया गया है। तथापि, सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने तर्क दिया कि इस विचाराधीन उत्पाद का शीर्षक 39072090 के अंतर्गत भी आयात किया जा रहा है और उसने उन आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है जिनमें दोनों शीर्षकों के अंतर्गत किए जाने वाले आयातों को शामिल किया गया है।

- (ग) जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 5 में यह उल्लेख किया गया है कि यह उल्लेख किया गया है कि डीजीसीआईएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर विचार किया गया है। आवेदनकर्ता ने अपनी याचिका में तथा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान जो प्रस्तुतिकरण किए वह वैकल्पिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित थे और उन्होंने प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए डीजीसीआईएस आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया है। यह नोट किया जा सकता है कि दोनों स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों में न केवल मात्रा के रूप में बल्कि दर के रूप में भी भारी विसंगतियां हैं। दोनों आंकड़े आयातों में वृद्धि के बिल्कुल भिन्न आंकड़े दर्शाते हैं।
- (घ) जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 7(ख) में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक की वर्तमान संस्थापित क्षमता 25,000 एमटी है। तथापि, सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने यह तर्क दिया कि उसकी संस्थापित क्षमता 50,000 एमटी है।
- (ङ) जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 7(ग) में भारतीय बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग और घरेलू उद्योग एवं आयातों के बाजार हिस्से के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। उक्त आंकड़े याचिका में उल्लिखित आंकड़ों और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतिकरणों से बिल्कुल भिन्न हैं।
- (च) पाटनरोधी प्राधिकारियों के समक्ष दायर याचिका में आवेदन ने तर्क दिया है कि इसकी लाभप्रदता में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में 20 प्रतिशत की कमी आई है। तथापि, महानिदेशक रक्षोपाय के समक्ष प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में आवेदक ने उसी अवधि के दौरान अपनी लाभप्रदता में 224 प्रतिशत की वृद्धि होने का दावा किया है। आवेदक द्वारा महानिदेशक पाटनरोधी के समक्ष दायर याचिका (अगोपनीय पाठ) के संगत पृष्ठ इसके साथ संलग्न है और उन्हें अनुबंध-1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

2. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपनी याचिका में और सार्वजनिक सुनवाई में जिन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, उनमें और इन आंकड़ों में बहुत अंतर है जिनको आधार बनाकर महानिदेशक रक्षोपाय ने इस जांच की शुरुआत की है। चूंकि घरेलू उद्योग को ही जांच शुरुआत में उल्लिखित आंकड़ों से सहमत नहीं है इसलिए इस जांच शुरुआत को इस आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस विसंगति से यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का विस्तृत सत्यापन किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में इस जांच शुरुआत पर ही संदेह हो रहा है और उस समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
3. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिका में उल्लिखित सूचना के लिए 100 प्रतिशत सही होना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 में जांच शुरुआत के लिए तरीके का प्रावधान किया गया है।
4. नियम 5 के अनुसार आवेदक को चाहिए कि वह संवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति तथा आयातों एवं अभिकथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के साक्ष्य प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी प्रावधान है कि प्राधिकारी कोई जांच तब तक प्रारंभ नहीं करेंगे जब तक कि वह आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए साक्ष्य की उपयुक्तता एवं यथार्थता की जांच न कर लें।
5. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ न तो उपयुक्त है और न ही यथार्थ। तदनुसार प्राधिकारी ने ऐसे साक्ष्यों को नामंजूर कर दिया और डीजीसीआईएस से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर, न कि आवेदनपत्र में उल्लिखित आंकड़ों के आधार पर, कार्रवाई करने का निश्चय किया।

6. यदि यह मान भी लिया जाए कि इस जांच का जारी रखा जाए, और घरेलू उद्योग से कहा जाए कि वह याचिका में सही आंकड़ों के अनुरूप सुधार कर ले और यदि आवश्यक हो तो नए सिरे से जांच पुनः प्रारंभ की जाए तथा उसके बाद सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाए। ऐसा न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सकल उल्लंघन करना होगा। यह आवेदक विगत 16 वर्षों से विभिन्न शुल्कों का लाभ प्राप्त कर रहा है।
7. मनाली को आयातों के विरुद्ध शुल्क संरक्षण प्राप्त है। इस समय भी, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए आवेदनपत्र के साथ-साथ मनाली ने पाटनरोधी शुल्कों का अधिरोपण/विस्तारण की मांग करते हुए दो अन्य आवेदनपत्र दायर कर रखे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने लंबे समय से इन शुल्कों का संरक्षण प्राप्त होते हुए भी मनाली अभी भी आयातों के साथ समायोजन करने में असमर्थ है। यह स्पष्ट नहीं है कि अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किस तरह मनाली को समायोजन करने में सहायता करेगा जब यह पिछले 16 वर्ष से समायोजन नहीं कर पाई है।
8. याचिका में किए गए प्रस्तुतिकरणों से यह ज्ञात है कि क्या आवेदक अपनी क्षमता में विस्तार करना चाहता है या वह अपने क्षमता उपयोग के स्तर में सुधार करना चाहता है। आवेदक ने अपनी याचिका में यह प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2013-14 में उनके पास 45 प्रतिशत निष्क्रिय क्षमता है। यह स्पष्ट नहीं है कि मनाली जब अपनी वर्तमान क्षमता का ही उपयोग कर पाने की स्थिति में नहीं है तो क्षमता विस्तार करने से इसे सहायता कैसे प्राप्त होगी। हर हाल में, आवेदक ने इस संबंध में कोई भी सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि वह क्षमता में या क्षमता उपयोग के स्तर में कैसे और कब तक वृद्धि कर लेगा।
9. इसके अतिरिक्त, एक सामान्य सा यह अभिकथन कर देना कि अवरोधों को दूर करके क्षमता में विस्तार किया जाएगा, इससे आवेदक की समायोजन योजना पर भरोसा कर लेना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता में न तो अपनी याचिका में और न ही सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कहीं भी यह उल्लेख किया है कि मनाली आयातों के साथ समायोजन करने के लिए योजना पर कार्रवाई करने की योजना बना रहा है।
10. सर्वोत्तम रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना रक्षोपाय शुल्क की अवस्थिति के दौरान बिक्री और उत्पादन में वृद्धि करने की एक छद्म योजना है। यह एक स्वाभाविक उपनिगमन है कि एक बार रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर दिए जाने पर मनाली की बिक्री और उत्पादन में शुल्क के संरक्षण में वृद्धि होगी। तथापि, चूंकि मनाली के पास स्वयं को/अपने उत्पादकों आयातों की तुलना में प्रतिस्पर्धा स्तर पर लाने की कोई वास्तविक योजना नहीं है इसलिए शुरू को हटा लिए जाने पर मनाली की बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग फिर पुराने स्तर पर ही पहुंच जाएगा।
11. इसके अतिरिक्त, आवेदक ने यह तर्क भी दिया है कि वे भारी परिवहन में और प्रोपायलीन आक्साइड (कच्चे माल) के संभारतंत्र में सुधार करके समायोजन करने की योजना बना रहे हैं। यह देखा जा सकता है कि महानिदेशक रक्षोपाय के समक्ष 1998 में प्रस्तुत की गई समायोजन योजना भी कच्चे माल से संबंधित संभारतंत्र में सुधार करने की ही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक उसी समय इस तथ्य के प्रति जागरूक था कि कच्चे माल का परिवहन उनके लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है और इस संबंध में समायोजन बहुत पहले ही कर लिया जाना चाहिए था। तथापि, वे कच्चे माल की समस्या में सुधार करने में अभी भी स्पष्ट तौर पर असफल ही रहे हैं। यह बात नहीं है कि अगले 2 या 3 वर्षों में इस समस्या में सुधार करने के लिए वे कौन सी आपवादिक योजना बना रहे हैं।
12. इसके अतिरिक्त, आवेदक ने यह तर्क दिया है कि वह प्रोपायलीन आक्साइड उत्पादन सुविधा की क्षमता में वृद्धि करने की योजना बना रहा है। तथापि, अपनी वर्ष 2012-13 की वित्तीय रिपोर्ट में, उसने यह उल्लेख किया है कि पीओ के लिए थोक में भंडारण/प्रहस्तन सुविधा वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही तक प्रचालनात्मक हो जाएगी। इस प्रकार, चूंकि संवर्धित क्षमता वर्ष 2012-13 से प्रतिष्ठापित कर दी गई है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि यह समायोजन योजना का भाग कैसे बन सकती है। रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग को दिए जाने वाला एक ऐसा संरक्षण है जिससे वह अपनी समायोजन योजना पर कार्रवाई कर सके। चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित योजना पहले से ही मौजूद है इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की कोई जरूरत नहीं है।

13. इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आवेदक इस विचाराधीन उत्पाद के लिए या कच्चे माल के लिए क्षमता में वृद्धि करके या क्षमता उपयोग के स्तर में वृद्धि करके समायोजन करने का प्रस्ताव कर रहा है। किसी भी स्थिति में, संवर्धित क्षमता से उत्पादन लागत में कमी करने में कोई सहायता प्राप्त नहीं होने वाली। ऐसा कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है कि मनाली घरेलू बाजार में अपनी बिक्रियों को अर्थक्षम करके किस तरह अपनी उत्पादन लागत में कमी करने जा रहा है।
14. इसके अतिरिक्त, आयातों के साथ समायोजन करने की आवेदक की अक्षमता और अनिच्छुकता इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने 16 वर्षों तक शुल्क का लाभ प्राप्त करने के पश्चात भी आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जरूरी उपाय नहीं किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समायोजन योजना भी शुल्क की प्रवर्तन अवधि के दौरान क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री के स्तर में उच्चतर स्तर प्राप्त करना है। एक बार शुल्क को हटा लिए जाने पर आवेदक पुनः अपनी पिछली स्थिति में ही पहुंच जाएगा और भारतीय उद्योग के एक भाग बने अन्य आयातकों के मूल्य पर पुनः संरक्षण प्रदान करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष एक अन्य याचिका दायर करेगा।
15. अब यह एक सुस्थापित विधि है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल तभी किया जा सकता है तब यह प्रदर्शित हो कि संबद्ध वस्तु का भारत में आयात इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा है कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है।
16. महानिदेशक रक्षोपाय ने डीजीसीआईएस से प्राप्त आयात आंकड़े के आधार पर यह जांच प्रारंभ की है। रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि शीर्षक संख्या 39072010 के अंतर्गत किए गए सभी आयातों को "संबद्ध वस्तु" के आयातों के रूप में माना गया है। यह सूचना दी गई है कि सौदेवार आंकड़े नहीं प्राप्त किए गए हैं।
17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबद्ध वस्तु के दायरे के बाहर रहने वाली कई मदों को भी इस उपर्युक्त शीर्षक के अंतर्गत आयात किया है [विभिन्न प्रकार के पाली (ईयर) अल्कोहल और 3000 मालिक्यूलर भार से कम या 4000 मालिक्यूलर भार से अधिक के मालिक्यूलर भार वालों को भी इस शीर्षक के अंतर्गत कवर किया जाता है।] इसके अतिरिक्त, इस संबद्ध वस्तु का आयात अन्य उप-शीर्षकों के अंतर्गत भी किया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों की प्रमात्रा का निर्धारण करने के उद्देश्य से डीजीसीआईएस से लेनदेन संव्यवहार-वार सूचना प्राप्त की जा सकती है और संबद्ध वस्तु से संबंधित लेनदेन संव्यवहार पर ही इस जांच के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है।
18. अतः रिकार्ड में यह दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि आयातों में वृद्धि हुई है और आयातों में बहुत बड़ा उद्रेक हुआ है। इसके विस्तृत रूप से पहले ही यह प्रस्तुत कर दिया है कि विचाराधीन उत्पाद पर विचार करते हुए प्राधिकारी को आयातों की प्रवृत्ति और प्रमात्रा संबंधी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आयातों से संबंधित लेनदेन संव्यवहार-वार सूचना की जांच करनी पड़ती है।
19. इस तथ्य के मद्देनजर कि कोई ऐसे प्राधिकृत आंकड़े नहीं हैं जो यथा तथ्य आंकड़े और आयातों में यदि कोई उद्रेक हुआ हो तो उसे दर्शाते हों, इसलिए रक्षोपाय करार के साथ पठित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख की अपेक्षा पूरी नहीं होती है। चूंकि यह जांच शुरुआत किसी ऐसी सूचना पर आधारित नहीं है जो आयातों के उद्रेक से संबंधित प्रथमदृष्टया निर्धारण के लिए समुचित एवं यथोचित हो।
20. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने यह प्रस्तुत किया कि जरूरी नहीं है किया याचिका 100 प्रतिशत परिशुद्ध हो। यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक द्वारा समुचित होने के लिए कितनी परिशुद्धता पर विचार किया जाना चाहिए।
21. आवेदक ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि वे "भारत में इस संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं"। तथापि, सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने यह स्वीकार किया कि इस संबद्ध वस्तु का मैसर्स एक्सपैंडेड पालिमर सिस्टम्स नाम एक अन्य उत्पादक भी है, परंतु दावा किया कि अन्य उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं किया है। आवेदक ने मूल याचिका में न केवल गलत तथ्य प्रस्तुत

- किए बल्कि उसने प्राधिकारी को यह गलत सूचना देकर कि अन्य उत्पादक जांच की अवधि के दौरान प्रचालन में नहीं था, भ्रमित करने का प्रयास किया है।
22. जांच शुरू अधिसूचना में जांच की अवधि को 2010-11 से 2013-14 तक परिभाषित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक्सपैंडेड पालिमेर सिस्टम्स भी जांच की अवधि के दौरान प्रचालन में था। हमने फरवरी, 2012 में दो बीजकों पर और जून, 2012 माह में तीन बीजकों पर एक्साफ्लेक्स 3056 (संबद्ध वस्तु) की खरीद की है। बीजकों में से एक बीजक क्रमांक 222 है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अप्रैल, 2012 से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के कम से कम 221 बीजकों का क्लीयरेंस पहले ही हो चुका था।
23. हम भरोसा करते हैं कि मैसर्स कर्लआन लिमिटेड जैसे अन्य उपयोगकर्ता ने भी जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद की खरीद मैसर्स एक्सपैंडेड पालिमेर सिस्टम्स से की होगी। मैसर्स एक्सपैंडेड पालिमेर सिस्टम्स से संबद्ध वस्तु के अधिप्रापण के साक्ष्य स्वरूप बीजकों की प्रतियां गोपनीय के रूप में इसके साथ अनुबंध-2 पर संलग्न हैं।
24. द्वितीयतः, सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मनाली ने यह दावा किया कि उनकी क्षमता 50,000 एमटी है। तथापि, अपनी याचिका में उन्होंने यह प्रस्तुतिकरण किया कि वर्ष 2013-14 में उनकी संस्थापित क्षमता 25,000 एमटी है। यदि मनाली का यह दावा सही है तो यह स्पष्ट नहीं है कि याचिका में सूचना क्यों दी गई। इसलिए यह जांच शुरूआती विधि विरुद्ध हो जाती है क्योंकि यह मनाली द्वारा प्रस्ताव किए गए गलत तथ्यों पर आधारित है।
25. यह निवेदन किया जाता है कि अन्य उत्पादक की मौजूदगी को छिपाना इस जांच को स्वयं ही निष्प्रभावी कर देता है क्योंकि :
- (क) मनाली की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
 - (ख) हो सकता है कि एक्सपैंडेड को क्षति न हो रही हो।
 - (ग) हो सकता है कि एक्सपैंडेड की उत्पादन लागत मनाली की उत्पादन लागत से कम हो जिससे मनाली की अकुशलता का साक्ष्य मिलता हो।
 - (घ) एक्सपैंडेड के उत्पादन और बिक्री आंकड़े विभिन्न क्षति पैरामीटरों जैसे कुल मांग, कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात, आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, को प्रभावित कर सकते हैं।
26. प्राधिकारी यह विचार कर सकते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में बिक्री कीमत में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उत्पादन लागत में आधार वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसे परिदृश्य में जहां उत्पादन लागत में वृद्धि बिक्री कीमत की तुलना में अधिक अनुपात में हुई हो वहां तो लाभ में गिरावट आएगी ही। परंतु, याचिका के अनुसार, आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में यह लाभ बढ़कर तीन गुना हो गया। यह एक असंभव स्थिति है। इसी तरह, आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में बिक्री कीमत में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उत्पादन लागत में नगण्य वृद्धि हुई, इसलिए वर्ष 2012-13 में होने वाला लाभ आधार वर्ष में हुए लाभ की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। तथापि, याचिका में वर्ष 2012-13 में भारी घाटा दिखाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिका में प्रदान कराए गए आंकड़े स्पष्टतः अवास्तविक एवं भ्रामक हैं। ऐसा लगता है कि ऐसी अविश्वसनीय सूचना आवेदक द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत की गई है जिससे कि वास्तविक स्थिति का प्रकटन किए जाने से बचा जा सके और हितबद्ध पक्षकारों को किए गए दावे के संबंध में सार्थक प्रस्तुतिकरण करने से रोका जा सके।
27. चतुर्थतः यह भी नोट किया जा सकता है कि आवेदक ने इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की मांग करते हुए एक आवेदनपत्र दायर कर रखा है। डीजीएडी के समक्ष दिए गए अपने आवेदनपत्र में उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है कि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में उनकी लाभप्रदता में 20 प्रतिशत की कमी आई है। तथापि, महानिदेशक, रक्षोपाय के समक्ष प्रस्तुत किए गए आंकड़ों

- में आवेदक ने दावा किया है कि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में उनकी लाभप्रदता में 224 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या दो समानांतर प्राधिकारियों के समक्ष ऐसे भिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
28. पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिका में प्रस्तुत की गई सूचना में भी कंपनी के लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तुलना में भारी अंतर है। मनाली की लेखापरीक्षित रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण जांच अवधि के दौरान उन्होंने निरंतर भारी लाभ अर्जित किया है। मनाली निरंतर भारी लाभ अर्जित करती रही है और उसने अपने शेयरधारकों भारी लाभांश का भुगतान किया है।
29. इसके अतिरिक्त, यदि यह मान भी लिया जाए कि मनाली का यह दावा कि उसे विचाराधीन उत्पाद पर भारी घाटा उपगत हुआ है, सही है तो भी उसे इस स्तर का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए इस उत्पाद पर असाधारण लाभ अर्जित करना होगा।
30. अतः यह अनुरोध किया जाता है कि उत्पादन लागत का खुलासा करना चाहिए। आवेदक से उसके द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु तथा अन्य उत्पादों के बीच सामान्य लागत से आबंटन के आधार पर प्रकटन करने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि उत्पादन लागत को गोपनीय भी माना जाए तब भी लागत आबंटन के आधार पर इस तरह विचार नहीं किया जा सकता है। यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसी सूचना अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी अविलंब उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
31. गाट 1994 के अनुच्छेद XIX : 1(क) में यह अपेक्षा की गई है कि आयातों में वृद्धि "अनपेक्षित विकास" (इस पर जोर दिया गया है) के परिणामस्वरूप होना चाहिए। विशेषकर, इस मामले में संबद्ध वस्तु के आयातों में होनी वाली कोई भी वृद्धि भारत सरकार आशियान-भारत एफटीए (एआईएफटीए) के तहत प्रदान की गई प्रशुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप हुई है। तथापि, आईईएफटीए के अंतर्गत भारत द्वारा प्रदान की गई एक ठोस प्रतिबद्धता है और उसे "अनपेक्षित विकास" के रूप में नहीं माना जा सकता है।
32. वर्तमान मामले में चूंकि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और आवेदक द्वारा सुनवाई के समय एवं जांच शुरुआत अधिसूचना के समय भरोसा किए गए, लगभग सभी क्षति पैरामीटरों के संबंध में, आंकड़ों में अपसरण है, इसलिए हम घरेलू उद्योग को कारित की जा रही अभिकथित क्षति के संबंध में कोई भी प्रस्तुतिकरण करने में सक्षम नहीं है। चूंकि आयातों, लाभप्रदता, क्षमता, उत्पादन लागत, बाजार हिस्सा के पहलू के संबंध में आंकड़ों की विश्वसनीयता ही संदेह से परे नहीं है इसलिए हम इस पहलू पर अपना प्रस्तुतिकरण करने में सक्षम नहीं है। हम माननीय प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह इस कार्रवाई को समाप्त कर दें और आवेदक से कहें कि वह परिशुद्ध आंकड़ों सहित एक सही याचिका दायर करें जिसके आधार पर एक नई जांच की शुरुआत की जा सके।
33. वर्तमान स्थिति में, चूंकि कार्रवाई गलत आंकड़ों पर आधारित है और घरेलू उद्योग स्वयं ही उन आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर रहा है जिन पर यह जांच प्रारंभ की गई है, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अपने विचार व्यक्त करने के लिए उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। वर्तमान कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सकल उल्लंघन है और इसलिए उन्हें आगे और नहीं चलाया जाना चाहिए।
34. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा आंकड़ों का सार्थक संक्षिप्तीकरण या अनुक्रमणीकरण प्रदान किए बिना अतिशय गोपनीयता का दावा किया गया है, इसलिए, हमारे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के संबंध में अपने प्रस्तुतिकरण करना संभव नहीं है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह घरेलू उद्योग से ऐसे आंकड़ों का प्रकटन करने के लिए कहें जो गोपनीय प्रकृति के नहीं हैं अथवा उनका कम से कम सार्थक संक्षिप्तीकरण तो प्रदान करें।
35. शुरुआत में, हम प्रस्तुत करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े भारतीय रक्षोपाय नियमावली और डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अंतर्गत "यथापेक्षित व गंभीर क्षति" की उच्चतर आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।
36. उपर्युक्त बाध्यताओं के आलोक में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदनपत्र के आधार पर भारत में आने वाली संबद्ध वस्तु के आयातों तथा याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में गिरावट के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित

- नहीं होता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि आयातों में वृद्धि होने अथवा कमी होने के प्रभाव के बिना ही याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में सतत गिरावट आई है।
37. यह दावा किया गया है कि वर्ष 2012-13 में आयात 42026 थे जिनमें 30 प्रतिशत होकर वर्ष 2013-14 में 54507 हो गए। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री स्थिर बनी रही अर्थात् यह वर्ष 2012-13 में 13451 थी और वर्ष 2013-14 में 13473 थी। वास्तव में उत्पादन और क्षमता उपयोग भी वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कमोवश रूप से समान ही बना रहा जिससे यह संकेत मिलता है कि आयातों तथा आवेदक द्वारा दावाकृत क्षति के बीच कारणात्मक का अभाव है।
38. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 5(2) (ख) में प्रावधान है कि घरेलू उद्योग से संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसी तरह, रक्षोपाय नियमावली का अनुबंध यह अपेक्षा करता है कि प्राधिकारी संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति का दायित्व आयातों पर उपरोपित नहीं करेंगे।
39. वर्तमान जांच में भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के अलावा कई अन्य ऐसे कारक भी हैं जिससे याचिकाकर्ता को क्षति हो सकती है। उन्हें निम्नवत सूचीबद्ध किया जा सकता है :
- (क) गुणवत्ता संबंधी मुद्दे तथा प्रदाय में असंगति
 - (ख) मांग आपूर्ति अंतराल
 - (ग) घरेलू उद्योग को अवस्थानिक नुकसान – अधिकांश प्रयोक्ता उद्योग उत्तर भारत में स्थित है जब कि घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधा दक्षिण भारत में है।
 - (घ) घरेलू उद्योग उच्च स्तर का क्षमता उपयोग प्राप्त करने में असमर्थ मांग में कमी के कारण नहीं बल्कि आपूर्ति अवरोधों के कारण है। घरेलू उद्योग को नैमित्तिक रूप से कच्चे माल के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके पास प्रोपायलीन आक्साइड जैसी महत्वपूर्ण सामग्री की व्यवस्था करने की अवसंरचना नहीं है।
 - (ङ) आशियान – भारत एफटीए के कारण आयातों में वृद्धि होना।
40. यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुल अहमद टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड बनाम काउंसिल आफ यूरोपियन यूनियन (ओजेसी 331, 12.11.2011) के पैरा 81 में इसी न्यायालय ने काटन टाइप बेडलिनेन के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यूरोपियन कमीशन संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि के संबंध में सामान्यीकृत प्रशुल्क अधिमानों और ईयू में घरेलू उद्योग को उत्तरवर्ती क्षति की स्कीम की जांच करने में असफल रहा था। अन्य कारकों पर विचार करना भी पाटनरोधी प्रावधानों के अंतर्गत विचार करने के समान ही है। अतः, यूरोपियन कमीशन का उपर्युक्त निर्णय इस विशिष्ट मामले में संगत है। इस संबंध में भारत में आशियान देशों के साथ एफटीए एक महत्वपूर्ण कारक है। इस संधि के अंतर्गत वस्तु व्यापार, उद्गम के नियम, निवेश आदि के संबंध में विभिन्न रियायतें दी गई हैं, जिन पर दोनों राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। इस "महत्वपूर्ण" अन्य कारक, जो हो सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा हो, का प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए।
41. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 में प्रावधान है कि इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को युक्तियुक्त सार्वजनिक नोटिस दिया जाना चाहिए और सार्वजनिक सुनवाई अथवा कोई अन्य ऐसी कार्यवाई की जानी चाहिए जिसमें आयातक, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य और अपने विचार प्रस्तुत कर सकें जिनमें अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्रत्युत्तर देने और अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार करने का अवसर शामिल हो कि क्या रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करना जनहित में होगा या नहीं।
42. इसके अतिरिक्त, 25 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का फोम की लागत पर 15 प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रभाव होगा। इन फोम्स का प्रयोग गद्दों, तकिया तथा दिन प्रतिदिन के उपयोग की अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने

के लिए किया जाता है। इस शुल्क को उन आयातकों द्वारा सहन किया जाएगा जिन्हें शुल्क पर ध्यान दिए बिना मजबूरन आयात करना पड़ता है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह भारतीय मांगको पूरा कर सके। इन हालातों में, आयात विनिर्माता को मजबूरन अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ेगी और इसका बोझ अंततोगत्वा अंतिम ग्राहक पर ही पड़ेगा।

43. इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता उद्योग लगभग 50,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और शुल्क का उदग्रहण करने के परिणामस्वरूप मूल्यवर्धित उत्पादों का अधिक आयात होगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उपयोगकर्ता उद्योग उन शुल्कों का बोझ सहन कर रहा है जिनको पिछले 16 वर्षों मनाली द्वारा उपभोग किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान 50 फोम विनिर्माताओं को अपना उद्योग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा।
44. हम दिनांक 26.06.2014 को किए गए हमारे प्रारंभिक प्रस्तुतिकरणों में किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा करने की अनुमति की मांग करते हैं, जिनको यहां संक्षिप्तता के कारण पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है।
45. उपर्युक्त प्रस्तुतिकरणों में किए गए तर्कों के आधार पर हम माननीय महानिदेशक रक्षोपाय से अनुरोध करते हैं कि वह इस कार्यवाही को तत्काल समाप्त कर दें।

(ख) मैसर्स वीतराग फोम प्राइवेट लिमिटेड, निकट साबर डेयरी, गोधोडा तालोड रोड हिम्मत नगर 383001, ने मैसर्स शीला फोम प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्तुतिकरण अपने प्रस्तुतिकरणों के अनुरूप प्रस्तुत किया।

(ग) मैसर्स रायल सिंथेटिक्स ने मैसर्स शीला फोम प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तुतिकरणों को ही, अपने प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रस्तुत किया।

(घ) मैसर्स स्प्रिंगफील पालीयूरीथीम फोम्स प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- क. मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (डब्ल्यूपीसी संक्षेप में) की फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल का उत्पादन करने की संस्थापित क्षमता संपूर्ण भारत में स्थित विभिन्न पालीयूरीथीम फोम (संक्षेप में पीयूपी) उद्योग के लिए मांग की तुलना में बहुत कम है।
- ख. कीमत औचित्य : एमपीएल अन्य देशों को स्लैबस्टाक पालियोल का निर्यात भी कर रहा है। इसे कस्टम्स के पास उपलब्ध रिकार्डों की प्रतियों से देखा जा सकता है कि वह कीमत जिस पर हम आयात कर रहे हैं उसी कीमत के अनुरूप है जिसपर एमपीएल उसी समयावधि के दौरान निर्यात कर रहा है और यह कि यह कीमतें इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित देशों के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप हैं।
- ग. एमपीएल ने दावा किया है कि स्लैबस्टाक पालियोल के उत्पादन और उसकी बिक्री में कमी आई है। यह नोट किया जाना चाहिए कि एमपीएल की विभिन्न मध्यवर्तियों तथा उन उत्पादों, जिनकी वे पेशकश करते हैं, का विनिर्माण करने के लिए मिलीजुली उत्पादन क्षमता है। इस तरह की मिलीजुली उत्पादन क्षमता का आशय यह होता है कि स्लैबस्टाक पालियोल के उत्पादन में कमी होने का आशय यह होता है कि वे अपनी संस्थापित क्षमता का कम उपयोग कर रहे हैं। इसका सीधा सादा आशय यह है कि वे कुछ अन्य उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं (उदाहरण के लिए डीपीजी)। इसका शून्य उत्पादन के दिनों की संख्या और उसके परिणामस्वरूप एमपीएल द्वारा संयंत्र को बंद किए जाने वाले दिनों की संख्या से आसानी से सत्यापन किया जा सकता है।
- घ. एमपीएल ने आपके कार्यालय को दिए गए आवेदन में यह दावा किया है कि उन्हें घाटा उपगत हो रहा है। यह सही नहीं है। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए प्रकाशित उनके तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखाओं का अध्ययन लाभ दर्शा रहा है और इसने अपने शेयरधारकों को लाभान्वित की घोषणा भी की है।
- ङ. अत्यधिक आदरपूर्वक यह तर्क दिया जाता है कि एमपीएल द्वारा रक्षोपाय शुल्क के लिए दिए गए आवेदनपत्र को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

- च. यह कि फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल की कीमत निर्धारण का निश्चय बाजार की गतिविधियों द्वारा किया जाता है।
- छ. फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक फोम में विनिर्माता के रूप में हम पर पालियोल के आयातों पर अतिरिक्त शुल्क के गैर न्यायोचित उदग्रहण का कोई बोझ नहीं है।

(ड.) मैसर्स डयूरापफ (सिल्वासा) प्राइवेट लिमिटेड, 121/122/123, पिपरिया इंडस्ट्रियल एस्टेट, दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र सिलवासा-396230, द्वारा वापी (पश्चिम रेलवे) ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

1. उपर्युक्त विषय पर और उपर्युक्त संदर्भ में हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, अपने द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद (पालियोल) का एकमात्र उत्पादक है और उसकी कुल संस्थापित और उत्पादन क्षमता इतनी भी नहीं है कि वह पालीईथर पालियोल की कुल भारतीय मांग के 20/25 प्रतिशत को भी पूरा कर सके।
2. इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जा सकता है कि जापान/कोरिया/जर्मनी/सिंगापुर के सभी अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं, जो पालियोल के संभरक हैं, का कीमत स्तर मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के कीमत सतर से सस्ता है। इस कारण से उपभोक्तागण उसका आयात करते हैं। हम उपर्युक्त सामग्री का आयात विनिर्माताओं/निर्यातकों से सीआईएफ आधार पर करते हैं और यदि हम उसकी मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से स्थानीय खरीद करते हैं तो हमें 2 प्रतिशत सीएसटी और परिवहन प्रभार का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।
3. चूंकि मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ही भारत में एकमात्र उत्पादक है जो पालियोल का उत्पादन कर रहा है इसलिए वे व्यक्तिगत ग्राहक को उसकी कीमत निर्धारण और आपूर्ति मात्रा का निर्धारण करने के लिए एकाधिकारवादी आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।
4. इसके अतिरिक्त, पीयू फोम विनिर्माता के रूप में हम कस्टम्स ड्यूटी, वैट, उत्पाद शुल्क, सीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष शुल्कों का सरकार को भुगतान कर रहे हैं। रक्षोपाय शुल्क की शुरुआत कर देने से इस उत्पाद की हमारी लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी और इसलिए हम यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि स्थानीय रूप से केवल एक विनिर्माता के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार भारत में 80-100 पीयू फोम विनिर्माताओं से भारी मात्रा में राजस्व क्यों खोना चाहती है।
5. हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि कई देशों में न तो शुल्क है अथवा न ही शुल्क की न्यूनतर दर और वे स्थानीय रूप से प्रचलित उच्चतर कीमतों का लाभ ले रहे हैं, इसलिए हम, उनको उच्चतर कीमतें देकर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खो रहे हैं। कृपया यह नोट करें कि इसके बावजूद भी उनकी कीमतें मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की कीमतों से सस्ती हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया, आपकी उपर्युक्त अधिसूचना में यथा उल्लिखित पालीईथर पालियोल पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का विचार न करें।

(च) मैसर्स एलाइड फोम प्राइवेट लिमिटेड, डी-32, महेन्द्र एन्क्लेव, दिल्ली-110033 ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

1. आवेदक इस तथ्य के प्रति अच्छी तरह से जागरूक था कि एक अन्य विनिर्माता अर्थात् एक्सपैंडेड पालिमर सिस्टम्स भी मौजूद है। मनाली के एमडी और एक्सपैंडेड के एमडी दोनों ही वर्षों से आईपीयूएस के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। इसलिए वे यह दावा कैसे कर सकते हैं कि उन्हें उनकी मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है।
2. इसी तरह वे आयात आंकड़े, जिनपर उन्होंने भरोसा किया है, भी सही नहीं हैं, जैसा कि शीला फोम के अटार्नी ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उल्लेख किया है। सही आयात आंकड़ों के अभाव में कोई भी रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।
3. आवेदक की उत्पादन क्षमता पिछले 27 वर्षों से लगभग वही बनी हुई है और यह 15,000 मीट्रिक टन वार्षिक के आसपास है।

4. मनाली और यूबी दोनों ने अपने पालियोल संयंत्रों की स्थापना 7500 टन की उत्पादन क्षमता के साथ वर्ष 1987 में की थी।
5. उस समय पालियोल पर आयात शुल्क 100 प्रतिशत था।
6. कुछ वर्षों बाद मनाली ने यूबी को खरीद लिया इसलिए उसकी क्षमता बढ़कर 15,000 टन हो गई।
7. श्री मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने के पश्चात उन्होंने नब्बे के दशक में शुल्क में कमी करना प्रारंभ कर दी। पालियोल पर शुल्क घटता रहा है और नब्बे के दशक से ही मनाली रक्षोपाय शुल्क या पाटनरोधी शुल्क के लिए सरकार समक्ष दस्तक देती रही है और वे एक न एक शुल्क अधिरोपित कराने सफल भी रहे हैं।
8. पिछले पांच वर्षों से उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनका उत्पादन 15,000 टन है।
9. उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मनाली के उत्पादन में 1987 से लेकर वर्ष 2009 तक कोई वृद्धि नहीं हुई। यह केवल उनके अनुसार है।
10. अब वे यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाकर 25,000 टन कर ली है, जैसाकि आपको दिए गए आवेदक में उल्लेख किया गया है।
11. उनके प्रस्तुतिकरण की कार्यवाही के दौरान उनके प्रतिनिधि ने दावा किया कि उनकी उत्पादन क्षमता 50,000 टन प्रति वर्ष है। वे यहां पर भी एक बार परस्पर विरोधी उल्लेख कर रहे हैं। सच्चाई क्या है।
12. क्या उनकी क्षमता में वास्तव में वृद्धि हुई है। अथवा वे एक निरर्थक तथ्य देने का प्रयास कर रहे हैं।
13. 22 वर्षों से एक कंपनी ने अपना उत्पाद 1 प्रतिशत भी नहीं बढ़ा पाया और अब यकायक वे अपनी उत्पादन क्षमता में 66 से 333 प्रतिशत वृद्धि होने का दावा कर रहे हैं। क्या इसके इस अंकित मूल्य पर भरोसा करना चाहिए।
14. मनाली की यथार्थ एकाधिकारवादिता रही है और उसने विदेश से प्रतिस्पर्धी उत्पाद पर शुल्क अधिक हो जाने पर अपनी उत्पादन क्षमता में किसी भी तरह का विस्तार किए बिना भारी लाभ कमाया है।
15. पिछले तीन वर्षों से, उनके प्रतिस्पर्धी उत्पाद पर शून्य शुल्क होते हुए भी भारत के विभिन्न भागों में कई ऐसे छोटे-छोटे फोम उत्पादक हैं जो प्रतिमाह 5 से 10 टन पालियोल की खपत करते हैं। इन उद्योगों के पास स्थानीय विनिर्माण से खरीद करने या उसका आयात करने, जहां उन्हें अधिक कीमतों का भुगतान करना पड़ता था के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था, इसलिए स्थानीय विनिर्माता की एक निश्चित बाजार थी जिसके लिए वह उत्पादन करने में सक्षम थे।
16. यह कंपनी ठीक कार्य कर रही है और चूंकि उनके तुलनपत्र में समग्र लाभ हो रहा है इसलिए उनका यह दावा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए कि उन्हें अन्य व्यवसाय से लाभ हो रहा है।
17. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उनके आवेदन की उपर्युक्त कुछ विसंगतियों के संबंध में जब उनको बताया गया तो उनके अधिवक्ता ने यह दलील दी कि कोई आवेदनपत्र 100 प्रतिशत सही नहीं हो सकता है।
18. हो सकता है कि वे 100 प्रतिशत सही न हों परंतु यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वे जानबूझकर भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसे अलग ढंग से लिया जाना चाहिए और उनके आवेदन को केवल इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।
19. पिछले 5 वर्षों में फ्लोक्सिबिल फोम का उत्पादन दोगुना हो गया है और इसलिए पालियोल की मांग 42,000 टन से बढ़कर 84,000 टन लगभग हो गई है।
20. पालियोल का घरेलू उत्पादन अपरिवर्तित बने रहने से फ्लेक्सिबिल फोम के विनिर्माताओं को आयातों का आश्रय लेना पड़ा। इसलिए घरेलू की तुलना में आयात का अनुपात अधिक हो गया।
21. फ्लेक्सिबिल फोम में दो अंकों की वृद्धि होने पर मांग और उपलब्ध स्थानीय आपूर्ति में अंतराल बढ़ जाने से कुल बाजार में उनका हिस्सा कम हो गया क्योंकि उन्होंने कभी अपना उत्पादन बढ़ाने अथवा अपनी गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास नहीं किया।
22. इसके अलावा, दोनों स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम बनी रही।

23. तथ्यात्मक रूप से, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण भी समकक्ष सामग्री पर किया जाना चाहिए और यह कहा जा सकता है कि जो माल हम (स्थानीय विनिर्माता, कुछ व्यापारी) आयात कर रहे हैं उसका दोनों विनिर्माताओं में से किसी भी विनिर्माता द्वारा विनिर्माण नहीं किया जा रहा है। (एक प्राक्कल्पित उदाहरण के रूप में, भारत में चमड़े के जूतों का एक विनिर्माण है और पीवीसी जूतों का विनिर्माता कोई भी नहीं है। तो क्या चमड़े के जूतों का विनिर्माण को पीवीसी के जूतों पर भी रक्षोपाय शुल्क प्राप्त करने का हक होगा या उसे केवल चमड़े के जूतों के लिए रक्षोपाय शुल्क की हकदारी होगी)।
24. जैसाकि मैंने अपने प्रस्तुतिकरण में उल्लेख किया है कि वह विधि जिसके अंतर्गत आवेदक एक स्थानीय विनिर्माता के रूप में संरक्षण की मांग कर रहा है उससे तो सभी स्थानीय विनिर्माताओं को संरक्षण प्राप्त होगा और फ्लेक्सिबिल पीयू के लगभग 100 विनिर्माता हैं और हजारों फर्नीचर और बेडिंग विनिर्माता हैं। यदि पालियोल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो हमारा को नुकसान होगा और केवल दो पालियोल विनिर्माताओं को ही लाभ होगा।
25. मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप ऊपर उद्धृत सभी तथ्यों एवं कारणों पर विचार करें और इस आवेदन को अस्वीकार कर दें तथा हजारों स्थानीय विनिर्माताओं को होने वाली क्षति से बचा लें और इस अनुचित कीमत वृद्धि से करोड़ों भारतीय उपभोक्ताओं की रक्षा करें।

(छ) मैसर्स स्पिंगवेल मैटरेसेस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण किए हैं :

- (क) मनाली द्वारा दिए गए आयात आंकड़ों तथा जांच शुरूआत नोटिस में दिए गए आंकड़ों में भारी अंतर है। इस मुद्दे को सभी पक्षकारों ने अच्छी तरह प्रस्तुत किया है और मनाली ने भी यह स्वीकार किया है कि आयात आंकड़ों के इन दो सेटों में भारी अंतर है इसलिए कोई भी जांच शुरूआत नहीं की जा सकती है।
- (ख) मनाली द्वारा, अन्य विनिर्माता मैसर्स एक्सपेंडेड फोम के पालियोल की मांग में वृद्धि के संबंध में जो आंकड़े/सूचना प्रस्तुत की है उसमें भारी अंतर है।
- (ग) मनाली की उत्पादन क्षमता कम है और वह बाजार की मांग को पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि बाजार की मांग लगभग 84,000 टन है जबकि उसकी संस्थापित/संवर्धित क्षमता केवल 25,000 टन है। मनाली किसी भी पैमाने से मांग की पूर्ति नहीं कर सकता है।
- (घ) मनाली काफी लंबे समय से मौजूद है परंतु वह प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने का अपने को अद्यतन/अपग्रेड नहीं कर सकता।
- (ङ.) कई पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि मनाली को रक्षोपाय/पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि मनाली ने इस लाभ का फायदा वर्षों से उठाया है।
- (च) मनाली को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह स्लैब स्टॉक फोम के विनिर्माताओं, फर्नीचर और बेडिंग विनिर्माताओं तथा उन अन्य छोटे विनिर्माताओं को, जो अपने उत्पाद में पीयू फोम का प्रयोग करते हैं, क्षति कारित करेगा। हम अनुरोध करते हैं कि आप मनाली के इस आवेदन के संबंध में हमारी आपत्तियों पर विचार करेंगे और उसके आवेदन को जनहित में अस्वीकार कर देंगे।

(ज) मैसर्स तिरुपति फोम लिमिटेड

1. जांच शुरूआत के लिए प्रयोग किए गए आयात आंकड़े मनाली पेट्रोकेमिकल्स द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े भिन्न हैं। आपके कार्यालय द्वारा प्रयोग किए गए आंकड़ों में संबद्ध पालियोल के अलावा, अन्य कई प्रकार के पालियोल को भी शामिल किया गया है। कस्टम्स प्रशुल्क शीर्ष 39072010 के समस्त आयात आंकड़ों को 3000-4000 एमडब्ल्यू पालियोल के रूप में माना गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। आयातों के सही आंकड़ों के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि आयातों में कोई उद्रेक हुआ है। इसलिए सही आयात आंकड़े मंगाए जाएं और तब यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि आयातों में कोई उद्रेक है, जिससे मनाली पेट्रोकेमिकल्स को क्षति हो रही है, तभी सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाए।

2. हमें पालियोल का आयात करना पड़ता है क्योंकि मनाली पालियोल की आपूर्ति करने के अयोग्य है। उनकी क्षमता पालियोल के घरेलू मांग के 30 प्रतिशत की भी आपूर्ति पाने की नहीं है।
3. हम मनाली से पालियोल प्राप्त करते हैं जो आयातों की तुलना में, राशनिंग प्रक्रम में, कम गुणवत्ता वाला है।
4. यह स्पष्ट नहीं है कि जब मनाली को भारी लाभ अर्जित हो रहा है और संबद्ध उत्पाद उनका प्रमुख उत्पाद है, जैसाकि उन्होंने वर्ष 2013-14 की बोर्ड रिपोर्ट में उल्लेख किया है, तो उन्हें क्षति कैसे हुई और घाटा कैसे उपगत हुआ।
5. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से हम जैसे छोटे-छोटे विनिर्माताओं, जो आयात करने के लिए मजबूर हैं, को मनाली से पालियोल की अनुपलब्धता के कारण गंभीर क्षति होगी।
6. मनाली इस संरक्षण का रक्षोपाय शुल्क/पाटनरोधी शुल्क के रूप में विगत 16 वर्षों से फायदा उठा रहा है और अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और अपनी क्षमता बढ़ाने की उनकी कोई योजना नहीं है।
7. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और रक्षोपाय शुल्क, जो पूर्णतया गैर न्यायोचित है और जिससे केवल एक बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने से कई छोटी-छोटी यूनिटें बंद हो जाएगी, का अधिरोपण न करें।

घ. घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रत्युक्तियां

(I) घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रत्युक्तियां

1. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि हम, जब तक उनको हमारे द्वारा विशेष रूप से स्वीकार न किया जाए तब तक, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी प्रस्तुतिकरण नकारते हैं। घरेलू उद्योग आवेदनपत्र में किए गए सभी प्रस्तुतिकरणों, टिप्पणियों, लिखित प्रस्तुतिकरणों और अन्य प्रस्तुतिकरणों को पुनः दोहराता हूं और उन पर भरोसा करता हूं। उन प्रस्तुतिकरणों को संक्षिप्तता के कारण पुनः यहां दोहरा नहीं रहा हूं। हितबद्ध पक्षकारों के ऊपर उल्लिखित लिखित प्रस्तुतिकरणों में दिया गया कोई तथ्य या प्रकथन, जिसे एतदपश्चात विशेष रूप से स्वीकार नहीं किया है, यह माना जाए कि उसे विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।
2. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी निदेशालय का आश्रय पहले से ले रखा है और इसलिए वर्तमान रक्षोपाय जांच की कोई जरूरत नहीं है। सिंगापुर के बड़े-बड़े निर्यातकों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि चूंकि संबद्ध वस्तु के आयातों में से 98 प्रतिशत का उदभवन सिंगापुर में होता है, इसलिए सभी देशों के विरुद्ध रक्षोपाय शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विरोधकर्ता पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों में विधि या तथ्यों के आधार पर कोई गुण नहीं है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो दो भिन्न व्यापार उपचारी उपायों के लिए एक साथ जांच की मनाही करता हो। इसके अतिरिक्त, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क दोनों साथ-साथ लगाए गए।
3. इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय महानिदेशक ने इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के मामले में सीमाशुल्क प्रशुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली 2002 के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी। साथ ही, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा केवल चीन के विरुद्ध पाटनरोधी जांच भी शुरू की गई थी। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि महानिदेशक को रक्षोपाय जांच नामंजूर कर देनी चाहिए क्योंकि सिंगापुर की खबर तो पाटनरोधी जांच द्वारा ली जाएगी। परंतु उनके इस तर्क में कोई दम नहीं है।
4. उपर्युक्त के अलावा महानिदेशक ने रबड़ रसायनों, कास्टिक सोडा, कार्बन ब्लैक सोडा ऐश आदि के कई मामलों में, पाटनरोधी जांच पहले से ही प्रभावी होते हुए भी, रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया और पाटनरोधी शुल्क के

- साथ-साथ रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण भी किया था। इसलिए यह कहना गलत है कि दोनों शुल्क एक साथ ही लगाए जा सकते हैं और इसलिए उसे नामंजूर कर दिया जाए।
5. महानिदेशक का ध्यान एन 1, 3-डाइमिथायल ब्यूटायल-ए फिनायलीनिडायामाइन (पी एक्स 13, जिसे 6 पीपीडी, वल्कोनाक्स 4020 आदि के रूप में भी जाना जाता है) (फाइल संख्या डी 22011/32/2010 दिनांक 6.6.2011) के मामले में अंतिम जांच परिणाम की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें महानिदेशक ने निःसंदेह रूप से यह रिकार्ड किया था कि विधि द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क पहले से ही अधिरोपित होने पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है।
 6. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि महानिदेशक की यह एक उल्लिखित स्थिति है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल इस आधार पर न करने पर विधिसम्मत या तर्किक रूप से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक समानांतर रक्षोपाय जांच मौजूद है। उपर्युक्त के मद्देनजर, हम डीजी से यह अनुरोध करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को इस विषय पर उपलब्ध न्यायशास्त्र के अनुरूप और रक्षोपाय महानिदेशालय की पिछली परम्परा के अनुरूप नामंजूर कर दें।
 7. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि डीजी ने यह रक्षोपाय जांच इस तथ्य के बावजूद प्रारंभ कर दी कि संबद्ध वस्तु का 98 प्रतिशत का आयात आशियान देशों के एक सदस्य सिंगापुर, जिसके साथ भारत का द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार और भारत-सिंगापुर सीईसीए है, से होता है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क भी दिया गया कि इन करारों का उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना है और कोई भी सिफारिश इस करार के उद्देश्य के विपरीत होगी। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग यह निवेदन करता है कि सैचुरेटेड फैटी अल्कोहलों की अभिनव जांच में डीजी ने एफटीए के मुद्दे का विश्लेषण किया है और वह अधिगम एवं उसका निष्कर्ष इस जांच पर भी अनुप्रयोग्य होगा।
 8. उपर्युक्त की पूर्वधारणा के बिना यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि पाटनरोधी शुल्क एक अलग जांच अवधि पर आधारित होगी, जबकि वर्तमान रक्षोपाय शुल्क अधिक अभिनव अवधि पर आधारित होने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
 9. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि यदि कोई विशिष्ट देश एफटीए के अंतर्गत या किसी अन्य द्विपक्षीय करार के अंतर्गत कवर होता है तब भी माननीय डीजी जांच प्रारंभ कर सकते हैं और शुल्क की सिफारिश कर सकते हैं।
 10. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों में इस बात पर बल दिया है कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचारों का प्रयोग करने का आदी है। एक पूर्वाग्रह सृजित करने के उनके गलत उत्साह से यह मिथ्या उल्लेख किया गया कि घरेलू उद्योग पिछले 16 वर्षों से शुल्क का लाभ प्राप्त कर रहा है। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त अभिकथन गलत है और तथ्यों के विपरीत है। पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इरादतन इस तथ्य को छिपाए रखा कि वर्ष 1998 के पश्चात घरेलू उद्योग ने महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास संवर्धित आयातों के विपरीत पहली बार पहुंच बनाई है और वह भी तब जब आयातों में यकायक भारी उद्रेक हो गया है।
 11. पाटनरोधी शुल्क के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि कतिपय देशों के निर्यातकों के आवेदन पाटन व्यवहार के कारण घरेलू उद्योग को अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए मजबूरन निर्दिष्ट प्राधिकारी की शरण में जाना पड़ा है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी अपने जांच परिणाम विधि की उचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात और समुचित विश्लेषण करने के पश्चात देते हैं। यह एक मिथ्याभासी स्थिति है कि, वे निर्यातक जो पाटन की प्रक्रिया में हैं, वे ही घरेलू उद्योग पर दोषारोपण कर रहे हैं। इसलिए घरेलू उद्योग को दोषी ठहराने के लिए निर्यातकों के प्रयास को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह के यह प्रस्तुत किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने डीजीएडी और डीजी (रक्षोपाय) द्वारा आयोजित की गई विभिन्न जांचों के संबंध में भी सही सूचना प्रदान नहीं की है। यह नोट किया जा सकता है कि अब तक इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में केवल एक रक्षोपाय जांच और दो पाटनरोधी जांच आयोजित की गई हैं।

12. डीजी इस तथ्य की सराहना करेंगे कि घरेलू उद्योग सिंगापुर, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, ताईवान, ईयू और यूएसए से निर्यातकों की पाटन प्रक्रियाओं के कारण सदैव ही प्राप्तकर्ता सिरे पर रहा है। यह ही वह एकमात्र कारण है जिसकी वजह से निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन स्रोतों पर शुल्क की सिफारिश की है। उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग को अपने हितों की रक्षा करने के लिए विधि सम्मत उपलब्ध सभी कार्रवाई करने का अधिकार है।
13. घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंधित मुद्दा गलत है और यह विधि की स्थिति के विरुद्ध है। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग को उपलब्ध सूचना के अनुसार वे एकमात्र ऐसे उत्पादक हैं जिन्होंने इस संबद्ध वस्तु की जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक रूप से उत्पादन किया है। हर हाल में, यह माना जाता है, परंतु स्वीकार नहीं किया जाता है कि इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहे अन्य उत्पादक भी हैं, परंतु मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स ही रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत कुल घरेलू उत्पादन के बड़े भाग का उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी है।
14. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शीला फोम्स के अलावा अन्य सभी आयातक और प्रयोगकर्ता इस तथ्य को मानते हैं कि व्यावहारिक तौर पर आवेदक ही भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।
15. मैसर्स शीला फोम के प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया यह प्रस्तुतिकरण घरेलू उद्योग द्वारा याचिका में और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान दायर किए गए आंकड़ों/प्रस्तुतिकरणों और जांच शुरूआत नोटिस में किए गए आंकड़ों/प्रस्तुतिकरणों के बीच भारी अंतर है। आयात आंकड़ों में अंतर इंगित करते समय प्रतिनिधियों ने इस तथ्य की अनदेखी कर दी कि आयात आंकड़ों के स्रोत अलग-अलग हैं।
16. उपर्युक्त के अतिरिक्त, उन्होंने संस्थापित क्षमता, संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की संख्या, कस्टम्स उप-शीर्षक, भारतीय बाजार में मांग और पाटनरोधी याचिका तथा रक्षोपाय याचिका में लाभ एवं हानि संबंधी आंकड़ों में अंतर का अभिकथन किया है। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैसर्स शीला के विधिक प्रतिनिधि का आधारभूत अभिकथन गलत है कि और बिना किसी विधिक या तार्किक आधार के है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ऐसे मुद्दों और प्रस्तुतिकरणों को उद्धृत करने का प्रयास किया है जो घरेलू उद्योग द्वारा अपने प्रस्तुतिकरणों में या याचिका में, कभी किसी प्रस्तुतिकरण में या सार्वजनिक सुनवाई में नहीं की गई है। ऐसा होते हुए भी, हम उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत कर रहे हैं :

क. संस्थापित क्षमता -घरेलू उद्योग यह सम्पुष्टि करती है कि उनकी पालियोल के लिए समग्र संस्थापित क्षमता 50,000 एमटी है जिसका 100 प्रतिशत प्रयोग संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, रिकार्ड के रूप में घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत का आबंटन संबद्ध वस्तु के लिए कर रखा है।

ख. अध्याय शीर्ष - अध्याय शीर्ष के संबंध में घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि डीजी ने केवल 39072010 कोड का प्रयोग किया है जिसके अंतर्गत संबद्ध वस्तु का तकनीकी रूप से वर्गीकरण किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से, सभी आयात केवल इस कोड के अंतर्गत ही आने चाहिए। तथापि, यह एक ज्ञात तथ्य है कि इस वस्तु की तकनीकी रूप से सही शीर्षक के अलावा अन्य वर्गीकृत शीर्षक भी हैं, विशेषकर तब जब वहां कोई शुल्क निहितार्थ न हो। वर्तमान मामले में यह रिकार्ड की वस्तु है कि संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्षक संख्या 39072090 के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया जा रहा है। महानिदेशक यह समझेंगे कि यदि दोनों ही शीर्षकों पर विचार किया जाता है तो डीजीसीआईएस भी विकास की वही प्रकृति दर्शाएगा जो आवेदक द्वारा प्रयोग किए गए आंकड़ों में दर्शायी गई है। उपर्युक्त के मद्देनजर महानिदेशक को चाहिए कि वह सभी प्रस्तुतिकरणों को नामंजूर कर दें क्योंकि उनमें कोई गुण नहीं है।

- ग. मांग और बाजार हिस्से में भिन्नता के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयात आंकड़ों से जुड़े सभी पैरामीटर अंतर दर्शाएंगे क्योंकि जिन आयात आंकड़ों पर विचार किया गया है उन्हें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया गया है।
- घ. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी और रक्षोपाय जांच के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़े अलग-अलग हैं और उनकी जांच की जानी चाहिए। इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पाटनरोधी जांच तथा रक्षोपाय जांच में प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई क्रिया पद्धति अलग-अलग है, इसलिए आंकड़ों में कुछ अंतर हो सकता है। किसी भी हाल में, रक्षोपाय जांच एक स्वतंत्र जांच है जहां माननीय डीजी अंतिम सिफारिश करने से पहले अपना सत्यापन करेंगे।
17. परिशुद्धता और यथार्थता से संबंधित मुद्दों के संबंध में हमने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2014 के अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में कर दिया है। उनको संक्षिप्तता के कारण यहां दोहराया नहीं जा रहा है। तथापि मैसर्स शीला के प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए मुद्दे में घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरणों में प्रयोग किए गए शब्दों का बिना सोचे समझे और विधि और इस विषय पर उपलब्ध विधि शास्त्र का सम्मान न करते हुए चुनिंदा रूप से चयन किया है। शीला फोम के विधि प्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किए गए और लिखित प्रस्तुतिकरणों के निवर्चन से आश्चर्यचकित और भौचक्के रह गए। घरेलू उद्योग ने पुनः-इस बात पर बल दिया है कि रक्षोपाय का नियम 5(3) केवल यह उल्लेख करता है कि जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ उपलब्ध आंकड़ों से महानिदेशक संतुष्ट होने चाहिए। वर्तमान मामले में इस जांच की शुरुआत का औचित्य बताने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के तर्क में कोई दम नहीं है।
18. घरेलू उद्योग पुनः यह प्रस्तुत करता है कि इस मामले में किसी भी पक्षकार ने यह सुझाव देने के लिए भी कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि जांच की शुरुआत के समय महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास उपलब्ध सूचना जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए "पर्याप्त" नहीं थी। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।
19. हितबद्ध पक्षकारों के तर्क गलत हैं और उन्हें नकार दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि डीजी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार आयात आंकड़ों की साफ्ट प्रति (स्केल फार्मेट में) हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं की जाती है। तथापि, यदि डीजी महसूस करते हैं कि वह सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान कराई जाए तो हमें साफ्ट प्रति देने में कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि अन्य सभी मामलों में भी यहीं प्रक्रिया अपनाई जाए।
20. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रस्तुतिकरणों में आयातों में वृद्धि के संबंध में विस्तृत तर्क दिए हैं। इस संदर्भ में, हमने आयातों में उद्रेक के संबंध में अपने दिनांक 10.10.2014 के प्रस्तुतिकरण में विस्तृत उल्लेख किया है। परंतु संक्षिप्तता के कारण उसे यहां दोहराया नहीं जा रहा है।
21. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि आयात जो वर्ष 2010-11 में 25849 एमटी थे, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 61075 एमटी हो गए, यह तीन वर्षों की अवधि के अंदर 35226 एमटी की बढ़त है। यह आधार वर्ष की तुलना में आयातों में 2.36 गुना वृद्धि या आधार वर्ष से 136 प्रतिशत वृद्धि है। बड़े आदर सहित यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह वृद्धि निश्चय ही बहुत अधिक अचानक तथा किसी अन्य मानदंड की तुलना में बहुत तीव्र है।
22. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि में आयातों में भारी वृद्धि हुई है। आयातों में इस वृद्धि को पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक और पर्याप्त तीव्र है।
23. आयात आंकड़ों की दोहरी गणना के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क गलत हैं और इसलिए उन्हें नकार देना चाहिए। घरेलू उद्योग यह निवेदन करता है कि देश में आयातों की दोहरी गणना नहीं की गई है और जोरदार ढंग से इस प्रस्थापना का खंड करता है कि आयात आंकड़ों वेयरहाउसेस (सीएफएस, आईसीडी) के जरिए होने वाले आयातों की दोहरी गणना की गई है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि

- आयातकों ने अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं परंतु केवल खोखले तर्क दिए हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि हितबद्ध पक्षकारों की इस आशंका को स्वीकार भी कर लिया जाता है तब भी संवर्धित आयातों एवं क्षति के लिए घरेलू उद्योग का मामला बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। उपर्युक्त के मद्देनजर हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों को अस्वीकार कर दें।
24. 9 माह के आयात आंकड़ों का वार्षिकीकरण करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया तर्क गलत है और इसलिए उसे नकार दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई ऐसे मामले हैं जिनमें डीजी ने जांच शुरुआत करते समय इसी सिद्धांत को अपनाया है। तथापि, हम डीजी से अनुरोध करते हैं कि वह राजस्व विभाग के डीजी (सिस्टम्स) या डीजीसीआई एंड एस से आंकड़े मंगा ले और इस विवाद को सुलझा लें।
25. घरेलू उद्योग इस तथ्य को अस्वीकार करता है कि भारत में वर्तमान आयात मांग एवं आपूर्ति में अंतराल होने के कारण आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग 55 प्रतिशत क्षमता से कार्य कर रहा है और उसकी 45 प्रतिशत क्षमता निष्क्रिय पड़ी रहती है। यह नोट करना भी कुल पालियोल क्षमता को संबद्ध वस्तु को आबंटित कर रखा है। यदि जरूरत पड़ी तो घरेलू उद्योग अपनी शेष बची क्षमता 25,000 एमटी को भी मोड़ सकता है। यह विपथन संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए 50,000 एमटी की क्षमता कर सकता है। यह भी सराहनीय है कि घरेलू उद्योग, संबद्ध वस्तु की मांग को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता में सतत वृद्धि कर सकता है।
26. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन (तुलनात्मक रूप से न्यूनतर कीमतों पर) निर्यात करना पड़ा जिसे घरेलू खपत के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की बिक्री किसी भी ग्राहक को करने से मना नहीं किया और इसलिए इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में मांग आपूर्ति अंतराल के तर्क का कोई महत्व नहीं है। किसी भी मामले में, रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य आयातों को अवरुद्ध करना नहीं है बल्कि संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्या का इस उद्देश्य से समाधान करना है कि घरेलू उद्योग उपचारी उपाय कर सकें। यह भी उल्लेख किया जाता है कि डीजीआई के समक्ष ऐसे ही तर्क विगत में भी उठाए गए थे परंतु उन्हें संगत रूप से अस्वीकार कर दिया गया। इस संदर्भ में हम माननीय डीजी के निम्नलिखित निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जिससे समान परिस्थितियों के अंतर्गत विरोधकर्ता पक्षकारों के तर्कों को डीजी ने नामंजूर कर दिया है :
- एन1, 3-डाइमिथायल ब्यूटायल – एन" फिनायलीमीडायमाइन (पीएक्स 13, जिसे 6पीपीडी, वल्कोनाक्स 4020 आदि नामों से भी माना जाता है): अंतिम जांच परिणाम, दिनांक 6.6.2011 ।
27. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य उत्पादक नामशः मैसर्स एक्सपैंडेड पालीयर्स, जिसकी क्षमता इस पीयूसी का लगभग 6080 एमटी उत्पादन करने की है, परंतु संवर्धित आयातों के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा सका। किसी भी रूप में यह किसी भी व्यक्ति का मामला नहीं हो सकता है कि रक्षोपाय शुल्क का आश्रय नहीं लिया जा सकता है जब तक कि घरेलू उद्योग देश में संपूर्ण मांग को पूरा नहीं कर सकता है।
28. क्षति पैरामीटरों के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि हमने अपने आवेदनपत्र में तथा दिनांक 10.10.2014 के हमारे लिखित प्रस्तुतिकरण में विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया है और इसलिए संक्षिप्तता के कारण उसे यहां दोहराया नहीं जा सकता है।
29. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की क्षति हुई तब भी उसे संवर्धित आयातों पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है। यह परिकल्पना करते हुए, परंतु उसे न मानते हुए, कि घरेलू उद्योग का

क्षति "संवर्धित" आयातों के अलावा अन्य कारकों से भी कारित हुई होगी, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस विषय पर पर्याप्त विधि शास्त्र उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि रक्षोपाय जांच का दायरा ऐसी स्थिति तक सीमित नहीं है जहां घरेलू उद्योग को क्षति बढ़ते आयातों के कारण ही हो रही है। इस संदर्भ में डीजी के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है।

30. अपीलीय निकाय ने यूएस – व्हीट ग्ल्युटेन ने निष्कर्ष निकाला कि संवर्धित आयातों का योगदान पर्याप्ततः स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि अपेक्षित "कारणात्मक संबंध" की स्थिति स्पष्ट हो सके परंतु पैनल के इस निष्कर्ष को नामंजूर कर दिया कि गंभीर क्षति केवल संवर्धित आयातों द्वारा की कारित की जानी चाहिए और यह कि संवर्धित आयात इतने अधिक होने चाहिए कि उससे "गंभीर क्षति" कारित हो सके।
31. उपर्युक्त के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि माननीय डीजी को यह निष्कर्ष निकालने और निष्कर्ष निकाले की आवश्यकता है कि आयात घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं और यह उन आधारों में से एक है (न कि एक मात्र आधार है) जो घरेलू उद्योग के निष्पादन के प्रभावित कर रहे हैं। उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति केवल संवर्धित आयातों के कारण हुई है।
32. संवर्धित आयातों और क्षति के बीच परिणामी कारणात्मक संबंधों और क्षति का साक्ष्य दर्शाते हुए विस्तृत सूचना, आंकड़े और प्रस्तुतिकरण निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष किए गए। असाक्ष्यांकित प्रस्तुतिकरणों की पेशकश की गई है जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई ऐसी वास्तविक सूचना एवं साक्ष्य का विरोध किया गया है। स्पष्टतः उन्हें अस्वीकार कर दिए जाने की आवश्यकता है।
33. हितबद्ध पक्षकारों ने कई वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में किए गए प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा किया है और इस दावे के समर्थन में कि वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं है, प्रारंभ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि वार्षिक रिपोर्ट विशिष्ट जांच अवधि से संबंधित नहीं होती हैं। हर हाल में यह अविवादित है कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और उसकी वार्षिक रिपोर्ट सभी उत्पादों के लिए इस समग्र प्रचालनों का प्रतिबिम्बन है। दूसरे शब्दों में, वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के निष्पादन पर पुनर्विलोकन है न कि किसी विशिष्ट उत्पाद जो जांचाधीन उत्पाद हो सकता है के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन हो सकता है। संगत रूप से यह धारित किया गया है कि व्यापार उपचारी उपाय विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन का विश्लेषण है न कि कंपनी के संबंध में समग्र विश्लेषण का। यह अधिगम ठोस विधिक धारणा पर आधारित है कि जांचाधीन वस्तु कंपनी नहीं बल्कि विचाराधीन उत्पाद होता है। इसलिए घरेलू उद्योग के निष्पादन को विधि के प्रावधानों के अंतर्गत केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्णित किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन को नहीं दर्शाती है बल्कि यह कंपनी के समग्र निष्पादन को प्रतिबिम्बित करती है। ऐसा होते हुए भी घरेलू उद्योग विशिष्ट मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित पैराग्राफों में उत्तर दे रहा है :

(i) उत्पादन में अवरोध घरेलू उद्योग

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि घरेलू उद्योग को तमिलनाडु में विद्युत की कमी के मुद्दे के कारण और ग्राही विद्युत संयंत्र के लिए बायोमास ईंधन की कमी के कारण उत्पाद में अवरोध का सामना करना पड़ा होगा। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि उठाए गए मुद्दे गलत हैं और इसलिए उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। यह दावा है कि तमिलनाडु में बिजली की कमी है बहुत ही सामान्यीकृत ढंग से, प्रस्तुत किया गया है और यह समझाने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग के इस कारण से नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि उसके पास विद्युत आपूर्ति के तीन स्रोत थे : नामशः स्व-जनित विद्युत (ग्राही विद्युत संयंत्र), राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत, और डीजल जनरेटर सेट। इससे घरेलू उद्योग को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लोचशीलता मिल गई कि किसी विशिष्ट स्रोत से विद्युत आपूर्ति के अभाव के कारण उत्पादन को क्षति नहीं होनी चाहिए। अतः, हितबद्ध

पक्षकारों का यह प्रस्तुतिकरण कि घरेलू उद्योग के उत्पादन को विद्युत की कमी के कारण क्षति हुई होगी, पूरी तरह से असंगत है और उसे नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

(ii) कच्चे माल की उपलब्धता

प्रोपायलीन आक्साइड की उपलब्धता के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी जरूरतों के लिए पीओ की पर्याप्त आपूर्ति के लिए व्यवस्था कर रखी थी। घरेलू पीओ का उत्पादन इन-हाउस करता है और जब कभी उसकी जरूरत पड़ती है तब उसका आयात भी करता है। उन्होंने ईटीटीएल पर पीओ का भंडारण करने की सुविधा भी कर रखी है जा उन्हें भारी मात्रा में आयात करने और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। उपर्युक्त के आलोक में यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमुख कच्चे माल अर्थात पीओ की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे में कोई दम नहीं है और उसे अस्वीकार कर दिए जाने की जरूरत है।

(iii) आवेदक की अपर्याप्त क्षमता

मनाली क्षेत्र, (जहां घरेलू संयंत्र स्थित है), में क्षमता में बढ़ोतरी करने संबंधी कतिपय प्रतिबंधों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया दावा गलत है और इसलिए उसे नकार दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक की पालियोल की कुल क्षमता 50,000 एमटी है जिसका प्रत्यक्ष प्रयोग संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। अतः, इस तथ्य को देखते हुए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता है और घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर पाटित आयातों का प्रभाव विगत में लगे कतिपय प्रतिबंधों के कारण तनुकृत नहीं हो जाता है। हर हाल में, यद्यपि यह सच होते हुए कि क्षमताओं में वृद्धि करने के संबंध में लगा प्रतिबंध सितम्बर, 2013 से उठा लिया गया है। उपर्युक्त के मुद्देनजर क्षमता से संबंधित मुद्दे को अस्वीकार कर दिए जाने की आवश्यकता है।

34. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र में तथा दिनांक 10.10.2014 को किए गए अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में विस्तृत पुनर्गठन योजना प्रदान की है। उनको संक्षिप्तता के कारण यहां दोहराया नहीं जा रहा है और उन्हें इस प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण का एक भाग माना जाए।
35. उपर्युक्त के अलावा, यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग को समायोजन योजना के संबंध में उठाए गए मुद्दे निराधार हैं और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया है कि समायोजन योजना व्यवहार्य नहीं है और उसमें कौन-कौन सी कमियां हैं जिस से वह योजना अर्थक्षम नहीं रह जाएगी। वे सभी तर्क केवल अभिग्रहणों पर आधारित हैं और यह आकलन घरेलू उद्योग के दावों का खंडन करते हैं इसलिए उन्हें नकार दिया जाना चाहिए।
36. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने उसी समायोजन योजना पर भरोसा किया है जो पिछली रक्षोपाय जांच में दिया गया था और रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात उन्होंने उस योजना को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संदर्भ में, यह निवेदन किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया दोषारोपण गलत है और उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।

- (i) आवेदनक ने उच्चतर गुणवत्ता के लिए सीपीसीएल के साथ कीमत निर्धारण करार किया है। इस करार के कारण अब कीमतें अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों + संपरिवर्तन लागत के आधार पर तय की जाती है।
- (ii) प्रोपायलीन का कीमत निर्धारण जापान के एफओबी मूल्य पर विचार करते हुए आयात बराबरी कीमतों के आधार पर किया गया था।

- (iii) सीपीसीएल संयंत्र बंद होने के मामले में आवेदक ने प्रोपायलीन का प्रापण गेल, एचपीसीएल, विजाग आदि से किया था।
- (iv) वर्ष 1999-2000/2000-01 से पीओ क्षमता उपयोग प्रोपायलीन की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित नहीं हुआ था।
- (v) इसके अतिरिक्त, पीओ की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से आवेदक ने पीओ संयंत्र की कमियों को दूर किया और इस संयंत्र की क्षमता 24,000 एमपीटीए से बढ़ाकर 36,000 एमपीटीए कर दी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने अपनी पीओ संयंत्र को सुप्रवाही बनाने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए हैं और वर्ष 2000 से प्रोपायलीन की उपलब्धता पर कोई अवरोध नहीं है।

37. घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किए जाने के पश्चात भी अपनी ऊर्जा खपत को कम करने का निरंतर प्रयास किया है। यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग अपनी समायोजन योजना के संबंध में गंभीर है और इस समय भी वे अनुसूची के अनुरूप ही कार्य करेंगे। डीजी यह सराहेंगे कि ईटीटीपीएल पर पीओ भंडारण सुविधा को पहले से ही प्रचालनात्मक बना दिया गया है, जिसे समायोजन योजना के एक भाग के रूप में प्रदान किया गया था। घरेलू उद्योग एक बार फिर डीजी से अनुरोध करता है कि वह घरेलू उद्योग के विधिसम्मत हितों की रक्षा करने के लिए यथाशीघ्र रक्षोपाय की संस्तुति करें।
38. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ऐसी कोई अनापेक्षित परिस्थितियां नहीं हैं जिनके कारण आयातों में वृद्धि हुई है और जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है। इस संदर्भ में यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका के अगोपनीय पाठ में उन सभी अनपेक्षित परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनके कारण आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, हमने अपने दिनांक 10.10.2014 के लिखित प्रस्तुतिकरणों में भी अन अपेक्षित परिस्थितियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की है।
39. बिना किसी पूर्वाग्रह के यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि यद्यपि महानिदेशक रक्षोपाय पर भारतीय विधि के अंतर्गत अनापेक्षित परिस्थितियों का विश्लेषण करने का कोई नैतिक दायित्व/अपेक्षा नहीं है तथा हम यह महसूस करते हैं कि जीडी फिर भी "अनापेक्षित विकास" का विश्लेषण करना पसंद करेंगे। हर हाल में, यह नोट किया जा सकता है कि गाट या रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में भी ऐसा कोई दिशानिर्देश या क्रियापद्धति नहीं है जिसका अनापेक्षित विकास का विश्लेषण करते समय अनुसरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रारूप में भी घरेलू उद्योग या घरेलू उत्पादकों के लिए ऐसा कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं है जिसमें यह सूचना फाइल की जा सकती है।
40. घरेलू उद्योग के इस विशिष्ट मामले से पहले भी "अनापेक्षित विकास" के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। यहां अर्जेंटीना फुटवियर मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय का उल्लेख करना संगत होगा जहां यह धारित किया गया कि वाक्यांश "अनापेक्षित विकास" का आशय उस विकास से होता है जो अप्रत्याशित हो। "अनापेक्षित विकास" में यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास जिसके कारण किसी उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत होना प्रारंभ हो गया जिससे घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो "अप्रत्याशित" होना चाहिए। अपीलीय निकाय ने कोरिया डेयरी मामले में यह धारित किया कि अनापेक्षित विकास वह विकास होता है जो सदस्य द्वारा उक्त दायित्व उपगत करते वक्त पहले से ज्ञात या प्रत्याशित न हो।
41. यह उल्लेख किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने तो यह प्रत्याशा कर सका और न ही यह पूर्वानुमान लगा सका कि संबद्ध वस्तु इस तथ्य के बावजूद कि कुल वैश्विक पालियोल क्षमता में सिंगापुर केवल 2.87 प्रतिशत का ही उत्पादन करता है। [(पीयू पत्रिका वाल्यूम II, संख्या 1 – फरवरी/मार्च, 2014 के (अग्रणी

- उत्पादकों 2012-17 द्वारा (पूर्वानुमान)/केटी) वैश्विक पालियोल क्षमता के पृष्ठ 30, तालिका 10 पर दी गई सूचना के आधार पर] केवल सिंगापुर से ही जाएगी। एकमात्र ऐसे स्रोत से, जहां एफटीए कारण शुल्क को कम कर दिया गया था, आयातों में अचानक वृद्धि होना घरेलू उद्योग के लिए अनापेक्षित था या किसी वार्ताकार द्वारा पहले से नहीं देखा जा सकता है।
42. आपूर्ति शृंखला का संकेंद्रण : इस संदर्भ में यह पुनः दोहराया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह प्रत्याशा नहीं की थी कि भारत-आशियान एफटीए और भारत-सिंगापुर सीईसीए के कारण बड़े-बड़े आपूर्तिकर्ता इसका लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष और शायद अवैध व्यवस्था करेंगे। डीजी सह सराहेंगे कि अब इन बड़े आपूर्तिकर्ताओं का बाजार तथा आपूर्ति शृंखला पर नियंत्रण है। यथार्थतः, इस कारण से ही बड़े-बड़े आपूर्तिकर्ता इस एफटीए का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए एकजुट हो गए थे। इसी कारण से आयातों का 98 प्रतिशत आयात सिंगापुर से हुआ जिसकी इस मुक्त बाजार में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस स्रोत से इस माल के आगम की अचानक वृद्धि और वह भी अलाभकर कीमतों पर, होना घरेलू उद्योग के लिए अनापेक्षित है।
43. घरेलू उद्योग यह पूर्वानुमान नहीं कर सका कि संपूर्ण विश्व में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद इस संबद्ध वस्तु की कीमतों में भारी कमी आ जाएगी। कीमत में इस कमी होने के कारण ही भारत में इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक वृद्धि हुई। इसे आयात आंकड़ों से देखा जा सकता है। यह एक संयोग ही है कि घरेलू उद्योग ने जब अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया उसी अवधि में संबद्ध वस्तु की कीमत में अचानक गिरावट हुई और आयात मात्रा में अचानक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तु की कीमत में कमी से ग्राहकों के साथ बेहतर कीमतों के लिए वार्ता करने से घरेलू उद्योग की क्षमता कम हो गई।
44. इसके अतिरिक्त, वह रियायतें, जिन पर सरकार द्वारा चर्चा की जा रही है, उसमें विशिष्ट स्तर की आयात मात्रा प्रचलित कीमत स्तर पर विचार किया जाता है। यदि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनकी वार्ताकारों ने वार्ता के समय प्रत्याशा न की हो तो निश्चय ही वह अनापेक्षित विकास का मामला बनता है। इसके अतिरिक्त, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी सरकार या वार्ताकार इस बात की प्रत्याशा करने में समर्थ नहीं होगा कि एफटीए के पश्चात आयात मुख्यतः केवल एक बड़े स्रोत से ही होंगे। उपर्युक्त घटनाएं अनापेक्षित परिस्थितियां हैं जिनकी प्रत्याशा भारत-आशियान एफटीए और भारत-सिंगापुर सीईसीए के लिए वार्ता करते समय न तो घरेलू उद्योग ने और न ही वार्ताकारों ने की थी।
45. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि वास्तव में कुछ ऐसी अनापेक्षित परिस्थितियां रही हैं जिनकी घरेलू उद्योग प्रत्याशा नहीं कर सका था।
46. यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे केवल अनुमानों पर आधारित हैं और वे अभिनति सृजित करने के लिए उठाए गए हैं। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादों की गुणवत्ता आयातित सामग्री के गुणवत्ता के अनुरूप ही है। इसकी अभिव्यक्ति हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाई गई सामग्री की मात्रा से की जा सकती है और उनके द्वारा उसकी बार-बार खरीद करना हमारी गुणवत्ता का एक सबूत है। इसे अनुबंध-1 में संलग्न किया गया है।
47. उपर्युक्त के अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि फोम का रंग अंतर्निविष्टियों की कैमिस्ट्री पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आयातकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि उन्हें मनाली के उत्पादों के कारण अल्प गुणवत्ता वाला फोम प्राप्त हो रहा है, गलत है और निराधार है। फोम का दर्शाया गया पीला रंग उस अभिक्रिया का परिणाम होता है, जब फोम को कुछ दिनों के लिए खुले में रखा जाता है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि मेटरेसेस के रंग का संबद्ध वस्तु की गुणवत्ता से अधिक भी लेना-देना नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, बिना किसी पूर्वाग्रह के यह एक सुस्थापित तथ्य है कि रक्षोपाय जांच में गुणवत्ता कोई मुद्दा नहीं हो सकता है।

48. **प्रोपायलीन आक्साइड का उत्पादन करने के लिए प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता :** विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रमुख कच्चे माल अर्थात् प्रोपायलीन की इस कारण से उपलब्धता कम थी कि घरेलू उद्योग पीओ की खरीद सीपीसीएल से कर रहा है। यह तथ्य भी सही नहीं है क्योंकि वे गेल, एचपीसीएल, विजाम आदि से भी उसका प्रापण कर रहे हैं। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर इस तर्क में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
49. **कीमत अधोरदन, अवमंदन और निग्रहण :** हितबद्ध पक्षकारों ने कीमत अधोरदन अवमंदन और निग्रहण के संबंध में विरोधाभाषी वक्तव्य दिए हैं। एक ओर तो वह यह आरोप लगा रहे हैं कि कोई कीमत अधोरदन, अवमंदन या निग्रहण नहीं हुआ है और दूसरी ओर वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि आयातित सामग्री अधिक सस्ती है और इसी कारण वे उसका अधिप्रापण कर रहे हैं। इयूरा पफ (सिलवासा) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण का पृष्ठ 1)। इन सभी तथ्यों के आलोक में हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों को अस्वीकार कर दें। हर हाल में उपर्युक्त पैरामीटरों के संबंध में उनके द्वारा दिए गए तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं, जैसाकि डीजी द्वारा रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से देखा जा सकता है।
50. **घरेलू उद्योग की क्षमता :** घरेलू उद्योग यह निवेदन करता है उनकी क्षमताओं के संबंध में कोई परस्पर विरोध नहीं है। यह सत्यापन करने योग्य तथ्य है कि घरेलू उद्योग की संस्थापित पालियोल क्षमता 50,000 एमटी है। इस क्षमता का उल्लेख आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया है। तथापि, आयातों के अविराम दबाव पर विचार करते हुए केवल 25,000 एमटी क्षमता का ही उपयोग कर रहा है। सुनवाई के समय तथा लिखित प्रस्तुतिकरणों में किए गए उल्लेख के अनुसार घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और उनके प्रस्तुतिकरणों में जांच के किसी भी स्तर पर कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उड़ाए गए मुद्दों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
51. **स्थान का नुकसान –** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए यह स्थित होने के कारण लाभ नहीं हो रहा है और अधिकांश फोम विनिर्माता उत्तर भारत में स्थित हैं, गलत है और उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। फोम विनिर्माता देश के सभी भागों में स्थित है।
52. **अतिशय गोपनीयता :** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अतिशय गोपनीयता के संबंध में किए गए दावे गलत हैं और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने केवल उसी सूचना की गोपनीयता का दावा किया है जो बिजनेस संवेदी है और जिसका खुलासा करने से हमारे प्रतिस्पर्धा को लाभ होगा। इसके विपरीत, निर्यातकों और आयातकों ने तो मात्रा संबंधी सूचना के लिए भी गोपनीयता का दावा किया है। निर्यात शेल, जो कुल आयातों का 90 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, ने तो निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर भी दायर नहीं किया है और वेयर, जो कुल आयातों का 4 प्रतिशत के लगभग आयात करता है, ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों के साथ दायर किया है। उपर्युक्त के मद्देनजर हम डीजी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इन सभी तर्कों को अस्वीकार कर दें और निर्यातकों से कहें कि वे इस विषय पर जारी व्यापार नोटिस में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार प्रश्नावली प्रत्युत्तर के समुचित गोपनीय और अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करें।
53. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कई फोम विनिर्माताओं ने अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं और कोई भी रक्षोपाय शुल्क जनहित में नहीं होगा। इस संदर्भ में यह निवेदन किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने तो साक्ष्य का एक आयोरा भी नहीं दिया है कि देश में कुछ संयंत्र बंद क्यों हो गए। इन तर्कों को तो सिरे से ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह के यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बाजार आसूचना के अनुसार कुछ फोम विनिर्माताओं ने अपने प्रचालन निम्नलिखित तथ्यों के कारण बंद किए हुए हैं :

- क. बड़े-बड़े विनिर्माताओं के साथ, उनके हाथों में बाजार संकेंद्रण हो जाने के कारण, कटु प्रतिस्पर्धा।
 ख. असंगत नकदी प्रवाह और कमजोर वित्तीय प्रबंधन।

- ग. प्रौद्योगिकी उन्नयन का अभाव।
 घ. कर चोरी के मामलों सहित कर विवाद।
 ङ. बड़े-बड़े विनिर्माताओं द्वारा छोटी-छोटी सुविधाओं का अधिग्रहण।
 च. कोयम्बटूर में सुपर फोम और सोनीपत कुंडली में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जैसी कई बड़ी कंपनियों द्वारा नई सुविधाओं की स्थापना।
54. यह भी प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि एक बड़े आयातक मैसर्स शीला फोम ने कर लाभ प्राप्त करने के लिए पांडिचेरी स्थित अपनी सुविधाओं का विस्तार किया है परंतु जब कर प्रोत्साहन मिलना बंद हो गए तो इसे बंद कर दिया।
55. उपर्युक्त के मद्देनजर यह प्रस्तुत किया जाता है कि फोम के विनिर्माताओं द्वारा अपने संयंत्र को बंद कर दिए जाने के मामले को पालियोल के मुद्दे पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है। इसलिए दुराशय के इरादे से उठाए गए मुद्दों को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।
56. घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री संपूर्ण भारत में बड़े कारपोरेट घरानों से लेकर छोटे-छोटे फोम विनिर्माताओं और व्यापारियों को भी कर रहा है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि कुछ बड़े आयातकों, जो भारी मात्रा में स्वयं आयात कर रहे हैं, के अलावा किसी भी अन्य उपयोगकर्ता उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण किए जाने का विरोध नहीं किया है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से न केवल घरेलू उद्योग को विधिसम्मत हितों की रक्षा होगी बल्कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना निम्नलिखित कारणों से जनहित में होगा। जनहित रक्षोपाय साधनों के प्रभाव का अध्ययन सामान्यतः तीन विभिन्न पक्षकारों – उत्पादकों, उपभोक्ताओं और आम जनता के परिदृश्य से किया जाता है :
- क. **उत्पादकों का हित** : संबद्ध वस्तु के आयातों पर रक्षोपाय वस्तु के घरेलू उद्योग के हित में होगा। इस साधन से और अधिक होने वाली क्षति कम होगी और इससे उसे अपनी क्षमता का उपयोग करने का समय मिलेगा जिसका उपयोग करने का अवसर उसे संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिए जाने के कारण प्राप्त नहीं हुआ।
- ख. **उपभोक्ताओं का हित** : यदि घरेलू उद्योग विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाती है तो यह संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं के हित में होगा। यह तभी संभव है जब घरेलू उद्योग आयातों में होने वाली अचानक वृद्धि से हुई क्षति से अपने को उबार सके। यदि वर्तमान स्थिति को ही बने रहने दिया जाता है तो भारतीय घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी तथा विदेशी उत्पादकों को घरेलू उत्पादकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, यदि घरेलू उद्योग को नुकसान सहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो यह समाप्त हो जाएगी और उपभोक्ताओं को आयातों की दया पर छोड़ दिया जाएगा और उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :
- उच्च मालसूची लागत
 - विनिमय का उतार-चढ़ाव
 - सुपुर्दगी का समय
 - तकनीकी सहायता
- ग. **अंततः जनहित** : सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी भारतीय घरेलू उद्योग होना अंततः जनहित में है। परंतु यदि संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को बरकरार रखने दिया जाता है तब यह किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। इसे अतिरिक्त, शुल्क का जनता पर नगण्य प्रभाव होगा। इसे अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

| | | |
|-----------------------------------|------------|------|
| औसत मेट्रेस की खुदरा कीमत (जोड़ा) | रुपए/जोड़ा | 6500 |
|-----------------------------------|------------|------|

| | | |
|--|----------------|------|
| मैटरेस की लागत (जोड़ा) (फोम की लागत 3000 रुपए/किलोग्राम + फेब्रिक की लागत 700 रुपए (जोड़ा) | रुपए/जोड़ा | 3100 |
| लाभ-हानि | रुपए/जोड़ा | 3400 |
| लाभ और हानि (कीमत के प्रतिशत के रूप में) | % | 52% |
| प्रति जोड़ा मैटरेस का भार | किलोग्राम | 8 |
| एफएसपी | रुपए/किलोग्राम | 140 |
| मैटरेस में एफएसपी का भार 40/किलोग्राम की दर से | किलोग्राम | 3.2 |
| मैटरेस की कुल एफएसपी लागत | रुपए/जोड़ा | 448 |
| 25 प्रतिशत के रक्षोपाय शुल्क का अतिरिक्त प्रभाव | रुपए/जोड़ा | 112 |
| 25 प्रतिशत की दर से रक्षोपाय शुल्क का कीमत पर प्रभाव | % | 1.7% |

- घ. उपर्युक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि अंतिम उपभोक्ता पर 25 प्रतिशत की दर से रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा और यह अंतिम उत्पाद का मात्र 1.7% ही बनता है। इसके परिणामस्वरूप, संबद्ध वस्तु का अंतिम उपभोक्ता को कीमत में कोई भारी वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- ङ. लोहा, अलाय या नॉन-अलाय स्टील (ढलवा लोहा और स्टेनलेस स्टील के अलावा) ट्यूब्स, पाइप्स और होला-प्रोफाइल्स, सीमलेस" (फाइल संख्या डी-22011/17/2012 दिनांक 11.3.1024) में अभी हाल में दिए गए निर्णय के संबंध में डीजी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें डीजी ने यह रिकार्ड किया कि यदि उपभोक्ता उद्योग इस शुल्क के प्रभाव को सहन करने की स्थिति में हैं तो इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अधिरोपण जनहित में नहीं है।
- च. यदि इस स्तर पर घरेलू उत्पाद को संरक्षण प्रदान नहीं कराया जाता है तो इस बात का खतरा होगा कि घरेलू उत्पाद लंबे समय तक अपने व्यवसाय को नहीं बनाए रख पाएगा और अन्ततोगत्वा वह अपने प्रचालनों को बंद कर देने का निश्चय कर लेगा जैसाकि एक्सपेंडेड पालिमर्स द्वारा किया गया है। यह बंदी फोम विनिर्माताओं के लिए और भी घातक होगी क्योंकि इससे उनकी सतत एवं भरोसेमंद कच्चे माल की आपूर्ति बंद हो जाएगी और उन्हें पूरी तरह से निर्यातकों की दया पर ही रहना पड़ेगा। अतः, दीर्घावधिक जनहित की रक्षा करना अनिवार्य जो अंततः प्रयोगकर्ता उद्योग के हित में भी होगा।
57. उपर्युक्त प्रस्तुतिकरणों के मद्देनजर, घरेलू उत्पाद यह निवेदन करता है कि :
- संबद्ध वस्तु के आयातों में अभिनव, तीव्र, अचानक और भारी वृद्धि हुई है।
 - संबद्ध वस्तु के संवर्धित आयातों ने घरेलू उत्पाद को भारी क्षति कारित की है अथवा भारी क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है।
 - संवर्धित आयातों तथा बाजार विकृति अथवा बाजार विकृति की चुनौती के बीच एक कारणात्मक संबंध है।
 - उपर्युक्त के मद्देनजर घरेलू उत्पाद यह निवेदन करता है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) यथाशीघ्र समुचित शुल्क की सिफारिश करे जिससे कि बढ़ते आयातों द्वारा घरेलू उत्पाद के समक्ष उपस्थित हो रही समस्याओं का प्रशमन किया जा सके।

II. निर्यातकों द्वारा की गई प्रत्युक्ति

(1). डीसीआईपीएल और डाव यूरोप

1. यह प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण 25 जुलाई, 2014 को दायर किए गए प्रारंभिक प्रस्तुतिकरणों और 29 सितम्बर, 2014 को किए गए पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरणों तथा 10 अक्टूबर, 2014 को दायर किए गए सुनवाई पश्चात लिखित प्रस्तुतिकरणों के अलावा हैं। डीसीआईपीएल डाव यूरोप उपर्युक्त प्रस्तुतिकरणों का उल्लेख करता है और उन्हीं पर भरोसा करता है और उनको संक्षिप्तता के मद्देनजर यहां दोहराया नहीं जा रहा है।
2. इसे अतिरिक्त, डीसीआईपीएल और डाव यूरोप घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित सीमित प्रत्युक्तियां दायर कर रहा है।
3. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि एक्सपैंडेड पालीमर्स ने जांच की अवधि के दौरान केवल 6 एमटी का उत्पादन किया, गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक्सपैंडेड पालीमर ने दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के समय यह सूचना दी थी कि उन्होंने वर्ष 2012-13 में 800 एमटी का उत्पादन किया था और वर्ष 2013-14 में 6 एमटी का उत्पादन किया था। इसलिए, घरेलू उद्योग यह दावा नहीं कर सकता है कि जांच की अवधि के दौरान वे संबद्ध वस्तु के एकल उत्पादक हैं।
4. घरेलू उद्योग द्वारा लिखित प्रस्तुतिकरणों में प्रस्तुत किए गए आंकड़े महानिदेशालय रक्षोपाय द्वारा जांच शुरुआत नोटिस में दिए गए आंकड़ों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों एवं तथ्यों का कड़ाई से सत्यापन एवं संवीक्षा की जानी चाहिए। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का उद्देश्य आयातों में वृद्धि दर्शाना है जबकि जांच शुरुआत नोटिस में दर्शाए गए आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के आयातों में इतनी अधिक वृद्धि प्रदर्शित नहीं करते हैं जिससे कि संबद्ध वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना आवश्यक हो जाए।
5. पैराग्राफ 39 में किए गए प्रस्ताव के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा करना न केवल वांछित है बल्कि घरेलू उद्योग की सही-सही और वास्तविक वित्तीय स्थिति को जानने के लिए आवश्यक भी है और ऐसा इस मामले में तो और भी अधिक है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में वर्षों के संबंध में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा करना वांछित है क्योंकि यह ही वह दस्तावेज है जो घरेलू उद्योग की वास्तविक को दर्शाता है। यदि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित सूचना असंगत है तो रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की मांग करते हुए घरेलू उद्योग को अपने द्वारा दायर आवेदनपत्र के एक भाग के रूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
6. यथा अभिव्यक्त पैराग्राफ 39(i) में विद्युत के 3 स्रोतों का उल्लेख किया गया है, यह प्रस्तुत किया गया है कि बायोमास ईंधन लकड़ी की अनुपलब्धता के कारण कारगर नहीं है और डीजल विद्युत पर निर्भरता भी बहुत मंहगी है जो विद्युत के इन स्रोतों का लागत प्रभावी बनाती है।
7. जांच शुरुआत अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता 25,000 एमटी है और अब घरेलू उद्योग का कहना है कि पोलियोल के लिए 50,000 एमटी की क्षमता का उपयोग संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि 50,000 एमटी संपूर्ण पालियोल सेगमेंट के लिए समग्र क्षमता है और घरेलू उद्योग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्वीकार किए गए अनुसार घरेलू उद्योग का मुख्य ध्यान उच्च मार्जिन वाले उत्पादों पर होगा और उसकी रुचि उच्च मालिक्यूलर भार के उत्पादों का उत्पादन करने की है, न कि एफएससी का उत्पादन करने की। इसे डाव द्वारा अपने पिछले प्रत्युत्तरों में पहले ही साक्षात्कृत किया जा चुका है कि कैसे घरेलू उद्योग का पालियोल से राजस्व जांच की अवधि के दौरान निरंतर बढ़ा है।
8. घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि उसके पास प्रोपायलीन आक्साइड (पीओ) की पर्याप्त आपूर्ति है और यह कि इसने ईटीटीएल पर पीओ का भंडारण करने की सुविधा बना रखी है जिससे उन्हें भारी मात्रा में

- आयात करने की अनुमति मिल जाती है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग यह स्वीकार करने में असफल रहता है कि पीओ की यह सुविधा वर्ष 2013 के अंत तक पीओ की भारी मात्रा प्राप्त करने के लिए तैयार हो पाई थी और उस समय तक घरेलू उद्योग पीओ का उच्चतर मात्रा में आयात टैंकों में करने के लिए बाध्य था जिससे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत उप-इष्टतम बन जाती थी।
9. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने कहीं भी यह करार प्रदान नहीं कराया है कि उन्होंने पीओ, जोड़ इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रमुख कच्चा माल है, का आयात करने के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने से पहले अपनी पालियोल क्षमता का विस्तार क्यों किया था। एक बार पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान पीओ का आयात घरेलू उद्योग की इस अक्षमता के कारण ही हुआ जबकि पालियोल के लिए उसने अपनी क्षमता में वृद्धि की जो न्यूनतर क्षमता उपयोग के लिए एक प्रमुख कारक है। तदनुसार, हम विद्वान महानिदेशक रक्षोपाय से यह अनुरोध करते हैं कि इस पहलू की जांच की जाए।
 10. पिछले प्रस्तुतिकरणों और ऊपर उल्लिखित सभी प्रस्तुतिकरणों के आलोक में एक बार पुनः यह दोहराया जाता है कि रक्षोपाय का अधिरोपण करने का कोई मामला नहीं बनता है और विद्वान महानिदेशक रक्षोपाय इस जांच को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दें। इसके अलावा भी, घरेलू उद्योग का यह मामला आंकड़ों की अयथार्थता निग्रहण, प्रमुख आंकड़ों और अनिवार्य सूचना की तोड़-मरोड़ के कारण भी अस्वीकार करने के योग्य है।

2. बेयर एंड शेल द्वारा की गई प्रत्युक्ति

- (क) आवेदक द्वारा दायर किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों का प्रतिवादियों द्वारा किया गया विस्तृत पैरावार प्रस्तुतिकरण :
आवेदक द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरणों के पैरा 1 की अंतर्वस्तु (जिसे एतदपश्चात् लिखित प्रस्तुतिकरण कहा गया है) तथ्यात्मक है और उसका खंड किए जाने की जरूरत नहीं है।
- (ख) लिखित प्रस्तुतिकरणों के पैरा 2-3 की अंतर्वस्तु के संदर्भ में प्रतिवादीगण आवेदक के आधार पर मुद्दों के संबंध में सभी पिछले प्रस्तुतिकरणों को दोहराते हैं।
- (ग) लिखित प्रस्तुतिकरणों के पैरा 4-9 की अंतर्वस्तु को अस्वीकृत डीजीएसजी द्वारा विहित समय-सीमा का उल्लेख किया और उन्होंने जांच शुरूआत अधिसूचना जारी होने के 40 दिनों के अंदर सभी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दीं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगणों ने आवेदक द्वारा दायर की गई याचिका में कई अयथार्थताओं का भी विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया है जिसे यहां संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं जा रहा है। यह नोट करना भी दिलचस्प है कि आवेदक ने पैरा 6 में यह उल्लेख किया है कि वह "पाटित" वस्तुओं के संरक्षण की मांग कर रहा है। प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि यदि आवेदक पाटित वस्तुओं से संरक्षण की मांग कर रहा है तो सही मंच पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय है और इसलिए वर्तमान जांच को समाप्त कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण यह स्पष्ट करते हैं कि कई पत्रों और दिनांक 16 जून, 2014, 23 जून, 2014 और 25 सितम्बर, 2014 तथा 10 अक्टूबर, 2014 के प्रस्तुतिकरणों द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद मांगी गई सूचना और स्पष्टीकरण प्रतिवादीगण को प्रदान नहीं कराए गए हैं।
- (घ) पैरा 10-12 की अंतर्वस्तु के संबंध में प्रतिवादीगण यह तर्क देते हैं कि आयात आंकड़ों को यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है कि इसमें केवल विचारणीय उत्पाद के संबंधित आयात सांख्यिकी ही अंतर्निहित है, न कि इन उत्पादों के किसी अन्य प्रकारान्तर की।
- (ङ) पैरा 13-17 की अंतर्वस्तु को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि वे गलत एवं त्रुटिपूर्ण हैं। प्रतिवादीगण अभिकथित संवर्धित आयातों के मुद्दे के संबंध में किए गए अपने पिछले प्रस्तुतिकरणों को दोहराते हैं और उनके अतिरिक्त निम्नलिखित बिंदुओं पर पुनः जोर देते हैं :

1. याचिका में किए गए सभी दावों का समुचित विश्लेषण करने के लिए यह अनुरोध किया जाता है कि डीजीएसजी या आवेदक हितबद्ध पक्षकारों को लेनदेन संव्यवहार-वार आयात आंकड़े तथा वर्गीकृत

किए गए आयात आंकड़े एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए। डीजीएसजी से यह अनुरोध भी किया जाता है कि वह आवेदक को यह स्पष्टीकरण प्रदान कराने का निदेश दें कि उसने अपरिष्कृत आंकड़ों से आंकड़ों की छंटाई किस तरह की है।

2. आयात आंकड़ों का एमएस-एक्सेल रूपांतरण संगत है क्योंकि इसमें दोहरी गणना और आयातों का अनुलिपिकरण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप सिंगापुर से आयात की संवर्धित मात्रा दर्शाई गई है। प्रतिवादीगण यह हाइलाइट करना चाहते हैं कि जब संबद्ध उत्पाद का भारत को आयात किया जाता है तो उनका भंडारण सर्वप्रथम वेयरहाउसिंग प्रविष्टि बिल भरकर कस्टम्स बांडेड वेयरहाउसेस में किया जाता है और फिर एक समयावधि के अंदर गृह खपत के लिए प्रविष्टि बिल भरकर वहां से छोटी-छोटी मात्राओं में हटाया जाता है।
3. एमएस-एक्सेल फारमेट में आंकड़े प्रदान कराए जाने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी न तो डीजीएसजी ने और न ही आवेदक ने उन्हें आंकड़े प्रदान कराए। इसलिए प्रतिवादी ने सीमाशुल्क प्रशुल्क के अध्याय 39 की सीमाशुल्क प्रशुल्क मद 39072010 के आयात आंकड़े इंटरनेशनल बिजनेस इन्फार्मेशन सर्विसेज से उपार्जित किए जिससे कि जांच की अवधि के दौरान आयात का मात्रा का विश्लेषण किया जा सके। संबद्ध वस्तु के आयातों की सही मात्रा का निर्धारण करने के लिए प्रतिवादी द्वारा निम्नलिखित क्रियापद्धति का अनुसरण किया गया है :

- क) इस विचाराधीन उत्पाद का दायरा 3000 से 4000 मालिक्यूलर भार का फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए विभिन्न विनिर्माताओं/निर्यातकों के ब्रैंड नामों के आधार पर प्रतिवादी ने सर्वप्रथम अपरिष्कृत आंकड़ों से फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (किसी भी मालिक्यूलर भार के) के आयातों को अभिज्ञात किया।
- ख) उसके पश्चात अन्य मालिक्यूलर भार (4000 से अधिक और 3000 से कम) के फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल के आयातों का अपवर्जन कर दिया गया।
- ग) तत्पश्चात, दोहरी गणना, जहां कहीं पता चला, के उदाहरणों को आयात सांख्यिकी से हटा दिया गया।
- घ) ऊपर बिंदु क, ख और ग में गिनाए गए प्रयासों का अनुकरण करने के पश्चात 3000 से 4000 मालिक्यूलर भार के फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल के परिशुद्ध आंकड़ों का निर्धारण किया गया।
- ङ) डीजीएसजी द्वारा यह देखा जा सकता है कि यदि सही-सही आयात सांख्यिकी को ध्यान में रखा जाता है तो जांच की अवधि के दौरान आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में आयात मात्रा में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है।

| वर्ष | आयात (एमटी) |
|---------|-------------|
| 2010-11 | 48,485 |
| 2011-12 | 22,133 |
| 2012-13 | 28,223 |
| 2013-14 | 34,727 |
| महा-योग | 133,568 |

4. इस संबंध में आयात आंकड़े का विस्तृत विवरण प्रदर्श 1 के रूप में संलग्न है।
5. प्रतिवादीगण डीजीएसजी से अनुरोध करते हैं कि वह प्रतिवादियों द्वारा किए गए कामकाज की जांच करें और हमें यह बताएं कि उन्हें प्रस्तुत किए गए कामकाज में कोई त्रुटि तो नहीं है।
6. प्रतिवादीगण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित वार्षिकीकृत आंकड़ों का इस आधार पर विरोध करते हैं कि यह आंकड़े अयथार्थ हैं और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह नोट

किया जाता है कि जांच शुरुआत नोटिस में प्रदान कराए गए वार्षिकीकृत आंकड़े बढ़-चढ़ कर दर्शाए गए हैं और वह सही स्थिति नहीं दर्शाते हैं। प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि उनकी जानकारी के अनुसार बीएसएफ के दक्षिणपूर्व एशिया में इस संबद्ध वस्तु की बिक्री करना बंद कर दी है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 की द्वितीय छमाही में कम आयात हुए।

7. जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदक द्वारा दायर याचिका में दी गई आयात मात्रा परस्पर विरोधी है और उसकी डीजीएसजी द्वारा जांच की जानी चाहिए।
8. यदि आयातों में वृद्धि हुई भी है तब भी आवेदक ने गाट 1994 के अनुच्छेद XIX के अंतर्गत अधिदेशित अपेक्षा के अनुरूप किसी अनपेक्षित विकास को या गाट 1994 के अंतर्गत किसी प्रतिबद्धता के प्रभाव को अभिज्ञात नहीं किया है जिसके कारण आयातों में इतनी अधिक वृद्धि हुई। प्रतिवादी अपने पिछले प्रस्तुतिकरणों को पुनः दोहराते हैं कि आयातों के लिए भारत और सिंगापुर के बीच इस समय मौजूद व्यापक आर्थिक भागीदारी करार ("सीईसीए") को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसकी वजह से सिंगापुर से भारत को संबद्ध वस्तु के आयात अधिक आकर्षक हो गए। यह नोट किया जा सकता है कि संबद्ध वस्तु पर आयात शुल्क दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 106/2011 के तहत घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया है।
9. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत-सिंगापुर सीईसीए अनुच्छेद XIX के अंतर्गत अनपेक्षित विकास की जरूरत को संतुष्ट नहीं करता है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क को घटाने की दर का उल्लेख करते हुए समय सारणी जून, 2015 में भारत-सिंगापुर सीईसीए होने के तत्काल पश्चात सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी। इसलिए स्पष्टतः ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इसकी पहले से ही यह प्रत्याशा न कर ली गई हो कि संबद्ध वस्तु पर शुल्क की दरें करार के अंतर्गत की गई वचनबद्धताओं की भारत की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुरूप कभी नहीं कर दी जाएगी। भारत-सिंगापुर सीईसीए के अंतर्गत 0 प्रतिशत शुल्क के कारण आयातों में वृद्धि भी कोई अनपेक्षित विकास या डीएस 415-418 डामिनिकल-रक्षोपाय साधन में पैनल द्वारा धारित किए गए के अनुरूप अनुच्छेद XIX के अनुसार गाट के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को अनपेक्षित विकास के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसमें पैनल ने निष्कर्ष निकाला था कि जिस सीमा तक डामिनिकल गणराज्य द्वारा उठाए गए नैतिक दायित्व क्षेत्रीय मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत था न कि गाट के अंतर्गत, इसलिए अनुच्छेद XIX की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं।

च. पैरा 18-35 तक की विषयवस्तु को गलत एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण नामंजूर किया जाता है। प्रतिवादी ने आवेदक द्वारा कथित तौर पर सहन की जा रही "गंभीर क्षति" के मुद्दे पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया है और इसके अतिरिक्त वह निम्नलिखित तर्क पुनः दोहराते हैं :

- (i) प्रारंभ में, प्रतिवादी यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक द्वारा रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कराने के लिए दायर अपनी याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों और संबद्ध वस्तु के विरुद्ध रक्षोपाय जांच की शुरुआत करते हुए दिनांक 22 मई, 2014 की जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रदान कराए गए आंकड़ों के बीच भारी अंतर है।
- (ii) यह भी नोट किया जा सकता है कि आवेदक ने अपने द्वारा उत्पादित लगभग सभी संबद्ध वस्तु की बिक्री कर दी है। उत्पादन के प्रतिशत के रूप में वह बिक्री 2010-11 में 101 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 99 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में 96 प्रतिशत और वर्ष 2013-14 में 98 प्रतिशत है। यह सिद्ध करता है कि आवेदक को संबद्ध वस्तु की बिक्री करने में कोई समस्या नहीं है, इससे उत्पादन की झूठ साबित हो जाती है।
- (iii) इसके अतिरिक्त, जांच शुरुआत नोटिस में लाभप्रदता से संबंधित अनुक्रमित आंकड़ों को वर्ष 2010-11 में 8100 अनुक्रमित बिंदु, इस वर्ष 2011-12 में तीव्र एवं पर्याप्त वृद्धि होकर 324 अनुक्रमित बिंदु और वर्ष 2012-13 में कमी होकर (331) अनुक्रमित बिंदु तथा जांच की अवधि के दौरान (559) अनुक्रमित बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। इसी तरह, आवेदक द्वारा दायर याचिका में बिक्री कीमत

वर्ष 2010-11 में 100 अनुक्रमित बिंदुओं से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 115 अनुक्रमित बिंदु और वर्ष 2012-13 में घटकर 110 अनुक्रमित बिंदु थी और वर्ष 2013-14 में पुनः बढ़कर 128 अनुक्रमित बिंदु हो गई। बिक्री लागत के संबंध में, यह वर्ष 2010-11 में 100 अनुक्रमित बिंदु से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 120 अनुक्रमित बिंदु तथा, वर्ष 2012-13 में घटकर 102 अनुक्रमित बिंदु और वर्ष 2013-14 में पुनः बढ़कर 124 अनुक्रमित बिंदु हो गई।

- (iv) यह देखा जा सकता है कि जब वर्ष 2011-12 में बिक्री लागत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई और बिक्री कीमत बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई, तब आवेदक का लाभ बढ़कर तीन गुना हो गया। तथापि, वर्ष 2012-13 में जब आवेदक की बिक्री कीमत 4.35 प्रतिशत तक कम हो गई और बिक्री लागत में भी 15 प्रतिशत की कमी आ गई तब आवेदक को अचानक भारी घाटा (331) अनुक्रमित बिंदु हो गया। उपर्युक्त तालिका से लाभप्रदता की प्रवृत्ति यह व्यक्त करती है कि यह आंकड़े संदेहास्पद हैं। यह संभव नहीं है कि बिक्री लागत में वृद्धि होने पर लाभप्रदता में तीन गुनी वृद्धि हो जाए और बिक्री लागत में घटौती हो जाने पर इसमें तेजी से बोझ बढ़ जाए। यह प्रवृत्ति व्यक्त करती है कि हो सकता है कि लाभ से संबंधित आंकड़े परिशुद्ध आंकड़े न हों और उसके आलोक में, प्रतिवादीगण महानिदेशक से यह अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच करें।
- (v) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुल खपत के अनुपात में आवेदक की बिक्री का बाजार हिस्सा वर्ष 2010-11 में 39 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 28 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में 22 प्रतिशत और जांच की अवधि के दौरान 18 प्रतिशत हो गया तथापि, ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार संबद्ध उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित फीडस्टॉक (प्रोपायलीन आक्साइड) के अपर्याप्त रिजर्व के कारण इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में असमर्थ है।
- (vi) इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि आवेदक अपनी 100 प्रतिशत क्षमता से प्रचालन करने में सक्षम होता तो भी वह बाजार की केवल 34 प्रतिशत जरूरत को ही पूरा करने में सक्षम होता क्योंकि इसकी संस्थापित क्षमता केवल 25,000 एमटी की है जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान उसकी कुल मांग 74624 एमटी थी। इसलिए, भारत के उपयोगकर्ताओं को अनिवार्यतः अपनी अपेक्षित मांग का कम से कम 66 प्रतिशत का आयात करना पड़ेगा और यदि वे एकमात्र आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा और यदि वे उन्हें दीर्घावधि आपूर्तिओं को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी संबंधों में निवेश करना पड़ेगा।

छ) पैरा 39-42 तक की अंतर्वस्तु को त्रुटिपूर्ण और गलत के रूप में अस्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण संबद्ध वस्तु के आयातों तथा आवेदक द्वारा सहन की गई अभिकथित गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों को स्थापित करने के लिए किए गए अपने सभी पिछले प्रस्तुतिकरणों को पुनः दोहराते हैं। उपर्युक्त के अलावा प्रतिवादीगण निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण पुनः करते हैं।

- (i) आवेदक ने पैरा 39 में यह उल्लेख किया है कि संबद्ध वस्तु उत्पादन करने की आवेदक की अक्षमता को सामान्यीकृत ढंग से बिना किसी सबूत के बताया गया है। प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि उसके द्वारा किए गए विगत प्रस्तुतिकरणों में आवेदक की अपनी वार्षिक रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है और आवेदक इसे एक अपर्याप्त साक्ष्य के रूप में नहीं मान सकते हैं।
- (ii) इसके अतिरिक्त, आवेदक ने पैरा 39 में कतिपय दावे किए हैं कि उसने पीओ का आयात करने और अन्यथा पीओ का उत्पादन करने के लिए करार किए हैं। प्रतिवादीगण इस स्थिति और आवेदक द्वारा पहले से ही उल्लेख की जा रही स्थिति में कोई अंतर नहीं पाते हैं। कहीं भी आवेदक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह पीओ का उत्पादन करने के लिए प्रमुख कच्चे माल प्रोपायलीन का अभिग्रहण कैसे करेगा और कैसे आवेदक प्रोपायलीन की वैश्विक आपूर्ति की कमी की समस्या का समाधान करेगा। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने उल्लेख किया है कि उसने पीओ का भंडारण करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। यह नोट किया जाना चाहिए कि यह बल्क भंडारण अभी भी प्रगतिरत होगा और यह अभी भी पूरा नहीं

हुआ होगा। इसे आवेदक ने अपनी याचिका के साथ संलग्न वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 179 पर स्वीकार किया है।

- (iii) आवेदक ने पैरा 39 में यह दावा भी किया है कि मनाली क्षेत्र में लगा प्रतिबंध सितम्बर, 2013 से उठा लिया गया है। प्रतिवादीगण आवेदक से अनुरोध करते हैं कि वह इसे दावे के समर्थन में किसी तरह का साक्ष्य प्रस्तुत करें। किसी भी मामले में, क्षमता में किसी भी तरह की वृद्धि से कच्चे माल के अधिप्रापण के उपर्युक्त मुद्दे के कारण आवेदक द्वारा सहन की जा रही अभिकथित क्षति कम नहीं हो जाएगी।
- (iv) आवेदक ने पैरा 40-41 में यह तर्क दिया है कि यह जरूरी नहीं है कि क्षति के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक आयात ही हों। इस संबंध में प्रतिवादीगण यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक द्वारा उद्धृत किया गया निर्णय केवल इस तथ्य पर ही बल देता है कि आवेदक द्वारा वहन की गई अभिकथित "गंभीर क्षति" और संबद्ध वस्तु के आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध होना चाहिए। हालांकि यह हो सकता है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का मुख्य कारण आयात नहीं हो सकते हैं तथापि यह आवेदक द्वारा वहन की जा रही क्षति का प्रधान कारण हो। वर्तमान जांच में आवेदक द्वारा सहन की गई कोई भी क्षति संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की इसकी अपनी अक्षमता के कारण है, न कि संबद्ध वस्तु का आयात होने के कारण। इससे संबद्ध वस्तु के संवर्धित आयातों और आवेदक द्वारा सहन की गई अभिकथित "गंभीर क्षति" के बीच कारणात्मक संबंध टूट जाता है।
- (v) यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पादन और बिक्री में कमी होने का कारण आयातों की मात्रा नहीं है बल्कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए फीडस्टाक की अनुपलब्धता है। यह नोट किया जाता है कि प्रोपायलीन आक्साइड जो संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फीडस्टाक है की गंभीर कमी है।
- (vi) इसके अतिरिक्त, क्षमता उपयोग में कमी होने का कारण फीडस्टाक प्रोपायलीन आक्साइड (पीओ) की अनुपलब्धता है, जैसाकि ऊपर हाइलाइट किया गया है, इससे क्षमता का अनुपयोग बढ़ता है और क्षमता उपयोग में कमी आ जाती है।
- (vii) यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा ऊपर किए गए प्रस्तुतिकरणों के अनुसार आवेदक फीडस्टाक (पीओ) की पर्याप्त मात्रा का अधिप्रापण न करने और तत्पश्चात संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने और उसकी बिक्री करने की अपनी अक्षमता के कारण अपनी लाभप्रदता प्राप्त नहीं कर सका।
- (viii) तथापि, प्रतिवादीगण द्वारा ऊपर किए गए प्रस्तुतिकरणों से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सहन की गई कोई भी गंभीर क्षति कई अन्य घटकों के कारण भी हुई है जैसे फीडस्टाक उपलब्धता की कमी, उत्पादन और बिक्री में परिणामी कमी, भारत में प्रोपायलीन के एकल आपूर्तिकर्ता, चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड पर निर्भरता; और संबद्ध वस्तु की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति करने की आवेदक की अक्षमता है।

ज) पैरा 43 से 47 तक की अंतर्वस्तु को गलत एवं अयथार्थ होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी ने आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई समायोजन योजना की अव्यवहार्यता के संबंध में किए गए अपने पिछले प्रस्तुतिकरणों को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण आवेदक से अनुरोध करते हैं कि वह अपने इस दावे के समर्थन में प्राइवेट लिमिटेड (ईटीटीपीएल) कोई ठोस साक्ष्य प्रदान करे कि पीओ की भंडारण सुविधा ने एन्नौर टैंक टर्मिनल पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

झ) पैरा 48-53 तक की अंतर्वस्तु को गलत एवं अयथार्थ होने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण आवेदक तथा डीजीएसजी के लिए इस अनिवार्य अपेक्षा के संबंध में कि वह अनपेक्षित विकास तथा गाट 1994 के अंतर्गत नैतिक दायित्वों की पहचान करे और उसका विश्लेषण करे, अपने पिछले सभी प्रस्तुतिकरणों को दोहराते हैं।

ञ) पैरा 54 की अंतर्वस्तु को गलत एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। प्रतिवादीगण ने सभी अपेक्षित सूचन डीजीएसजी को प्रस्तुत कर दी है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जा सकता है कि रक्षोपाय जांच में निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करना अनिवार्य नहीं है। यदि डीजीएसजी को कोई अन्य सूचना चाहिए तो प्रतिवादी उसे प्रदान कराने के लिए तैयार हैं।

ट. पैरा 55-56 की अंतर्वस्तु को गलत एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पैरा 15-16 की अंतर्वस्तु को गलत एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। प्रतिवादियों ने सभी अपेक्षित जानकारी डीजी के समक्ष प्रस्तुत कर दी है और डीजीएसजी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया है। यदि महानिदेशक रक्षोपाय को कोई अन्य सूचना चाहिए तो प्रतिवादीगण उसे सहर्ष प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा दायर की गई याचिका त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें कई अवांछित गोपनीयता के दावे किए गए हैं।

ठ। प्रतिवादीगण महानिदेशक रक्षोपाय से पुनः अनुरोध किया है कि वह उनके द्वारा किए गए सभी पिछले प्रस्तुतिकरणों को इन प्रस्तुतिकरणों का अभिन्न अंग माने क्योंकि संक्षिप्तता के कारण उनको यहां दोहराया नहीं गया है।

इ. महानिदेशक के जांच परिणाम

1. मैंने, इस मामले के रिकार्डों, घरेलू उद्योग, उपयोक्ताओं/आयातकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा दायर प्रत्युत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों का इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर निराकरण कर दिया गया है।

2. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख में भारत में आयातों पर गैर-विभेदाकारी ढंग से रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का विवरण है। धारा 8ख (1) में किसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रावधान है यदि उक्त वस्तु का भारत को आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया जाए कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।

3. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में जांच को शासित करने वाले ढंग एवं सिद्धांतों का विवरण है।

4. तदनुसार, यह जांच उक्त नियमों के अनुसार आयोजित की गई है और अंतिम जांच परिणाम 35 अधिसूचना के तहत दर्ज कर दिया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद 3000 से 4000 मालिक्यूलर भार का फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल है। यह एक पालीईथर है और कैटालिस्ट्स और एडिटिब्स के साथ अनुक्रिया करने पर पालीयूरीथीन फोम उत्पन्न करता है और इसका प्रयोग अपहोल्स्टरी, मैटरेसेस, तकिया, बोल्सटर्स, परिवहन सीटों और पैकेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है।

6. फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक संख्या 39072010 और 39072090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद 3000 से 4000 मालिक्यूलर भार का फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (एफएसपी) है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

8. इसलिए, 3000 से 4000 मालिक्यूलर भार का घरेलू रूप से उत्पादित फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (एफएसपी) आयातित फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (एफएसपी) से बिल्कुल समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद के दायरे में आता है और घरेलू रूप से उत्पादित फ्लेक्सिबिल पालियोल (एफएसपी) रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 2(ड.) के आशय के अंतर्गत समान वस्तु है (जिसे एतदपश्चात् विचाराधीन उत्पाद कहा गया है)।

ख. घरेलू उद्योग

9. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (6) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है।

"ख "घरेलू उद्योग" का आशय

(i) भारत में समान उत्पाद या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद के समग्र रूप से उत्पादकों; अथवा

(ii) उन उत्पादकों से होता है जिनका समान उत्पाद अथवा भारत में प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद का सामाहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।"

10. यह आवेदनपत्र मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड चेन्नई द्वारा अपने परामर्शदाता मैसर्स एपीजे एसएलजी ला आफिसेस के जरिए भारत में 3000 से 4000 मालिक्यूलर भार के फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (जिसे

एतदपश्चात् पीयूसी कहा गया है) के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कराने के लिए दायर किया गया है ताकि इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों के द्वारा कारित की जा रही गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से रक्षा की जा सके। आवेदक ने दावा किया है कि वह इस विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी देश समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद की निम्नलिखित मात्रा में उत्पादन होना प्रदर्शित करती है :

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| आवेदक | एमटी | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |
| अन्य भारतीय उत्पादक | एमटी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल भारतीय उत्पादन | एमटी | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |
| आवेदक का हिस्सा % | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

11. इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक का इस विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक होने के विरुद्ध दावा किया है। उन्होंने इस विचाराधीन उत्पाद के एक अन्य विनिर्माता मैसर्स एक्सपैंडेड पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिया है। मैसर्स शीला फोम्स ने मैसर्स एक्सपैंडेड पालीमर्स द्वारा वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान बेची गई 80 एमटी विचाराधीन उत्पाद का विवरण भी प्रदान कराया है। तदनुसार, उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से सूचना मांगी गई जिन्होंने इस पीयूसी के संबंध में उत्पादन क्लियरेंस आंकड़े प्रदान कराए। इन आंकड़ों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि मैसर्स एक्सपैंडेड पालीमर्स केवल नगण्य मात्रा में ही इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहा है। क्षेत्राधिकार वाले उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से घरेलू उद्योग के संबंध में प्राप्त सूचना का आकलन करने से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं :

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| आवेदक | एमटी | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |
| अन्य भारतीय उत्पादक | एमटी | 533 | 2011 | 405 | 258 |
| कुल भारतीय उत्पादन | एमटी | 17043 | 20392 | 14391 | 14069 |
| आवेदक का हिस्सा % | | 96.87 % | 90.14 % | 97.18 % | 98.16 % |

इस प्रकार, यह धारित किया जाता है कि यह आवेदक सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (6) (ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं।

ग. जांच की अवधि (पीओआई)

12. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997, रक्षोपाय करार और GATT का संगत अनुच्छेद XIX में विशेष रूप से यह परिभाषित नहीं किया गया है कि जांच की अवधि क्या होनी चाहिए। रक्षोपाय साधनों संबंधी विभिन्न मामला विधियों से यह स्पष्ट है कि न तो घरेलू रक्षोपाय विधि और न ही रक्षोपाय करार तथा GATT के अनुच्छेद XIX में जांच की अवधि के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देशों का इस तथ्य के सिवाय कोई प्रावधान है कि जांच की संगत अवधि पर्याप्ततः दीर्घ होनी चाहिए जिससे कि संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके।

13. वर्तमान मामले में आवेदक ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के आयात एवं क्षति आंकड़ों का विवरण प्रस्तुत किया है। इस निदेशालय ने वर्ष 2010-11 से प्रारंभ करके वर्ष 2013-14 तक के क्षति पैरामीटरों से संबंधित आंकड़ों का यथासंभव सीमा तक सत्यापन किया है और वर्ष 2010-11 से 2013-14 (दिसम्बर, 2013 तक) तक के आयात एवं क्षति आंकड़ों को नियमित करते हुए दिनांक 22.5.2014 को जांच शुरूआत नोटिस जारी किया गया है।

14. तदनुपरांत, आवेदक ने जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 तक की अवधि के आयात आंकड़े प्रस्तुत किए। इन 3 महीनों की अतिरिक्त सूचना सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराई गई तथा रक्षोपाय नियमावली, 1997 के नियम 6(7) के अंतर्गत यथापेक्षित सार्वजनिक फाइल में रखी गई।

15. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चयन की गई अवधि पर्याप्ततः लंबी होनी चाहिए जिससे संवर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकें और सीजनल अंतर के प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सके, वित्त वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के आंकड़ों पर विचार किया गया है। जांच शुरूआत नोटिस में दिसम्बर, 2013 तक के आयात आंकड़ों पर विचार किया गया है। अब इन आयात आंकड़ों को मार्च, 2014 तक के लिए अद्यतन कर दिया गया है। इस जांच के प्रयोजनार्थ वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013 तक की अवधि को लिया गया है। याचिका/नोटिस में दिसम्बर 2013 तक की अवधि के आंकड़ों को उल्लिखित किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अप्रैल-दिसम्बर, 2011 तक के आंकड़ों का वार्षिकीकरण करना उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं मार्च, 2014 तक की अवधि के आंकड़ों को प्रयोग करना उपयुक्त एवं आवश्यक समझता हूँ।

घ. आंकड़ों का स्रोत

16. वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक के आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से लिए गए हैं। यह आंकड़े जांच शुरूआत नोटिस में दिए गए आंकड़ों के अनुरूप हैं। आयात आंकड़ों की परिशुद्धता के संबंध में एक आपत्ति इस आधार पर उठाई गई कि इस प्रशुल्क शीर्षक में 3000-4000 मालिक्यूलर भार की पीयूसी के अलावा अन्य विनिर्देशनों के विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख है और यह कि इन आंकड़ों में कतिपय आयातों की दोहरी प्रविष्टि के आंकड़े भी शामिल हैं। मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड, मैसर्स शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लिमिटेड और मैसर्स बेयर (दक्षिण पूर्व एशिया) पीटीई लिमिटेड (दोनों का प्रतिनिधित्व मैसर्स लक्ष्मी कुमारन एवं श्रीधरन, एडवोकेट्स किया गया) ने लेनदेन संव्यवहार आंकड़ों को आईबीआईएस और आईएससीआईसीए से प्रदान कराया है और आयात आंकड़ों की दोहरी प्रविष्टि की संख्या का विवरण भी उपलब्ध कराया है। तदनुसार, आयात आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए लेनदेन संव्यवहारवार आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए। घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों ने इस विचाराधीन उत्पाद के परिशुद्ध आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए लेनदेन संव्यवहारवार आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए इस विचाराधीन उत्पाद के ब्रैंड नाम भी प्रदान कराए। दोहरी प्रविष्टियों के लिए लेनदेन संव्यवहारवार आंकड़ों की भी जांच की गई। घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में वर्ष 2013-14 तक के लिए प्रदान कराए गए विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित आंकड़ों का भी इस निदेशालय द्वारा यथासंभव सीमा तक सत्यापन किया गया है और क्षति विश्लेषण के लिए इन सत्यापित आंकड़ों पर ही विचार किया गया है।

ड. प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता

17. घरेलू उद्योग ने सूचना गोपनीय आधार पर प्रदान कराई है और प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता की मांग की है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली, 1997 और दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुरूप रक्षोपाय साधन के लिए आवेदन सहित सभी प्रस्तुतिकरणों का अगोपनीय पाठ प्रदान कराया है।

18. रक्षोपाय नियमावली के नियम 07 और रक्षोपाय पर डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.2 में गोपनीयता का प्रावधान किया गया है। आवेदक से ऐसी सूचना का प्रकटन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो किसी कंपनी की अपनी गोपनीय सूचना है तथा जिसका प्रकटन करना कंपनी के व्यवसाय हितों को गंभीर चोट पहुंचा सकता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और जिसका आवेदक ने विगत में जनता के समक्ष कभी प्रकटन नहीं किया है। तदनुसार घरेलू उद्योग को, मांगी गई गोपनीयता प्रदान कर दी है।

च. संवर्धित आयात

19. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की केंद्रीय सरकार के अधिकारों का उल्लेख करता है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है :

"(1) यदि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है

जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो तो यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है।"

20. इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2(ग) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

"(ग) संवर्धित मात्रा में आयातों में वृद्धि उत्पादन के समग्र या रूप में होना शामिल है।"

21. नियम में यह निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है कि क्या विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में संवर्धित मात्रा में किया जाना रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने की एक पूर्वापेक्षा है अतः, यह निर्धारित करने के लिए संवर्धित शुल्क का अनुप्रयोग करने के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के आयातों में "इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है" कि जिससे नियमों के अंतर्गत इन संवर्धित आयातों की दर एवं मात्रा का विश्लेषण, घरेलू उत्पादों और खपत के संगत रूप में और समग्र रूप में करना आवश्यक हो गया है जैसा कि पैनल द्वारा धारित किया गया है और बाद में जिसकी संपुष्टि अर्जेंटीना फुटवीयर मालमे में भी की गई है।

22. अपने इस मूल्यांकन में कि क्या अर्जेंटिना के प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच अर्जेंटिना फुटवीयर (ईसी) डब्ल्यूटी/डीएस 121/एबी/आर, दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 में अनुच्छेद 2.1 और 4.2(क) के अंतर्गत आयातों में अपेक्षित प्रदर्शित हुई है, अर्जेंटिना फुटवीयर मामले में पैनल ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है :

".....इस करार में आयातों में केवल वृद्धि (अर्थात् कोई वृद्धि) होना ही अपेक्षित नहीं है बल्कि यह वृद्धि "ऐसीमात्रा" में होनी चाहिए जिससे गंभीर क्षति हो सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके। इस करार में किसी संख्यात्मक मार्गदर्शन का प्रावधान नहीं है कि इसका निर्णय कैसे किया जाएगा, और हमारे विचार से ऐसा किया भी नहीं जा सकता है। परंतु इसका आशय यह नहीं है कि यह जरूरत निरर्थक है। इसके विपरीत, हम विश्वास करते हैं कि इसका आशय है कि आयातों में वृद्धि का निर्णय इसके पूर्ण संदर्भ में, खासकर अनुच्छेद 4.2(क) में यथापेक्षित इसकी "दर एवं मात्रा" के संबंध में किया जाना चाहिए। अतः संपूर्ण जांच अवधि, जिसकी ऊपर चर्चा की गई है, के दौरान आयात के स्तर में हुए परिवर्तन पर विचार करते हुए यह निर्धारण करते समय ऐसा अपरिहार्य प्रतीत होता है कि क्या आयातों में यह वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के आशय के अनुरूप "ऐसी मात्रा में" हुई है। (बल दिया गया)।

23. आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में, पैनल के विपरीत अर्जेंटिना फुटवीयर ईसी में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया है कि आयातों में यह वृद्धि अभिनव, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक होनी चाहिए कि उससे गंभीर क्षति कारित हो सके या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न हो सके। संगत उद्धरण निम्नलिखित है :

"131. यह निर्धारण, कि क्या आयातों "में इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि" की अपेक्षा पूरी होती है या नहीं केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी जांच में साधारण रूप से यह दर्शाना ही पर्याप्त नहीं है कि इस उत्पाद के इस वर्ष किए गए आयात पिछले वर्ष -----या पांच वर्ष पहले हुए आयातों की तुलना में अधिक हैं। पुनः, ऐसा पुनरावृत्तिक लगता है कि, आयातों में किसी निश्चित मात्रा में वृद्धि होना ही पर्याप्त नहीं होगा। यह वृद्धि इतनी अधिक मात्रा में हो कि उससे, रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने के लिए यह अपेक्षा पूरी होती हो, घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति कारित होने की चुनौती उत्पन्न हो गई हो और यह भाषा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 तथा गाट 1994 के अनुच्छेद XIX : 1 (क) दोनों में और हमारा विश्वास है कि, अपेक्षा करती है कि आयातों में यह वृद्धि, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में, पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त महत्वपूर्ण हो जिससे कि "गंभीर क्षति" कारित हो सके या उसकी चुनौती उत्पन्न हो सके।"

24. यूएस व्हीट ग्लूटेन संबंधी पैनल ने "ऐसी संवर्धित मात्रा में वाक्यांश का निर्वचन निम्नवत किया है :

8.31 [गाट 1994 का अनुच्छेद XIX :1(क) और रक्षोपाय करार ("एसए") का अनुच्छेद 2.1]में आयातों में केवल "वृद्धि" का उल्लेख नहीं है। बल्कि, उनमें संबंधित उत्पाद के आयातों में परिमाणात्मक एवं गुणवत्ता प्रकृति की "वृद्धि" के संबंध में विशिष्ट जरूरत का उल्लेख है। गाट 1994 का अनुच्छेद XIX :1(क) और एसए का अनुच्छेद 2.1 दोनों यह अपेक्षा करते हैं कि संबंधित सदस्य के भूभाग में किसी उत्पाद का आयात इतनी

अधिक संवर्धित मात्रा (घरेलू उत्पादन में संगत एवं समग्र रूप से) में किया जा रहा हो कि उससे गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। अतः आयातों में केवल कोई वृद्धि ही पर्याप्त नहीं होगी। बल्कि, हम अर्जेंटीना फुटवीयर रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय के जांच परिणाम से सहमत हैं कि यह वृद्धि, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों में, पर्याप्त अभिनव, अचानक तीव्र और इतनी महत्वपूर्ण हो कि उससे गंभीर क्षति कारित हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके।" 2. अर्जेंटीना फुटवीयर (ईसी) संबंधी पैनल रिपोर्ट डब्ल्यूटी/डीएस 121/आर दिनांक 25 जून, 1993, 3. अर्जेंटीना फुटवीयर (ईसी) डब्ल्यूटी/डीएस 121/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 पर अपीलीय निकाय रिपोर्ट यूएस हवीट ग्ल्युटेन डब्ल्यूटी/डीएस 166/आर, 31 जुलाई, 2000 संबंधी पैनल रिपोर्ट।

25. यूएस - लाइन पाइप में पैनल में, अपीलीय निकाय द्वारा समीक्षा न किए गए एक विवरण में, पाया कि शब्द "अभिनव" का आशय "भूतलक्षी विश्लेषण" है; परंतु इसका आशय प्राधिकारी के निर्णय से ठीक पहले की स्थिति का विश्लेषण करना नहीं है और न ही इसका आशय यह है कि इस विश्लेषण में जांच की अवधि की तत्काल समाप्ति की स्थितियों पर अनन्यतः प्रकाश डाला जाए। संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं :

7.024. हम नोट करते हैं कि अर्जेंटीना फुटवीयर रक्षोपाय में अपीलीय निकाय ने यह पाया कि कि वाक्यांश "आयात किया जा रहा है" का आशय है कि आयातों में यह वृद्धि अचानक और अभिनव हो। कोरिया के अनुसार वाक्यांश "इतनी संवर्धित मात्रा में आयात किया जा रहा है" में "प्राधिकारी के निर्णय से तत्काल पूर्व की अवधि" का संदर्भ है। शब्द "अभिनव" --जिसका प्रयोग अपीलीय निकाय ने वाक्यांश "आयात किया जा रहा है" का निर्वचन करते हुए कि है, --को दीर्घ विगत नहीं"; जो अभी हाल में ही घटित, प्रकट, अवस्थित होना शुरू हुआ हो या अवस्थित हो, के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में शब्द "अभिनव" का आशय एक तरह का भूतलक्षी विश्लेषण है। इसका आशय प्राधिकारी के निर्णय से ठीक पहले की स्थितियों का विश्लेषण करना नहीं है। न ही इसका आशय यह है कि इस विश्लेषण में अनन्यतः जांच की अवधि की समाप्ति के समय की स्थितियों पर प्रकाश डाला गया हो। हम विचार करते हैं कि वह विश्लेषण जिसमें वर्ष 1998 के प्रथम सेमेस्टर की तुलना वर्ष 1999 के प्रथम सेमेस्टर से की गई हो, आयातों में "अभिनव" वृद्धि की जरूरतों से असंगत नहीं है।

26. फ्लोक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (विचाराधीन उत्पाद) के संवर्धित आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त मूल्यांकनों के आलोक में किया गया है। फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (पीयूसी) का भारत में कई देशों से और प्राथमिकतः सिंगापुर से आयात किया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि :

(क) चूंकि आयातों के आंकड़े अध्यक्ष शीर्षकवार लिए गए हैं इसलिए उसमें 3000 से 4000 मालिक्यूलर भार की पीयूसी के अलावा अन्य उत्पादों के संबंध में भी आंकड़े हो सकते हैं। डीजीसीआईएस से लेनदेन संव्यवहारवार आंकड़े मांगे गए थे। घरेलू उद्योग/मैसर्स शेल/मैसर्स शीला फोम ने 3000 से 4000 मालिक्यूलर भार की पीयूसी के भारत में किए जा रहे आयातों के ब्रैंड नाम प्रदान कराए। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 2.12.2014, 09.12.2014 के पत्र के तहत और मैसर्स लक्ष्मीकुमारन (मैसर्स शेल) द्वारा दिनांक 5.11.2014 के पत्र के तहत प्रदान कराए गए व्यौरों को ध्यान में रखते हुए लेनदेन संव्यवहारवार आंकड़ों की छंटाई की गई। घरेलू उद्योग/शेल/बेयर/शीला फोम द्वारा यथासूचित और इंटरनेट से खोज किए गए ब्रैंड नामों अर्थात् अल्कूपोल एफ 5511, अरकोल पालियोज 5613, करडोल एससी 5616, एससी 5616एस, एससी 4803, एससी 4808, एक्सेनाल 3031, सैन्निक्स 3030, पेटोल 48-03, पेटोल 53-03, पोलियोल डिप 5631डी, पोलियोल जेएच 3031के, पीपीजी 3001, पीपीजी 3002, पीपीजी जेएच 3031, रेपोल 3003, वोरालक्स एचएल 106, योकोल 5613, योकोल 5603, कोनिक्स जीपी 3001, लैप्रोल 3003, लुप्रानोल 2025, एसजी, वोरानोल 1900, वोरानोल 3010, 3136, 3010, 3322, 3595, 3943 पर आंकड़ों की छंटाई करने के लिए विचार किया गया।

(ख) हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा भी उठाया था कि इन आयात आंकड़ों में आयातित वस्तु की दोहरी प्रविष्टियां भी शामिल हैं, पहली प्रविष्टि भारत में वस्तु के आयात के लिए प्रविष्टि बिल और दूसरी उसी वस्तु को सीमाशुल्क के वेयरहाउसों से क्लीयर किया जा रहा है। मैसर्स शेल ने अपने दिनांक 5.11.2014 के पत्र के तहत आईएससीआईसी संख्या का विवरण भी दिया है जिसमें आईबीआईएस आंकड़ों के आधार पर आयातित

वस्तु की दोहरी प्रविष्टियां दिखाई गई हैं। मैसर्स शेल ने अपने दिनांक 11.12.2014 के पत्र के तहत पुनः दोहराया कि आयात आंकड़ों में दोहरी प्रविष्टियां हैं। दोहरी प्रविष्टियों के संबंध में प्रदान किए गए आईएससीआईएससी संख्या की डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेनदेन संव्यवहारवार आंकड़ों से जांच की गई और यह प्रेक्षण किया गया कि डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेनदेन संव्यवहारवार आंकड़ों में कोई दोहरी प्रविष्टि नहीं है।

- (ग) नियम में यह अपेक्षा की जाती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी न केवल संवर्धित आयातों की जांच करेंगे बल्कि उन स्थितियों की भी जांच करेंगे जिनके अंतर्गत यह आयात किए गए हैं। धारा 8 ख (1) में यह अपेक्षा की जाती है कि महानिदेशक यह जांच करेंगे कि क्या उक्त वस्तु का भारत में आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिससे कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है। अतः, वह स्थिति भी संगत है जिसके अंतर्गत संवर्धित आयात किए गए हैं।

27. उपर्युक्त के मद्देनजर, मैंने जांच की अवधि के लिए फ्लोक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (पीयूसी) के संवर्धित आयातों का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेनदेन संव्यवहारवार आंकड़ों (घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान कराए गए सुझावों/इनपुटों के आधार पर छंटाई करके) के आधार पर निम्नवत किया है :

(क) आयात :

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|
| कुल आयात | एमटी | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 |
| प्रवृत्ति | | 100 | 111 | 146 | 159 |

28. आयातों में समग्र और संगत दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। यह आयात जो वर्ष 2010-11 में 31778 एमटी थे, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 50632 एमटी हो गए अर्थात् आयातों में आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) उत्पादन के संबंध में आयात

29. यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई है जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| कुल भारतीय उत्पादन | एमटी | 17043 | 20392 | 14391 | 14069 |
| आयात | एमटी | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 |
| उत्पादन के संबंध में आयात | % | 186 | 173 | 322 | 360 |

कुल उत्पादन की तुलना में आयातों में यह वृद्धि वर्ष 2010-11 में केवल 186 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 360 प्रतिशत हो गई।

(ग) खपत/मांग के संबंध में आयात

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| मांग/खपत | एमटी | 48896 | 55369 | 60341 | 64462 |
| प्रवृत्ति | % | 100 | 113 | 123 | 132 |
| आयात | एमटी | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 |
| मांग/खपत की तुलना में आयात | % | 65 | 64 | 77 | 79 |
| प्रवृत्ति | % | 100 | 98 | 118 | 121 |

30. तथापि, वर्ष 2010-11 (आधार वर्ष) और 2013-14 के बीच, जब मांग/खपत में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तब भी कुल मांग के संबंध में आयातों में यह वृद्धि केवल 21 प्रतिशत ही थी।

31. अतः यह देखा गया कि फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (विचाराधीन उत्पाद) का भारत को आयात घरेलू उत्पादन की तुलना में समग्र रूप से संवर्धित मात्रा में किया गया। वर्ष 2010-11 (आधार वर्ष) और वर्ष 2013-14 के बीच घरेलू मांग/खपत में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयातों में केवल 21 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। यह प्रतिपादित किया जाता है कि आधार वर्ष (2010-11) की तुलना में आयातों में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है, जो अधिनियम की धारा 8ख के आशय के अंतर्गत संवर्धित आयात बनने के लिए पर्याप्त है।

छ. अनपेक्षित विकास

32. यह नोट किया जाता है कि भारतीय नियमावली या रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में क्रियापद्धति के संबंध में ऐसी कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं है जिसका अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करने के लिए अनुसरण किया जाना चाहिए। रक्षोपाय संबंधी करार में भी क्रियापद्धति संबंधी ऐसा कोई विहितिकरण नहीं है जिसका अनपेक्षित विकास का निर्धारण करते समय अनुसरण किया जाना चाहिए या पैरामीटरों को पूरा किया जाना चाहिए। तथापि, उन परिस्थितियों की जांच करना महत्वपूर्ण है कि जिनके कारण इन आयातों में वृद्धि हुई।

33. अर्जेंटीना फुटवियर और कोरिया डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि "डब्ल्यूटीओ करार के प्रभावी होने के पश्चात अधिरोपित किसी भी रक्षोपाय साधना के लिए रक्षोपाय करार और गाट 1994 के अनुच्छेद XIX दोनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए। गाट का अनुच्छेद XIX में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :

1. (क) यदि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप और इस करार के अंतर्गत किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा प्रशुल्क रियायतों सहित सौंपे गए किसी दायित्व के प्रभावस्वरूप उस संविदाकारी पक्षकार के भूभाग से किसी उत्पाद का आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में या ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है जिससे उस भूभाग के समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित होती है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाती है तो संविदाकारी पक्षकार ऐसे उत्पाद के संबंध में ऐसी सीमा तक अथवा ऐसे समय तक के लिए जो उस क्षति से बचने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक हो, उस प्रतिबद्धता को समग्र रूप से या उसके किसी भाग को समाप्त करने अथवा रियायत को वापस लेने या उसमें कोई संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

34. अर्जेंटीना फुटवियर (ई सी मामले) में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि पदबंध अनपेक्षित विकास का आशय उस विकास से है जो अप्रत्याशित हो। "अनपेक्षित विकास" यह अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण किसी उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में निर्यात किया जा रहा हो कि उससे घरेलू उत्पादकों को "अप्रत्याशित" गंभीर क्षति होने लगी हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। निकाय ने उसी मामले में गाट की एक पैनल रिपोर्ट को भी नोट किया जिसमें धारित किया गया कि यह विकास प्रशुल्क वार्ताओं के समय अनपेक्षित होना चाहिए। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास वह विकास होता है जो अनपेक्षित न हो या किसी सदस्य द्वारा कोई दायित्व लिए जाने के समय प्रत्याशित न हो।

35. अर्जेंटीना फुटवियर मामले में अपीलीय निकाय ने तब यह धारित किया है कि "अनपेक्षित विकास" की जरूरत रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए कोई पृथक "शर्त" स्थापित नहीं करता है, परंतु यह केवल परिस्थितियों के एक निश्चित "समूह" को वर्णित करता है।

36. पैनल ने यूएस - स्टील रक्षोपाय के संबंध में यह निष्कर्ष दिया कि कई घटनाओं का समग्र संगठित होकर अनपेक्षित विकास का आधार बन सकता है :

".....संयुक्त राज्य यह तर्क देता है कि यूएस डालर में मजबूती होना ऐसा विकास था जिसने अन्य विकासों नामशः एशिया और पूर्ववर्ती यूएसएसआर में मुद्रा संकट और संयुक्त राज्य बाजार में स्टील की मांग में निरंतर वृद्धि जबकि अन्य बाजारों में गिरावट आई के साथ मिलकर आयातों में वृद्धि कर दी।"

37. मैं यह पाता हूं कि आवेदक ने सूचना दी कि आयातों में यह उद्रेक भारतीय बाजार में कीमत आकर्षकता के साथ-साथ सिंगापुर की अतिशय बेशी क्षमता के कारण आया। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क किया गया कि सिंगापुर के निर्यातक इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात गैर-लाभकारी कीमतों पर कर रहे हैं। तथापि, मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग ने अपने इस तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। घरेलू उद्योग ने पुनः यह दावा किया है कि भारत-आशियान एफटीए और भारत-सिंगापुर सीईसीए के कारण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं ने घरेलू उद्योग के अहित के लिए तथा अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बाजार तथा आपूर्ति श्रृंखला पर अपना नियंत्रण करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। तथापि, इस संबंध में भी घरेलू उद्योग ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

38. व्यक्ति सुनवाई के समय घरेलू उद्योग ने यह भी अभिकथित किया कि कुल आयातों का 98 प्रतिशत आयात सिंगापुर से किया जाता है और आपूर्तिकर्ता भारत-आशियान एफटीए तथा भारत-सिंगापुर सीईसीए का प्रयोग कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वे इन व्यापार करारों का फायदा उठाने के लिए निर्यातकों की दुरभिसंधि की प्रत्याशा नहीं कर सके।

39. भारत-सिंगापुर सीईसीए वर्ष 2005 में किया गया था और शुल्क को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। यह करार सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है और सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सीमाशुल्क प्रशुल्क धीरे-धीरे कम होता रहेगा। वर्ष 2008 से प्रभावी सीमाशुल्क की गणना निम्नवत है :

| वर्ष | विवरण | शुल्क की दर |
|------|--|-------------|
| 2008 | अधिसूचना संख्या 10/2008 दिनांक 15 जनवरी, 2008 | 6% |
| 2009 | अधिसूचना संख्या 70/2009 दिनांक 19 जून, 2009 | 4.5% |
| 2009 | अधिसूचना संख्या 150/2009 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 | 3% |
| 2010 | अधिसूचना संख्या 131/2010 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 | 1.5% |
| 2011 | अधिसूचना संख्या 106/2011 दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 | 0% |

40. घरेलू उद्योग इस विचाराधीन उत्पाद का एक बड़ा उत्पादक होने के कारण इस तथ्य के प्रति जागरूक है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा अनपेक्षित विकास की शर्त को पूरा नहीं किया गया। वर्तमान मामले में अधिकांश आयात (डीआई और डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के अनुसार) सिंगापुर से किए गए हैं और इसलिए, मैं यह धारित करता हूं कि सिंगापुर से फ्लेक्सबिल स्लैबस्टाक पालियोल (पीयूसी) के आयातों में हुई वृद्धि को अनपेक्षित विकास नहीं कहा जा सकता है जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षतिकारित हुई या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई।

ज. गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती

41. "गंभीर क्षति" का आशय ऐसी क्षति से जिसके कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में समग्र परिक्षण हुआ; और "गंभीर क्षति की चुनौती का आशय गंभीर क्षति का स्पष्ट एवं आसन्न संकट है।

42. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 यह अपेक्षा करता है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तथापि, इन प्रावधानों में यह विशिष्टीकृत नहीं किया गया है कि इस मूल्यांकन में क्या दर्शाया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी मूल्यांकन विशिष्ट मामलों के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए भिन्न-भिन्न होगा। चूंकि प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन अनिवार्यतः यह नहीं दर्शाएगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है। उदाहरण के लिए एक मामले में उद्योग का "समग्र परिक्षण" हो सकता है। अतः, सभी सूचीबद्ध कारकों की तकनीकी जांच तथा किसी अन्य संगत कारकों की जांच करने के अतिरिक्त, यह अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन संगत कारकों के आलोक में किया जाए जिनका उद्योग की समग्र स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

43. अर्जेन्टीना फुटवियर (ईसी) 6, में अपीलीय निकाय ने अनुच्छेद 4.1(क) में "गंभीर क्षति" की परिभाषा तथा अनुच्छेद 4.2 (क) में सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करने की जरूरत के बीच संबंधों पर चर्चा की गई :
"जब उन सभी संगतकारकों के आलोक में, जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है तभी यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या उस उद्योग की स्थिति में "भारी समग्र परिक्षण" हुआ है। यद्यपि अनुच्छेद 4.2(क) में तकनीकी रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि कतिपय सूचीबद्ध कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यह कि अन्य सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए परंतु यह प्रावधान विशिष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि इस मूल्यांकन में क्या प्रदर्शित होना चाहिए। स्पष्टतः, ऐसा कोई भी मूल्यांकन किसी विशिष्ट मामले के कारकों तथा संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न मामलों में, भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए भिन्न-भिन्न होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन अनिवार्यतः यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में गिरावट आ रही है। उदाहरण के लिए किसी एक मामले में बिक्री रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट हो सकती है जो घरेलू उद्योग की स्थिति में "भारी समग्र परिक्षण" दर्शाएगी और इसलिए यह गंभीर क्षति के कतिपय मामलों में गिरावट न हो परंतु ऐसे होते हुए भी समग्र तस्वीर उस उद्योग की स्थिति में "भारी समग्र परिक्षण प्रदर्शित" करेगी। अतः, इस तकनीकी परीक्षण के अलावा कि क्या किसी विशिष्ट मामले में सक्षम प्राधिकारी ने सभी सूचीबद्ध कारकों और कतिपय अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया है, हम विश्वास करते हैं कि पैनल के लिए यह आवश्यक है कि वह गंभीर क्षति के निर्धारण की ऐसी कोई समीक्षा करते वक्त रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1 (क) में "गंभीर क्षति" की परिभाषा को ध्यान में रखेंगे।"

44. यूएस-व्हीट ग्ल्युटेन संबंधी पैनल ने अपीलीय निकाय द्वारा समुष्ट एक जांच परिणाम में वाक्यांश "गंभीर क्षति" के आशय का स्पष्टीकरण किया है : ऐसे "भारी समग्र परिक्षण" का निर्धारण घरेलू उद्योग की उस समग्र स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर उन सभी संगत कारकों के आलोक में किया जा सकता है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

"हम यह विचार नहीं करते हैं कि किसी उद्योग को भारी समग्र परिक्षण की स्थिति में होने के लिए यह आवश्यक है कि जांच किए गए प्रत्येक एकल कारक में ऋणात्मक प्रवृत्ति हो। बल्कि प्रवृत्ति की संपूर्णता और उनकी अनुक्रिया को गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए कई कारकों में ऐसे अपटर्न से अनिवार्यतः यह प्रतिसिद्ध नहीं होगा कि गंभीर क्षति का निर्धारण हुआ है। अर्जेन्टीना फुटवियर (ईसी) डब्ल्यूटी/डीए 121/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 के मामले में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में यह जांच अधिकारियों के लिए छोड़ दिया गया है कि वे उनके समक्ष दिए गए साक्ष्यों का आकलन को एवं उनकी गंभीरता का अंदाजा करें और इस तथ्य का समुचित, तर्किक और तर्कसंगत स्पष्ट कर दें कि यह तथ्य किस तरह निर्धारण का समर्थन करते हैं।"

45. तदनुसार, गंभीर क्षति का गंभीर क्षति की चुनौती का विश्लेषण करते समय सभी कारकों, जिनका नियमावली में उल्लेख है तथा अन्य कारकों जो गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने संगत है, पर विचार किया गया है। किसी भी एक कारक को डिस्पोजिटिव माना गया है। संगत व्यवसाय चक्र के संदर्भ के अंतर्गत सभी संगत कारकों और स्थितियों, जो प्रभावित उद्योग से संगत हैं, पर विचार किया गया है। गंभीर क्षति या गंभीर क्षति

की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग का समग्र स्थिति का उन सभी संगत कारकों के आलोक में मूल्यांकन पर आधारित है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

46. यह धारित किया जाता है कि फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल के संवर्धित आयातों ने फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित नहीं की है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न नहीं की है जैसाकि निम्नलिखित कारकों से संकेत मिलता है :

(i) बाजार हिस्सा

47. अधोलिखित तालिका से यह देखा जाता है कि कुल खपत में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

| वित्त वर्ष | कुल आयात (एमटी) | घरेलू उद्योग (एमटी) | कुल मांग (एमटी) | बाजार हिस्सा (%) | | मालसूची (एमटी) |
|------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|------|----------------|
| | | | | घरेलू उद्योग | आयात | |
| 2010-11 | 31778 | 16,615 | 48896 | 34 | 65 | 319 |
| 2011-12 | 35186 | 18,192 | 55369 | 33 | 64 | 691 |
| 2012-13 | 46364 | 13,451 | 60341 | 22 | 77 | 637 |
| 2013-14 | 50634 | 13,473 | 64462 | 21 | 79 | 645 |

48. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 34 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2013-14 में 21 प्रतिशत हो गया। कुल मांग जो वर्ष 2010-11 में 48896 एमटी थी बढ़कर वर्ष 2013-14 में 64462 एमटी हो गई। मालसूची वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में बढ़ गई थी परंतु वर्ष 2012-13 और 2013-14 में लगभग समान बनी रही।

(ii) उत्पादन

49. उत्पादन का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पाद शुल्क रिकार्ड में रिपोर्ट किए गए उत्पादन के आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग के उत्पादन से संबंधित सांख्यिकी निम्नलिखित है :

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| कुल क्षमता | एमटी | 18375 | 25000 | 25000 | 25000 |
| उत्पादन | एमटी | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |

50. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 2010-11 में 16510 एमटी से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 18381 एमटी हो गया परंतु यह वर्ष 2012-13 और 2013-14 में समान बना रहा। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान और वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान भी, अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया है। इस कम उत्पादन के लिए इस कारण को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि उनका ग्राही विद्युत संयंत्र भी न्यूनतर लोड्स पर चल रहा था जिससे कि इसके प्रचालनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वर्ष 2013-14 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट के प्रचालनात्मक हाइलाइट्स शीर्षक के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 2 पर घरेलू उद्योग यह उल्लेख किया है कि "ग्राही विद्युत संयंत्र (सीपीपी) के लिए बायोमास की उपलब्धता कागज के कुछ कारखानों और समान विद्युत संयंत्रों से मांग के कारण सीमित नहीं। बढ़ती हुई लागत पर भी आपूर्तियां नहीं की जा रही थीं जिससे कंपनी को सीपीपी न्यूनतर लोड पर चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इष्टतम लोड पर प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए सीपीपी हेतु वैकल्पिक ईंधन के लिए प्रयास किया जा रहा है। कंपनी ने विद्युत की ऊर्जा विनिमय और तीसरे पक्षकारों से भी खरीद की है जिससे कि

कमी को दूर किया जा सके। इनके परिणामस्वरूप विद्युत की उच्च लागत आई और परिणामस्वरूप उसकी लाभप्रदता पर इसका प्रभाव पड़ा।"

(iii) घरेलू बिक्री

51. घरेलू उद्योग की बिक्री का निर्धारण घरेलू उद्योग के लिए उनके फैक्टरी परिसरों से घरेलू उद्योग द्वारा कलीयर किए गए समान के आधार पर किया गया है, जैसा कि उत्पाद शुल्क में रिकार्ड में उल्लेख किया है। अधोलिखित तालिका में घरेलू उद्योग की बिक्री और कुल निर्यात की मात्रा दी गई है :

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| कुल मात्रा -घरेलू | एमटी | 16615 | 18192 | 13451 | 13473 |
| बिक्री मात्रा - निर्यात | एमटी | 0 | 0 | | 505 |
| बिक्री मात्रा - कुल | एमटी | 16615 | 18192 | 13451 | 13978 |

52. यह देखा गया है कि घरेलू बिक्रियां जो वर्ष 2010-11 में 16615 एमटी थी बढ़कर वर्ष 2011-12 में 18192 एमटी हो गई और फिर यह घटकर वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः 13451 एमटी और 13473 एमटी हो गई। तथापि, यह देखा गया कि घरेलू मांग में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। यह बिक्री मात्रा वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्थिर बनी रही।

(iv) क्षमता उपयोग

53. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग निम्नलिखित है :

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|
| संयंत्र क्षमता | एमटी | 18375 | 25000 | 25000 | 25000 |
| पीयूसी का उत्पादन | एमटी | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |
| क्षमता उपयोग | % | 90 | 74 | 56 | 55 |
| घरेलू मांग | एमटी | 48896 | 55369 | 60341 | 64462 |
| कुल मांग के संदर्भ में क्षमता की प्रवृत्ति | % | 38 | 45 | 42 | 39 |

54. यह देखा गया कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है परंतु वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान यह स्थिर रही। तथापि, घरेलू उद्योग की क्षमता का अनुपात (वर्ष 2011 में क्षमता 18375 से बढ़ाकर 25,000 कर दिए जाने पर भी) कुल मांग का 50 प्रतिशत से कम है। इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(v) मालसूची

55. मालसूची में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में वृद्धि हुई है परंतु वर्ष 2011-12 से समान बना रहा जिससे यह संकेत मिलता है कि बिक्री प्रणाली में स्थिरीकरण हुआ है। घरेलू उद्योग अपना समस्त उत्पादन बिक्री करने में समर्थ रहा क्योंकि इसकी मालसूची की स्थिति वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक स्थिर बनी रही।

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| मालसूची | एमटी | 319 | 691 | 637 | 645 |

(vi) रोजगार और उत्पादकता

56. क्षति अवधि के दौरान रोजगार तथा उत्पादकता के स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। इस अवधि के दौरान इसने सामान्य वृद्धि प्रदर्शित की है। यह पाया गया है कि यह पैरामीटर अन्य कई पैरामीटरों पर निर्भर हैं और वे घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। घरेलू उद्योग एक आटोमेटेड संयंत्र चला रहा है और इसलिए रोजगार का स्तर उत्पादन पर निर्भर नहीं है बल्कि यह संयंत्र और मशीनरी के आटोमेशन पर निर्भर होता है। बेहतर आटोमेशन से रोजगार में कमी आती है।

(vii) लाभ एवं हानि

57. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और निवेश पर प्रतिलाभ में जांच की अवधि (वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए तुलनपत्र) के दौरान सुधार हुआ है। कर पूर्व लाभ जो आधार वर्ष 2010-11 में 100 से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 130 तथा वर्ष 2014-15 वार्षिकीकृत में 192 हो गया। यह अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :-

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15* (वार्षिकीकृत) |
|------------|---------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| लाभ/(हानि) | रुपए/लाख | **** | **** | **** | **** | **** |
| लाभ/हानि | (अनुक्रमित) % | 100 | 172 | 103 | 130 | 192 |

* लाभ को दिनांक 30.09.2014 को समाप्त तिमाही के लिए अर्धवार्षिक स्टैंड अलोन लेखापरीक्षा में किए गए परिणामों के आधार पर वार्षिकीकृत किया गया है।

58. इस मामले में यह भी देखा गया कि घरेलू उद्योग की पीबीटी में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई और उसे जांच की अवधि के दौरान समग्रतः निवल लाभ में रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि उन्हें पीपयूसी के संबंध में घाटा हुआ है। इसलिए घरेलू उद्योग की लागत लेखा जांच करना आदेशात्मक है। घरेलू उद्योग विभिन्न प्रकार के पालियोल्स का विनिर्माण कर रहा है और पीयूसी उनमें से एक है घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 5.11.2014 के पत्र के तहत प्रदत्त लागतकरण रिपोर्ट की जांच करने पर यह पाया गया कि घरेलू उद्योग ने लागत को घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 26.9.2014 के पत्र के तहत प्रदान कराई गई पालियोल की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप अनुपातिक आधार पर नहीं लिया है। यदि पीयूसी का विनिर्माण करने के लिए लागत प्रभारों को पालियोल की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आनुपातिक आधार पर लिया गया होता तो घरेलू उद्योग को इस पीयूसी पर भी लाभ हुआ होता।

59. घरेलू उद्योग से उसके द्वारा विनिर्मित किए जा रहे सभी उत्पादों के आयात लेखापरीक्षा आंकड़े प्रदान कराने का अनुरोध किया गया था। तथापि, डीआई ने दिनांक 19.12.2014 के पत्र के तहत केवल पालियोलों के लागत लेखापरीक्षा आंकड़े ही उपलब्ध कराए हैं।

60. अतः, मेरे विचार से यह तथ्य कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद को पालियोल्स की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप आनुपातिक आधार पर लागत का उपरोपण नहीं कर रहा है, इसलिए उसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा दावाकृत क्षति हुई है और इस विचाराधीन उत्पाद पर होने वाली क्षति आयातों के कारण नहीं हुई है।

झ. अन्य महत्वपूर्ण कारक

61. अधोलिखित तालिका से यह नोटिस किया जाता है कि मांग के संबंध में आयात जो वर्ष 2010-11 में 65 प्रतिशत थे, 14 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में 79 प्रतिशत हो गए। तथापि, वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन स्थिर बना रहा। घरेलू मांग में भी आधिक्रमी वृद्धि हुई।

| वर्ष | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| घरेलू उद्योग बिक्री | एमटी | 16615 | 18192 | 13451 | 13473 |
| घरेलू खपत | एमटी | 24 | 50 | 48 | 163 |
| अन्य उत्पादों की बिक्री | एमटी | 479 | 1941 | 478 | 192 |
| आयात मात्रा | एमटी | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 |
| कुल मांग/खपत | एमटी | 48896 | 55369 | 60341 | 64462 |
| प्रवृत्ति | % | 100 | 113 | 123 | 132 |
| मांग/खपत के संबंध में आयात | % | 65 | 64 | 77 | 79 |
| प्रवृत्ति | | 100 | 98 | 118 | 121 |

62. उपर्युक्त विश्लेषण से यह देखा जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में और समग्र रूप से वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 के संबंध में आयात वर्ष 2013-14 में स्थिर बने रहे। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता कुल घरेलू मांग/खपत के संबंध में 50 प्रतिशत से कम है। घरेलू उद्योग कुल घरेलू मांग/खपत को पूरा नहीं कर सकता है।

63. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाया जा रहा घाटा इस विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन और बिक्री लागत को, अन्य उत्पादों के आनुपातिक आधार पर न कि आयातों की लेखाओं के आधार पर, प्रभाजन न करने के कारण हुई है।

64. अतः, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी कारकों, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, के आलोक में करने से यह स्पष्ट होता है कि उसकी स्थिति में भारी सुधार हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जांच की अवधि के दौरान उद्योग उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई या गंभीर क्षति की कोई चुनौती नहीं रही।

3. संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध

65. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली के नियम 8 के अनुसार महानिदेशक रक्षोपाय का यह दायित्व है कि वह "इन नियमों के अनुबंध में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करें।" इसके अतिरिक्त अनुबंधन के पैराग्राफ 2 में यह अपेक्षा या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करे। नियमावली के अनुबंधन का पैराग्राफ 2 निम्नवत है :

"पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, उद्देश्यपरक साक्ष्यों के आधार पर, जांच यह प्रदर्शित नहीं करती है कि संबंधित वस्तु के संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है। साथ ही यदि उसी समय संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं तो यह क्षति संवर्धित आयातों पर उपरोपित नहीं की जाएगी।

66. कोरिया-डेयरी संबंधी पैनल ने "कारणात्मकता" का निर्धारण करने के लिए आधारभूत अधिगम का निर्धारण किया है :

"अपने कारणात्मक संबंध आकलन का निष्पादन करने में, हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने और निर्धारण करने की जरूरत होती है कि क्या उद्योग का विकास, गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा विचारित, संवर्धित आयातों द्वारा कारित किया गया है। अपने कारणात्मक

संबंधी आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को प्रयोजनमूलक और परिमाणात्मक प्रकृति के उन सभी संगतकारकों का मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है, जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अलावा कुछ ऐसे कारकों को अभिज्ञात किया है जिन्होंने घरेलू उद्योग को क्षति कारित की है तो यह सुनिश्चित करेगा इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वह क्षति संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई है।

कारणात्मक संबंधी स्थापित करने के लिए कोरिया को यह प्रदर्शित करना है कि घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में कोरिया को यह प्रदर्शित करना है कि एसएमपीपी के आयात दुग्ध पावडर और अपरिष्कृत दुग्ध का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात कोरियाई प्राधिकारी का यह नैतिक दायित्व है कि वह अन्य कारकों द्वारा कारित की गई क्षति को संवर्धित आयातों पर उपरोपित न करें।¹

67. कारणात्मक की निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन सभी उद्देश्यपरक और परिमाणात्मक प्रकृति के संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। उत्पादन और क्लीयरेंस स्थिर बने रहे। आयात (वार्षिकीकृत आंकड़े) वर्ष 2014-15 में घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है। घरेलू उद्योग लाभ में वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर लगभग दो गुने हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों से कोई क्षति कारित नहीं हुई है, इसलिए ऐसा लगता है कि संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कोई कारणात्मक संबंधी स्थापित करने की जरूरत नहीं है।

4. समायोजन योजना

68. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की यह पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 का नियम 5(2) (ख) में "आयात प्रतिस्पर्धा से सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे या योजनागत या दोनों तरह के प्रयासों" के संबंध में विवरण प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार क अनुच्छेद 7.1 में यह प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय साधन का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब गंभीर क्षति से बचने के लिए या उसका समाधान करने के लिए आवश्यक सीमा तक प्रयास किए गए हो और समायोजन आसान बनाया गया हो।

69. निर्णयात्मक रक्षोपाय साधन का उद्देश्य घरेलू उद्योग को एक ऐसी समयावधि प्रदान करना है जिसके अंतर्गत वह स्वयं को पुनर्गठित कर सके ताकि वह आयातों से अधिक कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सके। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(4) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 16(2) में यह प्रावधान है कि यदि ऐसा कोई साक्ष्य न हो कि घरेलू उत्पादक समायोजन कर रहा है, तो इस संभावित वृद्धि करने से निषेध है।

70. इस मामले में घरेलू उत्पादकों ने निम्नलिखित समायोजन योजना निर्धारित की है :

- (i) मौजूदा क्षमता के अवरोधों को दूर करके क्षमता बढ़ाना
- (ii) क्षमता उपयोग का स्तर बढ़ाना
- (iii) ग्राही प्रोपाईलीन आक्साइड का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाना
- (iv) पीओ का बल्क परिवहन और संभारतंत्र में सुधार करना।

71. इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने एक समायोजन योजना प्रदान की है जो संपूर्ण समयावधि में क्रियान्वित की जाएगी और घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समायोजन के लिए कोई समयबद्ध ठोस योजना की परिकल्पना नहीं की गई है। यह भी देखा गया है कि वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान भी, जब घरेलू उद्योग ने लाभ प्रदर्शित किया है तब भी, घरेलू उद्योग ने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया। घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 19.12.2014 के एक पत्र के जरिए अपने पोलिओल संयंत्र के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग सर्विस करवाने का आशय दिया है, किन्तु इसके लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह क्रम भी पालियोल संयंत्र के लिए है और विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। विस्तार

¹ कोरिया-डेयरी संबंधी पैनल रिपोर्ट पैरा 7.88.90

के संबंध में भी घरेलू उद्योग द्वारा कोई अतिरिक्त, संदर्भ प्रदान नहीं कराया गया है। मेरे विचार से, घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद की चुनौती का सामना करने के लिए कोई व्यवहार्य समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है।

5. जनहित

72. केवल घरेलू उत्पादकों के हित को ही जनहित नहीं माना जा सकता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा तो उसे जनहित के रूप में नहीं माना जा सकता है। भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग घरेलू उद्योग जो भारत में इस पीयूसी का प्रमुख उत्पादक है, की उत्पादत/क्षमता से दोगुनी से भी अधिक है और चूंकि अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए घरेलू उद्योग की समायोजन योजना प्रस्ताव की प्रकृति की है और यह किसी समयबद्ध प्रकृति की नहीं है, इसलिए घरेलू उद्योग जब तक अपनी प्रस्तावित क्षमता में वास्तव में विस्तार करेगा तब तक मांग-आपूर्ति में अंतर और भी अधिक बढ़ जाएगा। मांग और आपूर्ति में भारी अंतर और घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षमता में उस सीमा तक विस्तार में अक्षमता, जिस सीमा तक निकट भविष्य में कुल भारतीय मांग में वृद्धि होगी, को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इससे उपयोगकर्ता उद्योग के हितों को गंभीर क्षति पहुंचेगी। इसलिए, इन परिस्थितियों में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा।

6. जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों की जांच

73. मौजूदा परिस्थितियों में, जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में प्रवृत्ति का विश्लेषण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के तीव्रीकरण की संभावना के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष निकालने के लिए किया गया। घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 के पत्र के तहत भारत में आयातित "विचाराधीन उत्पाद" के संबंध में कतिपय आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित वर्ष 2014-15 की पहली छमाही के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं।

| विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (वार्षिकीकृत) |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| कुल आयात (एमटी) | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 | 44648** |
| उत्पादन (एमटी) | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 | 17108* |
| घरेलू बिक्री (एमटी) | 16615 | 18192 | 13451 | 13473 | 16456* |
| कुल मांग (एमटी) | 48896 | 55369 | 60341 | 64462 | 61104 |
| आयातों का बाजार हिस्सा % | 65 | 64 | 77 | 79 | 73 |
| घरेलू उद्योग का % बाजार हिस्सा | 34 | 33 | 22 | 21 | 27 |
| लाभ/(हानि) (रुपए/लाख)# | **** | **** | **** | **** | **** |
| (अनुक्रमित) % | 100 | 172 | 103 | 130 | 192 |

* वार्षिकीकृत आंकड़े एफएसपी के उत्पादन/क्लीयरेंस के संबंध में अर्धवार्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं।

** वार्षिकीकृत आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त पहली तिमाही के लेनदेन संव्यवहारवार आंकड़ों के आधार पर हैं।

आंकड़े घरेलू उद्योग के वित्तीय रिकॉर्ड से यथा तुलनपत्र/वित्तीय परिणाम।

74. उपर्युक्त आंकड़ों की संवीक्षा करने पर यह नोट किया जाता है कि कुल घरेलू मांग के संबंध में आयातों का बाजार हिस्सा कम हो रहा है तथा घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ रहा है। वर्ष 2013-14 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में भी वर्ष 2012-13 की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में भी इसी तरह का रुझान प्रदर्शित हो

रहा है जहां लाभ 2013-14 के संबंध में बढ़ रहा है (घरेलू उद्योग की वित्तीय अभिलेखों के आधार पर)। इससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हो रहा है और उसकी स्थिति में भविष्य में भी सुधार होगा।

अ. निष्कर्ष

संगत कारकों की जांच करने के पश्चात मैं यह उपपादित करता हूं कि :

75. आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन के संबंध में तथा समग्र रूप से आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

76. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 34 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2013-14 में 21 प्रतिशत रह गया। तथापि, वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान कुल मांग में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के हिस्से में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में आयातों में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है।

77. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान स्थिर बनी रही तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में इसमें बढ़ने की प्रवृत्ति बनी हुई है।

78. आयातों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है परंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे ऐसा लगता हो कि घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र परीक्षण हुआ हो क्योंकि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को समग्र लाभ ही हुआ है और घाटा, यदि कोई, है भी तो वह अन्य कारकों से हुआ है। वास्तव में, मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए घरेलू उद्योग ने 10 प्रतिशत लाभान्श की घोषणा की है, यह कार्य भी दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति सही है। आयात स्थिर रहे हैं, उत्पादन और क्लियरेंस भी समान प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में तो इसमें बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि संवर्धित आयातों के द्वारा कोई गंभीर क्षति कारित नहीं की गई है।

79. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घाटा दर्शाया है। तथापि, ऐसा देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने इस विचाराधीन उत्पाद की लागत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 26.09.2014 के अपने पत्र के तहत उसके द्वारा प्रदान कराई गई पालियोल की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप समानुपातिक आधार पर नहीं किया है। यदि इस विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए लागत प्रभार का निर्धारण लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप समानुपातिक आधार पर किया गया होता तो घरेलू उद्योग इस विचाराधीन उत्पाद में भी लाभान्वित हो सकता था। घरेलू उद्योग से यह अनुरोध किया गया था कि वह उसके द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों के लागत आंकड़े प्रदान करे। तथापि, घरेलू उद्योग ने केवल पालियोल्स के ही लागत लेखा आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, न कि किसी पृथक उत्पाद के। इसके अतिरिक्त, चूंकि डीआई को समग्र लाभ हो रहा है, इसलिए स्पष्टतः उनके पास इस विचाराधीन उत्पाद के सस्ते आयातों द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने की क्षमता है।

80. घरेलू उद्योग यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि आयातों में यह वृद्धि अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण हुई

81. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजन योजना में किसी विशिष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं है। घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए एक आशयपत्र प्रस्तुत किया है। तथापि, विस्तार के लिए यह आशयपत्र भी पालियोल्स संयंत्र के बारे में है, न कि इस विचाराधीन उत्पाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिस्पर्धी बनने हेतु कोई व्यवहार्य समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है।

82. घरेलू बाजार की मांग आपूर्ति के बीच भारी अंतर है। संवर्धित आयातों के बावजूद भी जांच की अवधि के दौरान लाभों में वृद्धि प्रदर्शित की है। जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में लाभों (वार्षिकीकृत) में यह वृद्धि आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में लगभग दोगुनी है। घरेलू उद्योग के हिस्से में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है और घरेलू मांग की तुलना में आयातों के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है।

83. अतः, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान अभिकथित गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती की मौजूदगी प्रतिकारी प्रवृत्ति की प्रतीत नहीं हो रही है और इसलिए, मेरे विचार से, किसी तरह के संरक्षण, जैसा कि अनुरोध किया गया है, की जरूरत नहीं है।

ट. सिफारिश

84. ऊपर उल्लेख किए गए विवरण और निकाले गए निष्कर्ष के मद्देनजर "3000 से 4000 एमडब्ल्यू के फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलियोल" के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है और इस मामले में जांच खारिज की जाती है।

[फा. सं. डी-22011/4/2014/पार्ट-III/4050]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS

(CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2015

Subject:-Safeguard investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (FSP) –Final findings under Rule 11 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997

G.S.R. 28(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 11 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

A. Procedure

1. An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by M/s. Manali Petrochemicals Ltd, Chennai through their consultant M/S. APJ-SLG Law Offices for imposition of Safeguard Duty on imports of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 (hereinafter referred to as PUC) into India to protect the domestic producers of PUC against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of PUC into India. The Notice of Initiation of safeguard investigation concerning imports of PUC into India was issued on 22nd May, 2014 and was published in the Gazette of India Extraordinary.

2. A copy of the Notice of Initiation dated 22nd May, 2014 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce and other ministries concerned, Governments of exporting countries through their Embassies/High Commission in New Delhi and all known interested parties listed below in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty) Rules, 1997:

I. Domestic Producers

A) M/s. Manali Petrochemicals Ltd, Chennai

II. Importers/Users

1. Aagosh Poly Foam Pvt. Ltd 40, Industrial Area, Phase –II, Chandigarh.
2. Arvind International Ltd. 15, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Calcutta.
3. Banmore Foam Pvt. Ltd. 106/107, Industrial Area, Banmore, Dist. Morena (MP)
4. Cozy Foams Pvt. Ltd. Plot 17, Survey NO 820/IP, Village-Mahim, Chantupada, Palghar Thana
5. D P Foam Pvt. Ltd. A 38-40, Industrial Estate, Sedarapet, Pondicherry – 605101
6. Dura Foam Inds Pvt. Ltd. 123, Industrial Estate, Piparia, Dadra Nagar, Haveli
7. Diana Foams Pvt. Ltd. Industrial Estate, Rairangpur, Orissa – 757043
8. Devi Polyurethane Pvt. Ltd. Gate No. 391/A Gondedumala, Taligatpuri, Nasik-Bomaby Highway, Dist-Nasik
9. Inkay Foam Pvt. Ltd. Village-Khekra, Tehsil-Baghpat, Delhi-Baghpat Road, Dist-Meerut (UP)
10. Feather Foam Enterprises Pvt. Ltd. A-10, Sector VIII, Noida – 201301 (UP)
11. Foam Home (India) Pvt. Ltd. H-30/2 MIDC Talao, Maharashtra
12. Feather Foam Enterprises Pvt. Ltd. Plot No. 257, Umarkui, Saily, Silvassa.
13. Joy Foam Pvt. Ltd. 30 & 35, Sidco Industrial Estate, Ranipet.
14. Juhi Foam Pvt. Ltd. Village-DHSU Majra, Dist-Ropar, Kharar. (P.B.) – 140031
15. Kurlon Ltd. Plot No. 88 B, Sector-Chandka Industrial Estate, Bhubneshwar – 751031
16. Kamal Foam B-110 & 111, Pipdic Industrial Estate, Mettupalayam, Pondicherry – 605009
17. M.R. Foams Plot 67, IDA Mellapur, Hyderabad.
18. Multiwyn foams Pvt. Ltd. 38, Camac Street, Calcutta-700016

19. Modern Foam Udyog, Village-Kakka, Ludhiana, Punjab Ropan
20. NL Foam Industries, Shed A 2, 3 & 4, GIDC, Vatva Industrial Estate, Ahmedabad.
21. Natson Foam Mfg. Pvt. Ltd. Block No. 218/1 TK Kalol, Dist. Mehsana, Village-Nondoli.
22. Panama Poly Products Pvt. Ltd. Site-1, Bulandshahar Area, B-8, UPSIDC Industrial Area, Ghaziabad (UP)
23. Pallavi Foam Inds Pvt. Ltd. Village-Habibpur, Dist. Ghaziabad, Noida Dadri Road (UP)
24. Poly Foam, Plot No. 3, Survey NO 820/IP, Village-Mahim Palghar, Dist. Thana (Chantupada)
25. Prabhat Polyurethane P. Ltd. Pipdic Industrial Estate, 42, 4th Cross Street, Sidarapet, Pondicherry
26. Pratap Polyurethane P Ltd. 530, Marshall House, 33/a, N.S. Road, Calcutta-700001
27. P.U. Faom Pvt. Ltd. 96, Muktaram Babu Street, Calcutta-700007
28. Raj Leather Cloth Inds Pvt. Ltd. 20th M.S. G.T. Karnal Road, vill-Badkhalsa, Dist. Sonpet, (Haryana)
29. Sheela Foam Pvt. Ltd. Plot No. 37/2 Site No. 4, Ghaziabad, Sahibabad, UP-20101
30. SSF Industries Ltd. Shivalay Market, Ashok Rajpath, Patna-800004
31. Sheela Foam Pvt. Ltd. Unit II, A-10, Sector 8, Noida (UP)
32. Tirupati Foam Ltd. Plot No. 1023, Mehsans Highway, Village-Rajpur, Kalol Talukakadi, Dist. Mehsana
33. Tirupati Foam Ltd. Plot No. 4-A, Block No. 65, Village-Khatraj, Post-Vadsar, Taluk Kalol.
34. U Foam Pvt. Ltd. B-15, 16 Industrial Estate, SanatNagar, Hyderabad-500018
35. M/s. Surya Foam, Sedarapet Main Road, Sedarapet, Pondicherry.
36. M/s. Aparna Polyproducts Ltd., 452, Ganapati Plaza, M.I. Road, Jaipur 302 001 (Rajasthan)
37. M/s. Soft Foam Industries Pvt. Ltd. Survey No.3852, Medchal Indl. Area, R.R. District, 501 401 (AP)
38. M/s. Madras Polymoulds 28, C & D Krishnaswamy Avenue, Mylapore, Chennai-4
39. M/s. J J Foams Pvt. Ltd. B-12/2, Site-IV, Sahibabad Indl. Area, Sahibabad (Dist. 666668bad) UP
40. M/s. M H Polymers Pvt. Ltd. B 15, Site B, Suraj Pur Indl. Area, Tehsil, Dadri Dist. Ghaziabad (UP)
41. M/s. Shree Malani Foams (P) Ltd, Ideal Towers, survey No 115, Akbar Road, Tadbund, Secunderabad-500009.
42. M/s. Allied Foams Private Ltd, D 32, Mahendru Enclave, GT Karnal Road, Delhi-110033
43. M/s. Natson Foam Manufacturers (Pvt) Ltd, 5, Panchayat Bhawan, Bhadra, Ahmedabad-380001
44. M/s. Chemie Products (Pvt) Ltd, 902, GD-ITL Towers, B-08, Netaji Subhash Place, N Delhi-110034
45. M/s. Tirupati Foam Ltd, Tirupati House, Nr Topaz Restaurant, University Road, Ambawadi, Ahmedabad-380015
46. M/s. Sheela Foam Pvt Ltd, C-55, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092
47. M/s. Banmore Foam (P) Ltd, 105-106, Industrial Area, Banmore-476444 (MP)
48. M/s. Bharat Foam Udyog Pvt Ltd, 15/4, Mathura Road, Faridabad-121003
49. M/s. Pyarelal Foams (P) Ltd, Koyyamarakkadu, Kanjikode, Palakkad-678621 (Kerala)
50. M/s. Pyarelal Coir Products (P) Ltd, 1501/A, Ram Gali, Bhagirath Palace, Delhi-110006
51. M/s. P U Foams Pvt Ltd, Dakhin Rajyadharpur, Delhi Road (Near Power House), Serampore, Hooghly (WB)
52. M/s. Moka Business Pvt Ltd, C-42, Sudershanpura Industrial Area, Bais Godown, Jaipur-302006
53. M/s. Dow Chemical International Pvt Ltd, 1st floor, Block B, 02 Godrej Business District, LBS Marg, Vikhroli(W), Mumbai-400079
54. M/s. Bayer Material Science Pvt Ltd, Plot 1A, Udyog Kendra, Sector Ecotech III, Greater Noida- 201306
55. M/s. Diana Foams (Pvt) Ltd, Rairangpur, Mayurbhanj, Orissa
56. M/s. Flexipol Foams Pvt Ltd, E-1162, Bhiwadi Industrial Area, Phase IV, Bhiwadi(Rajasthan)
57. M/s. Springwell Mattresses Pvt. Ltd., A-49, Mangol Puri Industrial Area, Phase-II, Delhi-34
58. Polyurethane Association of India, Mr. K. Ramamurthy, Secretary, 6/6 Poes Road, 1st Street, Chennai 600018

III. Exporters

1. S K Oxichemical Co Ltd. 23-10, Yoido Dong, Yongdungpo-GU, Seoul, South Korea 180-0101
2. Bayer Polyurethanes Taiwan Ltd. 2F290 Chung Hsiao E Rd, Sec 4, Taipei, Taiwan.
3. Zhejiang Sanhuan Chemical Company Ltd., No.1007. jiu Ling Xi Road, Yongkang Zhejiang, 321300. P.R. China
4. Dow Quimica SA, Rua Alexander Dumas, 1671 P.O. Box 9037, 010065 – 970, Sao Paulo, Brazil
5. Shell Chemicals, Shell Eastern Petroleum (PTE) Ltd. Singapore -239 920
6. Blue Diamond Australia Pty Ltd. Acn 00 3068344, P.O. Box. 349, Collaroy, Nsw 2097, Australia

7. Sanyo Chemicals, Japan
8. Bayer Polyurethane Asia (PTE) Ltd. 152 Beach Road,
37-00 Gateway East Singapore 189721
9. Bayer Polyurethane Asia (PTE) Ltd.,
Bayer Faser GmbH, Wolff Walsrode, Ag. Germany
10. Repsol Quimica. Sa, Paseo De La Castellana,
280, E-28046 Madrid, Spain
11. Toyota Tsusho Corporation, 2-3-13 Konan,
Minato-Ku, Tokyo (Japan)
12. M/s. Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd,
Singapore
13. M/s. Shell Eastern Trading (Pte) Ltd,
Singapore
14. M/s. Dow Europe GMBH
15. M/s. Dow Chemical Pacific (Singapore) PTE Ltd
16. M/s. Bayer (South East Asia) Pte Ltd, 63,
Chulia Street, 14th Floor, OCBC Centre East, Singapore 049514
17. M/s. IRPC Polyol Co.Ltd.,
555/2, Energy Complex, Building -B, 7th Floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchark, Bangkok10900, Thailand.

IV. Exporting Nations

1. M/s. European Union, Delegation to India, 65, Golf Links, New Delhi-110003
2. Embassy of Japan representing Govt of Japan, 50G, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110021
3. Embassy of Russia,
Shantipath, Chanakyapuri, New-Delhi – 110021
4. Embassy of Mexico,C-8, Benito Juarez Marg,
Anand Niketan, New Delhi, 110021.
5. Embassy of USA, Shantipath, New Delhi,
6. The High Commission of The Republic of Singapore,
E-6, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi
7. Embassy of South Korea,
9, Chandragupta marg, Chanakyapuri, New Delhi.
8. The Royal Thai Embassy,
13-1/3, Vasant Vihar, New Delhi
9. Taipei Economic and Cultural Centre in India,
34, Pashimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi.
10. Embassy of Netherland, 6/50F,
Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi.
11. Embassy of China,
50-D, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi, 110021
12. Embassy of Australia,
1/50-G, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi, 110021
13. Embassy of Republic of Indonesia,
50-A, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021
14. Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India
Block-50-E, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New-Delhi – 110021

6. The information presented by the applicants was verified by on-site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non confidential version of verification report is kept in the public file.

7. All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential information received or acquired has been kept in the public file. Many interested parties/importers/exporting nations also filed post initiation submissions.

8. A public hearing was held on 29.09.2014, notice for which was sent on 15.9.2014. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by 10.10.2014. Copy of written submissions filed by interested parties was made available to all the other interested

parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties by 17.10.2014.

9. All the views expressed by the interested parties and other domestic producers either in the written submissions or in the rejoinders and response to the domestic industry submissions were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

B. Views of Domestic industry and interested parties filed post notice of initiation:-

I) Views of Domestic Industry

a. The applicant constitutes domestic industry as per Customs Tariff Act' 75 as they are the only producer of PUC in India and thus they have the standing to file the present petition. They constitute the major proportion in the total Indian production of DOP.

b. A comprehensive evaluation of parameters such as production capacity, production, capacity utilization, employment, productivity, cash flow, return on capital employed, captive use, stocks, consumption, sales, market share, price, undercutting and profitability of the period from 2010-11 up to 2013-14 demonstrates serious injury or significant impairment of the Indian producer of subject goods.

c. The Indian producer's market share fell from 39% in 2010-11 to 19% in the POI. From the import levels of 2010-11, the imports increased drastically, due to the commissioning of export-oriented capacities in various countries. This demonstrates the increasing market penetration of imports.

d. There has been a fall in the sales volume of the domestic industry during the POI as compared to the base year. This is a clear indication that a major portion of the market share of the domestic industry has been taken away by imports.

e. The profitability of the Domestic Industry has also declined substantially during the POI as compared to the base year i.e., 2010-11. The profitability of the Domestic Industry in 2010-11 has changed into losses during the 2013-14. As compared to 2010-11 Domestic Industry incurred losses of **** Lacs. The profit/MT of the domestic industry has also declined by about 571% during the same period.

f. The capacity utilization of the Domestic Industry has also declined substantially by 34.60% during the injury investigation period. It is important to note that during the same period the demand has increase by 76%.

g. In sum, there is a direct correlation between the increase in imports at lower prices and serious injury suffered by the domestic industry and the increase in imports has had injurious effects in terms of pressure on prices and a reduction in volume sold by the domestic industry.

II. Views of Exporting Nations

(a). Russian Federation

The Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation submitted that during the period of investigation from 2010 to 2013 the import of goods falling under sub-heading 39072010 of the Customs Tariff Act 1975 and importing from the Russian Federation to India did not exceed three percent, in accordance with the Safeguard Provisions under the Customs Tariff Act, 1975 (Section 8B) and the Article 9 of the WTO Safeguards Agreement the Russian Federation should be excluded from the list of countries under investigation.

(III). Views of Exporters

(a) M/s. Shell Eastern Petroleum (Pte) Limited and M/s. Shell Eastern Trading (Pte) Limited have filed preliminary submissions through M/s. Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys as under:-

(i). PRELIMINARY OBJECTIONS

1. Initiation of the present investigation is bad in law as both India-ASEAN FTA and the India-Singapore CECA provide for specific guidelines to be followed in cases of safeguard investigations initiated under the two agreements respectively.
2. The Applicant is a serial user of trade remedy proceedings has applied for anti-dumping duties against almost all the major countries that have exported the subject goods into India and have in the course of last 14 years tried to smoke out all the imports of subject goods from various countries.

3. The Applicant had also approached the Directorate General of Antidumping seeking protection in the form of Antidumping Duty as recently as in 2013. The domestic industry itself has accepted that it suffered injury because of dumping, assuming if there was one, therefore there is also for that reason no substance in the present safeguard petition.
4. The Applicant has claimed in the petition that it is the sole producer of the like article in India. However, Respondents would like to submit that M/s. Expanded Polymer Systems might also qualify as a producer of the like article in India. They have not been communicated by the Applicant anywhere in the petition and the Authority should appropriately terminate this investigation for want of completeness of petition
5. The petition filed by the Applicant and the initiation notice issued by the DG (Safeguards) are based upon completely different sources of import statistics.
6. MS-Excel version of raw and sorted import statistics be provided to analyse the trend of the imports of the subject goods into India during the injury analysis period.
7. That there is double entry of imports as when the subject products are imported into India, they are first stored in customs bonded warehouses by filing a warehousing Bill of Entry and then removed in small quantities, by filing a Bill of Entry for home consumption over a period of time. However, in the import statistics both the transactions are separately reported resulting in double counting.
8. Annualisation of 9 months import statistics may not be a correct way to determine actual import figures for 2013-14 in the facts of the present case.
9. As per market intelligence, it is understood that the Applicant in fact offers discounts to their customers. The Respondents request the Authority to verify this fact.
10. The petition is also deficient as it contains a number of unwarranted confidentiality claims. The Applicant has not provided the indexed version of the above injury and costing data.
11. In the present investigation, the Applicant has neither provided any statement of reasons nor appropriately summarized any of the evidence referenced. The Applicant has also not offered an explanation as to why or how the release of said information would prejudice the legitimate commercial interests of the Applicant.
12. The applicant has also not disclosed the methodology followed for determination of fair market price.

II. SUBSTANTIVE SUBMISSIONS

- a) Compliance with Article XIX of the GATT 1994
 - b) Two-fold obligation on the Authority: (i) to identify the developments that were unforeseen and, (ii) establish link as to how those unforeseen developments led to increase of imports. *Neither the Applicant nor the Authority have identified any unforeseen developments*
 - c) Two fold obligation on the Authority: (i) to identify the specific obligation including tariff concessions incurred by India concerning the subject product under GATT and, (ii) to establish that specific obligation's link with increase of imports of the subject product in India.
 - d) In the present case, the imports are not recent, sudden, sharp and significant, because of which the threshold criteria itself is not met.
 - e) The DG (Safeguards) itself in its finding in Linear Alkyl Benzene (LAB) found that the requirements under Section 8B(1) remained unsatisfied even though the imports continued to increase in absolute terms over the period under review.
 - f) In the present case, there have been no increases in the period of injury comprising of 2010-11, 2011-12 and 2012-13 and as far as the data in the initiation notice is concerned, there is only a slight increase in imports in 2013-14 in 2013-14.
 - g) There is no suddenness of increase in imports, nor it is very sharp; it is simply a gradual increase. Thus, it is concluded that there is no sudden, recent, sharp and significant increase in imports and such contention by the Applicant is to be rejected.
 - h) No credible evidence whatsoever to make out a case of serious injury or causation:
 - i) Feedstock unavailability has negatively impacted production and sales.
 - j) The Applicant procures propylene from CPCL, who is the sole supplier of propylene to the Applicant. Such quantity is also limited by way of a maximum amount beyond which CPCL does not supply any more propylene. Therefore, with such a cap on supply of propylene by CPCL to the Applicant, it can only manufacture a certain amount of the propylene Oxide (PO) and use PO in manufacture of subject product and not more.
 - k) The Respondents submit that the veracity of the capacity provided by the Applicant is in doubt. The Authority is requested to investigate and clarify the contradictory data provided by the Applicant.
 - l) There are two reasons for reduction in capacity utilization:
 - i. Lack of availability of feedstock Propylene Oxide (PO) as highlighted above which would lead to non-utilization of capacity and a reduction in capacity utilization;

- ii. Increase in capacity of the Applicant by 36% which would also obviously lead to a reduction in the capacity utilization.
- m) Any reduction in capacity utilization is also attributable to the lack of availability of the feedstock (PO) for the manufacture of the subject product. The Applicant, in Annual Report 2010-11, has admitted that the reduction in capacity utilization is due to shortage of PO. They are taking steps to install an import terminal at Ennore Port to import 'PO' in bulk to improve availability of 'PO'.
- n) It is also noted that such bulk storage may still be in progress and not yet been completed. The same is admitted by the Applicant in Annual Report 2012-13 on page 179 of the petition.
- o) The profitability figures provided in the anti-dumping petition are at odds with the figures provided by the Applicant in the subject investigation.
- p) The Applicant was able to sell, as a percentage of its production, 101% in 2010-11, 99% in 2011-12, 96% in 2012-13 and 98% in POI. Therefore, there are no issues to the Applicant as far as proportion of sales and production is concerned; it is the non-availability of the feedstock (PO) that has resulted in reduced profitability.
- 17 Price undercutting, depression and suppression data has not been indicated even in indexed form in the NCV of the petition filed by the Applicant.
- 18 Applicant cannot cater to the demand even in the case of 100% capacity utilization. The users in India will necessarily have to import at least 66% of the required demand, and, in particular if they do not want to be dependent on a sole supplier, invest in sustainable relationships abroad to secure longer term supplies.
- 19 The Applicant wishes to increase capacity in order to cater to the demand, the same cannot be carried out as per the Applicant's own admission that the moratorium in the Manali area denies any scope of capacity additions.
- 20 In the Annual Report 2012-13 the Applicant has stated that the availability of bio mass fuel for the Captive Power Plant (CPP) had become scarce, which forced the Applicant to operate the CPP at lower loads.
- 21 From the above, it is clear that the restrictions with regard to consumption of power coupled with a reduction in the captive power generation exerted tremendous pressure on the Applicant which in turn triggered the drop in production.
- 22 That any "serious injury" that may have been sustained by the Applicant is due to a number of other factors such as:
 - i. Lack of feedstock availability;
 - ii. Consequent reduction in production and sales;
 - iii. Dependence on sole supplier Chennai Petroleum Corporation Ltd of propylene in India to the Applicant; and
 - iv. Inability of the Applicant to supply the required quantity of the subject product.
- 22. None of the reasons are in any way linked to import volume of the subject product. Therefore, the causation analysis fails in the present investigation and the same is liable to be terminated.
- 23. The applicants have submitted an unworkable adjustment plan.
- 24. Further debottlenecking is not possible as the Applicant has stated in the Annual Report 2010-11, provided on page 103 of the petition that the Applicant has already completed such an exercise and admittedly, it has not helped the Applicant overcome its injury.
- 25. It is also submitted that the Applicant's plan of reducing fixed cost per servicing is erroneous and liable to be rejected. In any event, the Applicant's plan to reduce fixed costs will have an effect of less than 1% on the final costs.
- 27 Capacity utilization cannot be increased as feedstock is not available:
- 28 The Applicant has also stated that it plans to increase captive propylene oxide production capacity; however, the same is ineffectual without adequate supply of the raw material, which is propylene.
- 29 Bulk Transportation of PO will have a very minimal impact.
- 30 The DG (Safeguards) in the safeguard investigation concerning imports of Methyl Acetoacetate vide Final Findings dated 8th October 2013 rejected the adjustment plan provided by the domestic industry observing that it did not contain concrete time-bound plan for positive adjustments and was merely a proposal which it intended to implement in the future. The same situation is applicable in the facts presented by the Applicant in the subject investigation.

b) M/s. Dow Europe GMBH-

1. The present Application has been filed with malafide intention besides being deficient and lacking material particulars and accordingly the applicable rules and treaty obligation mandates immediate termination.
2. As far as Dow is concerned and based on the data submitted in the Importers Questionnaire it is quite clear that there is no surge of imports at all. Imports from Dow Europe have significantly reduced as is evident from the confidential data.

3. The applicant is a habitual user of trade remedies and has been the beneficiary of safeguard and anti dumping duties since 1998.
4. The anti dumping investigations have been initiated at the behest of MPL since 2001. It is quite clear that this is a case of an inefficient industry which relies on a protectionist regime to survive against competition with regard to the subject goods. This is impermissible in law and therefore it was incumbent upon the Directorate General of Safeguards [‘DG’] to take note of this very publicly available information and reject the Application.
5. There is excessive confidentiality in the Application.
6. Gap between demand and supply necessitating exports. Even at cent percent capacity utilisation, MPL will not be able to cater to the demand for the subject goods in India.
7. Imports not substantial to warrant initiation of Safeguard Investigation or imposition of duty:
8. More significant, as far as Dow is concerned and based on the data submitted in the Importers Questionnaire it is quite clear that there is no surge of imports at all.
9. The profitability of MPL has increased during the period of Investigation (2010-14).
10. Based on the Annual reports /balance sheet of the domestic Industry, it is very clear that the gross margin has significantly increased during the POI from 2010-11 to 2013-14. This also clearly justifies an improvement in their profits over the years and not suffering from any financial losses.
11. Based on the annual report /balance sheet of the domestic company it appears that they have increased their polyol capacity from 33000 MT to 50000 MT but clearly mentioned in all their reports is the fact that the polyol installed capacity is grade dependent. Therefore the installed capacity of 25000 MT cannot be taken as only for flexible slab polyol (FSP).
12. It is well established that safeguard and anti dumping duties cannot be used to cover the inefficiencies of the domestic industries and certainly the benefit cannot be used to reward the shareholders. The domestic industry has increased the dividend payout from Rs.0.38 /share (FV :Rs.5) in 2010 to as high as Rs. 0.6/share in 2012.
13. The claim by the domestic Industry that the Propylene Oxide [PO] cost increased during POI but polyol price did not increase due to imports is misrepresentation of facts.
14. MPL has always been uncompetitive as their installed capacity and actual output is not large enough to achieve economics of scale of operations and meet market demands. Therefore in order to cover up the inefficiency the domestic industry has always looked for support using extreme emergency measures like safe guard and antidumping duty for past 15 years.
15. This is also confirmed by the fact that the per capita consumption of flexible slab foam is lowest in the region.
16. Petitioner have already filed for a Anti Dumping petition currently under review and it would be grossly unfair to the industry to have multiple forms of protection at the same time to render the downstream industry potentially totally uncompetitive.
17. No causal link between imports and injury. As demonstrated above any alleged injury to the domestic industry is on account of its own costing inefficiencies, import of raw materials at high costs, inability to cater to the market among other reasons.

(IV). Views of Importers/Users

a) M/s. Springfeel Polyurethane Foams Private Limited

- a. The installed capacity of M/s.Manali Petrochemicas Limited (WPC in short) for the production of flexible slabstock polyol is much less than the demand for the same from various polyurethane foam (PUP in short), situated across India.
- b. MPL is also exporting slabstock polyol to other countries. It can be observed from copies of records available with Customs that the price at which we are importing is very much in line with the prices at which MPL is exporting during the same period of time and that these prices are in line with the international prices in force for the countries in this geographical region.
- c. MPL has a shared production capacity for the manufacturing of the various intermediaries and commodity products that they offer. This kind of shared production capacity implies that a reduction in the production of slabstock polyol does not mean that they have been under utilising their installed capacities. It simply means that they have producing some other product (for example DPG).
- d. A study of their published Balance Sheet and Profit & Loss account for the years 2010-11. 2011-12, 2012-13 and 2013 -14 show profits and have in fact declared dividends to their shareholders.
- e. It is most respectfully pleaded that, The application for Safe Guard Duty made by MPL be dismissed ,
- f. That market dynamics decide the pricing of flexible slabstock polyol,
- g. As manufacturer of flexible slabstock foam we are not over burdened by the unjustified levy of additional duties on the import of polyol.

b) M/s. Tirupati Foam Ltd

- a. We are one of the major producers of Foam using the subjected Polyol.
- b. We strongly oppose the imposition of Safeguard duty on subjected Polyol, as this would lead to huge loss to our Company, Industry and Consumers.

- c. We are forced to import Polyol, not because it is cheaper to import but because the Domestic Supplier namely Manali Petrochemicals Limited is unable to provide us sufficient quantity.
- d. Their supplies are inconsistent and during peak season, we have to suffer if we depend upon the local source only.
- e. We state that the quality of imported Polyol is better than the quality of Polyol supplied by Manali Petro,
- f. It was noticed that the figure of Imports given in petition are different from the ones, used for initiation. The import data is based on custom tariff heading 39072010, which covers all types of Polyols, including those with Molecular weight of less than 3000 as well as more than 4000. On the other hand lot of subject Polyol is imported under Tariff heading 39072090, which is not included in the import data. As the whole initiation is based on wrong import data, the initiation proceedings must be dropped forthwith.

(c) M/s. Sheela Foam Pvt. Limited through M/s. TLC Legal

A. Initiation Notification is at variance with the application filed by domestic Industry as in the present case, the information furnished by the domestic industry was neither adequate nor accurate for purpose of initiation. The Authority has accordingly rejected such evidence and opted to proceed based on DGCIS data, not contained in the application and obtained by the Authority. There are glaring discrepancies between the information furnished by the applicants and that used by the Authority for the purpose of initiation.

B. From the above, it appears that the applicant has furnished incorrect information and for this reason itself, the application was liable to be rejected, as the information contained in the application is neither accurate nor adequate.

C. Information obtained from DGCIS not appropriate for It is submitted that many items falling outside the scope of subject goods i.e., are also being imported under the above heading. Similarly there are Polyols having molecular weight between 3000 — 4000, imported under 39072090.

D. In view of fact that, there is no authentic data to show the exact imports and surge if any, in the imports, the requirement of Section 8B of the Customs Tariff Act read with the AoS are not met.

Compliance of Article XIX of the GATT — Two-fold obligation on the Authority: (i) to identify the developments that were unforeseen and, (ii) establish link as to how those unforeseen developments led to increase of imports. The same has not been established.

E. Compliance of Article XIX of the GATT — Two fold obligations on the Authority: (i) to identify the specific obligation including tariff concessions incurred by India concerning the subject goods under GATT and, (ii) to establish that specific obligation's link with increase of imports of the subject product in India. The same has not been established.

F. India along with other countries agreed to lower the Customs Duties on imports and provided a maximum rate more than which it will not charge Basic Customs Duty. The maximum rate that is agreed is known as "Bound Rate" and that is the rate for which only India has incurred an obligation. Any further reduction in Customs Duties below that Bound Rate is not in terms of any obligation incurred by India. The Bound Rate is 40% and present Customs Duty Rate on import of the subject goods is 7.5% as per Customs Tariff of India 2013-14. Therefore, any increase in import due to reduction of Customs Duty below 40% cannot be attributable to the obligation and tariff concession incurred by India in 1994.

G. No surge in imports: The facts of the present case indicate that there is no cogent evidence on record to show, there is an increase in imports, let alone surge in imports.

G. Incorrect or false information given in application relating to profitability The profit on sales have been increasing continuously since the last two years. It is further requested that the cost of production used by the applicant for determination of profit may be disclosed. The applicant must be called upon atleast to disclose, the basis of allocation of common costs, between subject goods and other products manufactured by the applicant.

H. Unviable adjustment plan. The application gives very sketchy details of the adjustment plan of the domestic producers. It is stated that the levels of capacity utilization would be increased. It is not disclosed however, what structural changes will be made to improve capacity utilization. The plan indicates that, injury, if any is on account of the inefficiencies of the domestic producer.

I. No causal link between fall in profits and imports. This is evident from the fact that there is a consistent decline in the profitability of the Petitioner whether or not imports increase or decrease. Furthermore, any increase in imports over the past few years has been very gradual and not sudden nor significant. In fact even the production and capacity utilization have remained more or less the same in 2012-2013 and 2013-14 indicating a lack of causality between the imports and the injury claimed by the applicants.

J. In the present investigation, there exist other factors as well apart from imports of subject goods coming into India, which may be a cause of injury to the Petitioner.

a) The domestic industry is unable to supply subject goods of adequate quality and consistency. Often the material supplied cannot be used for further production due to inconsistency in quality.

b) The installed capacity of the domestic industry is 25,000 MT, which is about a 1/3 of the total demand in India. The domestic industry is not even able to meet the requirements of one unit, such as the present respondent, and consequently imports become a necessity. The demand supply gap is so significant that this is not a fit case for a safeguard action.

c) Most of the users industry are located in North India, whereas the, manufacturing facility of the Domestic Industry is in South India. The logistic costs for inland transportation are very high and, therefore, the injury is on account of the poor selection of location by the applicant for setting up its unit.

d) The domestic industry is unable to achieve high levels of capacity utilization, not for a lack of demand, but on account of supply side constraints.

e) It is abundantly clear that one of the biggest reasons for rise in imports from these countries is due to Indian Government's own initiative to boost trade with ASEAN countries and according them concessional rates of duties. In para 81 of Gul Ahmed Textile Mills Ltd v Council of European Union (0J C 331, 12.11.2011), EC Court annulled anti-dumping duty imposed on imports of Cotton Type Bed Linen on the ground that the European Commission failed to examine the scheme of generalized tariff preferences on the increase in import of the goods and subsequent injury to the Domestic Industry in EU.

K. Excessive confidentiality claimed.

L. Imposition of safeguard measure not in public interest.

(d) M/s. Allied Foams Private Ltd.

In this connection we submit as below:

1. Dealings with Manali Petrochemicals Ltd: We don't have a good experience of dealing with the Company. They are not able to meet their supply commitment especially during peak season. The quality of Polyol supplied by them is inferior to imported material because it is not BO (Ethylene oxide) capped, whereas the imported material is.

2: In the interest of the PU Foam Industry we request you to reject Manali Petrochemical's appeal for imposing of Safeguard duty on imported Polyol. In case, your office requires any further clarification or information, we would be too glad to provide the same.

(e) M/s. M.H. Polymers

1 We oppose the imposition of Safeguard duty on subjected Polyol for following reasons.

-This would lead to huge loss to our Company Industry and Consumers.

-Domestic Supplier namely Manali Petrochemicals Limited is unable to provide us sufficient quantity.

-The supplies from Manali Petrochemicals are inconsistent and during peak season, we suffer a lot if we depend upon the local source only

-The quality of imported Polyol is better than the quality of Polyol supplied by Manali Petro.

(C) Submissions filled post public hearing:-

The Public hearing in this case was held on 29.9.2014. The domestic industry as well as many interested parties have filed submissions and rejoinders as under:-

I) Domestic Industry :

1. The Domestic industry has reiterated its standing to file the safeguards application on the grounds that they are the only producers commercially producing the goods and the that the representative of Expanded Polymers clarified during the course of the public hearing that they had produced some 6 MT during the POI. The user industry also confirmed in their presentation made during the course of public hearing that the applicant is the only producer of subject goods in the market. Further, the fact remains that M/s. Manali Petrochemicals would still constitute a major share of the total production of the said article in India and will, therefore, fully satisfy the requirements of standing in term of Section 8B (6)(b).

2. The submissions have been made by the aforesaid interested parties after the prescribed time limits and therefore the submissions made with regard to adequacy and accuracy of the information contained in the application and the issues relating to the initiation ought not to be taken on record and the same are required to be rejected.

3. That the Domestic Industry has fulfilled the requirements of Rule 5(1) and (2) concerning the tests of sufficiency, adequacy & accuracy of evidence as obligated by the Rules.

4. The product under consideration in the present application is "Flexible Slabstock Polyol molecular weight 3000-4000. The main uses are in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. The product under consideration is imported and traded under different brand names. It may also be noted that these brands are owned by producer/exporters. Further, the technical specification of these brands can be observed from their respective exporter websites. None of the exporters has disputed the fact that the mentioned brands are not related to subject goods.

5. That the Domestic Industry is entitled to the protection of safeguard duties if there are "increased" imports in the country during the period of investigation. In the instant case, it can be seen that the imports have increased substantially and are at a considerably high and elevated level during the period of investigation.

6. That the DG is obliged to analyze the following factors to determine the serious injury to the domestic industry:

- a. Rate and amount of increase imports in absolute and relative terms,
- b. Share of Domestic market taken by imports,
- c. Changes in level of sales,
- d. Production,

- e. Productivity,
- f. Capacity utilization,
- g. Profit/losses,

7. The imports relative to the production of the DI have increased from 100 indexed points in 2010-11 to 282 indexed points in 2013-14. Similarly, imports in relation to the sales increased from 100 indexed points in 2010-11 to 291 indexed points in 2013-14 and imports in relation to the demand increased from 100 indexed points in 2010-11 to 134 indexed points in 2013-14. From the above, it may be clearly seen that imports have increased in absolute as well as relative terms.

8. The share of imports in the consumption or demand has increased from 60.87% in 2010-11 to 81.93% in 2013-14. It is clear that the increased imports has taken up the share of the domestic industry and if the same trend continues there will be threat to the survival of the domestic industry in the coming years.

9. That from 2010-11 to 2011-12 the sales of DI have increased and decreased sharply thereafter. This decreased sale is both absolute terms and relative to consumption.

10. The domestic industry submits that it has not gained from the growth in the domestic demand and its domestic production has fallen significantly, that from 2010-11 to 2011-12. The production of the DI has increased and thereafter decreased sharply. This fall in production has adversely hit the DI.

11. Productivity followed the same trends as of production, as productivity is measured by the production divided by number of days and if production will decline the productivity will also decline in the same ratio.

12. The capacity utilization has declined from 90% in the base year i.e., 2010-11 to 55% in POI i.e., 2013-14. The reduction in capacity utilization is directly linked to reduction in sales and production due to increase in imports.

13. The profitability of domestic industry has got fully eroded in 2011-12 and thereafter they incurred heavy losses.

14. All the relevant parameters show a decline in the financial position of the domestic industry. In view of the above, unless duties are imposed, the domestic industry would not be able to survive. Serious injury has been caused, as is evident from the above analysis. Further worsening in the condition of domestic industry is imminent.

15. The imports are currently at high levels and increasing.

16. The subject goods continue to be imported in large volumes since 2011-12. The domestic industry witnesses a declining market share and is facing huge losses. The very survival of the petitioner is at stake and the threat of further serious injury is imminent. Causal link between the imports and the serious injury suffered by the domestic industry

17. There is a direct correlation between the increased imports and serious injury caused to domestic industry. The imports were at their highest in 2012-13 and 2013-2014 and domestic industry suffered injury most in these two years. The market share, profitability, return on investment, domestic production of domestic industry declined significantly during this period. The condition of the petitioner has worsened considerably during the period when the imports were at high levels.

18. The above analysis clearly proves that the performance of the domestic industry has worsened in the POI. It is also important to note that the domestic industry is struggling to survive in the market as there is significant price undercutting, price underselling and price suppression from the imports. As stated earlier, profits of domestic industry have also declined drastically in the POI. This clearly indicates that serious injury has been caused and threat of further injury is imminent. The causal link between the imports and injury is also established.

19. There are no other factors which can be attributed to the injury to the domestic industry. The same is further, established by the fact that the demand for subject goods has been increasing consistently over the last three years. There is about 76% increase in demand over the base year and yet the domestic industry has not been able to increase its production, capacity utilization, sales or profits commensurate to this growth in the market.

20. It may also be noted that the interested parties during the public hearing have placed reliance on statements made in the annual reports of various years and have attempted to stretch that issue to the POI in support of their claim that there is no causal link established in the facts of the present case. This issue was subject matter of dispute in several other cases and it has been consistently held that no reliance can be placed on statements made in annual reports. This approach is based on the sound legal premise that what is under investigation is not the company but the product under consideration. The performance of the Domestic Industry has to be judged for the product under consideration alone in terms of the provisions of law.

21. The claim that there is shortage of electricity in Tamil Nadu has been presented in a very generalized manner without giving any evidence to even suggest that the Domestic Industry also suffered on this account. Further, the domestic industry submits that it has three sources of power supply namely, self-generated power (captive power plant), power from 15 State Electricity Board and Diesel Generator set. This gives enough flexibility to the Domestic Industry to ensure that their production does not suffer on account of any shortage in any particular source of power

supply. Therefore, the submission of the interested parties that the domestic industry's production may have suffered on account of power is totally irrelevant and needs to be rejected.

22. In relation to Non Availability of Raw material I.e. Propylene Oxide (PO), it is submitted that the domestic industry has made adequate supply PO for its requirements. The domestic industry is producing PO in-house and also importing the same as and when required. They have also made PO storage facility at ETTL which allows them to import large quantities and use it as per their requirement. In view of the aforesaid, it is submitted that issues relating to availability of key raw material i.e., PO is devoid of any merit and therefore, need to be rejected.

23. The claim of the interested parties regarding certain restrictions in Manali area with regard to increase in capacities, etc., (where the domestic industry's plant is situated) is wrong and hence denied. In this context, it is submitted that the applicant has a total 50000MT capacity of Polyol, which can be directly used for the production of the subject goods. Thus, there is no effect of the restriction on the fact that the Domestic Industry has enough capacity to produce the subject goods and that the effect of dumped imports on the performance of the Domestic Industry, does not get diluted due to certain restrictions in the past. In any case, even the moratorium with regard to increase in capacities was lifted with effect from September 2013. In view of the aforesaid, the issue relating to capacity needs to be rejected.

24. There are also no changes in the pattern of consumption, to suggest that injury is being caused by such factors. Further, demand has also increased therefore, same cannot be said to cause injury to DI.

25. Without prejudice to the above, it is submitted that in any case, it is not necessary that the imports should be the sole cause for injury, provided it can be shown that, it is one of the factors causing injury.

26. From the above, it is clear that there are no other circumstances or factors which are causing injury to the domestic industry.

27. Domestic industry in its application has provided the detailed restructuring plan.

28. In addition to above, it is submitted that the storage facility of PO commissioned at Ennore Tank Terminal Pvt. Ltd. (ETTPL) has started working and domestic industry has already received trial parcels of Propylene Oxide. Moreover, the engineering activity for conversion of ECH (Epichlorohydrin) to PO is under advance stages.

29. In relation to increase in its existing capacity through debottlenecking, it is submitted that due to R&D efforts, DI will be able to debottleneck its existing facilities and will be able to reduce its cost.

30. It is also important to note that the restrictions in Manali area for expansion of capacity removed with effect from September 2013 and domestic industry has already applied for Ministry of Environment and Forests (MOEF) clearance for adding to its capacity.

31. In view of the above, it is submitted that domestic industry has very concrete and reliable restructuring plan.

32. While there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyze unforeseen circumstances in terms of the Indian laws, we understand that the DG may still prefer to analyze the "unforeseen developments". In any case, it may be noted that even in the GATT or the WTO Agreement on Safeguards, there are no specific guidelines or methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments. However, the Domestic Industry has indeed given the grounds for unforeseen circumstances at other places in the application.

33. The Appellate Body decision in the Argentina-Footwear case (WT/DS121/AB/R dated 14 December 1999) held that the phrase "Unforeseen Developments" means the developments which were unexpected. The Appellate Body in Korea-Dairy case (WT/DS98/AB/R dated 14 December 1999) held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

34. It may be appreciated that the Domestic Industry did not anticipate nor could it have predicted that the prices of the subject goods will reduce significantly despite the increase in raw material prices world-wide. These reductions in prices led to sudden increase in imports of subject goods in India as can be seen from the import statistics. The period of sudden decline in prices of subject goods and sudden increase in import quantity coincided with the period when Domestic Industry commenced its commercial production. Further, this price reduction of subject goods has also reduced the capability of Domestic Industry to negotiate better price with the customers.

35. Further, it is submitted that due to Indo-ASEAN FTA and Indo-Singapore CECA, major suppliers made special arrangements to avail benefit of this. It is also important to mention that more than 98% of the imports are coming from Singapore, which is inconceivable in this current open market. This sudden increase of material from one source and that too at non-remunerative prices is unforeseen by the domestic industry.

36. Moreover, the concessions which are being negotiated by the government takes into account particular levels of import volume and the prevailing price levels. If there are significant changes that the negotiators could not have anticipated at the time of negotiations, then certainly it is a case of unforeseen developments. Further, it is important to note that no government or negotiator would be able to anticipate that imports will predominantly come only from a major source after the FTA. The above are the unforeseen circumstances which neither the Domestic Industry nor the negotiators of Indo-ASEAN FTA and Indo-Singapore CECA foresee at the time of negotiation.

37. It is submitted that the major exporters (Shell companies, in particular) have not filed the questionnaire response. It may kindly be appreciated that without filing the prescribed questionnaire, it cannot be said that their participation in the investigation is with the intent to cooperate with the DG.

38. The exporters and importers have claimed blanket confidentiality even with regard to the quantity of exports/imports into India.

39. In view of the above, we request the Hon'ble Designated Authority to kindly issue the Final Findings as early as possible to address the serious injury to the Domestic Industry. Furthermore, we request the Authority to consider all our previous submissions as a part of these submissions which have not been repeated here for the sake of brevity.

II). Views of Exporting Nations:-

1. High Commission of the Republic of Singapore-

i Singapore would like to underscore that while the WTO Agreements permit Members to take remedies, they also seek to ensure that these measures are not abused for protectionist purposes. Safeguard actions envisage domestic industries to make necessary structural adjustments with a view to enhancing competition in the market'.

ii. It is in this context that Singapore notes with concern that the petitioner, Manali Petrochemicals Ltd, has been a frequent applicant of anti-dumping action on Flexible Slabstock Polyols (FSP), including a recent case against Singapore that was terminated in 20112.

iii. In this present case, the company has concurrently applied for antidumping and safeguard measures on the same product. By concurrently claiming injury and seeking remedy through both measures, it appears that the complainant is merely seeking indiscriminate protection from import competition.

iv Singapore contends that the facts of this case, as expounded in subparagraph (v) below, do not support any claim that the increase in imports is as a result of unforeseen developments, especially given the historical upward trend of imports into India and the proliferation of India's downstream industries utilising FSP.

v. Singapore would also like to add that if the petitioner is indeed the sole domestic producer of the product under consideration, as it claims to be, the DGSG must take into account commercial availability of the product under consideration within the Indian market. Several facts attest to the petitioner's inability to fulfil this:

vi. The long list of importers and users who have registered themselves as interested parties⁴ to this case clearly indicate that there is a significant demand for this product that cannot be satisfied by this company alone.

vii Even as anti-dumping measures were in force on imports of FSP from Singapore between 2002 and 2011, India still registered a more than 10-fold increase in imports of these products from Singapore.

viii. The nature of this product, which has multiple end-uses ranging from mattresses to transport seating when converted to polyurethane foam, can only mean that a safeguard action is likely to harm India's downstream producers. This, in turn, would have a negative impact on these producers' ability to build a competitive market share.

(III). Views of Exporters

a) M/s. Shell Eastern Petroleum (Pte) Limited., M/s. Shell Eastern Trading (Pte) Limited and

b) M/s. Bayer (South East Asia) Pte Ltd., submitted submissions, both through Lakshmikumaran & Sridharan, Advocates, 5, Link Road Jangpura Extension, New Delhi – 110014, India

1. The Applicant in the public hearing conducted by DG (Safeguards) admitted that 98% of imports of the subject goods originate in Singapore. In such a situation, the imposition of a safeguard duty will not be appropriate as it will penalize imports from all other countries despite the fact that 98% of imports originate in only one country i.e. Singapore.

2. The Respondent submits that any issues arising out of imports of the subject goods from Singapore may be addressed in the anti-dumping investigation. In light of the above, the present safeguard investigation should be terminated.

3. India-ASEAN FTA and the India-Singapore CECA provide for specific guidelines to be followed in cases of safeguard investigations initiated under the two agreements respectively. Both the India-Singapore CECA and India-ASEAN FTA have distinct regimes for the imposition of bilateral safeguard measures, with additional mandatory requirements to be complied with.

4. The Applicant is a serial user of trade remedy proceedings, whereby one should question whether these proceedings are being abused by the Applicant. It has been involved in anti-dumping proceedings since 2001, in addition to safeguard proceedings in 1998.

5. Annex to Rule 8 the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred as "Indian Safeguard Rules") rule puts onus on the DG (Safeguards) to refer complaint to the antidumping/anti subsidy authority to investigate the matter which is said to cause injury to the domestic industry which cannot be attributed to increased imports. It has been demonstrated in the present submission that injury (if any) suffered by the

Applicant is due to factors (*other than increased imports*). Therefore, DG (Safeguards) must terminate the present safeguard investigation.

6. The petition is also deficient as it contains a number of unwarranted confidentiality claims.

7. In the present investigation, the Applicant has neither provided any statement of reasons nor appropriately summarized any of the evidence referenced. The Applicant has also not offered an explanation as to why or how the release of said information would prejudice the legitimate commercial interests of the Applicant.

8. To the extent the Applicant's confidential information cannot be verified for relevance, accuracy and completeness, it should be disregarded. In the interests of natural justice, we respectfully submit that the DG (Safeguards) must direct the Applicant to provide a revised and proper NCV of its petition.

9. The Respondents request the DG (Safeguards) that the information indicated above, comprising of import data, product information, price details, manufacturing process etc., be provided to us so that meaningful comments may be made regarding the claims of the Applicant.

10. The Applicant has claimed in the petition that it is the sole producer of the like article in India. However, the Respondents would like to submit that M/s. Expanded Polymer Systems might also qualify as a producer of the like article in India. They have not been communicated by the Applicant anywhere in the petition.

11. The Authority is required to examine the quantity of the subject product which is or can be manufactured by M/s. Expanded Polymer Systems. Additionally, it is also submitted that such information should have been disclosed by the Applicant in the petition and the Authority should appropriately terminate this investigation for want of completeness of petition. The Respondents submit that the Authority is required to verify the standing of the Applicant in this case.

12. The DG (Safeguards) has initiated the present safeguard investigation relying upon the transaction wise DGCI&S data. The Applicant has relied upon the import data obtained from "The EximNet BBS". Further, it has been stated by the Applicant that the transaction wise DGCI&S data is also not available. Thus, the petition filed by the Applicant and the initiation notice issued by the DG (Safeguards) are based upon completely different sources of import statistics.

13. From paragraph 5 of Initiation Notice, it can be also observed that the DG (Safeguards) has verified the other safeguard injury parameters for the injury analysis period. However, the same have not been provided to the other interested parties for their comments. Further, the Respondents are also apprehensive that the petition filed by the Applicant has not been updated in terms of the DG (Safeguards) verified injury parameters. Therefore, in line with our earlier request dated 16th June 2014, we request the DG (Safeguards) to direct the Applicant to withdraw such petition, or in the alternative, instruct the Applicant to correct the petition based upon the DGCI&S data with any relevant substantiations and provide the same to other interested parties for their comments.

14. For a proper analysis of all the claims in the petition, it is requested that either the DG (Safeguards) or the Applicant shall provide the transaction-wise raw import data as well as sorted import data to interested parties in MS-Excel format. The DG (Safeguards) is also requested to direct the Applicant to provide an explanation as to how it has sorted data from the raw data. The above information is vital to analyse the trend of the imports of the subject goods into India during the injury analysis period.

15. The Respondents submit that there are numerous inconsistencies between the data submitted by the Applicant in its petition for imposition of anti-dumping duty, and the data provided in the Initiation Notification dated 22nd May 2014 communicating the initiation of safeguard investigation against the subject goods.

16. In the present investigation, the product under consideration only includes Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000. However, some import transactions also show that Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 5000 has been included in the import statistics. The Respondents are apprehensive that there may be many such transactions in the import statistics which would enlarge the import quantity significantly. The Respondents request the DG (Safeguards) to investigate the same.

17. It is submitted that MS-Excel version of import data is also relevant because there exists double counting and duplication of imports which has resulted in inflated volume of imports from Singapore. At the outset, this conflict is to be resolved before drawing any conclusions from such import data.

18. The Respondents contest the annualized figures arrived at by the authority for 2013-14 on the ground that such figures are inaccurate and liable to be rejected. It is noted that the annualized figures provided in the initiation notice are inflated and do not reflect the correct position.

19. At Page 28 of the NCV of the petition, in reply to Question No. xii in Section 3 to Questionnaire for domestic producers, the Applicant has submitted that they do not offer any discounts. As per market intelligence, it is understood that the Applicant in fact offers discounts to their customers. The Respondents request the Authority to verify this fact.

20. The applicant has also not disclosed the methodology followed for determination of fair market price.

21. It is submitted that the initiation notice as well as the petition are silent on the aspect of unforeseen developments that have led to increase of imports of the subject product into India.

22. Pursuant to its obligations under the GATT, India may not impose a safeguard duty unless it can be demonstrated to the satisfaction of DG (Safeguards) that supposed increased imports and consequential injury arise as a result of unforeseen developments and of the effect of obligations incurred by India under the GATT.

23. The DG (Safeguards) in prior investigations, has consistently examined the requirement of unforeseen developments. In fact, in China specific safeguards initiated by the DG (Safeguards) on Hot Rolled Flat products of Stainless Steel of 304, the DG (Safeguards) found that no unforeseen development existed in that case. The DG (Safeguards) accordingly recommended that no safeguard duty be imposed.

24. Therefore, the Applicant has to show how certain developments were unforeseeable when India incurred the obligations under GATT in 1994, which have led to the increase of imports in the period of investigation. If the Applicant fails to explain the same, the burden still remains on the Authority to carry out the above analysis. Failure to do so would render the subject investigation liable to be terminated.

25. It is submitted that neither the petition, nor the initiation notification for the subject investigation has identified any unforeseen developments that led to an increase in imports of the subject product.

26. The Respondents submit that Article XIX of the GATT 1994 places a two-fold obligation on the Authority with regard to the subject investigation. Firstly, it requires the Authority to identify the specific obligation including tariff concessions, incurred by the member country, India in this case, concerning the subject product under GATT. Secondly, it requires the Authority to establish a causal link between the aforesaid specific obligation and increase of imports of the subject product into India, thereby analysing the effect of the obligation that causes or threatens to cause serious injury to the domestic industry. Failure to do the same would render the subject investigation liable to be terminated.

27. Even if the Applicant fails to explain the same, it is submitted that the obligation remains on the Authority to analyse this issue and give a finding in this regard. Failure to do the same would render any finding by the Authority inadequate, unreasonable and non-compliant with the obligations under Article XIX of the GATT.

28. In light of the above submissions, the Authority may be pleased to terminate the subject investigation. It is submitted that termination of the subject investigation would restore the confidence of traders and governments of other countries in India's administrative and judicial procedures, thereby preserving the legitimate expectations of all parties concerned.

29. The Respondents submit that the increase in volume of imports may be attributed to the Comprehensive Economic Partnership Agreement ("CECA") presently in existence between India and Singapore. The tariff concessions received by way of the India-Singapore CECA made it attractive for imports of the subject goods into India from Singapore.

30. The Respondents submit however that an increase in imports due to the tariff liberalization under the India-Singapore CECA cannot be considered to be an unforeseen development or an obligation under GATT. The timetable specifying the rate of reduction of anti-dumping duty was publicly available soon after the conclusion of the India-Singapore CECA in June 2005. Therefore, there is simply no way in which it could not have foreseen that the duty rates on the subject goods would be progressively reduced as per the timetable specified in India's schedule of commitment under that Agreement. An increase in imports due to the 0% duty under the India-Singapore CECA cannot be an unforeseen development or an obligation under GATT as per Article XIX of GATT. This issue is squarely covered by a recent WTO panel decision in DS 415-418 *Dominican Republic – Safeguard Measures* wherein the panel concluded that to the extent, the obligation in issue undertaken by Dominican Republic was that under a regional free trade agreement rather than that under the GATT, the requirements of Article XIX were not met. For this reason also, the above argument deserves to be rejected.

31. The position of law is quite clear on the fact that the increased imports must be recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough. In the present case, the imports are not recent, sudden, sharp and significant, because of which the threshold criteria itself is not met.

32. The applicant industry has presented no credible evidence to make out a case of serious injury. It has withheld crucial injury information on a number of factors. Furthermore, the facts presented in the application itself do not make out a case of serious injury.

33. It may also be noted that the Applicant has sold almost all the quantity of the subject goods that it has produced, given that sales as a percentage of production was 101% in 2010-11, 99% in 2011-12, 96% in 2012-13 and 98% in 2013-14. This establishes that the Applicant has no problem in selling the subjects; its issues lie in production.

34. As per the data provided by the Applicant, the production of the subject product by the Applicant has increased from 16510 MT in 2010-11 to 18381 MT in 2011-12, and undergone a slight decline with 13986 MT in 2012-13 and 13812 in 2013-14. The sales of the subject product by the Applicant increased from 16615 MT in 2010-11, to 18192 MT in 2011-12 and underwent a slight decrease with 13451 MT in 2012-13 and 13474 MT in 2013-14.

35. However, it is submitted that the reason for the decline in production and sales during 2012-13 and 2013-14 is not due to the volume of imports, but the non-availability of feedstock for the production of the subject product. It is noted that there is a severe shortage of Propylene Oxide (PO) which is the feedstock used for the manufacture of the subject product.

36. The Applicant procures propylene from CPCL, who is the sole supplier of propylene to the Applicant. Such quantity is also limited by way of a maximum amount beyond which CPCL does not supply any more propylene. Therefore, with such a cap on supply of propylene by CPCL to the Applicant, it can only manufacture a certain amount of the propylene Oxide (PO) and use PO in manufacture of subject product and not more.

37. At the outset, the Respondents submit that the veracity of the capacity provided by the Applicant is in doubt. The Authority is requested to investigate and clarify the contradictory data provided by the Applicant.

38. There are two reasons for reduction in capacity utilization:

1. Lack of availability of feedstock Propylene Oxide (PO) as highlighted above which would lead to non-utilization of capacity and a reduction in capacity utilization;
2. Increase in capacity of the Applicant by 36% which would also obviously lead to a reduction in the capacity utilization.

39. Any reduction in capacity utilization is attributable to the lack of availability of the feedstock (PO) for the manufacture of the subject product. The Applicant, in Annual Report 2010-11, has admitted that the reduction in capacity utilization is due to shortage of PO.

40. In the initiation notice, indexed figures relating to profitability have been indicated to be 100 indexed points in 2010-11, with a rapid and substantial increase to 324 indexed points in 2011-12 and a decline to (331) indexed points in 2012-13 and (559) indexed points in POI. Similarly, in the petition filed by the Applicant, the selling price has increased from 100 indexed points in 2010-11 to 115 indexed points in 2011-12, reduced to 110 in 2012-13 and again increased to 128 indexed points in 2013-14.

41. With regard to cost of sales, it increased from 100 indexed points in 2010-11 to 120 indexed points in 2011-12, reduced to 102 indexed points in 2012-13 and once again increased to 124 indexed points in 2013-14. It is not possible for profitability to triple when there is an increase in cost of sales, but plummet rapidly when cost of sales decreases. The trend reveals that the data relating to profits may not be accurate, and in light of the same, the Respondents request the DG (Safeguards) to investigate the same.

42. At the outset, the Respondents challenge the veracity of the profitability figures provided in the initiation notice. It is noted that the Applicant has filed an application for the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject product. The profitability figures provided in the anti-dumping petition are at odds with the figures provided by the Applicant in the subject investigation.

43. The Respondents also wish to highlight that the above is further confirmed by the fact that the Applicant was able to sell, as a percentage of its production, 101% in 2010-11, 99% in 2011-12, 96% in 2012-13 and 98% in POI. Therefore, there are no issues to the Applicant as far as proportion of sales and production is concerned; it is the non-availability of the feedstock (PO) that has resulted in reduced profitability.

44. Price undercutting, depression and suppression data has not been indicated even in indexed form in the NCV of the petition filed by the Applicant. The Respondents cannot make any meaningful submissions on the same without any data.

45. On Page 179 of the petition containing the Annual Report 2012-13 of the Applicant, the Applicant has stated that the availability of bio mass fuel for the Captive Power Plant (CPP) had become scarce, which forced the Applicant to operate the CPP at lower loads. Thus, if any injury is proved to exist, it is a direct consequence of the production constraints experienced by the Applicant.

46. The Respondents submit that even if the Applicant wishes to increase capacity in order to cater to the demand, the same cannot be carried out as per the Applicant's own admission that the moratorium in the Manali area denies any scope of capacity additions. The Applicant has admitted this fact in its Annual Report 2012-13, provided on page 180 of the petition.

47. That even if the Applicant were to operate at 100% capacity utilization, at best, it will be able to cater to only about 34% of the market, because it only has installed capacity of 25000 MT while the total demand during 2013-14 was 74624 MT.

48. The Respondents submit that the Authority is also required to establish a causal link between such "increased imports" and "serious injury" to the Applicant, as per Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 read with Rules 5 and 11 of the Indian Safeguard Rules. Without such a causal link, no safeguard duty can be imposed in the present investigation.

49. However, from the submissions of the Respondent above, it is clear that any "serious injury" that may have been sustained by the Applicant is due to a number of other factors such as:

1. Lack of feedstock availability;
2. Consequent reduction in production and sales;
3. Dependence on sole supplier Chennai Petroleum Corporation Ltd of propylene in India to the Applicant; and
4. Inability of the Applicant to supply the required quantity of the subject product.

None of the reasons are in any way linked to import volume of the subject product. Therefore, the causation analysis fails in the present investigation and the same is liable to be terminated.

50. An adjustment plan is an essential requirement in a safeguard investigation. While the adjustment plan has been claimed to be non-confidential by the Applicant, almost the entire details of adjustment plan have been kept confidential in the petition by the Applicant.

51. There are no details which have been indicated that can enable the Respondents to make any comments on the same. The Respondents cannot make any meaningful submissions on the adjustment plan without any information and it is requested that the Authority provide us with the details of the adjustment plan.

52. The Applicant has stated that it will take measures to increase capacity utilization due to de-bottlenecking of existing capacity. However, as per the admission of the Applicant, it has already completed such an exercise and admittedly, it has not helped the Applicant overcome its injury. Therefore, this portion of the adjustment plan, is redundant. The relevant extract is provided in Annual Report 2010-11, on page 103 of the petition.

53. In this regard, it is also submitted that the Applicant's plan of reducing fixed cost per MT is erroneous and liable to be rejected. In the table given in adjustment plan, the Applicant after making the above claim has listed utilities/consumables/labour costs, which are variable costs and not fixed costs. In any event, the Applicant's plan to reduce fixed costs will have an effect of less than 1% on the final costs.

54. The Applicant has stated it plans to achieve an increase in its capacity utilization levels. However, the Respondents have already established that the Applicant has a severe shortage of Propylene and PO, which the Applicant has not been able to overcome. Therefore, it is again redundant that the Applicant plans to achieve an increase in capacity utilization, as such an increase cannot be achieved without adequate supply of PO.

55. The Applicant has also stated that it plans to increase captive propylene oxide production capacity; however, the same is ineffectual without adequate supply of the raw material, which is propylene. Without adequate supply of raw material, the Applicant's plan of increasing captive propylene oxide capacity is a feeble attempt.

56. The Applicant has stated that it will implement bulk transportation of PO and improvement in logistics. The Respondents submit that this attempt will also affect only a marginal reduction in transportation cost and will not have any overall effect on the costs incurred by the Applicant.

57. The DG (Safeguards) in the safeguard investigation concerning imports of Methyl Acetoacetate vide Final Findings dated 8th October 2013 rejected the adjustment plan provided by the domestic industry observing that it did not contain concrete time-bound plan for positive adjustments and was merely a proposal which it intended to implement in the future. The same situation is applicable in the facts presented by the Applicant in the subject investigation.

58. It is also beyond doubt that the Applicant has been a user of anti-dumping and safeguard remedies for the past 16 years. Despite such protection having been provided to the Applicant, it has not been able to improve its performance, which establishes the fact that any injury suffered by it is due to its own intrinsic factors. For such reason also, we request the DG (Safeguards) to reject the adjustment plan provided by the Applicant and terminate the investigation.

c) M/s. IRPC Polyol Co., Ltd., 555/2, Energy Complex, Building-B, 7th Floor, Vibhavadi Rangit Road, Chatuchak, Bangkok-10900, Thailand submitted written submissions dated 24.9.2014 wherein they submitted that they had exported lower than 2% of the total import volume to India.

d) M/s. Dow Europe GMBH and M/s. Dow Chemical International Pvt. Ltd submitted submissions through M/s. Dua Associates, 202-206, Tolstoy House, Tolstoy Marg, New Delhi.

1. The instant submissions are further to the preliminary submissions filed by DCIPL and Dow Europe submitted on 25 July 2014 and the power point presentation made on 29 September 2014.

2. The instant case is unique. It demonstrates how the sole producer of the subject goods has repeatedly sought trade remedy protection from the Directorate General of Anti Dumping ('DGAD') and from Directorate General, Safeguards ('DG') over the last 15 years.

3. It is submitted that the Annual Reports and Balance Sheet available for the period of investigation ('PoI') portrays a robust and profitable image of the company.

4. The data available clearly demonstrates that imports are necessitated due to the market demand and the fact that the Domestic Industry is able to only cater to a fraction of the domestic demand. Any decline in profitability, if at all is due to factors unrelated to imports such as suboptimal cost structures, dependence on imports for raw materials among other factors.

5. The condition precedent for imposition of safeguard duty is the importation of the PUC into India in such increased quantities and under such conditions. Reference may be made to applicable legal provisions in this regard,

6. The imports are neither sudden, nor sharp or significant enough to satisfy the condition set out in Article 2 of the Agreement on Safeguards. In fact, during the years 2011-12 and 2012-13 the imports actually have declined when comparing with the base year.

7. Further the growth in the imports is in response to the increase in the domestic demand of the PUC and the inability of the Domestic Industry to meet this demand. Any increase in imports is only in response to increased demand of the PUC.

8. It is quite clear that the increase in imports is line with increase in demand of FSP in India. The fact that DI can only satisfy only a fraction of the demand is important since imports will prevail even if Manali is producing PUC at cent

percent capacity. The imports are neither sudden nor are they sharp. In fact in the years 11-12 and 12-13 imports have significantly declined.

9. Per Article 2 of the Agreement on Safeguards, imports of the PUC into India are required to cause 'serious injury' to the Domestic Industry. "Serious injury" means a significant overall impairment in the position of a domestic industry.

10. One of the parameters based on which the Domestic Industry has claimed serious injury is decline in capacity utilization. Domestic Industry has claimed a decrease in capacity utilization from 90% in base year to 55% in 2013-14 (annualized). This alleged decline in capacity utilization is not related to imports. Domestic Industry increased overall polyol capacity from 33000MT to 50,000MT. (page 103/127, DI Application, Annual Report). However expanding Polyol plant capacity does not serve the purpose without increase in Propylene Oxide capacity.

11. Domestic Industry claims installed capacity of 25,000MT for the PUC. However this capacity is not exclusive to the PUC. The reason for this is:

- a. It is known that Polyol plants typically tend to be multi product swing capacities that can very easily switch from one grade to another literally on a day to day basis. This is true for the whole industry and every producer globally swings capacity to produce grades based on the market dynamics.
- b. The allocation of cost in the case of such a multiproduct operation to one particular product amongst the total product mix has the potential to be distorted.
- c. In the instant case, Domestic Industry has a shared production line. The declining capacity utilization for PUC is therefore a result of the business decision of Domestic Industry to utilize the plant for other polyols for more lucrative markets/applications rather than the PUC. Therefore quite clearly decline in capacity utilization is not related to imports and is squarely attributable to the business decisions of the Domestic Industry.

12. Another plausible reason for decline in capacity utilization is the capacity for the PUC could also have been diverted to the export market. The Domestic Industry in its Director's Report for 13-14 states: 'The export sales increased from 2.83 crores to 17.58 crores highest ever recorded'.

13. From the financials of the Domestic Industry, it can be seen that the Company's exports have surged 600% from 2.51 Crore in 2010-11 to 17.58 crore in 2013-14 which confirms the intent of domestic industry to focus more on export of high value specialty Polyol utilizing the same asset instead of producing commodity FSP for the domestic market.

14. Further the Domestic industry cannot achieve economies of scale as some of the overseas players. The reason for this is that economies of scale in the polyol industry can only be achieved if the installed capacity of the plant is between 200,000MT to 400,000MT (approx). The domestic industry's plant with overall polyol capacity of 50,000MT is bound to be cost ineffective and can only use obsolete technology. Further Domestic Industry is also dependent on Propylene Oxide imports which expose them to high cost of production.

15. Domestic industry claims severe depletion of profits. However the Annual Reports and balance sheet show year on year profit and growth notably even in the polyol sector. Though Domestic Industry has claimed decreasing production and sales of the PUC, the Domestic Industry has failed to state that they have utilized the facility to produce other grades of Polyol which is the main reason for increase in revenue of Polyol sales. Therefore domestic industry should not show the PUC in isolation but declare profitability segment wise (for the polyol segment). Only if the entire Polyol segment is suffering, can it be said that there is a substantial injury or loss to the Domestic Industry.

16. The statements made by the domestic industry in their annual reports for year 2013-14 regarding profitability are extracted below for ease of reference:

"Operational Highlights (page 2)

During the year under review the operations of the Company were better than the previous year in spite of cut-throat competition from overseas polyol suppliers.... The net profit for the year was higher by about 6% at Rs. 29.05 crore against the Rs. 27.32 crore in the previous year. Industry Structure and development (page 2) ...Indian Polyurethane industry's performance during 2007-2012 had been impressive with double digit growth, but the market has become stagnant in 2013 due to various factors like overall economic growth slowdown, impact of global economic crisis on Indian manufacturers, inflationary pressures, monsoon failure, etc. Some revival was seen during the year under review. "

17. The Annual report for year 2012-13 of the Domestic Industry highlights following points:

- This is a cyclical industry with peak and off peak periods.
- The market depends on growth /consumption pattern

- Domestic Industry itself achieved highest Sales in 2011-12 with a decline immediately next year, not due to imports but admittedly due to reduction in economic growth.
- WTO has scaled down global trade growth forecast to 3.30% in 2013 from 5.11% in 2011. Therefore the alleged lack of profitability is evidently not import related.

18. Even though the Domestic Industry claims steep decline in profitability. It has still rolled out yearly dividends for its shareholders as evident from its Annual Reports and Balance sheets. A company with such severe profitability decline is usually not in a position to roll out dividends in the manner in which the Domestic Industry has in the POI.

19. Domestic Industry claims decrease in production from 16,510 MT in 2010-11 to 13,811 MT in 2013-14. However the reason for decrease in production is not related to imports but due to lack of raw materials:

- a. Domestic Industry has large dependence on Chennai Petrochemical Corporation Ltd (CPCL) sole supplier of propylene. CPCL itself has supply shortage issues as Domestic Industry acknowledges in its Annual Report 2010-11 at page 103 of the Application.
- b. Need to import Propylene Oxide. The import of Propylene Oxide is at a high cost and this makes the cost structure of the Domestic industry for the PUC sub optimal. The statements above are indicative of the fact that any decline in sales, production, profitability is inter-alia on account of lack of availability of key raw materials, Domestic Industry's business decisions and its sub-optimal cost structure.

20. The dip in Domestic Industry's market share is marginal of a single digit figure of 6% when comparing base year and current year. It may also be noted that even at cent percent production, Domestic Industry is only able to cater to a fraction of the domestic demand of the PUC, and therefore imports are necessary. Additionally, the product of the domestic industry suffers from the vices of erratic supplies, failure to meet timely commitments to consumers and quality issues. Therefore loss of market shares is not an indicator of injury to the domestic industry.

21. The Domestic Industry was able to move a significant amount of stock comparing the years 2012-13 and the current year.

22. The Domestic Industry claims that employment has shown a declining trend during the POI, however, the decline has no correlation with the imports of the PUC. The decline in the number of employees could be due to multitude of factors unrelated to imports such as: It is well known that typically when there is upgrade of technology there might be reduction in people and in this case Domestic Industry has admittedly increased the overall polyol plant capacity during POI. Domestic Industry may have reduced people by reducing the number of employees on the pay roll and employing more contract labour. The Polyol plant has multi swing capacity and actual apportionment of employment for the PUC needs to be validated.

23. It is settled that both under WTO law and municipal law there is a requirement to establish a causal link between Imports of PUC and alleged serious injury to the Domestic Industry as per rules 5 and 11 of the Safeguard Rules and 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975 and Article 4 (b) of the Agreement on Safeguards.

24. Based on all that has been discussed above, it is a legal requirement for the Domestic Industry to establish on the basis of evidence that there is a causal link between increased imports and the serious injury to the DI. However based on the facts and figures available in the matter no causal link has been drawn between the imports of the PUC and the alleged serious injury to the Domestic Industry.

25. Alleged loss of market sales, production and profitability, capacity utilization even if correct, is based on other factors: Scarcity of PO and propylene the main raw material for the PUC is import dependent and therefore cost efficiencies are sub optimal leading to decline in profits, Admitted cyclical nature of the industry and general economic slowdown. Domestic Industry is a monopolist and therefore has no incentive to improve cost efficiencies. Imports are inevitable due to the huge demand-supply deficit. Even producing at cent percent capacity Domestic Industry is able to cater to 25%-30% of the domestic market. Admittedly DI also face issues of power shortage which effects profitability. In Annual Report of 13-14 Domestic Industry acknowledges 'the company went in for purchase of power through energy exchanges and third parties to meet the shortfall. These resulted in higher cost of power and consequently the profitability was also impacted'.

26. The Domestic Industry is a habitual protection seeker and has been the beneficiary of safeguard and anti dumping duties since 1998. It is obvious that the Domestic Industry relies on the imposition of anti dumping duties and safeguard duties to compete in the market. Both in Anti dumping and Safeguard jurisprudence, it is quite clear that imposition of duties is to create a level playing field for the Domestic Industry and not a means of supporting an inefficient domestic industry through an oppressive tax regime.

27. It is quite clear that this is a clear case of an inefficient industry which relies on a protectionist regime to survive against competition with regard to the subject goods. This is impermissible in law and therefore it was incumbent upon DG to take note of this very publicly available information and reject the Application of the Domestic Industry. Even the mere initiation of the instant investigation is bad in law.

28. From a perusal of the non-confidential version of the Application, it becomes quite clear that excessive confidentiality has been claimed by the Domestic Industry.

29. Such measures have adversely affected the end users and almost 47 companies have shut shop during the period as they were not competitive due to the domestic producer. On an average a foaming plant has 15-20 employees and over 900 people have lost their jobs due to imposition of anti dumping and safeguard duties.

30. Further, the price of polyol in India is the highest in the Asia pacific region and therefore imposition of safeguard duty on the PUC would make the product even more expensive and harmful for the downstream user industry.

31. It is therefore submitted that the Learned DG should take into account the larger public interest and decline the imposition of safeguard duty on the PUC. It is quite clear that no public interest would be served by imposition of safeguard duties in fact the same would lead to closure of user industries and consequent unemployment.

(IV). Views of Importers/Users

(a) M/s. Sheela Foam Pvt. Ltd., submitted submissions through M/s. TLC, Legal R-163, 2nd floor, Greater Kailash-1, New Delhi.

1. Petition as well as the submissions made during the Public hearing are at variance with the Initiation notification

a. In para 2 of the initiation notification, it is mentioned that the domestic industry has claimed to be the sole producer of the PUC in India. However at the time of Public hearing, the Applicant admitted to the existence of another producer of the PUC. Thus, the initiation is based on a faulty presumption that the Applicant is the sole producer of the subject goods, whereas admittedly there is another manufacturer of subject goods in India.

b. In para 3 of the initiation notification, it is stated that the PUC is classified under Customs sub-heading 39072010 and the imports under the said heading only has been considered. However, during the public hearing the Applicant contended that the PUC is being imported under heading 390720 90 also and relied on import data which included imports under both the headings.

c. In para 5 of the initiation notification, it is stated that the import data obtained from DGCIS has been considered. The applicant in their petition as well as during the public hearing has made submissions based on data procured by them from an alternate source and has not referred to DGCIS data considered by the authority. It may be noted that the data collected from the two sources have glaring discrepancies not only in quantity terms but also in rate. The two data show entirely different trend of increase in imports.

d. In para 7 (b) of the initiation notification it is stated that the Installed capacity of the Applicant currently is 25000MT. However, during the public hearing the Applicant has contended that it has a capacity of 50,000 MT.

e. In para 7 (c) of the initiation notification the data relating to Demand of PUC in Indian market and the market share of the DI and Imports have been given. The said data is at total variance with the data mentioned in the petition and with the submissions made at the time of Public hearing.

f. In the petition filed before the Anti-dumping authorities, the applicant has contended that its profitability has reduced by 20% in 2011-12 as compared to 2010-11. However, in the data submitted before the DG Safeguards, the applicant has claimed a 224% increase in their profitability in the same period. The relevant page of the Petition (NCV) filed by the Applicant before DG Anti-dumping is enclosed herewith and marked as Annexure-1.

2. From the above, it is clear that the data relied by the applicant in the Public hearing and in the petition are at huge variance with the data based on which the DG Safeguards has initiated the investigations. As the domestic industry itself is not in agreement with the data contained in the initiation, the initiation is liable to be terminated on this count only. Further, such discrepancy raises doubts on whether a detailed verification of the data submitted by the applicant has been carried out. In such circumstances, the initiation gets tainted with suspicion and should be terminated.

3. It has been contended by the applicant during Public hearing that the information contained in the petition need not be 100 percent accurate. In this regard, it is submitted that the Rule 5, of the Safeguard Duty Rules provides for the manner of initiation.

4. In terms of Rule 5 that the application must provide evidence of increased imports, serious injury to the domestic industry and causal link between the imports and the alleged injury. It further provides that the Authority shall not initiate an investigation, unless he examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application.

5. In the present case, the information furnished by the domestic industry was neither adequate nor accurate for purpose of initiation. The Authority has accordingly rejected such evidence and opted to proceed with import data from DGCIS, not contained in the application and obtained by the Authority. There are glaring discrepancies between the information furnished by the applicants and that used by the Authority for the purpose of initiation.

6. Even if a view is taken that the investigations should be continued with, the domestic industry must be asked to amend the petition, as per the correct data, and thereafter fresh initiation should be done, if warranted and a Public hearing be held subsequently. Not doing so would be a gross violation of Principles of natural justice. Applicant enjoying benefit of various duties for past 16 years

7. Manali has got protection of duties against imports. At present also, along with the application for imposition of Safeguard duties, Manali has filed two other applications seeking imposition/extension of Anti-dumping duties. What is surprising is that inspite of getting protection of duties for so long, Manali is still unable to adjust to the imports. It is not clear how safeguard duty for a further period of three years is going to help Manali adjust, if it could not do the same in past 16 years.

8. From the submissions made in the petition, it is not known whether the applicant proposes to increase its capacity or to improve on its levels of capacity utilization. The applicant has submitted in the petition that in the year 2013-14 they had an idle capacity of 45%. It is not clear how increasing the capacity is going to help Manali, if it is not in position to utilize its existing capacity. In any case, no information whatsoever has been submitted by the applicant as to how and by when it proposes to increase its capacity or levels of capacity utilization.

9. Further, a generic statement that the capacity would be increased by debottlenecking does not give any credence to the applicant's adjustment plan. Neither in petition nor in its submissions during Public hearing, has the Applicant mentioned any cogent measures that Manali plans to put in action to adjust with the imports.

10. At best, the game plan appears to be to increase the sales and production during currency of the Safeguard duty, thereby reducing its fixed costs. It is a natural corollary that once Safeguard duty is imposed, under the protection of the duty Manali's sales and production will increase. However, since Manali has no real plan to adjust and bring itself /its product at competitive level as compared to the imports, once the duty is removed Manali's sales, production and capacity utilization will go back to original level.

11. The applicant has further contended that they plan to adjust by bringing improvements in bulk transportation and logistics of Propylene Oxide (raw material). It may be seen that the Adjustment plan submitted in 1998 before the DG Safeguards, was also to improve the logistics relating to the raw materials. It appears that since then the applicant was aware that the raw material transportation is a bottleneck for them, and adjustment on this account should have been done long back. However, evidently they have so far been unsuccessful in solving their raw material problem. It is not known what exceptional steps they plan to undertake to solve this problem in next 2 or 3 years.

12. Further, the applicant has contended that it plans to increase capacity of Propylene Oxide production facility. However, in their Financial Report for 2012-13, it is stated that bulk storage/handling facility for PO would become operational by Quarter 3 of 2012-13. Thus, since the increased capacity has already been put in place in 2012-13 only, it is not clear how this can be a part of adjustment plan. Safeguard duty is a protection given to a domestic industry to put its adjustment plan in action. As the proposed plan seems to be already in place, there is no requirement for imposition of duties.

13. Thus, it is not clear whether the applicant proposes to adjust by increasing capacity for PUC or for the raw material or by increasing its capacity utilization levels. In any case, increasing capacity is not going to help in reducing cost of production. No submission has been made as to how Manali plans to reduce its costs, making its sales in domestic market viable.

14. Further, the inability and unwillingness of the applicant to adjust to the imports is evident from the fact that they have not undertaken the necessary steps to compete with the imports, even after enjoying duties for past 16 years. Even the present adjustment plan appears to get higher level of sales, production and capacity utilization during the currency of the duty. Once the duty is removed, the applicant will again go back to its original position and might be

filing another petition before the authority to provide further protection, at the cost of various other importers, who are also a part of Indian industry.

15. It is a settled law now that safeguard duties can be imposed only where it is shown that subject goods are imported into the country at such increased quantities as to cause or threaten to cause serious injury to domestic industry.

16. The DG Safeguards has initiated the investigations based on the import data obtained from DGCIS. From the data as available on record, it appears that the all imports of heading 3907 20 10 have been considered as imports of “subject goods”. It was informed that transaction wise data has not been obtained.

17. It is submitted that many items falling outside the scope of subject goods i.e., are also being imported under the above heading. [Poly (ether) alcohols of different types and having molecular weight less than 3000 or more than 4000 are also covered under this heading] . Additionally, subject goods are being imported under other sub headings. It is submitted that in order to determine the quantum of imports of subject goods, transaction wise information may be obtained from DGCIS and only transactions relating to subject goods, be considered for purposes of the investigation.

18. Thus, there is no cogent evidence on record to show, there is an increase in imports, let alone surge in imports. It has already been submitted in detail, that considering the product under consideration, the Authority has to examine the transaction wise information relating to the imports, before coming to any conclusion on the quantum and trends in imports.

19. In view of fact that, there is no authentic data to show the exact imports and surge if any, in the imports, the requirement of Section 8B of the Customs Tariff Act read with the AoS are not met. As the initiation is not based on information which is accurate and adequate for prima facie determination on the surge in imports, the same should be terminated.

20. During the Public hearing, the Applicant submitted that the Petition need not be 100% accurate. It is not clear how much accuracy would be considered to be adequate by the applicant.

21. The applicant has claimed in the petition that they are the “only producer of the subject goods in India”. However, during the Public Hearing the applicant admitted that there is one other producer, i.e. M/s. Expanded Polymer Systems, of the subject goods, but claimed that the other producer has not manufactured subject goods during the period of investigation. Not only has the petitioner given incorrect facts in the original petition, but continues to try and mislead the authority by making an incorrect statement that the other producer was not in operation during the POI.

22. In the initiation notification, period of investigation is defined to be 2010-11 to 2013-14. It is submitted that Expanded Polymer Systems was in operation during the period of investigation. We have purchased Exaflex 3056, (subject goods) against two invoices in February 2012 and three invoices in the month of June 2012. The Serial No. of one of the invoices is 222, indicating that atleast 221 invoices for clearance of excisable goods had already been issued since April 2012.

23. We believe that other users such as M/s. Kurlon Ltd., have also purchased the PUC from M/s. Expanded Polymers during the period of investigation. A copy of invoices evidencing procurement of subject goods from M/s. Expanded Polymer Systems are enclosed herewith as Confidential Annexure-2.

24. Secondly, during the Public Hearing, Manali claimed that their capacity is 50,000 MT. However, in the petition they have submitted their installed capacity to be 25,000 MT in 2013-14. If the claim of Manali is correct, is not clear why wrong information has been given in the petition. The initiation therefore also becomes illegal, as it is based on incorrect facts represented by Manali.

25. It is submitted that concealment of the existence of the other producer itself vitiates the investigations as:

- a. Standing of Manali may be affected,
- b. Expanded may not be suffering injury,
- c. Expanded's cost of production may be lower than that of Manali, thus evidencing Manali's inefficiencies
- d. The production and sales data of Expanded will affect various injury parameters such as Imports in relation to total Indian Production, Total demand, Market share of Imports and domestic industry, etc.

26. The Authority may consider that in 2011-12, the selling price increased by 15% as compared to base year, whereas the cost of production increased by 20% as compared to base year. In such a scenario i.e., where the cost of production increased in a greater proportion as compared to the selling price, the profit can only decline. As per the petition, the profits have tripled in 2011-12 as compared to base year. This is an impossible situation. Similarly, in

2012-13 the selling price has increased by 10% as compared to base year, whereas there is a negligible increase in cost of production, the profit in 2012-13 should hence have been much greater than in the base year. The petition however, indicates a huge loss in 2012-13. It is submitted that clearly the figures provided in the petition are false and misleading. Such unreliable information appears to have been deliberately furnished by the applicants so as to avoid disclosure of the actual position and to prevent interested parties from making meaningful submissions on the claims made.

27. Fourthly, it may also be noted that the applicant has filed an application seeking imposition of anti-dumping duties on imports of PUC. In their application before the DGAD, they have submitted that their profitability has reduced by 20% in 2011-12 as compared to 2010-11. However, in the data submitted before the DG Safeguards, the applicant has claimed that their profitability has increased by 224% in 2011-12 as against 2010-11. It is astonishing how such a different figures be submitted before the two parallel authorities.

28. It is further submitted that the information furnished in the petition is also at stark variance from the audited balance sheet of the company. From the audited reports of Manali it appears that throughout the period of investigation, they have consistently earned huge profits. Manali has been consistently earning huge profits and has paid huge dividends to its shareholders.

29. Further, even if Manali's claim that it has incurred losses on the PUC is assumed to be true, in that case also, to achieve such levels of overall profit, it would have to earn inordinate profit on other products.

30. It is therefore requested that the cost of production used by the applicant for determination of profit may be disclosed. The applicant must be called upon at least to disclose, the basis of allocation of common costs, between subject goods and other products manufactured by the applicant. Even if the cost of production is considered to be confidential, the basis of allocation of costs cannot be considered to be so. It is requested that such information may be made available to other interested parties forthwith.

31. Article XIX:1(a) of GATT 1994 requires that the increase in imports must be as a result of "unforeseen developments"(emphasis added). In particular, in the case at hand, any increase in imports of the subject goods occurred as a result of the grant of tariff concessions by India under the ASEAN India FTA (AIFTA). However, the grant of tariff concessions by India under the AIFTA is a concrete commitment undertaken by India under the above FTA and cannot be considered an "unforeseen development".

32. In the present case as there is divergence in data submitted and relied by applicant at the time of hearing and the initiation notification, in respect of almost all the injury parameters, we are not in a position to make any submission on injury allegedly being caused to the domestic industry. As the reliability of data is itself in doubt, on the aspect of imports, profitability, capacity, cost of production, market share, we are at loss in giving our submissions on this aspect. We request the Hon'ble Authority to terminate the present proceedings and ask the domestic industry to file a correct petition with accurate data, on the basis of which fresh investigations may be initiated.

33. In the present situation, since the proceedings are based on incorrect data, and the domestic industry itself is not accepting the data based on which initiation has been made, a proper opportunity has not been made available to the other interested parties to put their views forward. The present proceedings are in gross violation of principles of natural justice and they should not be carried forward with.

34. Further, due to excessive confidentiality claimed by the Domestic industry, without providing any meaningful summarization or indexing of data, it is not possible for us to make submissions on the claims made by the domestic industry. We request the Authority to ask the domestic industry to disclose data which are not confidential in nature or at least provide meaningful summarization of the same.

35. At the outset, we submit that the data provided by the domestic industry does not fulfill the higher threshold of "serious injury" as required under the WTO Safeguards Agreement and the Indian Safeguard Rules.

36. In light of the above obligation, based on the application filed by the Petitioner, there does not seem to be any causal link between the imports of subject goods coming into India and decline in profitability of the Petitioner. This is evident from the fact that there is a consistent decline in the profitability of the Petitioner whether or not imports increase or decrease.

37. In 2012-2013 the imports are claimed to be 42026 which have increased to 54507 in 2013-14, i.e., an increase of 30%. Sales of domestic industry during this period have however, remained stagnant i.e., 13451 in 2012-13 and

13473 in 2013-14. In fact even the production and capacity utilization have remained more or less the same in 2012-2013 and 2013-14 indicating a lack of causality between the imports and the injury claimed by the applicants.

38. Article 5(2)(b) of AoS provides that factors other than increased imports which are causing injury to the domestic industry, shall not be attributed to increased imports. Similarly, Annexure to the Safeguard Rules require Authority not to attribute injury due to factors other than increased imports.

39. In the present investigation, there exist other factors as well apart from imports of subject goods coming into India, which may be a cause of injury to the Petitioner. These may be listed as follows:

- a) Quality issues and inconsistency in supplies
- b) Demand – Supply Gap
- c) Locational disadvantage of DI-Most of the users industry are located in North India, whereas the, manufacturing facility of the Domestic Industry is in South India.
- d) The domestic industry is unable to achieve high levels of capacity utilization, not for a lack of demand, but on account of supply side constraints. The domestic industry routinely suffers from a shortage of raw materials, as it does not have infrastructure to handle critical materials like propylene oxide.
- e) Increase in imports due to ASEAN-India FTA

40. It is submitted that in para 81 of Gul Ahmed Textile Mills Ltd v Council of European Union (OJ C 331, 12.11.2011), EC Court annulled anti-dumping duty imposed on imports of Cotton Type Bed Linen on the ground that the European Commission failed to examine the scheme of generalized tariff preferences on the increase in import of the goods and subsequent injury to the Domestic Industry in EU. Consideration of other factors is similar to that under anti-dumping provisions. Thus, the above judgment of European Commission is relevant in this particular case. The FTA between India and ASEAN countries is thus a crucial factor in this respect. Under the treaty, various concessions pertaining to trade in goods, rules of origin, investment, etc. have been agreed on by the two nations. This crucial 'other' factor which may have caused injury to the Domestic Industry, must be analysed by the Authority.

41. The Article 3.1 of AoS provides that investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest.

42. Further, imposition of 25% Safeguard duty will have a direct impact of 15% on the cost of Foam. These foams are used in manufacture of mattresses, pillow and other day to day products. The incidence of duty has to be borne by the importers, who will be forced to import irrespective of the duties, as the domestic industry does not have the required capacity to meet Indian demand. In such circumstances, the importer-manufacturers will be forced to raise their prices, passing on the burden of the duty to the ultimate customers.

43. Further, the user industry provides direct or indirect employment to more than 50000 people and levy of duties will result in imports of value added products. It is imperative to mention here that the user industry has been bearing the burden of duties, which are being enjoyed by Manali, for the last 16 years. During this period about 50 Foam manufacturers were forced to close shop. It is therefore, submitted that imposition of duty is not in Public interest.

44. We seek permission to rely on the various submissions made in our Preliminary submissions dated 26.06.2014, which are not being reproduced herewith for sake of brevity.

45. On the basis of the arguments submitted above, we respectfully request the Hon'ble DG Safeguards to terminate the present proceedings forthwith.

(b) M/s. Vitrag Foam Pvt. Ltd., Nr. Sabar Dairy, Godhoda, Talod road, Himatnagar-383001 submitted the presentation of M/s. Sheela Foam Pvt. Ltd., as their submissions.

(c) M/s. Royal Synthetics submitted the presentation of M/s. Sheela Foam Pvt. Ltd., as their submissions.

(d) M/s. Springfeel Polyurethane Foams Private Ltd., submitted the following submissions-

- a. The installed capacity of M/s. Manali Petrochemicals Limited (WPC in short) for the production of flexible slabstock polyol is much less than the demand for the same from various polyurethane foam (PUP in short), situated across India.

- b. Price justification: MPL is also exporting slabstock polyol to other countries. It can be observed from copies of records available with Customs that the price at which we are importing is very much in line with the prices at which MPL is exporting during the same period of time and that these prices are in line with the international prices in force for the countries in this geographical region.
- c. MPL has claimed that their production and sales of slabstock Polyol have declined. It must be noted that MPL has a shared production capacity for the manufacturing of the various intermediaries and commodity products that they offer. This kind of shared production capacity implies that a reduction in the production of slabstock polyol does not mean that they have been under utilising their installed capacities. It simply means that they have producing some other product (for example DPG). This can be easily verified from the number of days of nil production and resultant plant shut down days effected by MPL.
- d. MPL has claimed in their application to your office that they are incurring losses. This is not correct. A study of their published Balance Sheet and Profit & Loss account for the years 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14 show profits and have in fact declared dividends to their shareholders.
- e. It is most respectfully pleaded that, The application for Safe Guard Duty made by MPL be dismissed .
- f. That market dynamics decide the pricing of flexible slabstock polyol.
- g. As manufacturer of flexible slabstock foam we are not over burdened by the unjustified levy of additional duties on the import of polyol.

(e) **M/s. Durapuf (Silvassa) Pvt. Ltd., 121/122/123, Piparia Ind. Estate, U.T. of Dadra -Nagar Haveli, Silvassa -396 230. Via Vapi(W Rly.)** submitted the following submissions-

1. With reference & subject to above we would like to inform you that product under consideration (Polyol) produced by M/s. Manarli Petrochemicals Ltd who is only one domestic producer and their total installed and production capacity cannot meet even 20/25 % of India's total demand/consumption of Polyether Polyol.
2. Further please note that price level of all the international manufacturers from Japan/Korea/ Germany/ Singapore supply this Polyol at cheaper than M/s. Manali petrochemicals Ltd. Hence consumers tend to import the same. We import above mention material as CIF basis from manufacturer/exporters and if we purchase locally from M/s. Mernali Petrochemicals Ltd., we will have to pay 2% CST and transport charges which is extra.
3. As M/s. Manali Petrochemicals Ltd is only one producer producing polyol in India, they may act as monopolistic supplier for pricing and supply of quantity to individual customer.
4. Further as P.U. foam manufacturer, we are paying indirect taxes such as custom duty, VAT, Excise, CST to Government. Due to initiation of safeguard duty our cost of product will be increased substantially & herrece we fail to understand that to safeguard of only one manufacturer locally why Government wants to loose substantial revenue from approx. 80-100 P.U.Foam manufacturers in India.
5. We wish to draw your attention that many countries do not have any duty or lower rate of duty and they are taking advantage of higher prices prevailing locally hence we India is also losing precious foreign exchange by giving them higher price. Please note that still they are cheaper than M/s. Manali Petrochemical; Ltd. In the light of above facts we request you please do not consider imposing safeguard duty on polyether Polyol as mentioned in your above notification.

(f) **M/s. Allied Foams Private Limited, D-32, Mehendru Enclave, Delhi-110033** submitted the following submissions-

1. The applicant was well aware of the fact that the other manufacturer e.i. Expanded Polymer Systems Pvt. Ltd. Exists. The MD of Manali and MD of Expanded have been on the executive board of IPUA for a number of years. So how can they claim that they were unaware of their existence, hence it amounts to a wilful concealment of the facts on their part.
2. Similarly the import Data they have relied on is not correct as was pointed out by sheela foams attorney in the public hearing. In the absence of correct Import Data no safeguard duty can be imposed.
3. The applicants production capacity has been the same for last 27 years that is around 15000 metric ton per annum
4. Manali and UB started there polyol plants with capacity of 7500 tons of polyol each .way back in 1987,
5. The import duty on polyol then was more than 100%
6. UB was purchased after a few years by Manali so there capacity became 15000 tons
7. After Mr Manmohan Singh became the finance minister and he started reducing the duties gradually in early nineties. The duty on polyol kept on reducing and ever since late nineties Manali has been approaching Govt. for safeguard duty or anti dumping duty and they have succeeded in getting one or the other measure , imposed.
8. They have admitted their production at 15000 tons till last five years.

9. From the above facts it is clear that that there has been no increase in Manali production from 1987 till 2009. As per them only.
10. Now they claim that they have increased their capacity to 25000 tons . as per the application with you.
11. During the course of their presentation their rep claimed their production capacity as 50000 per. Annum. Here again they themselves are making a contradictory statement .What is the truth?
12. Has their capacity really increased? Or are they just trying to create a fact out of nothing?
13. 22 years a company has not increased their production by even 1% and now all of a sudden they are claiming jumps of 66 to 333% increase in the production capacities. Are they to be belived on their face value?
14. Manali has enjoyed a virtual monopoly and made good profits when the duties on their competitive product from abroad are kept at high levels.even, with no increase in their production capacities.
15. Durring last 3 years even with zero duties on their competitive product. There are a no of small foam producers in different parts of India who consume 5 to 10 tons polyol per month. These people have no option but to buy from the local manufacture or an importer where they have to shell out more prices hence the local Mnufacturerers have all most an assured market for what ever production they are capable of doing.
16. The company has been doing well and since the balance sheet over all is profit making their claim that this profit is from other business should be rejected .
17. During public hearing when some of the above anomalies in their application were pointed out then their lawyer. takes the plea that an application may not be 100% correct.
18. They may not be 100% correct but if it is proved that they are wilfully presenting misleading facts it should be taken differently. And their application needs to be rejected .on this cause itself.
19. The Flexible foam production has doubled during last 5 years there by increasing the demand for the polyol from 42000 tons to 84000 tons app.
20. With domestic production of polyol remaining the same the Flexible foam manufacturers have to rely on Imports. Hence the ratio of imports to domestic shows an increase.
21. With flexible foam having a double digit growth the gap in the demand and available local supply their share of the total market has to reduce As they have never tried to increase their production. Or improve their quality
22. Apart from this the quality of the product produced by both the local manufactures is much lower than the international standards .
23. As a matter of fact the imposition of safe guard duty should be only on equivalent materials and it can be said that what we (Local manufactures some traders) are importing is not manufactured by any of the two manufacturers. (just as hypothetical example , there is a manufacture of leather shoes in India and no manufactures of PVC Shoes. Is the leather shoe manufacture entitled to get safeguards imposed on shoes as such covering the PVC Shoes as well or only leather shoes as such)
24. As said in my presentation the law under which the applicant is seeking protection as a local Manufacturers protects all the local manufacturers and there are around 100 manufacturers of flexible P.U. and thousands furniture and bedding manufacturers. If safeguard measures are imposed. on the polyol ,thousands shall be hurt against the gain to only two polyol manufacturers.
25. I humbly request you to please consider all the above cited facts and reasons and reject this application and save thousands of local manufactures form injury. And saving crores of Indian consumers from an unjust price Increase.

(f) **M/s. Springwel Mattresses Pvt. Ltd.,** submitted the following submissions-

- A) There is big difference in the Data of Imports as given by M/s. Manali and given in Initiation Notice. This point was well represented by all the parties and even Manali accepted that there is huge gap in two sets of Import Data so no initiation should take place.
- B) There has been lot of variance in figures /information put forth by Manali in respect of not knowing about the other manufacturer M/s. Expanded Foam, their own production capacity, increase in Demand of Polyol in the market.
- C) Manali has less production capacity and cannot meet the Market Demand which is around 84000 ton against their installed /increased capacity of only 25000 tons. Manali cannot meet market demand in any yardstick.
- D) Manali is in existence for so long but could not update / upgrade itself to meet the competition .
- E) It is well represented by number of Parties that Manali should not be allowed to continue protection on account of Safeguard /Anti dumping Duty as they have already enjoyed for number of years already.
- F) Manali should not be given Protection as it will cause Injury to number of Slab Stock Foam manufacturers, furniture and bedding manufacturers, and other small manufacturers who are using PU Foam in their products. We request you to please consider our strong objections to the application of Manali and reject the same in public interest.

(g) M/s. Tirupati Foam Ltd

1. The Imports data used for initiation is different from the data submitted by the Manali Petrochemicals. In the data used by your good office, various kinds of Polyols, other than the subject Polyols are also included. The entire import of Customs tariff Heading 39072010 is treated as Polyol of MW 3000-4000, which is not correct. In the absence of correct data of import it can not be said that there is any surge in imports. Hence the correct import data may be called for and only if it is concluded that there is a surge in imports, which is causing injury to Manali Petrochemicals, fresh public hearing may be called.
2. We have no import Polyol as Manali is unable to supply us Polyol. Their capacity is not even 30% of the domestic demand of polyol.
3. we get Polyol from Manali, which is inferior in quality vis-a-vis imports, through rationing process.
4. it is not clear as to how Manali is injured and incurring losses, when they are making huge profits and the subject product is their major product, as stated in their own Board Report of 2013-14.
5. Any imposition of safeguard duty will seriously injure small manufacturers like us, who are forced to import, due to unavailability of Polyol with Manali.
6. Manali is enjoying protection for the last 16 years in the form of safeguard duty/Anti-Dumping duty and they have no plans to increase their capacity and improve the quality of product.
7. we request you to consider our plight with sympathy and do not impose any safeguard duty which is totally unjustified and can cause closure of so many small units only to further enrich one large company.

D. Rejoinder by Domestic industry and interested parties.**I. Domestic Industry.**

1. It is also submitted that we deny all the submissions made by the interested parties unless specifically accepted by us. The domestic industry also reiterates and relies on all the submissions made in the application, comments, written submissions and other submissions. The said submissions have not been repeated herein for the sake of brevity. Any fact or averment in the written submissions of interested parties mentioned above, which is not specifically admitted hereinafter may be treated as specifically denied.
2. It was argued by the interested parties that the domestic industry had already approached anti-dumping directorate and, therefore, there is no need of current safeguard investigation. It was also pointed out by the major exporters from Singapore that since 98% of imports of the subject goods originate in Singapore, there is no need to impose safeguard duties against all countries. In this context, it is submitted that the submission of the Opposite Parties is without any merit either in law or on facts. There is no bar whatsoever which prohibits simultaneous investigations for two different trade remedial measures. Further, there are several instances where parallel anti-dumping and safeguard investigation have been carried out.
3. In this context, it is submitted that Hon'ble DG in the case of Electrical Insulator had recommended safeguards duties under Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002. Simultaneously and anti-dumping investigation was also initiated by the Designated Authority against China only. Therefore, the argument of interested parties that DG should reject Safeguard investigation as Singapore will be taken care of by anti-dumping investigation measures, does not carry any weight.
4. In addition to above, the DG in the cases of Rubber Chemicals, Caustic Soda, Carbon Black, Soda Ash, etc., has recommended for levy of safeguard duties in addition to the anti-dumping duty already in force. The Government of India accepted the recommendation and imposed safeguard duty along with the anti-dumping duties. Hence, it is wrong to say that both duties cannot be levied and therefore same to be rejected.
5. Kind attention of the DG is also invited to the Final Findings in the case of N 1,3-dimethyl butyl-N' Phenylenediamine (PX-13 also known as 6PPD, Vulconox 4020 etc) [F.NO.D22011/32/2010 dated 6.6.2011] into India wherein the DG had categorically recorded that there is no bar imposed by law on imposition of Safeguard Duty when Anti dumping duty is already in place.
6. From the above, it is clear that it is the stated position of the DG that there is no bar, either legally or logically, to recommend safeguard duties merely because of the existence of a parallel safeguard investigation. In view of the above, we request the DG to kindly reject the issues raised by the interested parties in terms of available jurisprudence on the subject and past practice of the Safeguard Directorate.
7. It is submitted by the interested parties that the DG has initiated the Safeguard investigation despite the fact that 98% of the subject goods are coming from Singapore, a member country of ASEAN from which India had bilateral Free Trade Agreements and India-Singapore CECA. It was further contended that the purpose of these agreements is to increase the trade and any recommendation will be against the motive of the agreement. In this context, the domestic industry submits that in the recent investigation of Saturated Fatty Alcohols, DG has analyzed the issue of FTA's and the approach and conclusion is applicable to the current investigation also.

8. Without prejudice to the above, it is also important to appreciate that the anti-dumping duty will be based on a different investigation period, whereas the present Safeguard duty is being proposed based on much more recent period.
9. In view of the above, it is clear that the Hon'ble DG can initiate and recommend duties even if a particular country is covered under any FTAs or any other bilateral agreement.
10. The interested parties in their written submissions stressed upon the habit of domestic industry about using trade measures. In their misplaced enthusiasm to create a bias, it was falsely stated that the domestic industry is enjoying the benefit of duties for last 16 years. In this context, it is submitted that the said allegation is wrong and contrary to the facts. It is further submitted that the interested parties have intentionally withheld the fact after 1998, the domestic industry has approached the DG (Safeguards) for the first time for protection against increased imports and too when there is significant sudden surge of imports.
11. In relation to anti-dumping duties, it is submitted that it is due to the habitual dumping behavior of exporters from certain countries that the Domestic Industry is forced to approach the Designated Authority for redressal of their problems. The Hon'ble Designated Authority for Anti-dumping gives its findings only after following the due process of law and after proper analysis. It is a paradoxical situation that the exporters who are found to be indulging in dumping practices, are blaming the Domestic Industry. Therefore, the attempt of the exporters to blame domestic industry needs to be wholly rejected. Without prejudice, it is submitted that the interested parties have also not provided the correct information with regard to the various investigations conducted by the DGAD and the DG (Safeguards). It may be noted that there has been only one safeguard investigation and two anti-dumping investigations so far on the Product under Consideration.
12. The DG may like to appreciate that domestic industry is always on the receiving end due to the dumping practices of exporters from Singapore, China, Indonesia, Korea, Taiwan, EU and USA. This is the only reason why Designated Authority recommended duties against these sources. Without prejudice to above, it is submitted that Domestic Industry has every right to take appropriate actions as available under the law to protect their interest.
13. The issue related to standing of the domestic industry is wrong and contrary to the legal position. In this context, it is submitted that as per the information available to the domestic industry they are the only producers, commercially producing the subject goods during the period of investigation. In any case, even assuming but not accepting that there are other producers producing the subject goods, M/s. Manali Petrochemicals will account for a major proportion of the total domestic production in terms of Safeguard Rules.
14. Without prejudice to the above, it is submitted that except Sheela Foams all the importers and users acknowledged the fact that practically the applicant is the sole producer of the subject goods in India.
15. The representative of M/S. Sheela Foams submitted that there are variations in the data/submissions made in the petition and during the public hearing by the Domestic Industry and the initiation notification. While pointing out the differences in the import data, the representative ignored the fact that the sources of import data are different.
16. In addition to above, they have alleged differences in installed capacity, number of domestic producers of subject goods, customs sub-headings, demand in the Indian market and profit & loss figures of anti-dumping petition and safeguards petition. In this context, it is submitted that the basic premise of the legal representative of M/s. Sheela is wrong and without any legal or logical basis. Moreover, they have tried to quote issues and submissions which were never made by the domestic industry either in the petition, any of their submissions or in the public hearing. Nevertheless, we are offering our comments to the issues raised by them in the following paragraphs:
 - a. Installed Capacity: The domestic industry confirms that they have installed capacity of 50000MT for Polyol as a whole, which can be used 100% for producing the subject goods. However, as a matter of record, domestic industry has allocated 50% of their capacity for subject goods.
 - b. Chapter Heading: In relation to chapter heading, the Domestic Industry submits that the DG has used only 39072010 the code under which the subject goods are technically classifiable. Theoretically, all imports should come under this code only. However, it is a known fact that goods are classified headings other than the technically correct heading particularly when there is no duty implication. In the instant case, it is a matter of record that the subject goods are getting classified under Chapter Heading 39072090 also. The DG may like to appreciate that if both headings are taken in account, then the DGCI&S will also show the same growth trend as seen from the data used by applicant. In view of the above, DG should reject the submissions as they are devoid of any merit.
 - c. In relation to variation in demand and market share, it is submitted that all the parameters linked to import data will show variation as import data considered as the data used are from different sources.
 - d. The interested parties had argued that the figures submitted in anti-dumping and safeguards are different and same need to be checked. In this context, it is submitted that due to the difference in the methodology adopted by the authorities in anti-dumping and safeguard investigations, there might be slight variation in the figures. In any case, the safeguard investigations are independent investigations where the Hon'ble DG will carry out its own verification before arriving at the final recommendations.
17. All the issues related to adequacy and accuracy are explained in detailed in our written submissions dated 10.10.2014. Same are not repeated herein for the sake of brevity. However, the issue raised by representative of

M/s. Sheela selectively picked the words of the submissions of domestic industry without understanding and appreciating the law and available jurisprudence on the subject. We are surprised and shocked by the interpretation drawn by the legal representative of Sheela Foams during the public hearing and even in their written submissions. The domestic industry reiterated that Rule 5(3) of Safeguards only talks about the satisfaction of the DG on the available data for the purpose of initiation. In the instant case, there was sufficient evidence to justify the initiation of the investigation and, therefore, the contention of the interested parties is devoid of any merit.

18. Domestic industry further submits that in the instant case, no party has provided any evidence even to suggest that the information available with the DG (Safeguards) at the time of the initiation was not “sufficient” to justify the initiation of the investigation. In view of the aforesaid, it is requested that the submissions made by the interested parties should be rejected.
19. Contention of the interested parties is wrong and denied. In this context, it is submitted that as per the practice of the DG, soft copy (in excel format) of import data is not circulated to interested parties. However, if the DG feels that it should be given to all interested parties, we will have no issues to provide the soft copy provided the same practice is followed in all other cases also.
20. The interested parties in their submissions made detailed arguments about the increase in the imports. In this context, we had made our detailed submissions in relation to surge in imports dated 10.10.2014. The same are not repeated herein for the sake of brevity.
21. From the above, it is clear that the imports increased from 25849 MT in the year 2010-2011 to 61075 MT in 2013-14, which is an increase of 35226 MT within a period of three years. This is 2.36 times of imports in the base year or increase by 136% over the base year. It is respectfully submitted that this increase is certainly significant, sudden as well as sharp by any standards.
22. From the above, it is clear that imports have increased significantly in the period of investigation. The said increase in import can be termed as recent enough, sudden enough and sharp enough.
23. The contention raised by the interested parties in relation to double counting of import data is wrong and hence denied. The domestic industry submits that there is no double counting of imports into the country and vehemently denies the proposition that the imports through warehouses (CFS, ICDs) are counted twice in the import data. It is important to note that the importers have not given sufficient data in support of their claim but have merely made hollow contentions. Without prejudice, it is submitted that even if the apprehension of the interested parties is accepted, then also the Domestic Industry’s case for increased imports and injury will not be affected at all. In view of the aforesaid, we request the Authority to kindly reject the submissions made by the interested parties.
24. The contention raised by the interested parties in relation to annualization of 9 month import data is wrong and hence denied. In this context, it is submitted that there are plethora of the cases wherein DG has adopted the same principle while initiating the investigation. However, we request the DG to kindly call for the actual import data from DG (Systems) of the Department of Revenue or the DGCI&S and set the controversy to rest.
25. Domestic Industry denies the fact that the current imports are coming in India because of demand and supply gap. In this context, it is submitted that the domestic industry is operating at 55% and 45% of its capacity is lying idle. It is also important to note that domestic industry has only allocated 50% of their total Polyol capacity of 50000 MT to subject goods. If needed, the Domestic Industry can divert remaining 25000MT to produce subject goods. This diversion will make capacity 50000 MT to produce subject goods. It may also be appreciated that domestic industry has constantly increased its capacity, keeping in view the demand of the subject goods and in future also, if needed, they will increase the same. Therefore, to say that imports are inevitable is wrong and same needs to be rejected.
26. It is also submitted that the Domestic Industry is forced to export its production (at comparatively lower prices) which can be easily made available for domestic consumption. The Domestic Industry has not refused to sell the subject goods to any customer and, therefore, the argument of demand-supply gap does not hold any water in the facts and circumstances of this case. In any case, the objective of a safeguard duty is not to block the imports but to address the specific problem being faced by the Domestic Industry on account of increased imports with a view to allow the Domestic Industry to take remedial measures. It may also be mentioned that similar arguments have been raised in the past before the DG, but have been consistently rejected. In this context, we draw your kind attention to the following decision of the Hon’ble DG wherein the DG had rejected the arguments of the Opposite Parties under identical circumstances:
 - N 1,3-dimethyl butyl-N’Phenylenediamine (PX-13 also known as 6PPD, Vulconox4020 etc) Final Finding dated 6.6.2011.
27. Without prejudice to above, it is submitted that the other producer namely M/s. Expanded Polymers who has a capacity to produce about 6000MT of the PUC which could not be utilized due to increased imports. The existing capacity of the applicant along with their extended capacity utilization and the capacity of Expanded Polymers, would be able to adequately meet the demand in the country. In any case, it cannot be anybody’s case that safeguard measures cannot be taken if the Domestic Industry cannot meet the entire demand in the country.

28. In the context of injury parameters, it is submitted that we have made detailed submissions in our application as well as in our written submissions dated 10.10.2014 and therefore same are not repeated herein for the sake of brevity.
29. Some of the interested parties have argued that the Domestic Industry has not suffered injury. It is further argued that even if there is injury, the same cannot be attributed to increased imports. Assuming but not accepting that injury to the Domestic Industry could have been caused by factors other than “increased” imports also, it is submitted that there is enough jurisprudence available on the subject to establish that the scope of safeguards investigation is not restricted to the situation where Domestic Industry is suffering injury only because of increase in imports. In this context, the DG may like to appreciate the following:
30. The Appellate Body in *US — Wheat Gluten* concluded that the contribution by increased imports must be sufficiently clear so as to establish the existence of “the causal link” required, but rejected the Panel’s conclusion that the serious injury must be caused by the increased imports alone and that the increased imports had to be sufficient to cause “serious injury”.
31. In view of the above, it is clear that the Hon’ble DG only needs to analyze and conclude that the imports are causing injury to Domestic Industry and it is one of the grounds (and not necessarily the sole ground) which are affecting Domestic Industry’s performance. Without prejudice to above, it is submitted that the injury suffered by the Domestic Industry is primarily because of increase imports only.
32. Detailed information, data, and submissions have been made before the Designated Authority evidencing injury and consequent causal nexus between increased imports and injury. Unsubstantiated submissions are offered disputing such material information and evidence provided by the Domestic Industry. Clearly, they are required to be rejected.
33. Interested parties have placed reliance on statements made in the annual reports of various years and in support of their claim that there is no causal link established in the facts of the present case. At the very outset, it may be mentioned that the Annual Reports do not pertain to the specific period of investigation. In any case, it is undisputed that Domestic Industry is a multi-product company and its Annual Report is a reflection of its overall operations for all the products. In other words, the annual report is an overview of company’s performance and not a performance appraisal of specific products which may be under investigation. It has been consistently held that trade remedial measures have to analyze the performance qua the PUC and not in relation to the company as a whole. This approach is based on the sound legal premise that what is under investigation is not the company but the product under consideration. Hence, the performance of the Domestic Industry has to be judged for the product under consideration alone in terms of the provisions of law. The Annual Reports do not reflect the performance of the PUC but is a reflection of the performance of the company as a whole. Nevertheless, the domestic industry is providing reply to specific issues in the following paragraphs:

(i) Constraints in Production:

It is submitted by the interested parties that the Domestic Industry may have faced constraints in production possibly suffered due to electricity shortage issues in Tamil Nadu as well as shortage of bio mass fuel for captive power plant. In this context, it is submitted that the issues raised are wrong and hence denied. The claim that there is shortage of electricity in Tamil Nadu has been presented in a very generalized manner without giving any evidence to even suggest that the Domestic Industry also suffered on this account. Further, the domestic industry submits that it has three sources of power supply namely, self-generated power (captive power plant), power from State Electricity Board and Diesel Generator set. This gives enough flexibility to the Domestic Industry to ensure that their production does not suffer on account of any shortage in any particular source of power supply. Therefore, the submission of the interested parties that the domestic industry’s production may have suffered on account of power is totally irrelevant and needs to be rejected.

(ii) Non Availability of Raw material

In the relation to availability of Propylene Oxide (PO), it is submitted that the domestic industry has made adequate supply PO for its requirements. The domestic industry is producing PO in-house and also importing the same as and when required. They have also made PO storage facility at ETTL which allows them to import large quantities and use it as per their requirement. In view of the aforesaid, it is submitted that issues relating to availability of key raw material i.e., PO is devoid of any merit and therefore, needs to be rejected.

(iii) Inadequate Capacity of the Applicant

The claim of the interested parties regarding certain restrictions in Manali area with regard to increase in capacities, etc., (where the domestic industry’s plant is situated) is wrong and hence denied. In this context, it is submitted that the applicant has a total 50000MT capacity of Polyol, which can be directly used for the production of the subject goods. Thus, there is no effect of the restriction on the fact that the Domestic Industry has enough capacity to produce the subject goods and that the effect of dumped imports on the performance of the Domestic Industry, does not get diluted due to certain restrictions in the past. In any case, even the moratorium with regard to increase in capacities was lifted with effect from September 2013. In view of the aforesaid, the issue relating to capacity needs to be rejected.

34. Domestic industry has provided detailed restructuring plan in their application as well as in the written submissions filed on 10.10.2014. The same are not repeated herein for the sake of brevity and should be considered as part and parcel of the rejoinder submissions.
35. In addition to above, it is submitted that arguments raised by the interested parties in relation to the adjustment plan of the domestic industry are without any basis and should be rejected. The interested parties had not provided any hard facts to prove that adjustment plan is not workable or what are the flaws which will make adjustment plan unviable. They mere based on assumptions and assertions rebutted the claims of domestic industry which needs to be rejected by the DG.
36. Some of the interested parties submitted that the domestic industry had relied on the same adjustment plan as given in the last safeguard investigation and after imposition of duties they have not taken any action to complete that plan. In this context, it is submitted that the allegation made by the interested parties is wrong and without any factual basis.
- i. Applicant had entered pricing agreement with CPCL for higher quantity. Due to the agreement, now the prices are fixed based on International LPG price + Conversion cost.
 - ii. The propylene pricing was fixed on import parity price, considering FOB value of Japan.
 - iii. In case of any shutdown of the CPCL plant, applicant sourced propylene from Gail, HPCL Vizag, etc.
 - iv. From the years 1999-2000 /2000-01, the PO capacity utilization was not affected due to non-availability of propylene.
 - v. Further, in order to enhance the PO capacity, the applicant had debottlenecked PO plant and increased the capacity of the plant from 24000 MTPA to 36000 MTPA.
- In view of the above, it is clear that domestic industry has taken every necessary action to streamline PO plant and since 2000 there is no constraint in Propylene availability.
37. The domestic industry after imposition of safeguard duties constantly worked to reduce its energy consumption. it is clear that the Domestic Industry is serious about its adjustment plans and this time also they will deliver as per the schedule. The DG may like to appreciate that the PO storage facility at ETTPL was already made operational, which was provided as a part of adjustment plan. The domestic industry once again request the DG to kindly recommend the duties at earliest to safeguard the legitimate interest of the domestic industry.
38. Arguments have been made by the interested parties that there are no unforeseen circumstances which led to increase in imports and caused serious injury to Domestic Industry. In this context, it is submitted that the Domestic Industry in its non-confidential version of the petition had provided all the unforeseen circumstances which has resulted in increase in imports. In addition to this, we have also discussed the unforeseen circumstances in detail in our written submissions dated 10.10.2014.
39. Without prejudice, it is reiterated that while there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyze unforeseen circumstances in terms of the Indian laws, we understand that the DG may still prefer to analyze the “unforeseen developments”. In any case, it may be noted that even in the GATT or the WTO Agreement on Safeguards, there are no specific guidelines or methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments. Moreover, there is no specific question in the application format for the Domestic Industry or the domestic producers, wherein such information can be filed.
40. Before the specific case of the Domestic Industry is spelt out in the context of the “unforeseen developments”, it would be pertinent to refer to the Appellate Body decision in the Argentina-Footwear (EC case) held that the phrase “Unforeseen Developments” means the developments which were unexpected. ‘Unforeseen developments’ requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been ‘unexpected’. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.
41. It may be appreciated that the Domestic Industry did not anticipate nor could it have predicted that the subject goods will come through Singapore only, despite the fact that Singapore accounts for only 2.87% of the total Global Polyol capacity [(based on the published information on Page 30, Table 10 (Global Polyol capacity by leading producers 2012-17 (Forecast)/kt) of PU Magazine – Vol. II, No. 1-February/March 2014]. This sudden increase of imports from one source where duties are reduced due to FTA’s is unforeseen by the domestic industry or cannot be foreseen by any negotiator also.
42. Concentration of Supply Chains: In this context, it is reiterated that the Domestic Industry did not anticipate that due to Indo-ASEAN FTA and Indo-Singapore CECA, major suppliers will made special and perhaps illegal arrangements to avail benefit of this. The DG would like to appreciate that now these major suppliers control the market as well as the supply chain. It is precisely for this reason that the major suppliers have come together to take undue benefit of the FTA. It is also for this reason that 98% of the imports are coming from Singapore, which is inconceivable in this current open market. This sudden increase of material from one source and that too at non-remunerative prices is unforeseen by the domestic industry.

43. The domestic industry could not have predicted that the prices of the subject goods will also reduce significantly despite the increase in raw material prices world-wide. These reductions in prices led to sudden increase in imports of subject goods in India as can be seen from the import statistics. The period of sudden decline in prices of subject goods and sudden increase in import quantity coincided with the period when Domestic Industry commenced its commercial production. Further, this price reduction of subject goods has also reduced the capability of Domestic Industry to negotiate better price with the customers.
44. Moreover, the concessions which are being negotiated by the government takes into account particular levels of import volume and the prevailing price levels. If there are significant changes that the negotiators could not have anticipated at the time of negotiations, then certainly it is a case of unforeseen developments. Further, it is important to note that no government or negotiator would be able to anticipate that imports will predominantly imports will come only from a major source after the FTA. The above are the unforeseen circumstances which neither the Domestic Industry nor the negotiators of Indo-ASEAN FTA and Indo-Singapore CECA foresee at the time of negotiation.
45. Thus, it can be seen that there were indeed unforeseen circumstances which Domestic Industry could not foresee.
46. It is reiterated that the issues raised by the interested parties during the course of the investigation are merely based on the conjectures and with the intention to create a bias. In this context, it is submitted that the quality of domestic industry products are at par with imported material. The same can be demonstrated by the quantity of material lifted by our major suppliers and their repeated purchase is proof of our quality. The same is attached as Annexure 1.
47. In addition to above, it is submitted that the colour of the foam depends on the chemistry of the inputs. Moreover, as shown by the importers that they are getting poor quality foams due to Manali product, is wrong and baseless. The yellow colour shown of the foams is due to the reaction that takes place as they the foam is kept in open for few days. In view of aforesaid, it is clear that colour of the mattress has nothing do with the quality of the subject goods. Moreover and without prejudice, it is settled jurisprudence that quality cannot be an issue in a safeguard investigation.
48. Availability of Major Raw Material for Producing Propylene Oxide: It is submitted by the various interested parties that the availability of major raw material i.e., Propylene was limited due to the fact that domestic industry is only procuring the PO from CPCL. This fact is not correct as they are also procuring the same from Gail, HPCL Vizag, etc. In view of the aforesaid, their arguments hold no water and therefore, needs to be rejected.
49. Price Undercutting, Depression and Suppression: The interested parties have made contradictory statements in relation to price undercutting, depression and suppression. On the one hand, they are alleging that there is no price undercutting, depression and suppression and on the other hand they are admitting that the imported material is cheaper and that is why they are procuring the same (page 1 of the written submissions filed by Dura Puf (Silvassa) Pvt. Ltd.). In view of the current facts, we request the Authority to kindly reject the submissions made by the interested parties. In any case, their contention with regard to the above parameters is factually incorrect as can be seen by the DG from the information available on record.
50. Capacity of the Domestic industry: The Domestic Industry submits that there are no contradictions with regard to their capacities. It is a matter of verifiable fact, that the Domestic Industry has installed Polyol capacity of 50000 MT. This capacity has been indicated in the Annual Report of the applicant also. However, considering the incessant pressure of imports, the Domestic Industry has been utilizing only 25000 MT for the production of the subject goods. As mentioned during the hearing as well as in the written submissions, the Domestic Industry has the capacity to meet the demand and there are no contradictions in their submissions at any stage of the investigations. Therefore, the arguments raised by the interested parties should be rejected.
51. Location Disadvantage: The arguments made by the interested parties that domestic industry is at disadvantage due to its location in south and majority of the foam manufacturers are at north is incorrect and needs to be rejected. The foam manufacturers are located in all parts of the India.
52. Excess Confidentiality: The claims made by the interested parties in relation to excess confidentiality are wrong and ought to be rejected. In this context, the domestic industry has claimed confidentiality only on the information which is business sensitive and disclosure of the same will give advantage to its competitors. In contrast, exporters and importers have claimed confidentiality even on the volume related information. Exporter Shell, who accounts for more than 90% of the imports, has not even filed the exporter questionnaire response while Bayer, who accounts for around 4% of the imports, has filed exporter questionnaire response only with the written submissions. In view of thereof, we request the DG to kindly reject the arguments and compel the exporters to provide a proper confidential and non-confidential version of the questionnaire response in terms of the Trade Notice issued on the subject.
53. It is submitted by the interested parties that several foam manufacturers closed their operations and any safeguard duties will not be in the public interest. In this context, it is submitted that the interested parties have not given even an iota of evidence as to why some of the plants have closed down in the country. Such contentions ought to

be rejected outright. Without prejudice, it is submitted that as per the market intelligence of the Domestic Industry, some of the foam producers have closed down their operations on account of the following fact:

- a. Intense competition from bigger players due to market concentration in their hands.
- b. Inconsistent Cash Flow and poor financial management.
- c. Lack of upgradation of technology.
- d. Taxation disputes including tax evasion cases.
- e. Acquisition of smaller facilities by bigger players
- f. Setting up of new facilities by several companies like Superfoam in Coimbatore and by Hindustan Petrofac at Sonipet, Kundli.

54. It is also submitted that M/s. Sheela Foams, the major importer, has also expanded their facility in Pondicherry to avail tax benefit but subsequently closed it apparently after the tax incentive was over.

55. In view of the above, it is submitted that the closure of foam manufacturers cannot be attributed to the Polyol issues. Therefore, the issue raised with the mischievous intent, needs to be rejected.

56. Domestic Industry is selling its production in entire India from big cooperate houses to small foam manufacturers and to traders. It is important to note that besides some large importers who are themselves importing huge volumes, no other user industry has objected the imposition of Safeguard Duty. Imposition of Safeguard Duty will not only protect the legitimate interest of the Domestic Industry but will also be beneficial for the entire economy. The imposition of the proposed safeguard duty shall be in public interest for the reasons explained below. The effect of safeguard measures on public interest is commonly studied from the perspective of three different parties – the producers, the consumers and the general public at large.

- a. Producers' Interest: The imposition of safeguard duty on imports of subject goods would be in the interest of domestic industry of subject goods. The measure would prevent further injury and give time to utilize its capacities which could not be utilized due to the market share of domestic industry taken by the increased imports.
- b. Consumers' Interest: It would be in the interest of domestic consumers of subject goods to have an Indian domestic industry capable of competing with foreign producers. This is possible when the domestic industry is able to recover from the injury suffered due to the sudden increased imports. If the current situation is allowed to continue, the Indian domestic industry will face further injury giving foreign producers increased leverage as against domestic producers. Further if the domestic industry is allowed to suffer, it will eventually be wiped out and the consumers will be left at the mercy of the imported goods and will have to face many problems which, inter alia, include:
 - High inventory cost
 - Exchange fluctuations
 - Delivery time
 - Technical support
- c. Interest of the Public at Large: It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic industry. This will not be possible if injury to the domestic industry as a result of increased imports is allowed to be continued. Moreover, the impact of duties on the public at large is negligible. The same can be seen from the table below:

| | | |
|---|---------|------|
| Average Mattress Price in Retail (Pair) | Rs/Pair | 6500 |
| Cost of Mattress (Pair) [Foam cost Rs.300/KG + Rs. 700 Fabric cost/pair]. | Rs/Pair | 3100 |
| Profit & Loss | Rs/Pair | 3400 |
| Profit & Loss (as % of Price) | % | 52% |
| Weight per Pair of Mattress | KG | 8 |

| | | |
|---|---------|------|
| FSP | Rs/KG | 140 |
| Weight of FSP in Mattress @ .40/KG | KG | 3.2 |
| Total FSP Cost in Mattress | Rs/Pair | 448 |
| Additional Impact of Safeguard Duties @ 25% | Rs/Pair | 112 |
| Impact of Safeguard Duties @ 25% on Price | % | 1.7% |

- d. From the above table, it is clear that the impact of safeguards duty @ of 25 % on end consumer is hardly anything and forms 1.7% on final product. Consequently, the end consumer of subject goods will not face any significant increase in prices.
 - e. The kind attention of the DG is invited to the recent decision of “Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel) [F. No. D-22011/17/2012 dated 11.3.2014], wherein the DG has recorded that if the user industry is in the position to bear the impact of duties, then in that case imposition cannot be said to be against public interest.
 - f. If the protection is not provided to the Domestic Industry at this stage, there is danger that Domestic Industry cannot sustain its business in long run and eventually decides to either close down operations as done by M/s. Expanded Polymers. This closure will be more disastrous for the foam manufacturers as their continuous and reliable supply of raw material will be closed and they have to be totally dependent on the mercy of the exporters. Thus, it is a clear of protecting the long term public interest which will eventually be in the interest of the user industry as well.
57. In view of the above submissions, domestic industry submits that:
- (a) The imports of subject goods have shown a recent, sharp, sudden and significant increase.
 - (b) The increased imports of subject goods have caused serious injury or threat of serious injury to the domestic industry to the domestic industry, and
 - (c) A causal link exists between the increased imports and market disruption or threat to market disruption.
 - (d) In view of the aforesaid, the Domestic Industry implores that the DG (Safeguards) may kindly recommend appropriate duties at the earliest to mitigate the problems being faced by the Domestic Industry on account of significantly increased imports.

II. Rejoinder by Exporters

1. DCIPL and Dow Europe.

1. The instant rejoinder submissions are further to the preliminary submissions filed on 25 July, 2014, power point presentations made on 29 September, 2014 and the post hearing written submissions filed on 10 October, 2014. DCIPL and Dow Europe refer to and rely upon the aforesaid submissions and the same are not being reiterated herein for the sake of brevity.
2. Additionally, DCIPL and Dow Europe take this opportunity to submit the following limited rejoinder to the written submissions filed by the domestic industry:
3. Domestic Industry's claim that Expanded Polymers produced only 6 MT during POI is erroneous. It is submitted that Expanded Polymer at the time of public hearing held on 29 September, 2014 informed that they had produced 800 MT in 2012-13 and 6 MT in 2013-14. Therefore, DI cannot claim that they are the sole producer of the subject goods during POI.
4. The data submitted by DI in its written submissions is not in line with the Initiation Notification issued by DG, Safeguards. Therefore it is humbly requested that the data and facts submitted by the DI be strictly scrutinised and verified. This is important since the data furnished by DI purports to show increase in imports, whereas the data set out in the Initiation Notification does not show such increase in imports of the PUC, so as to trigger the imposition of a safeguard duty on the subject merchandise.
5. Apropos paragraph 39, it is submitted that reliance on Annual Reports of the Company for the POI is not only warranted but necessary to gauge the true and real financial condition of the DI and more so in this case where the data given by the DI is not reliable. It is submitted that the Annual reports of the DI clearly mentions about the Product under consideration(PUC) in all the years and reliance on Annual Reports is warranted as it is the only document which shows the reality of the DI. Had the information set out in the Annual Report of the company not been relevant, it would not be a requirement to furnish Annual Reports of the Domestic Industry as part of the Application by the DI seeking the imposition of Safeguard duty.

7. Apropos paragraph 39 (i) though DI has stated they have 3 sources of power, it is submitted that bio mass fuel is ineffective due to non-availability of wood and reliance on diesel power is also too costly which make these sources of power cost inefficient.

8. The Initiation Notification states that DI has capacity of 25,000 MT for flexible slab Polyol but now DI seems to submit that 50,000MT capacity for polyol can be used for the production of the subject goods. It is submitted that the 50,000 MT is the overall capacity for the entire Polyol segment and as accepted by the DI during public hearing, the focus of DI would be on high margin products and their interest is to produce high molecular weight products and not the FSP. This is already substantiated by Dow in its earlier responses demonstrating how DI's revenue from Polyol has consistently increased during POI.

9. DI submits that it has adequate supply of Propylene Oxide (PO) and that it has made PO storage facility at ETTL which allows them to import large quantities. In this regard, it is submitted that DI fails to admit that PO facility was ready to receive bulk PO only by end of 2013 and till that time DI was constrained to import higher quantities of PO imports in isotanks which made DI's cost of production sub optimal.

10. Further, DI has nowhere provided a reason as to why they expanded their Polyol capacity before ensuring adequate measures to import PO which is the key raw material for the PUC. It is once again submitted that it is this inability of DI to import PO, during the POI, while having increased capacity for Polyol which is the key factor for their lower capacity utilization. We accordingly request the learned DG Safeguards to investigate this aspect.

11. In light of the previous submission and all that has been stated above, it is once again reiterated that no case for imposition of safeguard duty has been set out and the Learned DG Safeguards should immediately terminate the instant investigation. Even otherwise, the case of DI deserves to be rejected due to inaccuracy of data, suppression misrepresentation of key data and essential information.

2. Rejoinder Bayer and Shell

Detailed para-wise submissions of the Respondents to the written submissions filed by the Applicant are as follows.

- A. The contents of para 1 of the written submissions filed by the Applicant (hereinafter referred to as the "written submissions") are factual and require no rebuttal.
- B. With regard to the contents of paras 2-3 of the written submissions, the Respondents reiterate all previous submissions made on the issue of standing of the Applicant.
- C. The contents of para 4 -9 of the written submissions are denied. The Respondents have scrupulously adhered to all the time limits prescribed by the DGSG and have filed all comments within 40 days of the initiation notification. Furthermore, the Respondents have also made detailed submissions as to the numerous inaccuracies in the petition filed by the Applicant which are not being repeated here for the sake of brevity. It is also interesting to note that in para 6 the Applicant has stated that it is seeking protection from "dumped" goods. The Respondents submit that if the Applicant is seeking protection from dumped goods then the correct forum is the Directorate General of Anti-dumping & Allied Duties, and the present investigation must be terminated. Additionally, the Respondents clarify that despite repeated requests by way of letters and submissions dated 16th June, 2014, 23rd June, 2014, and 25th September, 2014 and 10th October, 2014, information and clarifications requested have not been provided to the Respondents.
- D. With regard to the contents of paras 10-12, the Respondents contend that the import statistics needs to be verified to ensure that it only contains import statistics pertaining to the product under consideration and not any other variants of such product.
- E. The contents of paras 13-17 are denied as being wrong and incorrect. The Respondents reiterate submissions made previously on the issue of allegedly increasing imports and additionally emphasizes on the following points:
 1. For a proper analysis of all the claims in the petition, it is requested that either the DGSG or the Applicant shall provide the transaction-wise raw import data as well as sorted import data to interested parties in MS-Excel format. The DGSG is also requested to direct the Applicant to provide an explanation as to how it has sorted data from the raw data.
 2. The MS-Excel version of import data is relevant because there exists double counting and duplication of imports which has resulted in inflated volume of imports from Singapore. The Respondents wish to highlight that when the subject products are imported into India, they are first stored in customs bonded warehouses by filing a warehousing Bill of Entry and then removed in small quantities, by filing a Bill of Entry for home consumption over a period of time.
 3. Even after repeated requests of the Respondents for providing the import data in MS-Excel format, neither the DGSG nor the applicant provided the same to the Respondents. Therefore, the Respondents procured the import data of Custom Tariff item 39072010 of Chapter 39 of the Custom Tariff from INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION SERVICES to analyse the volume of imports during the Period of Investigation. In order to

arrive at the correct volume of imports of the subject goods, the following procedure has been adopted by the Respondents:

- (a) The scope of the product under consideration is Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000. Based upon the brand names of various manufacturers/exporters as provided by the domestic industry, the Respondents first identified the imports of Flexible Slabstock Polyol (of any molecular weight) from the raw data.
- (b) After that imports of Flexible Slabstock Polyol of other molecular weights (more than 4000 and less than 3000) were excluded.
- (c) Thereafter, the instances of double counting, wherever identifiable were removed from the import statistics.
- (d) After following the steps enumerated in points a, b and c above, the correct imports statistics for Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 was arrived at.
- (e) It can be seen by the DGSG that there is no increase in imports during the POI if the correct import statistics are taken into account. Infact, the import volume is showing a declining trend.

| <i>Year</i> | <i>Imports (MT)</i> |
|--------------------|---------------------|
| 2010-11 | 48,485 |
| 2011-12 | 22,133 |
| 2012-13 | 28,223 |
| 2013-14 | 34,727 |
| Grand Total | 133,568 |

4. Detailed workings of import data in this regard are attached as Exhibit 1.
 5. The Respondents request the DGSG to kindly go through the workings done by the respondents and let us know if DGSG has any issues in the working as submitted.
 6. The Respondents also contest the annualized figures arrived at by the authority for 2013-14 on the ground that such figures are inaccurate and liable to be rejected. It is noted that the annualized figures provided in the initiation notice are inflated and do not reflect the correct position. The Respondents submit that to the best of their knowledge, BASF has stopped the sale of subject goods in Southeast Asia which would result in lower imports into India during the second half of 2013-14.
 7. The import quantity given in the initiation notice and petition filed by the Applicant are contradictory and required to be investigated by the DGSG.
 8. Even if there was an increase in imports, the Applicant has not identified any unforeseen development or the effect of an obligation under GATT 1994 which has caused such increase in imports, as per the mandatory requirement under Article XIX of GATT 1994. The Respondents reiterate their earlier submission that imports may be attributed to the Comprehensive Economic Partnership Agreement (“CECA”) presently in existence between India and Singapore, which has made it attractive for imports of the subject goods into India from Singapore. It may be noted that the import duty on the subject goods was reduced to 0% vide Notification No. 106/2011 dated 1st December, 2011.
 9. The Respondents also additionally wish to clarify that India–Singapore CECA does not satisfy the requirement of an unforeseen development under Article XIX as the timetable specifying the rate of reduction of anti-dumping duty was publicly available soon after the conclusion of the India-Singapore CECA in June 2005. Therefore, there is simply no way in which it could not have foreseen that the duty rates on the subject goods would be progressively reduced as per the timetable specified in India’s schedule of commitment under that Agreement. An increase in imports due to the 0% duty under the India-Singapore CECA also cannot be an unforeseen development or an obligation under GATT as per Article XIX as held by the panel in DS 415-418 *Dominican Republic – Safeguard Measures* wherein the panel concluded that to the extent, the obligation in issue undertaken by Dominican Republic was that under a regional free trade agreement rather than that under the GATT, the requirements of Article XIX were not met.
- F. The contents of paras 18–35 are denied as wrong and incorrect. The Respondents have made detailed submissions on the issue of “serious injury” allegedly suffered by the Applicant and additionally reiterate the following contentions:
- i. At the outset, the Respondents submit that there are numerous inconsistencies between the data submitted by the Applicant in its petition for imposition of anti-dumping duty, and the data provided in the Initiation Notification dated 22nd May, 2014 communicating the initiation of safeguard investigation against the subject goods.

- ii. It may also be noted that the Applicant has sold almost all the quantity of the subject goods that it has produced, given that sales as a percentage of production was 101% in 2010-11, 99% in 2011-12, 96% in 2012-13 and 98% in 2013-14. This establishes that the Applicant has no problem in selling the subject goods; its issues lie in production.
 - iii. Furthermore, in the initiation notice, indexed figures relating to profitability have been indicated to be 100 indexed points in 2010-11, with a rapid and substantial increase to 324 indexed points in 2011-12 and a decline to (331) indexed points in 2012-13 and (559) indexed points in POI. Similarly, in the petition filed by the Applicant, the selling price has increased from 100 indexed points in 2010-11 to 115 indexed points in 2011-12, reduced to 110 in 2012-13 and again increased to 128 indexed points in 2013-14. With regard to cost of sales, it increased from 100 indexed points in 2010-11 to 120 indexed points in 2011-12, reduced to 102 indexed points in 2012-13 and once again increased to 124 indexed points in 2013-14.
 - iv. It can be seen that when the cost of sales increased by 20% and selling price increased by 15% in 2011-12, the Applicant's profit tripled. However, in 2012-13 when the Applicant's selling price decreased by 4.35% and cost of sales also decreased by 15%, the Applicant suddenly went into substantial losses at (331) indexed points. The trend of profitability from the above table reveals the data to be suspect. It is not possible for profitability to triple when there is an increase in cost of sales, but plummet rapidly when cost of sales decreases. The trend reveals that the data relating to profits may not be accurate, and in light of the same, the Respondents request the DG (Safeguards) to investigate the same.
 - v. In addition to the above, the market share of sales of the Applicant in proportion to total consumption has declined from 39% in 2010-11 to 28% in 2011-12, to 22% in 2012-13 and to 18% in POI. However, as highlighted above, because of the fact that the Applicant is unable to produce a sufficient quantity with inadequate reserves of the feedstock (Propylene Oxide) required for the manufacture of the subject product.
 - vi. Furthermore, it is submitted that even if the Applicant were to operate at 100% capacity utilization, at best, it will be able to cater to only about 34% of the market, because it only has installed capacity of 25000 MT while the total demand during 2013-14 was 74624 MT. Therefore, users in India will necessarily have to import at least 66% of the required demand, and if they do not want to be dependent on a sole supplier, invest in sustainable relationships abroad to secure longer term supplies.
- G. The contents of paras 36–42 are denied as being wrong and incorrect. The Respondents reiterate all previous submissions made on the requirement to establish causal link between imports of the subject goods and alleged serious injury suffered by the Applicant. In addition to the above, the Respondents reiterate the following submissions:
- i. The Applicant has stated in para 39 that the arguments relating to inability of the Applicant to produce the subject goods had been made in a generalized manner without adequate proof. The Respondents submit that the Applicant's own Annual Reports had been provided as evidence in earlier submissions, and the Applicant cannot consider this as inadequate evidence.
 - ii. Furthermore, the Applicant has made certain claims in para 39 that it has made arrangements to import PO and to otherwise produce PO. The Respondents see no difference in this situation than what was already being done by the Applicant. Nowhere has the Applicant clarified how it is going to procure Propylene which is the key raw material for producing PO and how the Applicant proposes to overcome the problem of global supply shortage of Propylene. Furthermore, the Applicant has stated that it has made PO storage facilities. It must be noted that such bulk storage may still be in progress and not yet been completed. The same is admitted by the Applicant in Annual Report 2012-13 on page 179 of the petition.
 - iii. The Applicant has also claimed in para 39 that the moratorium in the Manali area has been lifted in September 2013. The Respondents requests the Applicant to supply some sort of evidence to substantiate this claim. In any case, any increase in capacity will not reduce the alleged injury being suffered by the Applicant due to the aforementioned issues with the procurement of raw material.
 - iv. The Applicant has argued in paras 40 – 41 that imports need not be the sole factor to cause injury. In this regard, the Respondents submit that the decision cited by the Applicant only serves to emphasize that there must exist a causal link between the alleged "serious injury" sustained by the Applicant and imports of the subject goods. While imports need not be the sole cause of injury to the domestic industry, it must be the predominant cause of any injury suffered by the Applicant. In the present investigation, any injury sustained by the Applicant is due to its own inability to produce and not due to imports of the subject goods. This breaks the causal link between increased imports of the subject goods, and alleged "serious" injury" sustained by the Applicant.
 - v. It is submitted that the reason for the decline in production and sales during 2012-13 and 2013-14 is not due to the volume of imports, but the non-availability of feedstock for the production of the subject product. It is noted that there is a severe shortage of Propylene Oxide (PO) which is the feedstock used for the manufacture of the subject product. PO is manufactured from Propylene.

- vi. Additionally, the reason for reduction in capacity utilization is due to the lack of availability of feedstock Propylene Oxide (PO) as highlighted above which would lead to non-utilization of capacity and a reduction in capacity utilization.
 - vii. It is reiterated that as per the submission of the Respondents made above, the Applicant was not able to achieve profitability due to its inability to procure adequate amounts of feedstock (PO), and subsequent inability to manufacture and sell the subject product.
 - viii. However, from the submissions of the Respondent above, it is clear that any “serious injury” that may have been sustained by the Applicant is due to a number of other factors such as lack of feedstock availability; consequent reduction in production and sales; dependence on sole supplier of propylene in India, Chennai Petroleum Corporation Ltd; and inability of the Applicant to supply the required quantity of the subject goods.
- H. The contents of paras 43–47 are denied as being wrong and incorrect. The Respondents reiterate their earlier submissions on the non-viability of the adjustment plan provided by the Applicant. Furthermore, the Respondents request the Applicant to provide cogent evidence to substantiate its claim that the storage facility of PO commissioned at Ennore Tank Terminal Pvt Ltd (ETTPL) has started working.
- I. The contents of paras 48-53 are denied as being wrong and incorrect. The Respondents reiterate all submissions made previously on the mandatory requirement on the Applicant as well as the DGSG to identify and analyze unforeseen developments and obligations under GATT 1994.
- J. The contents of para 54 are denied as being wrong and incorrect. The Respondents have submitted all the required information to the DGSG. Additionally, it may be noted that it is not mandatory to submit the Exporters Questionnaire Response in a safeguard investigation. If the DGSG requires any other information, the Respondents would be happy to provide the same.
- K. The contents of paras 55-56 are denied as being wrong and incorrect. The contents of paras 15-16 are denied as being wrong and incorrect. The Respondents have submitted all the required information to the DGSG, and the DGSG has accepted its claim of confidentiality. If the DGSG requires any other information, the Respondents would be happy to provide the same. Additionally, the petition filed by the Applicant is deficient as it contains a number of unwarranted confidentiality claims.
- L. The Respondents further request the DGSG to consider all previous submissions as part and parcel of these submissions which have not been repeated here for the sake of brevity.

E. Findings of the Director General:

1. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, user/importers and exporting nations. Submissions made by the various parties and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places in the findings below.
2. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports into India on non discriminatory basis. Section 8B(1) provides for imposition of Safeguard Duty on the article if the article is being imported into India, in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to the Domestic Industry.
3. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation.
4. Accordingly, the investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification.

A. The product under investigation:

5. The product under investigation is Flexible Slabstock Polyol (FSP) of molecular weight 3000 to 4000. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging.
6. Flexible Slabstock Polyol (FSP) is classified under Customs Tariff Heading No. 39072010 and 39072090 under the Customs Tariff Act, 1975.
7. The product under investigation is Flexible Slabstock Polyol (FSP) of molecular weight 3000 to 4000. The interested parties have not raised any issue with regard to the product under investigation.
8. Therefore, domestically produced Flexible Slabstock Polyol (FSP) of molecular weight 3000 to 4000 falls under the ambit of like or directly competitive product in all respects to the imported Flexible Slabstock Polyol (FSP) and that the domestically produced Flexible Slabstock Polyol (FSP) is a like article to the imported Flexible Slabstock Polyol (FSP) (hereinafter referred to as 'PUC') within the meaning of Rule 2(e) of Safeguard Duty Rules 1997.

B. Domestic Industry:

9. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act, 1975 defines domestic industry as follows:

(b) “Domestic industry” mean producers –

(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.

10. The application has been filed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd., Chennai through their consultant M/s. APJ-SLG Law Offices for imposition of Safeguard Duty on imports of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 (hereinafter referred to as PUC) into India to protect the domestic producers of PUC against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of PUC into India. The applicants claimed to be the only producer of PUC. The information on record shows following volume of production of like or directly competitive article in the Country-

| Description | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Applicants | MT | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |
| Other Indian producers | MT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Indian production | MT | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |
| Share of applicants % | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

11. Further claim has been made by the interested parties against the applicants being the sole producer of PUC. They have named M/s. Expanded Polymers Pvt. Ltd., as another manufacturer of PUC. M/s. Sheela Foams also provided details of 80 MT of PUC sold by M/s. Expanded Polymers during 2011-12 and 2012-13. Accordingly, information was called from the Jurisdictional Excise Authorities who have provided the production clearance data in respect of PUC. From the perusal of data it is clear that M/s. Expanded Polymers is only producing negligible quantity of PUC. After, assessing the information received from the Jurisdictional Excise authorities with the information available in r/o DI the following details emerge:-

| Description | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Applicants | MT | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |
| Other Indian producers | MT | 533 | 2011 | 405 | 258 |
| Total Indian production | MT | 17043 | 20392 | 14391 | 14069 |
| Share of applicants % | | 96.87 % | 90.14 % | 97.18 % | 98.16 % |

Therefore, it is held that the applicant represents the domestic industry (DI) within the meaning of Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act, 1975.

C. Period of Investigation (POI):

12. The Customs Tariff Act, 1975, Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. From several case laws on safeguard measures, it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Article XIX of GATT provides specific guidelines on the period of investigation except the fact that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased imports and serious injury.

13. The applicants in the instant case submitted import and injury data from 2010-11 to 2013-14. The Directorate conducted the verification of data pertaining to injury parameters to the extent possible, starting from 2010-11 upto 2013-14, and the Notice of Initiation was issued incorporating import and injury data from 2010-11 to 2013-14 (upto Dec-2013) on 22.5.2014.

14. Subsequently, the applicant submitted the import data for the period January, 2014 to March, 2014. The additional information of 3 months was made available to all concerned and kept in the Public File as required under Rule 6(7) of Safeguard Rules 1997.

15. Considering that the period selected should be sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding existence of increased imports and to neutralize the effect of seasonal variation, data has been considered from F.Y. 2010-11 to 2013-14. In the notice of initiation, import data upto Dec 2013 had been considered. The import data has since been updated till March, 2014. The period has been taken from 2010-11 till 2013-14 for the purpose of the present investigations. The petition/Notice of Initiation contained data for the period up to Dec., 2013. The interested parties have argued that it would not be appropriate to annualize April-Dec., 2013. I therefore consider appropriate and necessary to use data for the period up to March, 2014.

D. Source of data:

16. The import data from 2010-11 up to 2013-14 has been taken from DGCI & S in consonance with data already taken in Notice of Initiation. An objection was raised regarding the correctness of import data on the grounds that the tariff heading also contains PUC of specifications other than PUC of molecular weight 3000-4000 and that the data contains certain double entries for import. M/s. Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd., /M/s. Shell Eastern Trading (Pte) Ltd., and M/s. Bayer (South East Asia) Pte Ltd., (both represented by M/s. Lakshmi Kumaran & Sridharan, Advocates) also provided transaction wise data from IBIS and ISCECA No's detailing the double entries of import data. Accordingly, to verify the import data, Transaction wise data was called for from DGCI & S. The DI and the interested parties also provided the brand names of the PUC to sort the transaction wise data to get the correct import figures of PUC. The transaction wise data was also checked for double entries. The data on various economic parameters submitted by the domestic industry in their petition till 2013-14 has been verified by this directorate to the extent possible and the verified data has been taken into consideration for injury analysis.

E. Confidentiality of Information submitted

17. The domestic industry has provided information on confidential basis and sought confidentiality on the information/data so submitted. The domestic industry provided non confidential version of all submission including the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules, 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dt. 06.09.1997.

18. Rule 7 of the Safeguards Rules and Article 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provide for confidentiality. The applicants is not required to disclose such information which is confidential information of an individual company, disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of the company, which is not in public domain and which the applicants has not disclosed before public at large in the past. Accordingly confidentiality, as prayed for by domestic industry is granted.

F. Increased Imports:

19. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose Safeguard Duty and provides as follows:

1. *"If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article:"*

20. Further, Rule 2(c) of Customs Tariff ((Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides as follows:

"(c) 'Increased quantity' includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production"

21. The rules require a determination of whether the product under consideration is imported into India in increased quantities as a basic prerequisite for the application of a safeguard measures. To determine whether imports of the product under consideration have "increased" "in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the rate and amount of the increase in imports, in absolute terms and in relation to domestic production and consumption, as has been held by the panel and later confirmed by the Appellate Body in Argentina – Footwear case¹ also.

22. In its evaluation of whether the investigation by the Argentine Authorities *Appellate Body Reports on Argentina — Footwear (EC) WT/DS121/AB/R dated 14 December, 1999* demonstrated the required increase in imports under Articles 2.1 and 4.2(a), the Panel in Argentina-Footwear case 2 stated the following:

... the Agreement requires not just an increase (i.e., any increase) in imports, but an increase in "such...quantities" as to cause or threaten to cause serious injury. The Agreement provides no numerical guidance as to how this is to be judged, nor in our view could it do so. But this does not mean that this requirement is meaningless. To the contrary, we believe that it means that the increase in imports must be judged in its full context, in particular with regard to its "rate and amount" as required by Article 4.2(a). Thus, considering the changes in import levels over the entire period of investigation, as discussed above, seems unavoidable when making a determination of whether there has been an increase in imports "in such quantities" in the sense of Article 2.1. (emphasis added)

23. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC)³, in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extracts are as follows:

"131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfil this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."

24. The Panel on US — Wheat Gluten 4, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:

*"8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."*² Panel Report on Argentina — Footwear (EC) WT/DS121/R dated 25 June 1999 ³ Appellate Body Reports on Argentina — Footwear (EC) WT/DS121/AB/R dated 14 December 1999 Panel Report on US — Wheat Gluten WT/DS166/R 31 July 2000

25. In US — Line Pipe, the Panel found, in a statement not reviewed by the Appellate Body, that the word "recent" implies a "retrospective analysis"; but that it does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation. Relevant extracts are as follows:

"7.024 [W]e note that the Appellate Body in Argentina-Footwear Safeguard found that 'the phrase "is being imported" implies that the increase in imports must have been sudden and recent'. According to Korea, the phrase 'is being imported ... in such increased quantities' refers to 'the period immediately preceding the authority's decision'. The word 'recent' — which was used by the Appellate Body in interpreting the phrase 'is being imported' — is defined as 'not long past; that happened, appeared, began to exist, or existed lately'. In other words, the word 'recent' implies some form of retrospective analysis. It does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision. Nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation. We consider that an analysis that compares the first semester of 1998 with the first semester of 1999 is not inconsistent with the requirement that the increase in imports be 'recent'."

26. The analysis of the increased imports of Flexible Slabstock Polyol (PUC) has been conducted in the light of the above mentioned evaluations. Flexible Slabstock Polyol (PUC) is imported into India from a number of countries, and primarily from Singapore. It has been argued by interested parties that:-

(a) As the data of import has been taken chapter heading wise, the same may also contain data in respect of products other than PUC of Molecular weight 3000 to 4000. The transaction wise data was called for from DGCI&S. The DI/M/s. Shell /M/s. Sheela Foam provided the brand names of the PUC of MW 3000 to 4000 being imported into India. Accordingly, the transaction wise data was sorted in view of the details provided by the DI vide letter dated 2.12.2014, 9.12.2014 and by M/s. Lakshmi Kumaran (M/s. Shell) vide letter 5.11.2014. The brand names i.e. Alcupol F5511, Arcol Polyol 5613, Caradol SC 5615, SC 5616, SC 5616S, SC 4803, SC 4808, Excenol 3031, Sannix GP 3030, Petol 48-03, Petol 53-03, Polyol Dep 5631D, Polyol JH 3031 K, PPG 3001, PPG 3022, PPG JH 3031, Raypol 3003, Voralux HL 106, Yukol 5613, Yukol 5603, Konix GP 3001, Laprol 3003, Lupranol 2025 SG, Voranol 1900, Voranol 3010, 3136, 3010,3322, 3595, 3943 as intimated by the DI /Shell/Bayer /Sheela Foam and searched from internet have been taken into consideration for sorting of the data.

(b) The Interested parties have also raised an issue that the import data contains duplicate entries of imported goods, first from the Bill of Entries for import of goods into India and second from the same goods being cleared from Customs Warehouses. M/s. Shell vide letter dated 5.11.2014 also provided the details of ISCEAC no. showing duplicate entries of the imported goods on the basis of IBIS data. M/s. Shell vide letter dated 11.12.2014 again reiterated that the import data contains duplicate entries. The ISCEAC numbers as provided in respect of the duplicate entries were checked in the transaction wise data received from DGCI&S and it was observed that there are no duplicate entries in the transaction wise data provided by the DGCI&S.

(c). The Rules require the designated authority to examine not only increased imports but also the conditions under which such imports have been made. Section 8B(1) requires the Director General to examine whether the article is imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. Thus, the conditions, under which the increased imports have been reported, are also relevant.

27. In view of the above, I have determined increased imports of Flexible Slabstock Polyol (PUC) for the POI on the basis of transaction wise data received from DGCI&S (Sorted on the basis of suggestion/inputs given by DI and Interested parties) which is as under:

(a) Imports:

| Description | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Total Imports | MT | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 |
| Trend | | 100 | 111 | 146 | 159 |

28. The import has increased both in absolute and relative terms. Imports increased from 31778 MT in 2010-11 to 50632 MT i.e. by 59% viv-i-vis base year (2010-11).

(b) Import in relation to production:

29. It is seen that during the POI, imports have also increased in relation to total domestic production, as shown below:

| Description | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| Total Indian Production | MT | 17043 | 20392 | 14391 | 14069 |
| Imports | MT | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 |
| Imports relation in to production | % | 186 | 173 | 322 | 360 |

There is a increase of imports to the total production to 360% in 2013-14 from just 186% in 2010-11.

(c) Import in relation to consumption/demand:

| Description | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| Demand/Consumption | MT | 48896 | 55369 | 60341 | 64462 |
| Trend | % | 100 | 113 | 123 | 132 |
| Imports | MT | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 |
| Imports in relation to Demand/consumption | % | 65 | 64 | 77 | 79 |
| Trend | % | 100 | 98 | 118 | 121 |

30. However, between 2010-11(base year) and 2013-14, whereas the demand/consumption increased by 32%, the imports increased only by 21% in relation to total demand.

31. It is thus seen that Flexible Slabstock Polyol (PUC) has been imported into India in increased quantities in absolute terms as compared to the domestic production. Between 2010-11(base year) and 2013-14, the domestic demand/consumption increased by 32%, whereas, the imports increased only by 21%. It is held that the increase in imports shows a rising trend with relation to the base year (2010-11) which is significant enough to constitute “increased imports” within the meaning of Section 8B of the Act.

G. Unforeseen Developments:

32. It is noted that there is no specific requirement either in Indian Rules or in WTO Agreement on Safeguards on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments. The Agreement on Safeguard also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. However, it is important to examine the circumstances which have led to increased imports.

33. In Argentina — Footwear (EC) and Korea — Dairy, the Appellate Body held that “any Safeguard measure imposed after the entry into force of the WTO Agreement must comply with the provisions of both the Agreement on Safeguards and Article XIX of the GATT 1994. Article XIX of GATT 1994 states as follows ;-

1. (a) If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.

34. The Appellate Body in Argentina – Footwear (EC case) held that the phrase unforeseen developments means the developments which were unexpected. ‘Unforeseen developments’ requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been ‘unexpected’. The Body in the same case noted a GATT panel report which held that the development must have been unforeseen at the time of tariff negotiation. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

35. The Appellate Body, in Argentina — Footwear (EC), then held that the requirement of “unforeseen developments” did not establish a separate “condition” for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of “circumstances”.

36. The panel on US-Steel Safeguards concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development:

“..... The United States argues that the robustness of the US dollar was a development which combined with the other developments, namely, the currency crises in Asia and the former USSR and the continued growth in steel demand in the United States’ market as other markets declined, lead to increased imports.”

37. I find that the applicant has intimated that the surge in imports is due to the price attractiveness of the Indian market combined with the excess capacities in Singapore. It has been contended by the DI that the exporters in Singapore are exporting the PUC at non-remunerative prices. However, I find that no evidence to support their contention has been submitted by the DI. The DI has further claimed that due to Indo-Asean FTA and Indo -Singapore CECA the international major suppliers have made special arrangements to control the market and supply chain with the motive of deriving undue benefit to the detriment of the DI. However, in this regard also no supporting evidence has been furnished by the DI.

38. At the time of Personal Hearing the DI also alleged that 98% of imports are from Singapore and the suppliers are using the provisions of the Indo-Asean FTA and Indo-Singapore CECA. It has been alleged by DI that they could not anticipate the collusion of exporters to take advantage of the trade agreements.

39. The Indo-Singapore CECA was made in the year 2005 and the duties have been gradually decreased. The agreements are in public domain and it is common knowledge that the the customs tariffs would gradually come down. The effective customs duties from the years 2008 onwards are enumerated below:

| Year | Particulars | Rate of Duty |
|------|--|--------------|
| 2008 | Notification No. 10/2008 dated 15th January 2008 | 6% |
| 2009 | Notification No. 70/2009 dated 19th June 2009 | 4.5% |
| 2009 | Notification No. 150/2009 dated 31st December 2009 | 3% |
| 2010 | Notification No. 131/2010 dated 24th December 2010 | 1.5% |
| 2011 | Notification No. 106/2011 dated 1st December 2011 | 0% |

40. The DI being the major producer of PUC would have been aware of the same. Hence, the condition of unforeseen circumstances is not fulfilled by the DI. In the present case the majority of the imports(as per the DI and DGCI&S data) are from Singapore and therefore, I hold the rise in import of Flexible Slabstock Polyol (PUC)from Singapore can not be an unforeseen development resulting in increase in imports causing serious injury or threat of serious injury to the domestic industry.

H. Serious Injury or Threat of Serious Injury:

41. “Serious injury” means an injury causing overall impairment in the performance of the domestic industry; and “threat of serious injury” means a clear and imminent danger of serious injury.

42. The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is “declining”. In one case, for example, “overall impairment” of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

43. In *Argentina — Footwear (EC)*⁶, the Appellate Body discussed the relationship between the definition of “serious injury” in Article 4.1(a) and the requirement of an evaluation of “all relevant factors” in Article 4.2(a):

“[I]t is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is ‘a significant overall impairment’ in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is ‘declining’. In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show ‘significant overall impairment’ in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate ‘significant overall impairment’ of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of

'serious injury' in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of 'serious injury'."

44. The Panel on *US — Wheat Gluten*⁷, in a finding upheld by the Appellate Body, elaborated on the meaning of the term "serious injury": "[A] determination as to the existence of such 'significant overall impairment' can be made only on the basis of an evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry....

"[W]e do not consider that a negative trend in every single factor examined is necessary in order for an industry to be in a position of significant overall impairment. Rather, it is the totality of the trends, and their interaction, which must be taken into account in a serious injury determination. Thus, such upturns in a number of factors would not necessarily preclude a determination of serious injury. It 6 Appellate Body Reports on *Argentina — Footwear (EC) WT/DS121/AB/R* dated 14 December 1999 is for the investigating authorities to assess and weigh the evidence before them, and to give an adequate, reasoned and reasonable explanation of how the facts support the determination made."

45. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury, all factors which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions which are relevant to the affected industry have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

46. It is held that the increased imports of Flexible Slabstock Polyol (PUC) have not caused or are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Flexible Slabstock Polyol (PUC) as indicated by the following factors:

(i) Market Share:

47. It is seen from the table below that the market share of the domestic industry in the total consumption has decreased.

| Financial Year | Total Import(MT) | Sales of DI (MT) | Total Demand (MT) | Market Share(%) | | Inventories (MT) |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | | | | DI | Import | |
| 2010-11 | 31778 | 16,615 | 48896 | 34 | 65 | 319 |
| 2011-12 | 35186 | 18,192 | 55369 | 33 | 64 | 691 |
| 2012-13 | 46364 | 13,451 | 60341 | 22 | 77 | 637 |
| 2013-14 | 50634 | 13,473 | 64462 | 21 | 79 | 645 |

48. The market share of the domestic industry has decreased from 34 % (2010-11) to 21 % (2013-14). The total demand has increased from 48896 MT in 2010-11 to 64462 MT in 2013-14. The Inventory has increased from 2010-11 to 2011-12 but has remained almost similar during 2012-13 and 2013-14.

(ii) . Production:

49. The production has been determined on the basis of production reported by the Domestic Industry in its excise records. The statistics relating to production pertaining to the domestic industry is shown below.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|----------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Total Capacity | MT | 18375 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Production | MT | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |

50. It is seen that the production of the domestic industry was increasing from 16510 MT to 18381 MT during 2011-12 but has remained similar during 2012-13 and 2013-14. The DI has not utilised its full capacity at any time during the POI not even during 2010-11 and 2011-12. The low production can also be attributed to the reason that their captive power plant was also running on lower loads so as to have adversely impacted its operations. In its annual report for 2013-14 on page 2 of the annual report under the head Operational highlights the DI has stated that- "*the availability*

of bio mass fuel for the Captive Power Plant (CPP) continued to be limited due to demand from paper mills and also similar power plants. Even at increased costs supplies were not forthcoming, forcing the company to operate the CPP at lower loads. Alternate fuels for the CPP are being tried to ensure operations at optimum load. The company went in for purchase of power through energy exchanges and third parties to meet the short fall. These resulted in higher cost of power and consequently the profitability was also impacted. “

(iii). Domestic sale:

51. The sale of the domestic industry has been determined on the basis of goods cleared by the Domestic Industry from their factory premises for domestic market, as reported in their excise records. The table below contains sales by domestic industry and total export.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Sales Volume – Domestic | MT | 16615 | 18192 | 13451 | 13473 |
| Sales Volume -Exports | MT | 0 | 0 | | 505 |
| Sales Volume -Total | MT | 16615 | 18192 | 13451 | 13978 |

52. It is seen that the domestic sales grew from 16615 MT (2010-11) to 18192 MT (2011-12) and decreased to 13451MT and 13473 MT subsequently during 2012-13 and 2013-14. However, it is seen that the domestic demand has been growing year on year basis. The sales volume has also been stable during the year 2012-13 and 2013-14.

(iv). Capacity Utilization:

53. Capacity utilization of the domestic industry was as follows –

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Plant Capacity | MT | 18375 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Production of PUC | MT | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 |
| Capacity utilization | % | 90 | 74 | 56 | 55 |
| Domestic demand | MT | 48896 | 55369 | 60341 | 64462 |
| Trend of capacity wrt total demand | % | 38 | 45 | 41 | 39 |

54. It is seen that the capacity utilization of the domestic industry is showing a decreasing trend but has stabilized during 2012-13 and 2013-14. However the ratio of the capacity of the DI (even after capacity enhancement during 2011-12 from 18375 to 25000) is less than 50 % of the domestic demand. The total capacity of domestic industry to produce the product under consideration is not sufficient to cater to the total demand in India.

(v). Inventories:

55. The Inventory has increased from 2010-11 to 2011-12 but has remained almost similar from 2011-12 onwards indicating therein that the sales pattern has stabilized. The DI is able to sell all its production as the inventories position stabilised from 2011-12 to 2013-14.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|-------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Inventories | MT | 319 | 691 | 637 | 645 |

(vi). Employment and productivity:

56. There is no significant change in the level of employment and in productivity over the injury period. It has shown normal growth over the period. It is observed that these parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of imports on the domestic industry. The DI is running an automated plant and hence the level

of employment is not dependent on the production but on the automation of the plant and machinery. With better automation the employment decreases.

(vii). Profit & Loss:

57. The profitability & returns on investments of the Domestic Industry has improved during the period of investigation (Balance sheets for the year 2010-11 to 2013-14). The profit before tax has increased from 100 (base year 2010-11) to 130 (2013-14) and 192 (2014-15 annualised). This is evident from the table below:-

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15* (annualised) |
|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Profit/(Loss) | Rs./Lacs | **** | **** | **** | **** | **** |
| Profit/Loss | (Indexed) % | 100 | 172 | 103 | 130 | 192 |

* The profit has been annualised on the basis of half yearly standalone unaudited results for the quarter ending 30.9.2014.

58. It is also seen in the instant case that the domestic industry PBT has increased during the period of investigation and is overall in net profit during the period of investigation. However, the domestic industry has stated that they have suffered losses with regard to the PUC. Therefore, it is imperative to examine the cost audit report of the domestic industry. The DI is manufacturing different types of polyols and PUC is one of them. On examination of costing report, provided by the DI vide letter dated 5.11.2014, it is found that the domestic industry has not taken the cost on proportionate basis as per the cost audit report of polyols provided by the DI vide letter dated 26.9.2014. Had the cost charges for manufacture of PUC been taken on the proportionate basis of cost audit report of polyols the domestic industry might have registered profit in the PUC also.

59. The DI was again requested to provide cost audit data of all the products being manufactured by DI. However, the DI only provided the cost audit data of Polyols vide letter dated 19.12.2014.

60. Thus, in my view, the fact that the domestic industry is not attributing the cost on proportionate basis as per cost audit report of polyols to PUC, has purportedly resulted in loss as claimed by them and import is not responsible for reported loss, if any, on PUC.

I. Other Important Factors:-

61. It is noticed in the table below that the import with respect to demand has increased from 65 % in 2010-11 to 79 % in 2013-14, i.e., by 14%. However, the production of DI has stabilised for the period 2012-13 to 2013-14. The Domestic demand has also increased exponentially.

| Year | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| Sales of Domestic Industry | MT | 16615 | 18192 | 13451 | 13473 |
| Captive consumption | MT | 24 | 50 | 48 | 163 |
| Sales of other producers | MT | 479 | 1941 | 478 | 192 |
| Imports Volume | MT | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 |
| Total Demand/Consumption | MT | 48896 | 55369 | 60341 | 64462 |
| Trend | % | 100 | 113 | 123 | 132 |
| Imports in relation to Demand/consumption | % | 65 | 64 | 77 | 79 |
| Trend | | 100 | 98 | 118 | 121 |

62. From the above analysis, it is seen that the imports of the product under consideration have increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Further, the production capacity of the DI is less than 50% of the total domestic demand/consumption. The DI cannot cater to the total domestic demand/consumption.

63. In the instant case the loss being shown by the DI is because of non-apportioning of the cost of production and sales of PUC on proportional basis to other products and not on account of imports.

64. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, shows a significant improvement in their position. It is thus concluded that, there exists no serious Injury or threat of serious injury to the domestic industry in the period of investigation.

(3). Causal Link between Increased Import and Serious Injury or Threat of Serious Injury:

65 As per Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, The Director General(Safeguards) is obligated to "determine serious injury or threat thereof of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the principles laid down in Annex to the these rules". Further, paragraph 2 of the Annex requires establishment of causal link between alleged increased imports and serious injury or threat thereof. The Paragraph 2 of Annex to Rule 8 provides as follows:

The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.

66. The Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the domestic industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports.

To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its domestic industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the domestic industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the domestic industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors." 1

67. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry have been evaluated. The production and clearance have stabilized. The imports (annualized) are showing a decreasing trend in the year 2014-15. The DI is showing increasing profits, which have almost doubled in the half year 2014-15. It appears that there is no serious injury caused by imports as narrated above, there appears no need for evaluation of causal link between Increased Import and Serious Injury or Threat of Serious Injury.

(4). Adjustment Plan:

68. Rule 5(2)(b) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 requires submission of a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". Further Article 7.1 of WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.

69. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act, 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.

70. The domestic producers in this case have laid down following adjustment plan:

- i) Increase capacity by De-bottlenecking of existing capacity
- ii) Increase capacity utilization levels
- iii) Increase Captive propylene oxide production capacity.
- iv) Bulk transportation of PO and improving logistics.

71. In this regard, it is noted that the DI has provided an adjustment plan which will be implemented across a period of time and no concrete time-bound plan for positive adjustments has been envisaged by the DI. It is also seen that even during 2010-11 and 2011-12 when the DI has shown itself in profit they did not utilize their full capacity. The DI vide letter dated 19.12.2014 has provided a letter of intent for carrying out detailed engineering services for polyol plant. However, there are no specifics regarding the time frame for implementations of the same. Also the order is for expansion of the polyol plant and no specific reference has been made for manufacture of PUC. No further evidence has been provided by the DI regarding expansion. In my view, the DI has not produced viable adjustment plan to become competitive to meet the challenge of imported PUC.

(5). Public Interest:

72. Interest of domestic producers alone cannot be seen as public interest. Even if it is admitted that imposition of safeguard duty on the product under consideration shall protect the domestic producers, the same cannot be termed as public interest. The demand of PUC in India is more 2 times of the total production/capacity of the DI who is the major producer of the PUC in India and as the adjustment plan to increase its capacity is in the nature of proposals and not time-bound in nature, the demand supply gap will increase over the time till DI actually expands the proposed capacity. In view of the huge demand-supply gap and inability of DI to expand its capacity to the extent to meet the total Indian demand in the near future, this will severely hamper the legitimate interest of the user industries. Hence, in these circumstances imposition of Safeguard Duty will not be in public interest at large.

6. Examination of Post POI data:

73. In the given circumstances, an attempt was made to analyse the trend in the period after the POI to draw a clear inference about the possibility of accentuation of the injury to the domestic industry. The domestic industry vide their letter dated 9th December, 2014 submitted the data pertaining to certain economic parameters for the subject "PUC" imported into India for the half year 2014-15.

| Particulars | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (annualised) |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| Total Imports (MT) | 31778 | 35186 | 46364 | 50634 | 44648** |
| Production (MT) | 16510 | 18381 | 13986 | 13811 | 17108* |
| Domestic Sales (MT) | 16615 | 18192 | 13451 | 13473 | 16456* |
| Total Demand (MT) | 48896 | 55369 | 60341 | 64462 | 61104 |
| Market share of imports % | 65 | 64 | 77 | 79 | 73 |
| Market share of DI % | 34 | 33 | 22 | 21 | 27 |
| Profit/Loss (Rs/lacs)# | **** | **** | **** | **** | **** |
| Trend % | 100 | 172 | 103 | 130 | 192 |

* The annualized figures are on the basis of half year data in respect of production/clearance of FSP

** The annualized figures are on the basis of 1st quarter transaction wise import figures received from DGCI&S

Figures from financial records of DI i.e. Balance sheets /financial results.

74. On scrutiny of the said data it is noted that the market share of imports is decreasing and the market share of DI is increasing with relation to the total domestic demand. The profitability of the DI in the year 2013-14 has also increased significantly with relation to the year 2012-13. The current year is also showing similar trends as the profit is on the increase with relation to 2013-14 (based on the financial records of the DI) . This indicates that the position of DI is improving and profitability will further improve.

J) Conclusion:

On examination of forgoing relevant factors I find that:

75. There has been a significant increase in imports in absolute terms as well as in relation to production in relation to the base year.

76. The Market share of the DI has decreased from 34% in 2010-11 to 21 % in 2013-14. However, the total demand increased by 32% in the year 2013-14 in relation to 2010-11. The share of domestic industry is showing an increasing trend and the imports are also showing a decreasing trend in post POI.

77. The production and sales of DI have stabilized during 2012-13 and 2013-14 and are showing increasing trend in post POI period.

78. Increase in imports have resulted in decline in market share of the domestic industry but there is no evidence to suggest overall impairment of the domestic industry as the domestic industry is in overall profit during the period of investigation and loss, if any, is due to other factors. In fact for the year ending March 2014, the domestic industry has announced 10% dividend which also shows that overall position of the domestic industry is good. The imports are showing a decreasing trend post POI, the production and clearance are also showing similar trend and are showing increasing trend in post POI period. It appears that there is no serious injury caused by increased imports.

79. The DI has shown loss in respect of the PUC. However, it is seen that the domestic industry has not taken the cost of PUC on proportionate basis as per the cost audit report of polyols provided by the DI vide letter dated 26.9.2014. Had the cost charges for manufacture of PUC been taken on the proportionate basis in terms of cost audit report the domestic industry might have registered profit in the PUC also. The DI was requested to provide cost data of all the products manufactured by DI. However, the DI provided only the cost audit data of Polyols and not of individual products. Further, since the DI is in overall profits, they apparently seem to have capability to fight the challenge posed by cheaper imports of PUC.

80. The domestic industry is not able to demonstrate that increase in imports is due to existence of unforeseen circumstances.

81. Adjustment plan submitted by the domestic industry has no specified time frame. The DI has submitted a letter of intent to increase the production capacity. However, the letter of intent for expansion is in respect of the polyol plant and no reference to PUC has been made. DI has not produced a viable adjustment plan to become competitive to meet the challenge of imported PUC.

82. There is a huge demand supply gap in the domestic market. In spite of the increased imports the DI has shown increase in profits in the POI. The increase in profits (annualized) in post POI period is almost double to the base year (2010-11). The share of the domestic industry is showing an increasing trend and the share of imports is showing a decreasing trend relative to the domestic demand.

83. Thus, the existence of alleged serious injury or threat of serious injury to domestic industry during the period of investigation does not stand vindicated and therefore, in my view, no protection as prayed for is warranted.

K). Recommendations:

84. In view of the discussions detailed above and the conclusions reached, safeguard duty on the imports of the “Flexible Slabstock Polyol of MW 3000 to 4000” is not recommended and the investigation in this case is terminated.

[F. No. D-22011/4/2014/Pt.-III/4050]

R. K. SINGLA, Director General